शिक्षा निदेशालय

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

सहायक सामग्री
(2023-2024)

कक्षा : ग्यारहवीं

राजनीति विज्ञान

मार्गदर्शन:

श्री अशोक कुमार
सचिव (शिक्षा)

श्री हिमांशु गुप्ता
निदेशक (शिक्षा)

डॉ. रीता शर्मा
अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (स्कूल एवं परीक्षा)

समन्वयक:

श्री संजय सुभास कुमार	श्रीमती रितु सिंघल	श्री राजकुमार	श्री कृष्ण कुमार
उप शिक्षा निदेशक (परीक्षा)	विशेष कार्याधिकारी (परीक्षा)	विशेष कार्याधिकारी (परीक्षा)	विशेष कार्याधिकारी (परीक्षा)

Production Team

Anil Kumar Sharma

Published at Delhi Bureau of Text Books , 25/2 Institutional Area, Pankha Road, New Delhi-110058 by **Rajesh Kumar,** Secretary, Delhi Bureau of Text Books and Printed by Supreme Offset Press, Greater Noida, U.P.

HIMANSHU GUPTA, IAS
Director, Education & Sports

Directorate of Education
Govt. of NCT of Delhi
Room No. 12, Civil Lines
Near Vidhan Sabha,
Delhi-110054
Ph.: 011-23890172
E-mail : diredu@nic.in

MESSAGE

"A good education is a foundation for a better future."
- Elizabeth Warren

Believing in this quote, Directorate of Education, GNCT of Delhi tries to fulfill its objective of providing quality education to all its students.

Keeping this aim in mind, every year support material is developed for the students of classes IX to XII. Our expert faculty members undertake the responsibility to review and update the Support Material incorporating the latest changes made by CBSE. This helps the students become familiar with the new approaches and methods, enabling them to become good at problem solving and critical thinking. This year too, I am positive that it will help our students to excel in academics.

The support material is the outcome of persistent and sincere efforts of our dedicated team of subject experts from the Directorate of Education. This Support Material has been especially prepared for the students. I believe its thoughtful and intelligent use will definitely lead to learning enhancement.

Lastly, I would like to applaud the entire team for their valuable contribution in making this Support Material so beneficial and practical for our students.

Best wishes to all the students for a bright future.

(HIMANSHU GUPTA)

ASHOK KUMAR
IAS

सचिव (शिक्षा)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054
दूरभाष: 23890187 टेलीफैक्स : 23890119

Secretary (Education)
Government of National Capital Territory of Delhi
Old Secretariat, Delhi-110054
Phone : 23890187, Telefax : 23890119
E-mail : secyedu@nic.in

06/09/2022

Message

Remembering the words of John Dewey, "Education is not preparation for life, education is life itself", I highly commend the sincere efforts of the officials and subject experts from Directorate of Education involved in the development of Support Material for classes IX to XII for the session 2023-24.

The Support Material is a comprehensive, yet concise learning support tool to strengthen the subject competencies of the students. I am sure that this will help our students in performing to the best of their abilities.

I am sure that the Heads of Schools and teachers will motivate the students to utilise this material and the students will make optimum use of this Support Material to enrich themselves.

I would like to congratulate the team of the Examination Branch along with all the Subject Experts for their incessant and diligent efforts in making this material so useful for students.

I extend my Best Wishes to all the students for success in their future endeavours.

(Ashok Kumar)

Dr. RITA SHARMA
Additional Director of Education
(School/Exam)

Govt. of NCT of Delhi
Directorate of Education
Old Secretariat, Delhi-110054
Ph.: 23890185

सत्यमेव जयते

संदेश

शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार का महत्वपूर्ण लक्ष्य अपने विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा निदेशालय ने अपने विद्यार्थियों को उच्च कोटि के शैक्षणिक मानकों के अनुरूप विद्यार्थियों के स्तरानुकूल सहायक सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। कोरोना काल के कठिनतम समय में भी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को निर्बाध रूप से संचालित करने के लिए संबंधित समस्त अकादमिक समूहों और क्रियान्वित करने वाले शिक्षकों को हार्दिक बधाई देती हूँ।

प्रत्येक वर्ष की भाँति इस वर्ष भी कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक की सहायक सामग्रियों में सी.बी.एस.ई. के नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। साथ ही साथ मूल्यांकन से संबंधित आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। इन सहायक सामग्रियों में कठिन से कठिन पाठ्य सामग्री को भी सरलतम रूप में प्रस्तुत किया गया है ताकि शिक्षा निदेशालय के विद्यार्थियों को इसका भरपूर लाभ मिल सके।

मुझे आशा है कि इन सहायक सामग्रियों के गहन और निरंतर अध्ययन के फलस्वरूप विद्यार्थियों में गुणात्मक शैक्षणिक संवर्धन का विस्तार उनके प्रदर्शनो में भी परिलक्षित होगा। इस उत्कृष्ट सहायक सामग्री को तैयार करने में शामिल सभी अधिकारियों तथा शिक्षकों को हार्दिक बधाई देती हूँ तथा सभी विद्यार्थियों को उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ।

रीता शर्मा

(रीता शर्मा)

शिक्षा निदेशालय

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

सहायक सामग्री

(2023-2024)

राजनीति विज्ञान

कक्षा : ग्यारहवीं

निःशुल्क वितरण हेतु

दिल्ली पाठ्य-पुस्तक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक [1]**[संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य]** बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन **सब में**

व्यक्ति की गरिमा और [2]**[राष्ट्र की एकता**

और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली **बंधुता**

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

---

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) ''प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) ''राष्ट्र की एकता'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a [1]**[SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC]** and to secure to all its citizens :

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the [2][unity and integrity of the Nation];

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949 do **HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.**

1. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, Sec.2, for "Sovereign Democratic Republic" (w.e.f. 3.1.1977)
2. Subs. by the Constitution (Forty second Amendment) Act, 1976, Sec.2, for "Unity of the Nation" (w.e.f. 3.1.1977)

भारत का संविधान

भाग 4क

नागरिकों के मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51 क

मूल कर्तव्य - भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह -

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;

(ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे;

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों;

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू सके; और

(ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

Constitution of India

Part IV A (Article 51 A)

Fundamental Duties

It shall be the duty of every citizen of India —

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;

(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;

(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for living creatures;

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;

*(k) who is a parent or guardian, to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.

Note: The Article 51A containing Fundamental Duties was inserted by the Constitution (42nd Amendment) Act, 1976 (with effect from 3 January 1977).

*(k) was inserted by the Constitution (86th Amendment) Act, 2002 (with effect from 1 April 2010).

SUPPORT MATERIAL
POLITICAL SCIENCE
Class XI (2023-24)

TEAM LEADER :

Sh. Santosh Sahni	Vice Principal	GBSSS-Nehru Vihar (School ID: 1207114)

MEMBER :

1. Nishi Prabha	Lecturer	Dr. BRA-SOSE/RPVV, Nand Nagri (School ID: 1106252)
2. Prem Kumar	Lecturer	Dr. BRA-SOSE/RPVV, Sector-10, Dwarka (School ID: 1821137)
3. Dr. Alpna Singhal	Lecturer	DR. BRA-SOSE, Sector-22, Dwarka (School ID: 1821282)
4. Ram Swaroop Meena	Lecturer	DR. BRA-SOSE/RPVV, Karol Bagh Link Road(School ID: 2128031)
5. Nand Kishore	Lecturer	RSBV Dallupura (School ID: 1002013) Members Core Acadmic Unit (old Secti)
6. Md. Nasir	Lecturer	SBV No. 1 (UM) Jama Masjid, Delhi-110006 (School ID: 2127002

POLITICAL SCIENCE SYLLABUS-2023-2024

CLASS XI
COURSE STRUCTURE

Chapter No.	Chapter Name	No. of Periods	Marks Allotted
PART A-INDIAN CONSTITUTION AT WORK			
1	Constitution: Why and How?	12	8
2	Rights in the Indian Constitution	8	
3	Election and Representation	14	6
4	Executive	14	12
5	Legislature	14	
6	Judiciary	14	
7	Federalism	14	6
8	Local Governments	10	4
9	Constitution as a Living Document	6	4
10	The Philosophy of the Constitution	6	
No. of periods & marks allotted to Indian Constitution at Work		**112**	**40**
PART B-POLITICAL THEORY			
1	Political Theory: An Introduction	8	4
2	Freedom	10	12
3	Equality	12	
4	Social Justice	12	6
5	Rights	14	4
6	Citizenship	12	8
7	Nationalism	15	
8	Seculansm	16	6
No. of periods & marks allotted for Political Theory		**99**	**40**
Total		**211**	**80**

CLASS XI-XI

QUESTION PAPER DESIGN

S. No.	Competencies	Marks	Percentage
1	Knowledge and Remembering: Exhibit memory of previously learned material by recalling facts, terms, basic concepts.	22	27.5%
2	Understanding: Understanding of facts and ideas by organizing, comparing, explaining, describing, and stating main ideas.	24	30%
3	Applying: Solve problems by applying acquired knowledge, facts to interpret a situation/ cartoon/ clippings/sources/Map	22	27.5%
4	Analysis and Evaluation: Classify, compare, contrast, or differentiate between pieces of information; organize and/ or integrate from a variety of sources; Examine, synthesize information into parts and identify motives or causes. Make inferences and find evidence to support generalizations.	12	15%
		80	**100%**

Note: Competency based questions for the examinations to be conducted in the academic year 2023-24 will be 40% in class XII.

QUESTION PAPER DESIGN

Book	Objective Type/ MCQ (1 Mark)	Short Answers Type I (2 Marks)	Short Answers Type II (4 Marks)	Passage Map Cartoon based (4 Marks	Long Answers (6 Marks)	Total Marks
Book 1 Contemporary World Politics	6	3	3	1 (Passage)	2	40
Book 2 Politics in India since Independence	6	3	2	2 (Cartoon and Map)	2	40
Project/Practical						20
Total No. of Marks and Questions	**1x12=12**	**2x6=12**	**4x5=20**	**4x3=12**	**6x4=24**	**80+20=100**

❑ Scheme of Options:

- Question paper will be in five parts (A, B, C, D & E). There will be an internal choice in Part C (Short Answer Type II in one or two questions) and Part-E. (Long Answers in all the questions)
- In order to assess different mental abilities of learners, question paper is likely to include questions based on passages, visuals such as maps, cartoons. No factual question will be asked on the information given in the plus
- (+) boxes in the textbooks.
- Map question can be given from any lesson of Book 2(Politics in India since Independence); but weightage of lessons should remain unaltered.
- Cartoon and passage-based questions can be asked from either textbook, but weightage of lessons should be maintained.

वषिय सूची

अध्याय	विषय	पृष्ट
अध्याय-1	संविधान क्यों और कैसे	1
अध्याय-2	भारतीय संविधान में अधिकार	23
अध्याय-3	चुनाव और प्रतिनिधित्व	43
अध्याय-4	कार्यपालिका	61
अध्याय-5	विधायिका	85
अध्याय-6	न्यायपालिका	107
अध्याय-7	संघवाद	123
अध्याय-8	स्थानीय शासन	139
अध्याय-9	संविधान : एक जीवंत दस्तावेज	159
अध्याय-10	संविधान का दर्शन	173
अध्याय-11	राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय	185
अध्याय-12	आजादी	197
अध्याय-13	समानता	215
अध्याय-14	सामाजिक न्याय	229
अध्याय-15	अधिकार	251
अध्याय-16	नागरिकता	273
अध्याय-17	राष्ट्रवाद	293
अध्याय-18	धर्म निरपेक्षता	307

अध्याय-1

संविधान क्यों और कैसे

संविधान की आवश्यकता क्यों, संविधान की सत्ता, भारतीय संविधान कैसे बना, विभिन्न देशो के संविधानों से लिए गए प्रावधान।

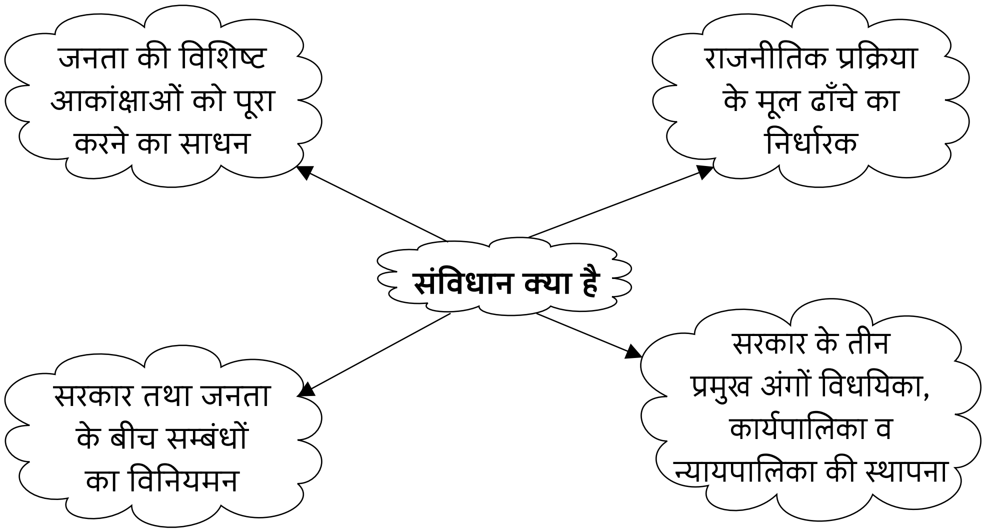

संविधान की आवश्यकताः-

- मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज विभिन्न प्रकार के समुदायों से बनता है। इन समुदायों में तालमेल बैठाने के लिए संविधान जरूरी है।
- संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध करवाता है।
- संविधान यह भी तय करता है कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी।
- संविधान सरकार निर्माण के नियमों एवं उपनियमों तथा उसकी शक्तियों एवं सीमाओं को तय करता है।
- एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भी संविधान जरूरी है।

→ **संविधान की आवश्यकता**

→ **तालमेल बढ़ाना**

→ **बुनियादी नियम निश्चित करना**

→ **सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाना**

→ **जनता की आकांक्षा को पूरा करना**

→ **राष्ट्र की बुनियादी पहचान सुनिश्चित करना**

संविधान की सत्ता

- राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरणा प्राप्त करना
- संविधान निर्माताओं में सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की क्षमता
- समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करने तथा सम्मान प्राप्त करने की क्षमता
- लोकप्रिय नेताओं तथा समर्थन पर आधारित
- अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण
- विधायिका कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच संस्थागत संतुलन स्थापित करना
- मूल्यों, नियमों तथा प्रक्रियाओं की कार्यप्रणाली में लचीलापन
- बदलती आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की कार्य क्षमता

संविधान सभा का गठन

संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई तथा 14 अगस्त, 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में पुनः इसकी बैठक हुई।

संविधान सभा की स्थापना ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति "कैबिनेट मिशन" के प्रस्ताव पर हुई।

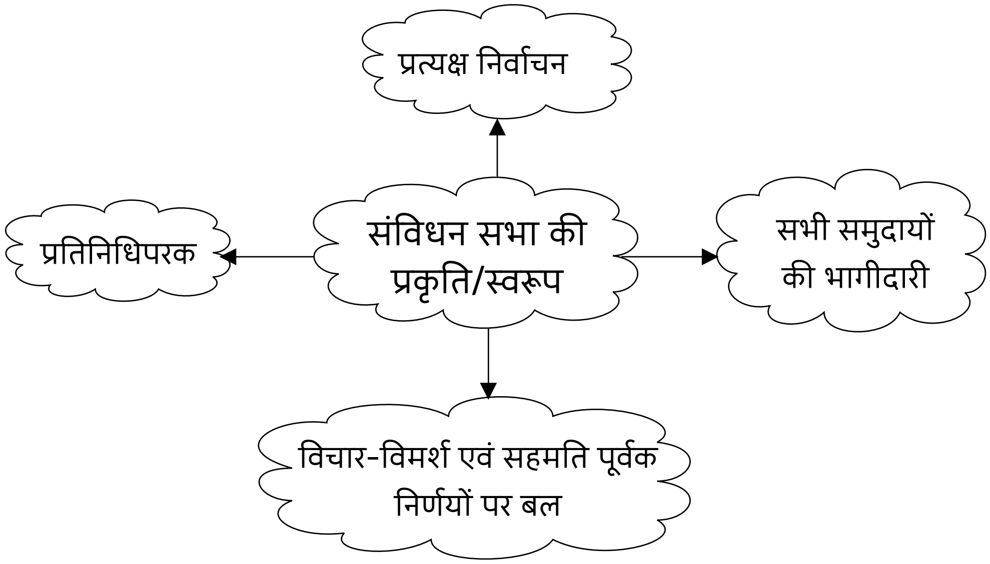

भारतीय संविधान कैसे बना

- संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन का समय लगा तथा कुल 166 बैठकें हुई।
- 26 नवम्बर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से लागू कर दिया गया।

राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत

↓

सहमति पर आधारित निर्णय

↓

1946 के उद्देश्य प्रस्ताव से प्रभावित

↓

बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया जाना

संस्थागत व्यवस्थाएं

- शासन के लिए विभिन्न अंगों विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच समुचित संतुलन स्थापित करना
- संवैधानिक प्रधानों को भारतीय समस्याओं तथा आशाओं के अनुरूप ग्रहण करना

भारतीय संविधान के स्रोतः-

- संविधान का लगभग 75 प्रतिशत अंश भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया था।
- 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट से मूल मानव अधिकारों को शामिल किया गया।
- अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली से भी कुछ बातें भारत के संविधान में समाहित की गई जैसे:-

(क) ब्रिटिश संविधानः

(i) सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला।
(ii) सरकार का संसदीय स्वरूप।
(iii) कानून के शासन का विचार।
(iv) विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी -कानून निर्माण की विधि।

(ख) अमेरिका का संविधानः

(i) मौलिक अधिकारों की सूची, संविधान की प्रस्तावना
(ii) न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उप राष्ट्रपति का पद

(ग) आयरलैंड का संविधानः

(i) राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का प्रावधान

(घ) फ्रांस का संविधानः

(i) स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का सिद्धान्त।

(ड.) कनाडा का संविधानः

(i) एक अर्द्ध-संघात्मक सरकार का स्वरूप (सशक्त केन्द्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था)।
(ii) अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धान्त।

इसलिए भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। दूसरी तरफ भारत के संविधान को पुष्प गुच्छ (Bouquet) भी कहा जाता है जिसमें विभिन्न देशो से लिए गए सिद्धान्त रुपी पुष्प शामिल है।

प्रश्नावली

1. अभिकथन एवं तर्क आधारित प्रश्न

अभिकथन (A) भारत कि संविधान को उधार का थैला कहा जाता है।

तर्क (R) भारतीय संविधान में कई प्रावधानों को अन्य देशों के संविधान से लिये गये है।

(क) कथन A तथा R दोनों सही है तथा R कथन A की सही व्याख्या है

(ख) दोनों कथन A और R सही है लेकिन R कथन A की सही व्याख्या नहीं है

(ग) A गलत है और R सही है

(घ) A सही है लेकिन R गलत है

2. अभिकथन (A) संविधान यह तय करता है कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी।

तर्क (R) संविधान कानून एवं नियमों का समुच्चय है।

(क) कथन A तथा R दोनों सही है तथा R कथन A की सही व्याख्या है

(ख) दोनों कथन A और R सही है लेकिन R कथन A की सही व्याख्या नहीं है

(ग) A गलत है और R सही है

(घ) A सही है लेकिन R गलत है

प्रश्नावली

एक अंकीय प्रश्नः-

1. भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे।

   (क) डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ख) राजेंद्र प्रसाद

   (ग) पंडित जवाहरलाल नेहरू (घ) सरदार वल्लभभाई पटेल

2. कठोर संविधान से आप क्या समझते हैं?

   (क) जिसमें आसानी से संशोधन हो सकते हैं

   (ख) जनता के निर्णयों पर आधारित।

   (ग) जिसमें सरलतापूर्वक संशोधन नहीं हो सकते

   (घ) इनमें से कोई नहीं

3. अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान सभा पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए?

   (क) 284 सदस्यों ने (ख) 288 सदस्यों ने

   (ग) 290 सदस्यों ने (घ) 294 सदस्यों ने

4. भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनूसूचियां है?

   (क) 8 (ख) 10

   (ग) 11 (घ) 12

5. मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया?

   (क) ब्रिटेन (ख) संयुक्त राज्य अमेरिका

   (ग) आयरलैंड (घ) जापान

6. संविधान का कौन-सा ऐसा प्रधान था जो लगभग बिना किसी वाद-विवाद के पारित हो गया?

   (क) संसदीय प्रणाली (ख) न्यायपालिका की शक्तियां

   (ग) विकेंद्रीकृत प्रणाली (घ) सर्व भौमिक मताधिकार

7. संविधान में व्यक्ति को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं

(क) 4 (ख) 6

(ग) 7 (घ) 8

8. संविधान सभा का निर्माण हुआ।

(क) कैबिनेट मिशन के सदस्यों द्वारा

(ख) 1935 में स्थापित प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा

(ग) माउंटबेटन प्लान द्वारा

(घ) क्रिप्स मिशन द्वारा

9. संविधान सभा की प्रकृति थी।

(क) प्रतिनिधिपरक (ख) स्वेच्छाचारी

(ग) अधिनायक वादी (घ) इनमें से कोई नहीं

10. अवशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत को लिया गया है।

(क) अमेरिका के संविधान से (ख) फ्रांस के संविधान से

(ग) श्रीलंका के संविधान से (घ) कनाडा के संविधान से

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें।

11. क्रिप्स मिशन .... वर्ष भारत आया।

12. सोवियत संघ के संविधान में निर्णय का अधिकार .... दिया गया।

13. संविधान सभा का निर्वाचन .... द्वारा किया गया।

14. संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव .... ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया।

15. भारतीय संविधान .... को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मर्पित किया।

निम्नलिखित कथन को सही करके लिखें।

16. समाज के सदस्यों में न्यूनतम समन्वय तथा विकास स्थापित करना संविधान सभा का कार्य है।

17. मौलिक अधिकारों का प्रावधान ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया।

निम्नलिखित कथन बताएं कि सही है या गलत।

18. भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला होता है।

19. कानून के शासन का अभिप्राय है सभी व्यक्ति कानून की नजर में समान है तथा कानून सभी पर समान रूप से लागू नहीं होगा।

20. भारतीय संविधान सभा का निर्माण माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप हुआ।

21. भारतीय संविधान सभा प्रतिनिधि परक नहीं थी।

अति संक्षिप्त प्रश्न

22. संविधान की प्रस्तावना से क्या अभिप्राय है?

23. क्रिप्स मिशन ने भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा था?

24. हमारा संविधान किसके प्रति प्रतिबद्ध है?

25. भारत में राज्य को धर्म के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की आवश्यकता क्या हैं?

26. किस देश के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है।

27. पारस्परिक निषेध का क्या अर्थ है?

28. अनुच्छेद 371 (ए) क्या है?

29. किसने 19वीं सदी के शुरूआती समय में ही प्रेस की आजादी पर प्रतिबंध का विरोध किया था?

30. मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में मताधिकार के बारे में क्या सुझाव दिया गया था?

31. भारतीय संविधान सभा के स्थाई अध्यक्ष कौन थे?

32. भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा?

33. फ्रांस के संविधान से भारतीय संविधान में किन प्रावधानों को अंगीकृत किया गया?

34. सुमेलित करें।

ब्रिटेन का संविधान	मूल अधिकार
कनाड़ा का संविधान	कानून का शासन
आयरलैण्ड का संविधान	अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धान्त
अमेरिका का संविधान	नीति निर्देशक तत्व

दो अंकीय प्रश्नः-

1. 'संविधान' क्यों महत्वपूर्ण है?
2. यदि संविधान में मूलभूत कानूनों/नियमों का अभाव होता तो क्या होता?
3. संविधान के दो महत्वपूर्ण कार्य लिखिए।
4. "संविधान समाज की सामूहिक भलाई करने वाला स्रोत है।" उपर्युक्त कथन को दक्षिण-अफ्रीका एवं इंडोनेशिया के संदर्भ मे समझाइए।
5. भारतीय संविधान की आलोचनाओं पर प्रकाश डालें।
6. अनुसूचित जाति और जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए संविधान में कौन से उपाय किए गए हैं?
7. भारतीय संविधान की क्या सीमाएं है?
8. संविधान राज्य पर कैसे अंकुश लगाता है?
9. सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार क्या है और उसे एक उपलब्धि क्यों माना जाता है?
10. भारतीय संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा तथा कुल कितनी बैठकें हुई?
11. संविधान सभा की प्रारूप समिति के गठन को संक्षेप में समझाइए।

चार अंकीय प्रश्न

1. भारतीय संविधान के गठन पर प्रकाश डालें।
2. संविधान सभा की क्या कमियां थी?
3. भारतीय संविधान को किस प्रकार संतुलित एवं सुदृढ़ बनाया गया है?
4. एक सफल संविधान की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है वर्णन करें।
5. किसी समाज में संविधान की जरूरत क्यों होती है?
6. संविधान सभा ने किस प्रकार सफलतापूर्वक अपना कार्य किया।
7. संविधान सभा की प्रकृति का वर्णन करें।
8. भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर प्रकाश डालें।

चार अंकीय प्रश्नः- (अवतरण आधारित प्रश्न)

1. संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। संविधान इस प्रश्न का भी उत्तर देता है कि वह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करेगा। संविधान यह तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की सीमा भी तय करता है। एक सभ्य समाज के लिए एक संविधान आवश्यक है। संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धातों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं।

   1. संविधान क्या है?

      (A) नियमों का समूह　　(b) आधारभूत सिद्धांतों का समूह
      (c) दिशा निर्देशों का समूह　　(d) उपयुक्त में कोई नहीं उपर्युक्त

   2. भारतीय संविधान में कानून निर्माण की शक्ति किसे प्रदान की है?

      (a) कार्यपालिका　　(b) न्यायपालिका
      (c) विधायिका　　(d) सरकार

   3. कौन सी संस्था लोगों को आधारभूत पहचान प्रदान करती है?

      (a) सरकार　　(b) कार्यपालिका
      (c) संविधान　　(d) उपरोक्त सभी

4. भारतीय संविधान कब बना?

(a) 24 नवंबर, 1949 (b) 26 नवंबर, 1949

(c) 28 नवंबर, 1949 (d) 30 नवंबर, 1949

2. भारतीय संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और सदस्यों के विचार विमर्श की जड़ में छुपे मूल्यों में ही संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता का आधार था। जहां प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली किसी सभा के लिए वांछनीय है कि उसमें सभी वर्गों की सहभागिता हो। वही यह भी आवश्यक है कि वे केवल अपनी पहचान या समुदाय का ही प्रतिनिधित्व नहीं करें। संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया। संविधान सभा की असली ताकत ऐसी बातें थी कि वह सार्वजनिक हित का काम कर रही थी और इसके सदस्यों ने चर्चा तथा तर्कपूर्ण बहसों पर काफी जोर दिया। यह बहसें फ्रांसीसी तथा अमेरिकी क्रांति की तरह संविधान निर्माण के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और यादगार अध्याय में से है।

1. संविधान सभा के कामकाज की शैली किस प्रकार थी?

(A) सर्वाधिकारवादी (b) लोकतांत्रिक

(c) अलगाववादी (d) उपयुक्त में से कोई नहीं

2. क्या आप जानते हैं कि संविधान सभा सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रही थी?

(A) सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व करती थी

(b) केवल कुछ वर्गों का प्रतिनिधित्व करती थी

(c) समाज के किसी भी वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी

(d) उपयुक्त में से कोई नहीं

3. संविधान सभा की लोकप्रियता का आधार क्या था?

(A) सैद्धांतिक संगठन (b) संकुचित दृष्टिकोण

(c) सार्वजनिक विश्वसनीयता (d) उपयुक्त में से कोई नहीं

4. संविधान सभा में मतभेदों को किस प्रकार से हल किया गया?

(A) विवाद द्वारा (b) टकराव द्वारा

(c) विचार-विमर्श द्वारा (d) उपयुक्त सभी द्वारा

चार अंक का प्रश्न (अभ्यास के लिए कार्टून आधारित प्रश्न)

नीचे दिए गए कार्टून को देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें

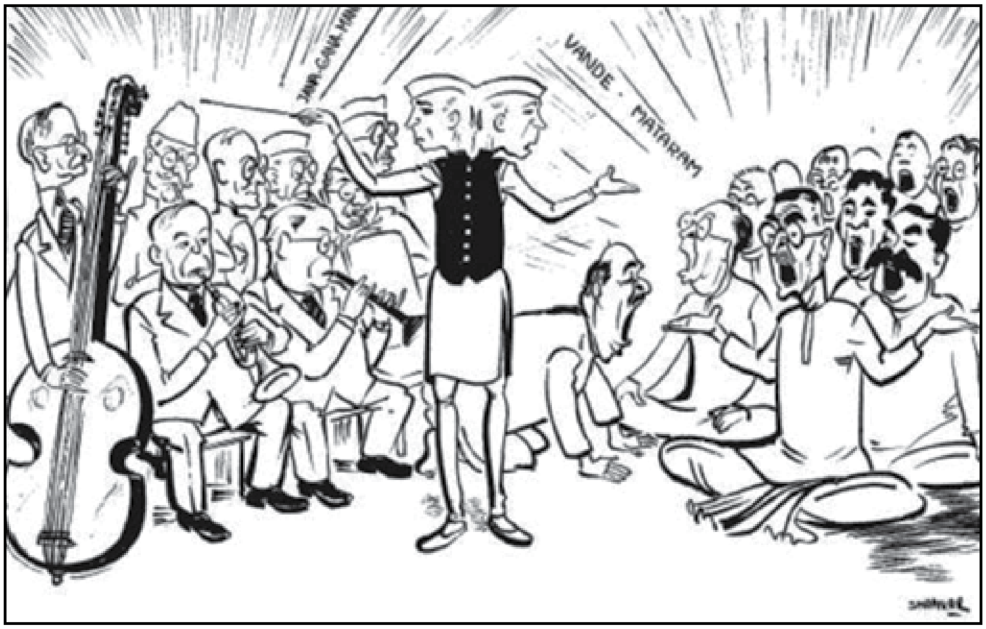

1.1 बीच में खड़ा व्यक्ति कौन है?

1.2 बाएं और बैठे लोगों के समूह की सांस्कृतिक विचारधारा क्या है?

1.3 दाहिने हाथ की ओर बैठे लोगों के समूह की सांस्कृतिक विचारधारा क्या है?

1.4 इन दोनों विचारधाराओं को संतुलित करने के लिए क्या निर्णय लिया गया?

(क) बीच में खड़ा व्यक्ति कौन है? 1

(ख) व्यक्ति के दायीं और बायीं ओर बैठे सदस्य किस-किस विचारधारा के हैं? 2

(ग) दोनों विचारधाराओं को संतुलित करने के लिए क्या निर्णय लिया गया? 2

अथवा

भारतीय संविधान को उधार लिए गये सिद्धांतों का टोकरा कहा जाता है उपरोक्त कथन को स्पष्ट करो।

छः अंकीय प्रश्नः-

1. एक सभ्य समाज के निर्माण में संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है, सविस्तार समझाइए।

2. भारतीय संविधान सभा की रचना, ब्रिटिश मंत्रीमंडल की किस समिति द्वारा प्रस्तावित की गई थी? इस योजना के प्रस्तावों को सविस्तार समझाइए।

3. कौन-सी विशेषतायें भारतीय संविधान को विशिष्ट बनाती है।

4. एक सफल एवं प्रभावी संविधान कठोरता एवं लचीलेपन का अद्भुत समन्वय होता है इस उक्ति को भारतीय संविधान के सन्दर्भ में पुष्ट करें।

5. भारतीय संविधान की प्रस्तावना मे वर्णित निम्नलिखित शब्दों को सविस्तार समझाइए- (क) न्याय, (ख) स्वतंत्रता, (ग) समानता, (घ) बंधुत्व, (ड.) धर्मनिरपेक्षता, (च) समाजवादी।

6. सिद्ध कीजिए कि भारतीय संविधान एक 'पुष्प-गुच्छ' (Bouquet) की भांति है जिसमें सभी देशों के पुष्प समाहित हैं।

अथवा

"भारतीय संविधान उधार लिए गये सिद्धान्तों का टोकरा है।" समझाइए।

उत्तरमाला

अभिकथन एवं तर्क (आधारित प्रश्नों के उत्तर)

1. (क)
2. (ख)

एक अंकीय प्रश्नों के उत्तरः-

1. डॉ राजेंद्र प्रसाद
2. जिसमें सरलतापूर्वक संशोधन नहीं हो सकते।
3. 284 सदस्यों ने
4. 12 अनुसूचियां
5. संयुक्त राज्य अमेरिका
6. (घ)
7. (ख)
8. (घ)
9. (ख)
10. (क)
11. मार्च 1942 में
12. कम्युनिस्ट पार्टी को
13. अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली
14. जवाहरलाल नेहरू
15. 26 नवम्बर 1949
16. समाज के सदस्यों में न्यूनतम समन्वय तथा विकास स्थापित करना संविधान का कार्य है।
17. मौलिक अधिकारों का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया।
18. सही

19. गलत

20. गलत

21. गलत

22. संविधान की प्रस्तावना में संविधान के लोकतांत्रिक आदर्श, मूल्य समाहित किए गए हैं।

23. क्रिप्स मिशन ने सुझाया कि भारतीय संघ की स्थापना संविधान के द्वारा होगी जिसका निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा।

24. हमारा संविधान लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है।

25. धर्म से संबंधित रिवाज जैसे छुआछूत की कुरीतियों को समाप्त करने में, किसी के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे इसके लिए राज्य व धर्म एक दूसरे के अंदरूनी मामलों से दूर रहेंगे।

26. जापान

27. धर्म व राज्य एक दूसरे के अंदरूनी मामलों से दूर रहेंगे।

28. अनुच्छेद 371 (ए) में नागालैंड को विशेष दर्जा दिया गया है।

29. राजा राममोहन राय

30. 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट से मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया।

31. डॉ राजेंद्र प्रसाद

32. भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा तथा कुल 166 बैठक हुई।

33. फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को अपनाया गया।

34.

ब्रिटेन का संविधान	कानून का शासन
कनाडा का संविधान	अवशिष्ट शक्तियों का हिस्सा
आयरलैण्ड का संविधान	नीति निर्देशक तत्व
अमेरीका का संविधान	मूल अधिकार

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तरः-

1. संविधान समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

2. संविधान के अभाव में समाज का प्रत्येक सदस्य अपने आपको असुरक्षित महसूस करता। क्योंकि उसे इस ज्ञान का अभाव होता कि दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है। समाज में अराज़कता होती है।

3. (1) मूलभूत नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराना, जिससे समाज में एक दूसरें में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बने।

   (2) यह तय करना कि समाज में अन्तिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी।

4. (1) दक्षिण अफ्रीका का संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है, जैसे- पर्यावरण संरक्षण करना तथा अन्यायपूर्ण भेदभाव को समाप्त करना

   (2) इंडोनेशिया में सरकारी जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए तथा गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करें।

5. a) विस्तृत संविधान

   b) भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं

   c) उधार मांगा हुआ संविधान।

   d) सबकी नुमाइंदगी नहीं। (कोई दो)

6. a) उचित प्रतिनिधित्व, संसद में सीटों का आरक्षण

   b) सरकारी नौकरी तथा शिक्षा संस्थानों में भी आरक्षण

7. a) राष्ट्रीय एकता की धारणा केन्द्रीकृत

   b) सामाजिक आर्थिक अधिकारों को राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाले खंड में डाला गया है।

   c) लिंगगत न्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे परिवार से जुड़े मामलों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है।

8. संविधान सिद्धान्तों का समूह है जिसके माध्यम से राज्य की सीमाएं निर्धारित होती जिससे किसी समूह के हितों का नुकसान न हो और लोगों के अधिकारों का दुरूपयोग न हो।

9. भारत के सभी लोगों को जो 18 वर्ष के हो चुके हैं उन्हें मत देने का अधिकार है।

   सर्वभौम मताधिकार उस समय प्रदान किया गया जब पश्चिम में कामगार वर्ग और महिलाओं को मताधिकार प्रदान नहीं किया गया था।

10. 2 वर्ष, 11 महीने 18 दिन तथा 166 बैठक है।

11. 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में सात सदस्य समिति का गठन इस समिति ने संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा अध्यक्ष को पेश किया।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तरः-

1. पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946, अस्थायी अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। 11 दिस्मबर 1946 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति।

   सदस्य संख्या 389, (292+4+93)। 14 अगस्त 1947, विभाजित भारत संविधान सभा बैठक, कुल बैंठकें-166।

संविधान सभा की कमियां:-

2. (i) प्रभुसत्ता की कमी।

   (ii) प्रांतों का अनुचित वर्गीकरण।

   (iii) देशी रियासतों को संविधान को मानने के लिए बाध्य नहीं किया।

   (iv) संविधान सभा के सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक तरीके से किया गया।

3. (i) शक्तियों का विकेन्द्रीकरण- संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची तथा विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में शक्तियों का बंटवारा।

   (ii) संवैधानिक निकायों को शक्तिशाली बनाना, जैस-स्वतंत्र चुनाव आयोग।

4. (i) एक सफल संविधान वही हैं जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों (स्वतंत्रता, समानता एवं सामाजिक न्याय) को तरजीह दी जायें।

   (ii) जनता के प्रति जवाबदेही संविधान की सफलता का आधार।

   (iii) सामाजिक समस्याओं का समाधान।

(iv) समुचित सन्तुलन एवं समन्वय।

5. (i) प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कारण अवश्य होना चाहिए।

(ii) बहुसंख्यको से अल्पसंख्यकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना

(iii) समान सुविधाएं उपलब्ध कराना।

(iv) छोटे सामाजिक समूहों की शक्ति को मजबूत करना।

(v) समाज में सभी की स्वतंत्रता की रक्षा करना।

6. (i) संविधान सभा द्वारा सरकार के तीनों अंगों के बीच समुचित संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत विचार मंथन किया।

(ii) विधायिका और कार्यपालिका के बीच तथा केन्द्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया।

7. 1. प्रतिनिधिपरकः

2. सभी समुदायों की भागीदारी

3. विचार-विमर्श एवं सहमति पर आधारित

4. अप्रत्यक्ष निर्वाचन

8. a) प्रभुत्व संपन्न e) गणराज्य

b) समाजवादी f) न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक)

c) धर्मनिरपेक्ष g) स्वतंत्रता (विचार, अभिव्यक्ति, धर्म)

d) लोकतंत्र h) समानता

1. अवतरण आधारित प्रश्नों के उत्तर

1-B, 2-C, 3-C, 4-B

2. 1-B, 2-A, 3-C 4-C

कार्टून आधारित प्रश्न का उत्तर

1.1 (a) जवाहरलाल नेहरू

1.2 (b) पश्चिमी विचारधारा

1.3 (c) स्वदेशी/ भारतीय विचारधारा

संविधान राष्ट्र के विभिन्न वर्गों और संस्कृतियों को कुछ सुरक्षा प्रदान करता है। देश में इतने सारे मतभेदों और विविधताओं के बावजूद सभी वर्गों, विचारधाराओं को उनकी गरिमा के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाता है।

चार अंकीय प्रश्न का उत्तर

अथवा

सिद्धांतों को टुकड़े के रूप में देखें तो टुकड़े में विभिन्न वस्तुएं होती हैं उसी भांति इस भारतीय संविधान रूपी टोकरे में- इंग्लैंड, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि का उदाहरण देते हुए स्वयं को वर्णन करेंगे। जैसे देशों के संविधानिक सिद्धांतों को लिया गया है जिसे हम उधार ली गई वस्तुओं के रूप में देखते हैं।

1. आवश्यकताओं के अनुरूप
2. परिस्थितियों के अनुरूप
3. आशाओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप

छः अंकीय प्रश्नों के उत्तरः-

1. सभ्य समाज में स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे मूल्य संविधान ही प्रदान करता है। संविधान ही सदस्यों के बीच सहयोग एवं तालमेल स्थापित करता है।
2. (i) ब्रिटिश मंत्रिमंडल समिति-'कैबिनेट मिशन'।
   (ii) सदस्यों का चयन - ब्रिटिश प्रान्तों से (292) + देशी रियासतों से (93) + चीफ कमिशनरों से (4) = 389 सदस्य।
   (iii) प्रत्येक प्रांत की सीटों को तीन प्रमुख समुदायों-मुसलमान, सिख और सामान्य में बंटवारा।
   (iv) प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना।
   (v) देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श इसे तय किया गया आदि।
3. संविधान की विशेषताएँ: जो भारतीय संविधान को विशिष्ट बनाते हैं-
   (i) जन प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित, लिखित एक सम्पूर्ण संविधान।
   (ii) यह सम्पूर्ण प्रभुत्वसंपन्न, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य का निर्माण करता है।

(iii) नागरिकों को मूल अधिकार के साथ मूल कर्त्तव्यों की याद दिलाता है।

(iv) स्वतंत्र न्यायपालिका है।

(v) संसदीय शासन व्यवस्था।

(vi) राज्य के नीति निर्देशक तत्व आदि।

4. न्याय-सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना।

   स्वतंत्रता-अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म, कर्म और उपासना भक्ति की स्वतंत्रता।

   समानता - सभी प्रकार के भेदभावों का अन्त या भेदभावों से मुक्ति।

   बंधुत्व- देश के हर नागरिक के बीच आपसी प्यार/स्नेह के भाव पैदा करना।

   धर्म निरपेक्षता-सभी धार्मिक विचारों वाले नागरिकों को धर्म को मानने की आजादी।

   समाजवादी- सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक जन कल्याण, समाज कल्याण के कार्य हो, लोकहित कारी कार्य हो। समाज सर्वोपरी।

5. भारतीय संविधान एक 'पुष्प गुच्छ' इस रूप में है कि इस गुच्छ में विभिन्न देशों के संवैधानिक सिद्धान्त रूपी फूल शामिल किए गये है। विभिन्न देशों की अच्छी बातों को संविधान में समाहित किया गया है।

अध्याय-2

भारतीय संविधान में अधिकार

भारतीय संविधान में अधिकार

अधिकार क्या है?

अधिकार सामाजिक जीवन की वे शर्त है जिनके बिना कोई भी मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता।

कर्तव्य

1976 में, 42वां संविधान संशोधन ने नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची को शामिल किया है। (अनुच्छेद 51 (A) 10 मौलिक कर्तव्य थे। 86वें संविधान संशोधन के आधार पर वर्ष 2002 में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया।

मौलिक अधिकार

संविधान में वर्णित छः मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3 इस प्रकार है-

(1) समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से 18)

(2) स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)

(3) शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)

(4) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)

(5) संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 -30)

(6) संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

अधिकारों की घोषणा

1928 में पंडित मोती लाल नेहरू द्वारा अधिकारों की मांग उठाई गई थी। मोती लाल नेहरू समिति ने अधिकारों की मांग को सूचीबद्ध किया था। संविधान में संपत्ति के अधिकार को **44वें** संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था।

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत

स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों में समानता और कल्याण लाने के लिए। मौलिक अधिकार के अलावा कई नियमों को संशोधित किया गया। राजनीति के निर्देशात्मक सिद्धांतों के तहत सरकारों को इसी तरह से नीति निर्देश दिए गए, जिन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती लेकिन लागू करने के लिए कहा जा सकता है, तो यह सरकार की जिम्मेदारी है कि इसे लागू किया जा सकता है।

निवारक नजरबंदी

सामान्यतः किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार करते हैं, जब उसने अपराध किया हो, पर इसके अपवाद भी हैं कभी-कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है, और फिर उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। इसे ही "निवारक नजरबंदी" कहते हैं

मुख्य बिंदु

1. अधिकार अर्थ एवं महत्व
2. अधिकारों का घोषणा पत्र
3. भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार
4. सामान्य अधिकार
5. मौलिक अधिकार
6. दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सूचीबद्ध प्रमुख अधिकार
7. राज्य के नीति निर्देशक तत्व
8. नागरिकों के मौलिक कर्तव्य
9. नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में संबंध
10. नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक अधिकारों में अंतर

1. अधिकार

- अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां है जिनके बिना कोई भी मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। अधिकार वे हक है, जो एक आम आदमी को जीवन जीने के लिए चाहिए, जिसको वह मांग करता है कानून द्वारा प्रदत्त सुविधाएं अधिकारों की रक्षा करती है।

2. अधिकारों का घोषणा पत्र:-

- अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया है ऐसी सूची को अधिकारों को घोषणापत्र करते हैं। जिसकी मांग 1928 में पंडित मोती लाल नेहरु जी ने उठाई थी।

3. भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार:-

- वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक या मौलिक समझे जाते हैं उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों/ स्वतंत्रता नायकों द्वारा नागरिक अधिकारों की मांग समय-समय पर उठाई जाती रही। 1928 में भी मोती लाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। फिर स्वतंत्रता के बाद इन अधिकारों में से अधिकांश को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में से निकाल दिया

गया। संविधान के अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है तथा 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 21(ए) में प्राथमिक शिक्षा को भी नागरिक के लिए मौलिक अधिकार बना दिया गया है। अप्रैल 2010 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू भी हो गया है।

4. सामान्य अधिकार :-

- वे अधिकार जो साधारण कानूनों की सहायता से लागू किए जाते हैं तथा इन अधिकारों में संसद कानून बनाकर परिवर्तन कर सकती है।

5. मौलिक अधिकार :-

- ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के विकास की आधारशिला होते हैं जो संविधान में सूचीबद्ध किए गए हैं। तथा जिन को लागू करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए है। इनकी गारंटी तथा सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। इन अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरूद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता।

भारतीय संविधान के भाग तीन में वर्णित छः मौलिक अधिकार निम्न प्रकार हैं:-

(1). समता का अधिकार(अनुच्छेद 4 से 8)।

(2). स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 9 से 22)।

(3). शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद23 से24)।

(4). धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार(अनुच्छेद 25 से 28)।

(5). संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार(अनुच्छेद 29 से 30)।

(6). संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)।

1. समता का अधिकार (अनुच्छेद 4 से 18) :-

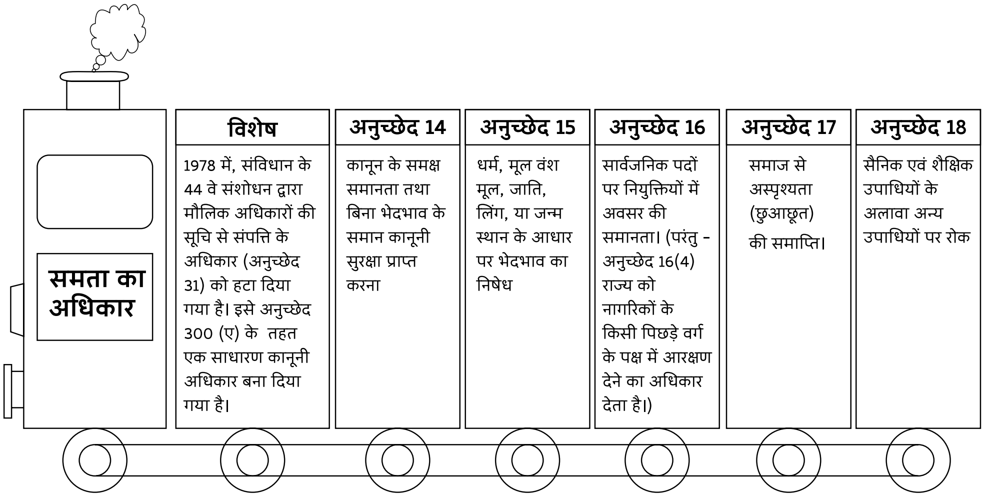

2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 से 22) :-

अनुच्छेद 19

इस अनुच्छेद के द्वारा भारत के नागरिकों को विशेष रूप से छः बुनियादी स्वतंत्रताए दी गई है :-

(i) भाषण और अभिव्यक्ति, (ii) बिना हथियारों के शांतिपूर्वक सम्मेलन, (iii) संघ, संगठन बनाने और (iv) भारत के किसी भी भूभाग में भ्रमण करने, (v) भारत के किसी भी भूभाग में निवास करने और (vi) व्यापार, व्यवसाय या कोई भी कारोबार, काम करने की स्वतंत्रता।

अनुच्छेद 20

- अनुच्छेद 20 अपराध में अभियुक्त या दंडित व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करना है।
- 44 वें संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 20 को आपात स्थिति के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद 21

- कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता।
- अनुच्छेद 21(क) RTE, 2022 86वा संविधान संशोधन शिक्षा का मौलिक अधिकार, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु प्राप्त बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा।

अनुच्छेद 22

- किसी भी नागरिक की विशेष मामलों में गिरफ्तारी एवं हिरासत से सुरक्षा प्रदान करना।

नोट:- 86 वें संविधान संशोधन (2002) द्वारा शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 (क) के द्वारा मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है।

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 से 24)

i. अनुच्छेद 23 : मानव व्यापार (तस्करी) और बल प्रयोग द्वारा बेगारी, बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध- जब भारत आजाद हुआ, तब भारत के कई भागों में दासता और बेगार प्रथा प्रचलित थी। जमींदार किसानों से काम करवाते थे, परंतु मजदूरी नहीं देते थे, विशेषकर स्त्रियों को पशुओं की तरह खरीदा और बेचा जाता था।

ii. अनुच्छेद 24- खदानों, कारखानों और खतरनाक कामों में बच्चों की मनाही।

iii. अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी जोखिम वाले काम पर नहीं लगाया जाएगा। जैसे खदानों में, कारखानों में इत्यादि।

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28)

अनुच्छेद-25

अपने अपने धर्म को मानने पालन करने एवं प्रचार प्रसार करने का अधिकार

अनुच्छेद-26

संगठित इकाई के रूप में धार्मिक तथा परोपकारी कार्य करने वाले संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार

अनुच्छेद-27

धर्म प्रचार एवं धार्मिक संप्रदाय की देखरेख के लिए कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा

अनुच्छेद-28

कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता

अनुच्छेद 28(1)

किसी भी सरकारी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी

5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29 से 30)

अनुच्छेद-29

भारत के किसी भी राज्य के नागरिकों को अपनी विशेष भाषा लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है।

अनुच्छेद-30

इसके अंतर्गत भाषा तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा उनके प्रशासन को चलाने का अधिकार प्रदान करता है

4. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद-32)

संविधान के जनक, डॉ भीमराव अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का "हृदय और आत्मा" की संज्ञा दी है। इसके अंतर्गत न्यायालय कई विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें रिट करते हैं। जो निम्न प्रकार है:-

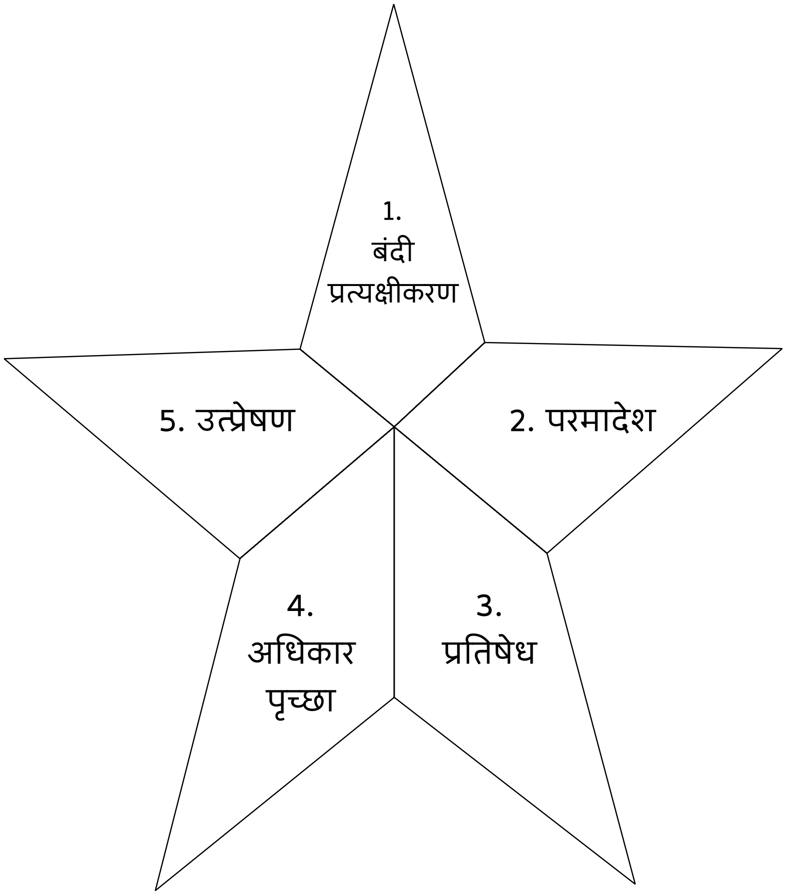

दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ, जब रंगभेद वाली सरकार हटने के बाद देश गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहा था। दक्षिण अफ्रीका में अधिकारों का घोषणा पत्र प्रजातंत्र की आधारशिला है । दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सूचीबद्ध प्रमुख अधिकार:-

i. गरिमा का अधिकार.

ii. निजता का अधिकार.

iii. श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार.

iv. स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार.

v. समुचित आवास का अधिकार.

vi. स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन, पानी और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार.

vii. बाल अधिकार.

viii. बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार.

ix. सूचना प्राप्त करने का अधिकार.

x. सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई समुदायों का अधिकार.

राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है?

(क) स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों में समानता लाने और सबका कल्याण करने के लिए मौलिक अधिकारों के अलावा बहुत से नियमों की जरूरत थी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत ऐसे ही नीतिगत निर्देश सरकारों को दिए गए, जिन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती परंतु इन्हें लागू करने के लिए सरकार से आग्रह किया जा सकता है। सरकार का दायित्व है कि जिस सीमा तक इन्हें लागू कर सकती है, करें ।

(ख) प्रमुख नीति निर्देशक तत्वों की सूची में तीन प्रमुख बातें हैं:-

(i) वे लक्ष्य और उद्देश्य, जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए।

(ii) वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए।

(iii) वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए।

नागरिकों के मौलिक कर्तव्य:-

- 1976 में, 42 वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची (अनुच्छेद 51 (क)) का समावेश किया गया है। इसके अंतर्गत नागरिकों के ग्यारह मौलिक कर्तव्य, निम्न प्रकार हैं:-

  (i) संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें।

  (ii) राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजाए रखना उनका पालन करना।

  (iii) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना।

  (iv) राष्ट्र रक्षा एवं सेवा के लिए तत्पर रहना।

(v) नागरिकों में भाईचारे का निर्माण करना।

(vi) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उस को बनाए रखें।

(vii) प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें, उसकी रक्षा करें।

(viii) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की संभावना का विकास करें।

(ix) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाएं और हिंसा से दूर रहे।

(x) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें।

(xi) माता-पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। (संशोधन 86)

नीति-निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों में संबंधः-

(i) दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वही नीति निर्देशक तत्व उसे कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा भी देते हैं।

(ii) मौलिक अधिकार खासतौर पर व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, वही नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं ।

नीति निर्देशक तत्वो एवं मौलिक अधिकारों में अंतरः-

- मौलिक अधिकारों को कानूनी सहयोग प्राप्त है परंतु नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी सहयोग प्राप्त नहीं है । अर्थात मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर आप न्यायालय में जा सकते हैं, परंतु नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन पर न्यायालय नहीं जा सकते।
- मौलिक अधिकारों का संबंध व्यक्तियों और निर्देशक तत्वों का संबंध समाज से है।
- मौलिक अधिकार प्राप्त किए जा चुके हैं जबकि नीति निर्देशक तत्वों को अभी लागू नहीं किया गया है।
- मौलिक अधिकारों का उद्देश्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, जबकि निर्देशक तत्वों / सिद्धांतों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है।
- मौलिक अधिकार व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देते हैं जबकि निर्देशक तत्व समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं।

प्रश्नावली

एक अंकीय प्रश्न

1. भारतीय संविधान के.................... में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है।
2. भारतीय संविधान में कुल छः ....अधिकारों का वर्णन किया गया है।
3. .... ने अनुच्छेद 32 में दिए गए संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा तथा ह्रदय बताया है।
4. अनुच्छेद 29 से 30 तक में............. का वर्णन किया गया है।
5. ....संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का रूप दिया गया है।
6. हमारे मौलिक अधिकार कितने अनुच्छेदों में दिए गए हैं?
   (a) अनुच्छेद 12 से 32 (b) अनुच्छेद 14 से 35
   (c) अनुच्छेद 14 से 32 (d) अनुच्छेद 12 से 35
7. संपत्ति का अधिकार है-
   (a) आर्थिक अधिकार (b) मौलिक अधिकार
   (c) नैतिक अधिकार (d) कानूनी अधिकार
8. मौलिक अधिकारों का रखवाला (संरक्षक) है-
   (a) प्रधानमंत्री (b) राष्ट्रपति (c) सर्वोच्च न्यायालय (d) राज्यपाल
9. मौलिक अधिकार हैं-
   (a) न्याय योग्य हैं (b) न्याय योग्य नहीं है (c) A तथा B दोनों से ही है
   (d) इनमें से कोई नहीं है।
10. समानता के अधिकार का वर्णन कितने अनुच्छेद में किया गया है?
    (a) अनुच्छेद 14 से 18 (b) अनुच्छेद 19 से 22
    (c) अनुच्छेद 29 से 32 (d) अनुच्छेद 25 से 281
11. अधिकारों के घोषणा पत्र से क्या अभिप्राय है?
12. स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू ने 1928 में अंग्रेजों से भारतीयों के लिए अधिकारों केघोषणा पत्र की मांग की थी, उसे किस नाम से जाना जाताहै?
13. सामान्य अधिकार किसे कहते हैं?
14. मौलिक अधिकारों से क्या आशय है?

15. विश्व में सबसे अधिक व्यापक अधिकार किस देश के संविधान द्वारा दिए गए हैं?

16. निवारक नजरबंदी किसे कहते हैं?

17. उत्प्रेषण रिट क्या होती है?

18. "परमादेश" से क्या अभिप्राय है ?

19. "अधिकार पृच्छा" से आप क्या समझते हैं?

20. मौलिक अधिकार कौन सी परिस्थिति में निलंबित हो सकते हैं?

21. निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें।

दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 लागू हुआ। इसे तब बनाया गया और लागू किया गया जब रंगभेद वाली सरकार के हटने के बाद दक्षिण अफ्रीका गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहा था । दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अनुसार " उसके अधिकारों का घोषणा पत्र, दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र की आधारशिला है ।" यह नस्ल, लिंग, गर्भधारण, वैवाहिक स्थिति, जातिय या सामाजिक मूल, रंग, आयु, अपंगता, धर्म, अंतरात्मा, आस्था, संस्कृति, भाषा और जन्म के आधार पर भेदभाव वर्जित करता है । संवैधानिक अधिकारों को एक विशेष संवैधानिक न्यायालय लागू करता है।

21.1 दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ?

(a) 1999 (b) 1996 (c) 1998 (d) 1995

21.2 दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अनुसार, उसके अधिकारों का घोषणा पत्र किसका आधार है?

(a) गणतंत्र का आधार (b) प्रजातंत्र का आधार

(c) राजतंत्र का आधार (d) कुलीन तंत्र का आधार

21.3 दुनिया में संभवत सबसे अधिक व्यापक अधिकार मिले हैं-

(a) अफ्रीका के नागरिकों को (b) भारत के नागरिकों को

(c) दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों को (d) दक्षिण कोरिया के नागरिकों को

21.4 दक्षिण अफ्रीका में संवैधानिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन सा न्यायालय बनाया गया है?

(a) सर्वोच्च न्यायालय (b) उच्च न्यायालय

(c) अधीनस्थ न्यायालय (d) संवैधानिक न्यायालय

22. संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है?

23. संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है ?

24. निम्नलिखित वाक्यों को सही करके पुनः लिखें-
    मौलिक अधिकार न्याय संगत नहीं है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत है।

25. निम्नलिखित प्रत्येक कथन के आगे सही अथवा गलत लिखिए (1+1+1+1+1)
    (i) विश्व के हर देश में मौलिक अधिकारों का घोषणा पत्र होता है।
    (ii) अधिकार पत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है।
    (iii) अधिकार पत्र में किसी देश की जनता को प्राप्त अधिकारों का वर्णन होता है।
    (iv) जब संविधान लागू हुआ, तब संविधान ने हमें छः मौलिक अधिकार दिए थे।
    (v) नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के भाग तीन में किया गया है।

दो अंकीय प्रश्न :

1. भारतीय संविधान में वर्णित छः मौलिक अधिकारों को मूल (मौलिक) की संज्ञा क्यों दी गई है?
2. मौलिक अधिकारों को किस परिस्थिति में निलंबित किया जा सकता है?
3. भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है?
4. बंधुआ मजदूरी से आप क्या समझते हैं?
5. बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है?
6. शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत कौन से दो प्रावधान है?
7. मौलिक अधिकारों के दो महत्व लिखिए।
8. कानूनी अधिकार कौन से होते हैं?
9. क्या नीति निर्देशक तत्व न्याय संगत है ?
10. मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में अंतर लिखिए ।
11. मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों के मध्य विवाद के केंद्र में कौन सा अधिकार था ?
12. भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 महत्वपूर्ण क्यों है ?

चार अंकिय प्रश्न :-

1. हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों है?
2. भारतीय संविधान में कब किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? किन्ही तीन कर्तव्यों का वर्णन कीजिए।
3. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पर टिप्पणी लिखिए।
4. हमारे संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की चार विशेषताएं लिखिए।
5. अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताओं में से किन्हीं चार को समझाइए।
6. नीति निर्देशक तत्व क्या है? इनकी तीन प्रमुख बातें लिखिए।
7. दिए गए चित्र/कार्टून का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

7.1 ऊपर दिया गया चित्र किसका है?

(a) सरदार हुकुम सिंह (b) सरदार हाकिम सिंह
(c) सरदार दारा सिंह (d) सरदार नेम सिंह

7.2 संविधान निर्माण में इनका क्या योगदान था?

(a) अल्प सक्रिय सदस्य (b) सक्रिय सदस्य
(c) संविधान सभा के उपाध्यक्ष (d) उपरोक्त में कोई नहीं

7.3 ये अल्पसंख्यकों के क्या थे?

(a) रक्षक (b) विरोधी
(c) निष्क्रिय सदस्य (d) उपरोक्त में कोई नहीं

छ: अंकीय प्रश्न:-

1. भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए।

2. समानता के अधिकार को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझाइए -

   (क) कानून के समक्ष समानता।

   (ख) भेदभाव का निषेध (मनाही)।

   (ग) रोजगार (नौकरियों) में अवसर की समानता।

3. धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को लोकतंत्र का प्रतीक या आधार माना जाता है। उपयुक्त कथन को तर्क सहित सिद्ध कीजिए।

4. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को “ संविधान का हृदय और आत्मा” की संज्ञा दी है। इसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा जारी विशेष आदेशों (रिटों) को सविस्तार समझाइए।

5. नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों एवं नीतियों को सविस्तार समझाइए।

6. मौलिक अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर स्पष्ट कीजिए।

उत्तरमाला

एक अंकीय के प्रश्नों के उत्तरः

1. भाग तीन।
2. मौलिक।
3. डॉ बी आर अंबेडकर।
4. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार।
5. 86 वें संविधान संशोधन।
6. (c) अनुच्छेद 14 से 32
7. (d) कानूनी अधिकार।
8. c) सर्वोच्च न्यायालय।
9. (a) न्याय योग्य हैं।
10. (a) अनुच्छेद 14 से 18।
11. संविधान द्वारा प्रदत और संरक्षित अधिकारों की सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं।
12. मोतीलाल नेहरू समिति।
13. ऐसे अधिकार जो सामान्य कानूनों की सहायता से लागू किए जाते हैं, उन्हें सामान्य अधिकार कहते हैं।
14. ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के विकास की आधारशिला होते हैं। जो संविधान में सूचीबद्ध किए जाते हैं तथा जिन को लागू करने के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं।
15. दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान द्वारा।
16. किसी व्यक्ति को इस आशंका के आधार पर गिरफ्तार करना कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है, इसे ही निवारक नजरबंदी कहते हैं।
17. उत्प्रेषण रिट का अर्थ है- हमें सूचना दी जाए। इसमें निचली अदालत को किसी विशेष मामले का ब्यौरा उच्च या उच्चतर अदालत को देने का आदेश दिया जाता है।
18. परमादेश का अभिप्राय है कि " हम आदेश देते हैं।" निचली अदालत अथवा किसी व्यक्ति को अपना कर्तव्य करने के लिए ऐसा आदेश दिया जाता है।

19. "अधिकार पृच्छा" ऐसा आदेश है, जो उस व्यक्ति के खिलाफ जारी होता है, जिसने गलत तरीके से कोई पद हासिल कर लिया हो।

20. अगर किसी देश में आपातकाल लागू हो तो उस स्थिति में मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। जीवन के अधिकार को छोड़कर।

21.1 (b) 1996

21.2 (b) प्रजातंत्र का आधार

21.3 (c) दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों को

21.4 (d) संवैधानिक न्यायालय

22. संविधान के भाग 4 में।

23. अनुच्छेद 51-A में

24. मौलिक अधिकार न्याय संगत है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत नहीं है।

25. (i) गलत (ii) सही (iii) सही (iv) गलत (v) गलत।

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तर:-

1. यह अधिकार वर्षो से चले आ रहे मूल्यों एवं सिद्धांतों का प्रतीक है। इसके द्वारा व्यक्ति का सर्वागीण विकास होता है।

2. मौलिक अधिकार, विशेषकर अनुच्छेद-19, आपातकाल की स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं।

3. इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने विचारों को शब्दों के रूप में लिख कर प्रेस द्वारा छपवा कर तस्वीरों के द्वारा या किसी अन्य माध्यम से लोगों तक पहुंचाना।

4. जमीदारों, सूदखोरों, और अन्य धनी लोगों द्वारा गरीबों से पीढ़ी दर पीढ़ी बिना वेतन मजदूरी करवाना। अब इसे अपराध घोषित कर दिया गया है।

5. न्यायालय द्वारा किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय/ जज के सामने उपस्थित होने / करने का आदेश दिया जाना बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है।

6. (i) अनुच्छेद-23, राज्य पर सकारात्मक जिम्मेदारी डालता है कि वह व्यक्तियों के व्यापार तथा बेगारी एवं बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाए।

7. (i) नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
   (ii) भारतीय लोकतंत्र का आधार है।

8. कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं, जिन्हें किसी देश के संविधान में सूचीबद्ध कर रखा है तथा जिसे उल्लंघन करने पर उल्लंघन करता को सजा मिलती है।

9. नहीं, नीति निर्देशक तत्व न्याय संगत नहीं है। इनके उल्लंघन पर आप न्यायालय में नहीं जा सकते। 10. अंतर-

   (i) मौलिक अधिकार न्याय संगत है । नीति निर्देशक तत्व न्याय संगत नहीं है।

   (ii) मौलिक अधिकारों का स्वरूप निषेधकारी है । जबकि नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप सकारात्मक है। 11. संपत्ति का अधिकार, जिसे 44 वे संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया।

12. भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अनुच्छेद 21 (क) द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तरः-

1. मौलिक अधिकार व्यक्ति के मूल विकास, सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। मौलिक अधिकार समाज में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, आर्थिक, सामाजिक विकास लाने में सहयोग प्रदान करते हैं।

2. 1976 में, 42 वें संविधान संशोधन द्वारा, देश की रक्षा करना, देश में भाईचारा बढ़ाना, पर्यावरण की रक्षा करना एवं संविधान का सम्मान करना।

3. 2000 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन । सदस्य- एक भूतपूर्व सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, एक भूतपूर्व उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा मानवाधिकारों के संबंध में ज्ञान रखने वाले या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले 2 सदस्य होते हैं। कार्य- शिकायतें सुनना, जांच करना तथा पीड़ित को राहत पहुंचाना।

4. मौलिक अधिकारों की विशेषताएं- (i) विस्तृत एवं व्यापक- संविधान के भाग 3 की 24 धाराओं में वर्णित । (ii) मौलिक अधिकार बिना भेदभाव के सभी के लिए (iii) मौलिक अधिकार असीमित नहीं है- आपातकाल में इन पर प्रतिबंध लग सकता है । (iv) मौलिक अधिकार न्याय संगत है- किसी के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर वह न्यायालय जा सकता है।

5. अनुच्छेद- 19

(i) भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।

(ii) संघ / समिति बनाने की स्वतंत्रता।

(iii) सभा करने की स्वतंत्रता।

(iv) भ्रमण करने की स्वतंत्रता।

(v) व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। (कोई चार)

6. मौलिक अधिकारों के अलावा जन कल्याण एवं राज्य के उत्थान के जरूरी नियमों को "राज्य के नीति निर्देशक तत्वों" के रूप में जाना जाता है। इन तत्वों के पीछे नैतिक शक्ति काम करती है। तीन प्रमुख बातें:-

   (i) वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए।

   (ii) वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलनी चाहिए।

   (iii) वह नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए।

7.1 (a) सरदार हुकुम सिंह

7.2 (b) सक्रिय सदस्य

7.3 (a) रक्षक

7.4 (b) पंजाब

छः अंकीय प्रश्नों के उत्तर:-

1. मौलिक अधिकार- (i) समानता, (ii) स्वतंत्रता, (iii) शोषण के विरुद्ध अधिकार, (iv) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, (v) शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, (vi) संवैधानिक उपचारों का अधिकार

2. (i) कानून की नजर में गरीब एवं अमीर एक समान है। कानून की धाराएं सभी पर एक समान लागू होते हैं।

   (ii) रंग, जाति, नस्ल, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव की मनाही।

   (iii) रोजगार (नौकरियों) में अवसर - समान योग्यता, समान परीक्षा में बैठने के मौके (अवसर)।

   (iii) रोजगार (नौकरियों) में अवसर समान योग्यता, समान परीक्षा में बैठने के मौके (अवसर)।

3. एक लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक नागरिक महत्वपूर्ण होता है। उसको मत देने, विचार मानने की आजादी होती है । लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है । इसलिए इस अधिकार को लोकतंत्र का प्रतीक कहते हैं । (i) किसी भी धर्म को मानने या प्रचार करने की आजादी । (ii) सर्वजन हिताय धार्मिक समुदाय बनाने की आजादी | (iii) धर्म विशेष के लिए "कर" देने की आजादी । (iv) सरकारी स्कूल, कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा पर पाबंदी।

4. संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है।

   रिटः- (i) बंदी प्रत्यक्षीकरण (ii) परमादेश, (iii) प्रतिषेध, (iv) अधिकार पृच्छा, (v) उत्प्रेषण ।

5. उद्देश्य - लोगों का कल्याण, सामाजिक, और एवं राजनीतिक न्याय।

   - जीवन स्तर ऊंचा उठाना, संसाधनों का समान वितरण।

   -अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा ।

   नीतियां- समान नागरिक संहिता, मद्यपान निषेध, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा, उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक। ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन।

6. (i) मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं। नीति निर्देशक तत्व नहीं।

   (ii) मौलिक अधिकार निषेधात्मक जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है।

   (iii) मौलिक अधिकार व्यक्ति से जबकि नीति निर्देशक तत्व समाज से संबंधित है।

   (iv) मौलिक अधिकार का क्षेत्र सीमित है । नीति निर्देशक तत्वों का क्षेत्र विस्तृत है।

   (v) मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र है। नीति निर्देशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र है, आदि।

   (vi) मौलिक अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाना है।

अध्याय-3

चुनाव और प्रतिनिधित्व

अध्याय के मुख्य बिंदु

- लोकतंत्र के प्रकार • भारत में चुनाव प्रणाली •चुनाव और लोकतंत्र
- आनुपातिक प्रतिनिधित्व • निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण • चुनाव सुधार

Mind-map

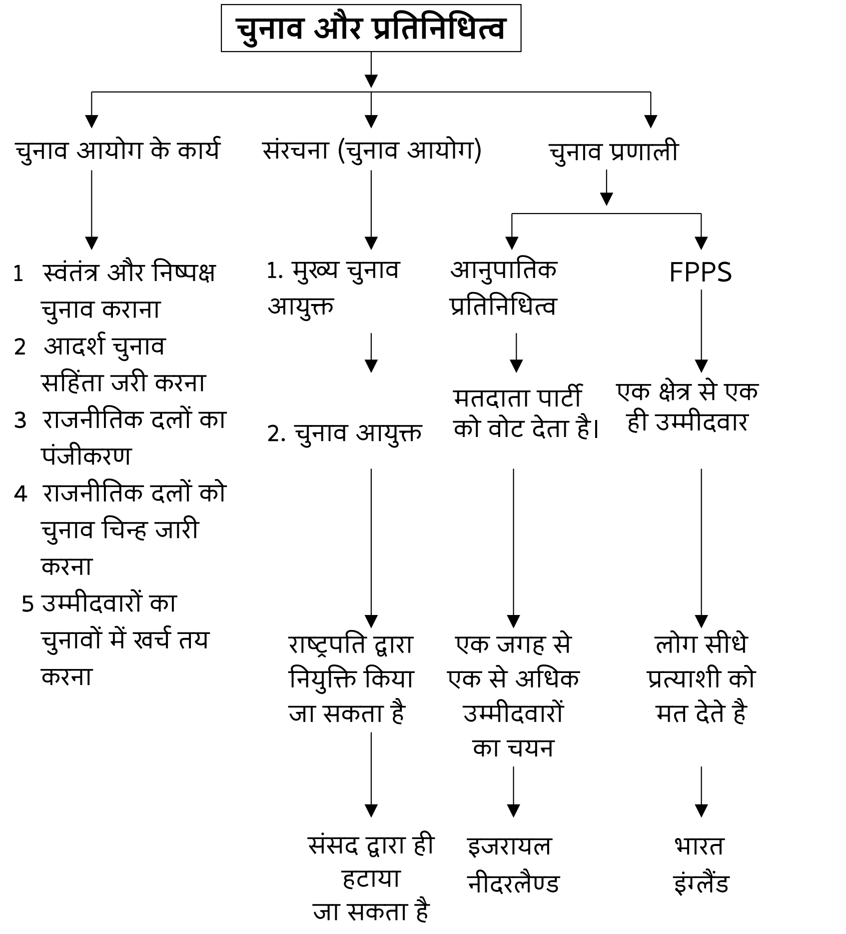

प्रतिनिधि → चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से जो व्यक्ति जनता द्वारा चुनकर संसद या विधानसभा में भेजा जाता है, उसे जनता का प्रतिनिधि कहा जाता है।

हम एक प्रतिनिधि क्यों चुनते हैं? :- विशाल जनसंख्या और बड़े क्षेत्रफल के कारण सभी नागरिक कानून बनाने या निर्णय लेने में सीधे भाग नहीं ले सकते हैं, इसलिए लोग प्रतिनिधियों का चयन करते हैं।

लोकतंत्र के प्रकार

- प्रत्यक्ष लोकतंत्र : नागरिक रोज़मर्रा के फैसलों और सरकार चलाने में प्रत्यक्ष भाग लेते हैं (हाथ उठाकर) उदाहरण: प्राचीन ग्रीस, ग्राम सभा
- अप्रत्यक्ष लोकतंत्र : लोग अपने प्रतिनिधि भेजते हैं और वही लोग सरकारी कार्यवाही में भाग लेते हैं जैसे: भारत, इंग्लैंड

चुनाव → जिस प्रक्रिया से लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं उसे चुनाव कहा जाता है।

भारत में चुनाव प्रणाली :-

चुनाव और लोकतंत्र :- चुनाव और लोकतंत्र दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चुनाव के बिना लोकतंत्र अधूरा है और चुनाव के बिना लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है।

भारत के संविधान में चुनाव के संचालन की प्रणाली का वर्णन किया गया है। इसके लिए प्राधिकरण (चुनाव आयोग) के गठन और नियमों का भी वर्णन किया गया है। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, चुनाव लड़ने की क्षमता, मतदाताओं की योग्यता और मतगणना की प्रक्रिया का भी वर्णन किया गया हैं।

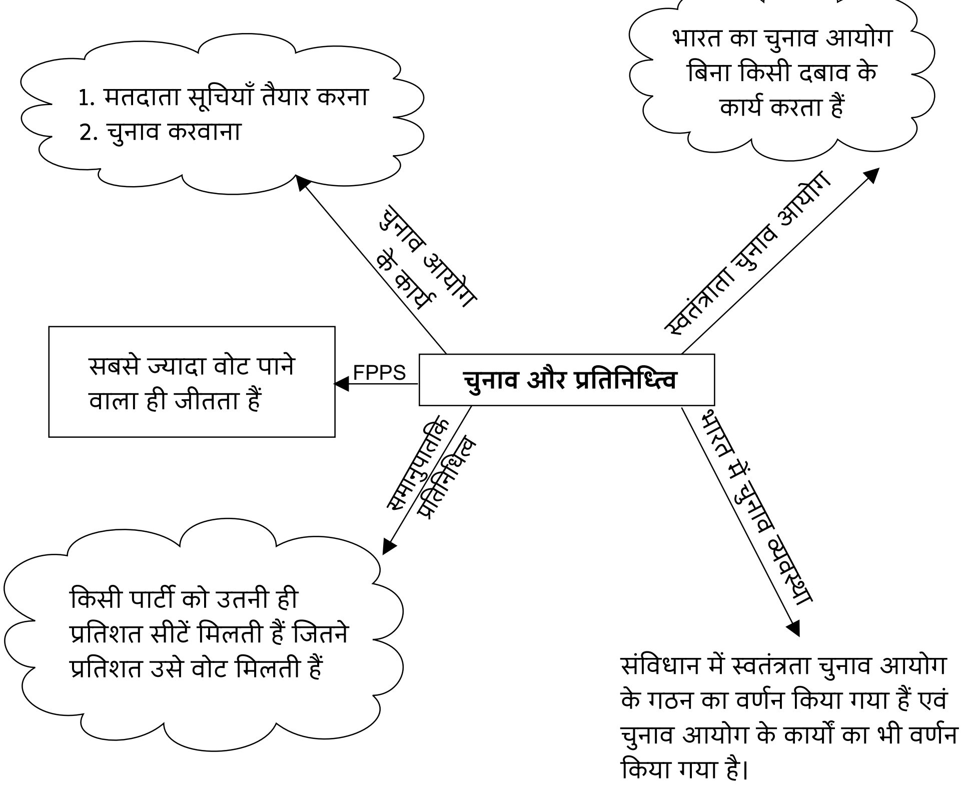

चुनाव आयोग → भारत के संविधन के अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत का स्वतंत्रता चुनाव आयोग होगा, जिसमें 3 सदस्य ;1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त होते है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त श्री सुकुमार सेन थे।

सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली → यह प्रणाली भारत में इंग्लैंड से ली गई हैं इसमें पूरे देश को छोटी भोगोलिक इकाइयों में बांट दिया जाता हैं जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं हर निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रत्याशी विजेता होता हैं इसमें सबसे अधिक वोट पाने वाला प्रत्याशी विजयी होता है।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व:

प्रत्येक पार्टी चुनाव में सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की प्राथमिकता सूची जारी करती है और प्राथमिकता सूची में से उतने उम्मीदवारों का चयन करती है जितनी सीटों को कोटा उसे मिलता है। चुनाव की इस प्रणाली को आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहा जाता है। इस प्रणाली में मतदाता को जितना प्रतिशत मत मिलता है अनुपात में उतनी ही सीटे उसे मिलती है, इस प्रणाली में मतदाता उम्मीदवार को नहीं बल्कि पार्टी को वोट देता है।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली दो प्रकार की होती है -

1. इज़राइल और नीदरलैंड में, पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनावों में प्राप्त मतों के अनुपात में सीटें दी जाती हैं।
2. अर्जेंटीना और पुर्तगाल में जहाँ पूरा देश बहु-सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता हैं भारत में 'सर्वाधिक वोट की जीत प्रणाली को क्यों स्वीकार किया गया?

   भारत में सर्वाधिक वोट की प्रणाली को क्यों स्वीकार किया गया:-

   1. यह प्रणाली सरल है
   2. चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होते हैं
   3. यह प्रणाली भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश के लिए उपयुक्त है।
   4. मतदाता उम्मीदवार को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, यह अवसर अन्य प्रणाली में उपलब्ध नहीं है

निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण :-

भारत के संविधान द्वारा संसद या राज्य विधान सभा में सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व देने के प्रयास में निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण दिया गया है। इस प्रणाली में सभी वर्गों के मतदाता मतदान करते है। लेकिन उम्मीदवार केवल उस सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। शुरुआत में यह व्यवस्था केवल 10 साल के लिए थी लेकिन अब इसे 2030 तक बढ़ा दिया गया है। 543 लोकसभा सीटों में से 84 अनुसूचित जाति और 47 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं । निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण परिसीमन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है जो राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है।

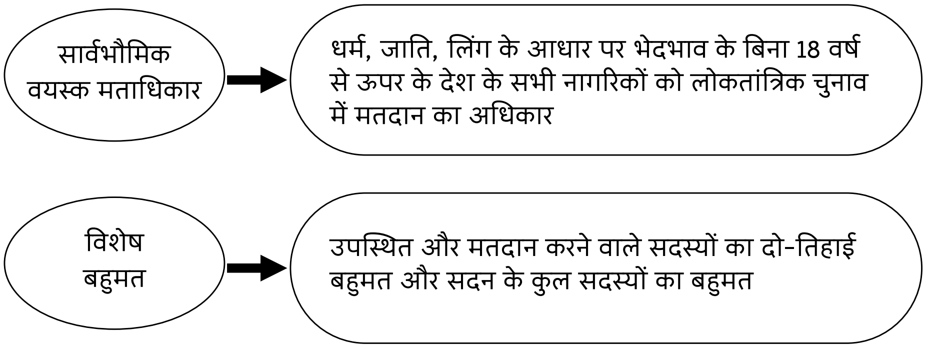

चुनाव सुधारः

कोई भी चुनाव प्रणाली कभी भी एक आदर्श प्रणाली नहीं हो सकती। प्रत्येक प्रणाली में कुछ कमियां होती हैं। लोकतांत्रिक समाज को अपने चुनावों को अधिक निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए लगातार प्रयास करने होंगे। इसे चुनाव सुधार कहा जाता है जैसे: भारत में आपराधिक भूमिका वाले लोगों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध, चुनावों में खर्च की एक निश्चित सीमा आदि।

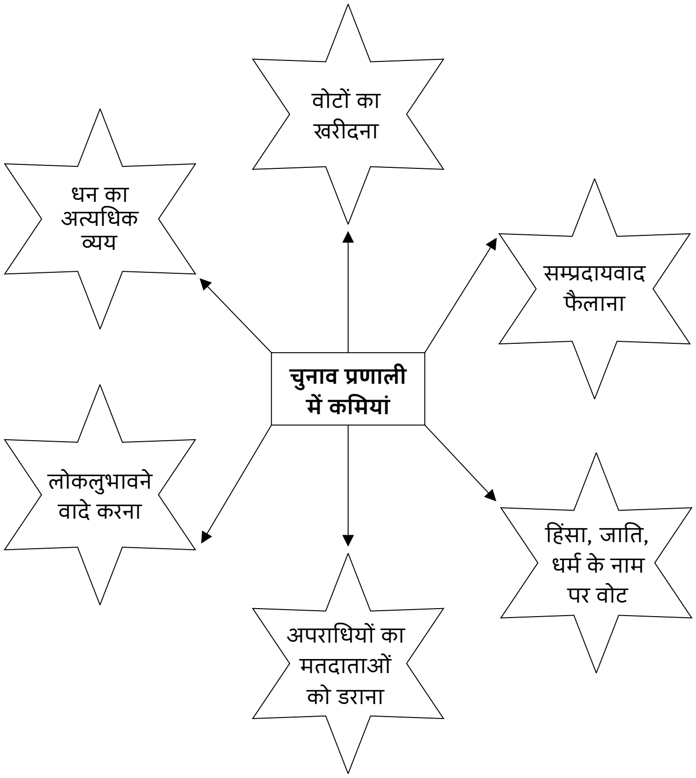

प्रश्नावली

एक अंक के प्रश्न :-

1. भारत में किस चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू होती हैं?
   (i) लोकसभा चुनाव
   (ii) राज्य विधानसभाएं चुनाव
   (iii) राज्यसभा चुनाव
   (iv) स्थानीय निकाय चुनाव

2. भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?
   a. प्रधानमंत्री
   b. लोकसभा
   c. राष्ट्रपति
   d. राज्य सभा

3. भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कौन सुनिश्चित करता है?
   a. सुप्रीम कोर्ट
   b. भारत का चुनाव आयोग
   c. उच्च न्यायालय
   d. संसद

4. वोट का अधिकार है?
   a. कानूनी अधिकार
   b. मौलिक अधिकार
   C. संवैधानिक अधिकार
   d. वैधानिक अधिकार

5. चुनाव विवादों को कहाँ चुनौती दी जा सकती हैं?
   A. संसद
   B. चुनाव आयोग
   C. राष्ट्रपति
   D. उच्च न्यायालय

अभिकथन और कारण प्रश्न

6. अभिकथन (A): चुनाव आयुक बिना किसी दबाव के काम करता है।

कारण (R): चुनाव आयुक को उनके पद से केवल संसद द्वारा ही हटाया जा सकता है

(ए) ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है।

(बी) ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है।

(सी) ए सत्य है. लेकिन आर असत्य है।

(डी) ए असत्य है लेकिन आर सत्य है।

7. अभिकथन (A): भारत के लोग सीधे अपना प्रधान मंत्री चुनते हैं।

कारण (R) भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

(ए) ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है।

(बी) ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है।

(सी) ए सत्य है, लेकिन आर असत्य है।

(डी) ए असत्य है लेकिन आर सत्य है।

प्रश्न संख्या 8 से 12 तक के रिक्त स्थान की पूर्ति करें

8. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है?

(i) उच्चतम न्यायालय

(ii) प्रधानमंत्री

(iii) लोक सभा

(iv) चुनाव आयोग

9. जब 5 साल बाद चुनाव होते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है।

(i) आम चुनाव

(ii) उपचुनाव

(iii) मध्यावधि चुनाव

(iv) उपरोक्त में से कोई नही

10. 18 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक व्यक्ति जब मतदान करता है तो उसे कहा जाता है।

(i) वैधानिक अधिकार

(ii) सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार

(iii) कानूनी अधिकार

(iv) उपरोक्त में से कोई नहीं

11. लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु________ है।

(i) 30 साल

(ii) 35 साल

(iii) 25 साल

(iv) 20 साल

12. _________की स्थापना संविधान में अनुच्छेद 324 (1) से की गई है।

(i) लोकसभा

(ii) राज्यसभा

(iii) उच्चतम न्यायालय

(iv) भारत का चुनाव आयोग

प्रश्न संख्या 16 से 20 बहुविकल्पीय हैं

13. भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है

(ए) विधानसभा (बी) संसद (सी) ग्राम सभा (डी) नगर निगम

14. निम्नलिखित में से किस देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गयी है

(ए) भारत (बी) इंग्लैंड (सी) अमेरिका (डी) इज़राइल

15. लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं?

(ए) 131 (बी) 84 (सी) 47 (डी) 125

16. मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी?

(ए) 1984 (बी) 1989 (सी) 1991 (डी) 1995

17. भारत में चुनाव लड़ने की प्रक्रिया किस आधार पर है?

(ए) आयु (बी) आय (सी) लिंग (डी) शिक्षा

दो अंक के प्रश्न :-

1. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बीच दो अंतर लिखिए
2. फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का क्या अर्थ है?
3. आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है?
4. गुप्त मतदान प्रणाली क्या है?
5. आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से आप क्या समझते हैं?
6. चुनाव प्रणाली की सफलता के दो तत्व क्या हैं?
7. परिसीमन आयोग से आप क्या समझते हैं?
8. भारतीय चुनाव प्रणाली के दोष लिखिए ?

चार अंक के प्रश्न

1. FPPS और आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली में चार अंतर लिखिए
2. सार्वभौम वयस्क मताधिकार के चार महत्व लिखिए
3. भारत के चुनाव आयोग के चार मुख्य कार्यों का वर्णन करें
4. प्राचीन यूनानी शहर / राज्य में जो लोकतंत्र स्थापित था उसकी व्याख्या करें
5. लोकसभा और विधानसभा के सदस्य बनने के लिए संविधान में क्या-क्या योग्यताएं निर्धारित की गई हैं?
6. लोकतंत्र में चुनावों के महत्व पर एक टिप्पणी लिखिए
7. पृथक निर्वाचक मंडल और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए

8. निम्नलिखित कार्टून को ध्यान से देखें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। (अभ्यास हेतु)

   i) कार्टून में हाथी किस समस्या का संकेत देता है?

   ii) हाथी की पूँछ खींचने वाले नेता का क्या नाम है?

   iii) उस नेता का नाम बताइए जिसने हाथी की पूंछ खींची।

   (iv) वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं?

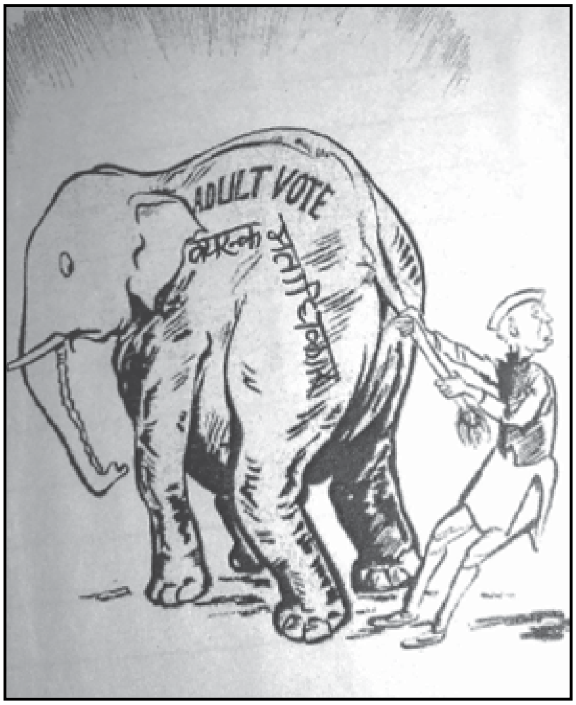

प्रश्नः 9 (अवतरण आधारित प्रश्न)

एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह है जहाँ नागरिक दिन प्रतिदिन के निर्णय लेने और सरकार चलाने में प्रत्यक्ष भाग लेते है। यूनान के प्राचीन नगर राज्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण माने जाते थे। कई लोग स्थानीय सरकारों, विशेषकर ग्राम सभाओं को प्रत्यक्ष लोकतंत्र के निकटतम उदाहरण मानते हैं। लेकिन जब लाखों-करोड़ों लोगों को कोई फैसला लेना हो तो इस तरह के प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अमल में नहीं लाया जा सकता। इसलिए जनता के शासन का अर्थ आमतौर पर जनप्रतिनिधियों का शासन होता है।

एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह है जहां नागरिक दिन-प्रतिदिन के निर्णय लेने और सरकार चलाने में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं।

9.1 (i) प्रत्यक्ष लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं?

(ए) राजशाही प्रणाली

(बी) लोग दिन-प्रतिदिन के मामलों में भाग लेते हैं

(सी) लोग अपना प्रतिनिधि भेजते हैं

(डी) दिन-प्रतिदिन के मामलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है

9.2 (ii) भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण है।

(ए) लोकसभा

(बी) राज्यसभा

(सी) ग्राम सभा

(डी) विधानसभा

9.3 (iii) हमने किस देश से FPPS को अपनाया है?

(ए) यूएसए

(बी) इंग्लैंड

(सी) फ्रांस

(डी) जर्मनी

9.4 (iv) किस प्राचीन शहर में हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण देख सकते हैं?

(ए) न्यूयॉर्क

(बी) दिल्ली

(सी) ग्रीस

(डी) पेरिस

छह अंक का प्रश्न

1. भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए किन्हीं 6 सुझावों का वर्णन कीजिए
2. भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया की व्याख्या करें और इसके प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए
3. भारत की चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए
4. भारत की चुनाव प्रणाली की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए
5. चुनाव और लोकतंत्र एक सिक्के के दो पहलू हैं, इस कथन को समझाते हुए लोकतंत्र में चुनाव के महत्व को भी समझाओ

उत्तरमाला

एक अंकीय के प्रश्नों के उत्तरः

1. राज्यसभा चुनाव
2. राष्ट्रपति
3. भारत का चुनाव आयोग
4. वैधानिक अधिकार
5. उच्च न्यायालय
6. A
7. D
8. चुनाव आयोग
9. आम चुनाव
10. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
11. 25
12. चुनाव आयोग
13 ग्राम सभा
14. इज़राइल
15. 131
16. 1989
17. आयु

दो अंकों के प्रश्न का उत्तर

1. प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती है, जबकि अप्रत्यक्ष चुनाव में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को शासक के रूप में मानता है, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से जनता का प्रतिनिधि स्वयं को ऐसा मानता है।

2. इस प्रणाली का अर्थ है कि जो उम्मीदवार चुनावी दौड़ में अन्य उम्मीदवारों से आगे निकल जाता है। वह विजेता होता है।

3. इस व्यवस्था में किसी दल को उतने ही अनुपात में सीटे मिलती है जिस अनुपात में उसे मत प्रतिशत मिलता है। यह दो प्रकार की होती है, जैसे कहीं कहीं पूरे देश को एक ही निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है व कही कही पूरे देश को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बाटा जाता हैं

4. अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली में प्रतिनिधियों का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है जिसमें मतदाता के अलावा कोई नहीं जानता कि किसे वोट दिया गया है।

5. संविधान में प्रावधान है कि अल्पसंख्यकों या निम्न वर्ग के जनप्रतिनिधियों की भी संसद में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन विभाग समय-समय पर सीटें आरक्षित करता हैं है, इसे आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है।

6. पारदर्शी चुनाव, स्वतंत्र चुनाव, जनता अच्छा काम नहीं करने वाले को हटा देती है।

7. भारत में चुनाव आयोग के साथ काम करने वाला एक संगठन, जो निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को निर्धारित करता है, निर्वाचन क्षेत्रों को निर्धारित करता है इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

8. मुख्य बिंदुओं से उत्तर देखें

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. FPPS:- देश को छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। मतदाता उम्मीदवार को वोट देता है और वह उम्मीदवार को व्यक्तिगत रूप से जानता है।

   आनुपातिक प्रतिनिधित्व पूरे देश का एक ही निर्वाचन क्षेत्र है जहाँ एक से अधिक उम्मीदवार निर्वाचित होते हैं। मतदाता गुप्त रूप से पार्टी को वोट देता है इसलिए उम्मीदवार को पता नहीं चलता है।

2. सार्वभौम मताधिकार सार्वजनिक संप्रभुता के सिद्धांत को लागू करता है।

   - यह लोकतांत्रिक सिद्धांत के अनुरूप है
   - व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक
   - यह राजनीति जागरूकता लाता है।

3. - मतदाता सूची तैयार करना
   - चुनाव का तरीका तय करने के लिए
   - चुनाव निरीक्षण कराने के लिए
   - चुनाव परिणाम जारी

4. पूरे नगर राज्य के लोग एक खुली जगह में इकट्ठा होते थे और हाथ उठाकर अपना प्रतिनिधि चुनते थे और सरकार के दैनिक फैसले को लेकर सीधे जनता का अनुमोदन प्राप्त करते थे, इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली कहा जाता है।

5. भारत का नागरिक होना चाहिए
   - 25 वर्ष की आयु
   - लाभ के पद पर नहीं होनी चाहिए
   - दिवालिया नहीं होना चाहिए
   - आपराधिक भूमिका का नहीं होना चाहिए

6. लोकतंत्र में चुनाव का बहुत महत्व है। चुनावी लोकतंत्र एक सिक्के के दो पहलू हैं। आज दुनिया के 100 से अधिक देशों में लोकतंत्र है, जहां लोकतंत्र है, वहां जनप्रतिनिधियों के चुनाव के लिए चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है।

7. पृथक निर्वाचक मंडल में एक समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग मतदान कर सकते हैं, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाता मतदान करेंगे लेकिन उम्मीदवार केवल उस समुदाय का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित है.

8. (i) अनुभवहीन मतदाताओं को नियंत्रित कर पहले आम चुनाव में सफल मतदान
   (ii) चुनाव में मतदान करने के लिए अनियंत्रित मतदाताओं को तैयार करने का प्रयास
   (iii) पंडित जवाहरलाल नेहरू
   (iv) 18 वर्ष की आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार देना ।

अवतरण आधारित प्रश्न का उत्तरः

9.1 (i) लोग दिन-प्रतिदिन के मामलों में भाग लेते हैं।

9.2 (ii) ग्राम सभा में

9.3 (iii) इंग्लैंड

9.4 (iv) ग्रीस

छह अंकों के प्रश्नों के उत्तर:-

1.

चुनाव सुधार:-

(i) FPPS प्रणाली के स्थान पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाना

(ii) संसदीय और विधानसभा की एक तिहाई सीटों पर महिलाओं का चुनाव

(iii) चुनाव में पैसे के प्रभाव को नियंत्रित करना

(iv) उम्मीदवार के आपराधिक मामले को उजागर करना

(v) चुनाव प्रचार में जाति और धर्म के इस्तेमाल पर रोक लगनी चाहिए

(vi) राजनीतिक दलों में पारदर्शिता और लोकतंत्र होना चाहिए

2. मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कि जाती हैं वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य करता हैं, उसका वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है।

कार्य:-

(i) मतदाता सूची तैयार करना

(ii) चुनाव कार्यक्रम निर्धारित करना

(iii) स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना

(iv) दलों को राष्ट्रीय एवं एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता देना

(v) चुनाव की निगरानी

(vi) राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कराना

3. **चुनाव प्रक्रिया:-**

1. चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी करना
2. आवेदन वापस लेने की तिथि व चुनाव की तिथि घोषित करना
3. चुनाव अभियान और चुनाव अभियान की निगरानी
4. चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष कराना
5. मतों की गणना करना
6. चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति
7. चुनाव परिणाम घोषित करना
8. मतदान केंद्रों की स्थापना

4. चुनाव प्रणाली की विशेषताएं:- भारत ने सर्वाधिक मतों से जीतने की प्रणाली को अपनाया है। इसकी विशेषताएं हैं।

यह सरल है। मतदाता और प्रतिनिधि का संपर्क बना रहता है यह प्रणाली क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित है इसमें पैसा कम खर्च होता है। इस प्रणाली से राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है।

5. लोकतंत्र में चुनाव का महत्व

प्रतिनिधि चुनाव जीतकर सरकार में जनभागीदारी सुनिश्चित करते हैं।

इसमें प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि जिले के अनुसार कार्य करेंगे इस व्यवस्था से जनता का विश्वास बढ़ता है लोकतंत्र में उचित प्रतिनिधित्व आवश्यक है जो केवल चुनावों के माध्यम से ही संभव है। नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा निष्पक्ष प्रतिनिधित्व से ही होती है। प्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया जाता है।

अध्याय-4

कार्यपालिका

अध्याय के मुख्य बिंदु

कार्यपालिका क्या है, विभिन्न प्रकार की कार्यपालिका, भारत में संसदात्मक कार्यपालिका, राष्ट्रपति की शक्तियां, विवेकाधीन शक्तियां, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, स्थायी कार्यपालिका: नौकरशाही

कार्यपालिका

↓

सरकार का वह अंग जो नियमों-कानूनों को लागू करें

कार्यपालिका का अर्थः-

- सरकार के उस अंग से है जो कायदे-कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते है।
- सरकार का वह अंग जो नियमों कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है कार्यपालिका कहलाता है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
- कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा (सिविल सेवा के सदस्य) भी आता है।
- राजनीतिक कार्यपालिका में सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को सम्मिलित किया जाता है। ये सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते है। राजनीतिक अधिकारी निर्वाचित होते है, स्थायी नही।
- स्थायी कार्यपालिका में जो लोग रोज-रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते है, को सम्मिलित किया जाता है। ये सिविल सेवक है जैसे आई० ए० एस०, आई० पी० एस०।
- अमेरिका में अध्याक्षात्मक व्यवस्था है और कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है।

- कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है जिसमें महारानी राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है।
- फ्रांस में राष्ट्रपति ओर प्रधानमंत्री अर्द्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है पर उन्हें पद से हटा नहीं सकता क्योंकि वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
- जापान में संसदीय व्यवस्था है जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है।
- इटली में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है।
- रूस में एक अर्द्धअध्यक्षात्मक व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है।
- जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमे राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान और चांसलर सरकार का प्रधान है।

कार्यपालिका के प्रकार

सामूहिक नेतृत्व के सिद्धान्त पर आधारित → संसदात्मक, अर्द्ध अध्याक्षात्मक

व्यक्तिगत नेतृत्व के सिद्धान्त पर आधारित → अध्यक्षात्मक

संसदात्मक	अर्द्ध अध्याक्षात्मक	अध्यक्षात्मक
सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है वह विधायिका में बहुमत दल का नेता होता है। वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है।	राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है।	राष्ट्रपति ही राज्य एवं सरकार दोनों का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति सामान्यतया जनता द्वारा निर्वाचित होता है। वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता।

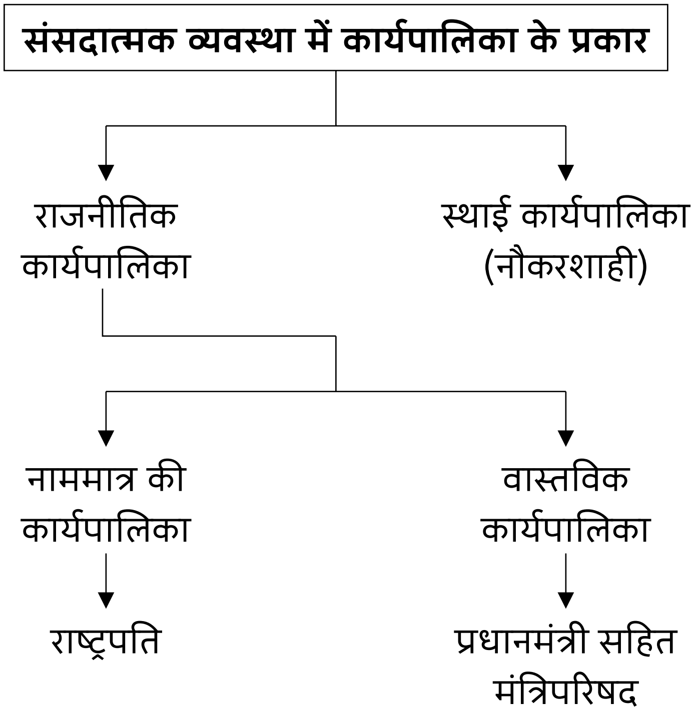
संसदात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका के प्रकार
राजनीतिक कार्यपालिका
स्थाई कार्यपालिका (नौकरशाही)
नाममात्र की कार्यपालिका
वास्तविक कार्यपालिका
राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद

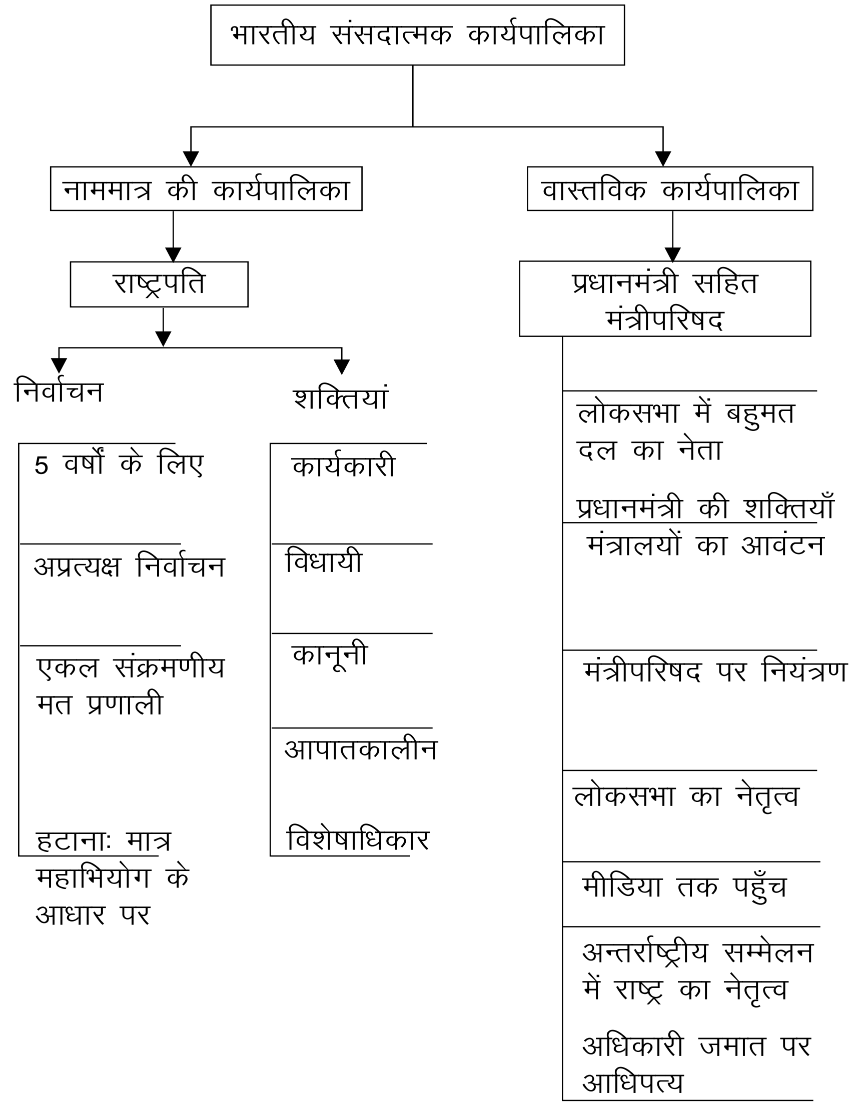

भारतीय संसदात्मक कार्यपालिका
नाममात्र की कार्यपालिका
वास्तविक कार्यपालिका
राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री सहित मंत्रीपरिषद
निर्वाचन
शक्तियां
5 वर्षों के लिए
अप्रत्यक्ष निर्वाचन
एकल संक्रमणीय मत प्रणाली
हटानाः मात्र महाभियोग के आधार पर
कार्यकारी
विधायी
कानूनी
आपातकालीन
विशेषाधिकार
लोकसभा में बहुमत दल का नेता
प्रधानमंत्री की शक्तियाँ
मंत्रालयों का आवंटन
मंत्रीपरिषद पर नियंत्रण
लोकसभा का नेतृत्व
मीडिया तक पहुँच
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्र का नेतृत्व
अधिकारी जमात पर आधिपत्य

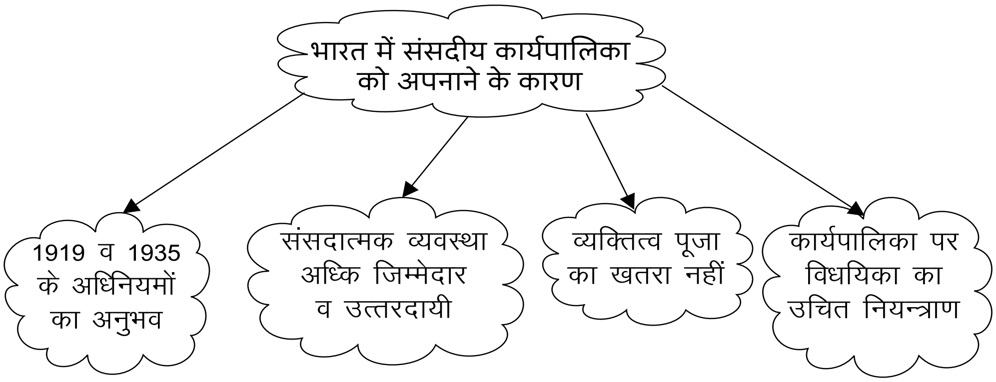

भारत में संसदीय कार्यपालिका को अपनाने के कारण
1919 व 1935 के अधिनियमों का अनुभव
संसदात्मक व्यवस्था अधिक जिम्मेदार व उत्तरदायी
व्यक्तित्व पूजा का खतरा नहीं
कार्यपालिका पर विधयिका का उचित नियन्त्राण

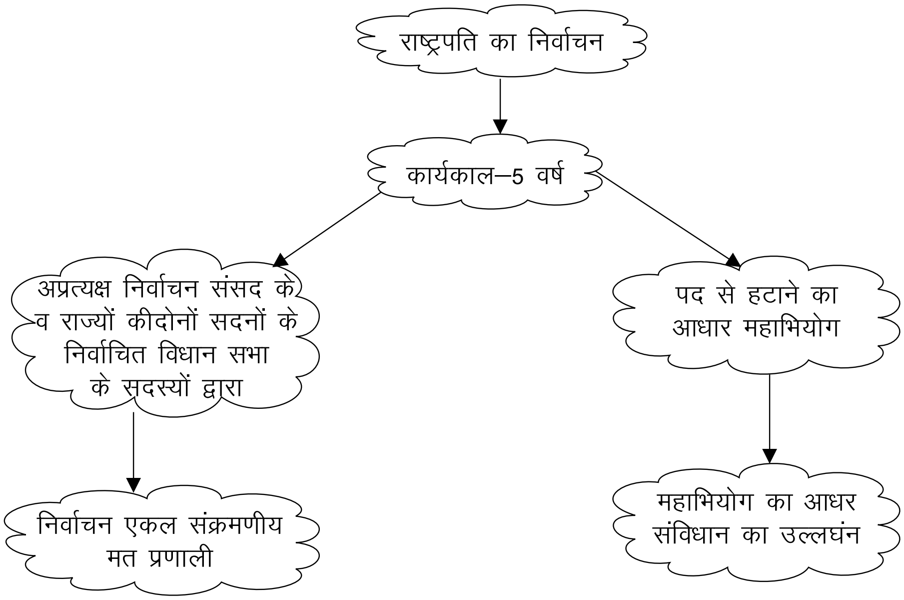

मन्त्रिपरिषद का आकार: संविधान के 91वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्रीपरिषद के सदस्यों की संख्या को सीमित एवं निश्चित किया गया है। मंत्रीपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कार्यस्तर के आधार पर मंत्रीयों का तीन स्तर में विभाजन होता है।

कार्यस्तर के आधर पर मंत्रीयों का तीन स्तर में विभाजन

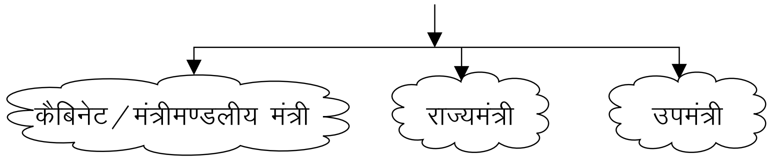

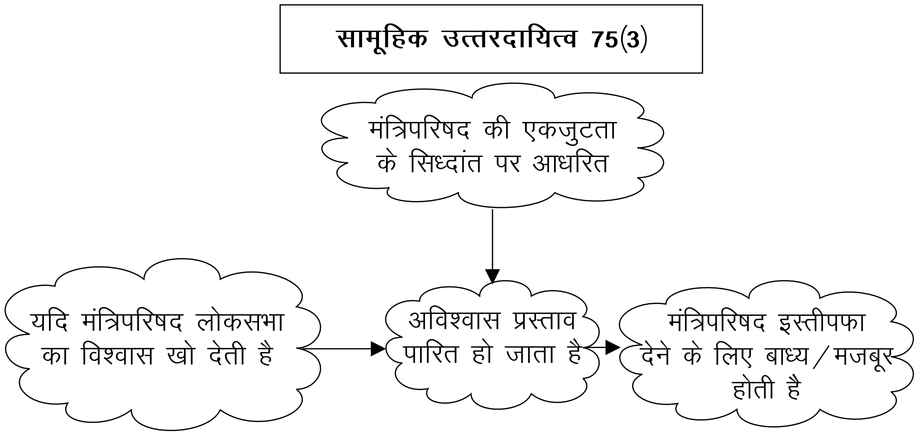

- अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में ही राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। अमेरिका, ब्राजील और लेटिन अमेरिका के कई देशों में यह व्यवस्था पाई जाती है।
- संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है इस व्यवस्था में एक राष्ट्रपति या राजा होता है जो देश का नाममात्र का प्रधान होता है। प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति होती है। भारत, जर्मनी, इटली, जापान, इग्लैंड और पुर्तगाल आदि देशों में यह व्यवस्था है।
- अर्द्धअध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं लेकिन उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हो सकती है फ्रांस, रूस और श्रीलंका में ऐसी ही व्यवस्था है।

भारत में संसदीय कार्यपालिकाः-

- अध्यक्षात्मक कार्यपालिका राष्ट्रपति की शक्तियों पर बहुत बल देती है, इससे व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ-साथ उसमें व्यक्ति पूजा पर भी पर्याप्त अंकुश लगें हो।
- संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और नियंत्रित भी। इसलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया।
- भारत में इस व्यवस्था में राष्ट्रपति, औपचारिक प्रधान होता है तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते है। राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते है।

राष्ट्रपति की शक्ति और स्थितिः-

- एक औपचारिक प्रधान हैः राष्ट्रपति को वैसे तो बहुत सी कार्यकारी, विधायी (कानून बनाना) कानूनी और आपात शक्तियाँ प्राप्त है परंतु इन सभी शक्तियों का प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है।

राष्ट्रपति के विशेषाधिकारः-

संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।

राष्ट्रपति के विशेषाधिकार

1. सदनों को पुर्नविचार के लिए लौटा सकता है।
2. वीटो शक्ति का प्रयोग करके संसद द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देने में विलम्ब।
3. चुनाव के बाद कई नेताओं के दावें के समय यह निर्णय करें कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा।

राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां

- संसदीय व्यवस्था मे, समर्थन न रहने पर, मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है, ऐसे समय में एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख की आवश्यकता पड़ती है जिसका कार्यकाल स्थायी हो, जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सकें।
- राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ये सभी कार्य करते हैं।
- भारत का उपराष्ट्रपतिः पांच वर्ष के लिए चुना जाता है, जिस तरह राष्ट्रपति को चुना जाता है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाया जाने या अन्य किसी कारन से पद रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है।

विभिन्न परिस्थितियों में प्रधनमंत्री की स्थिति

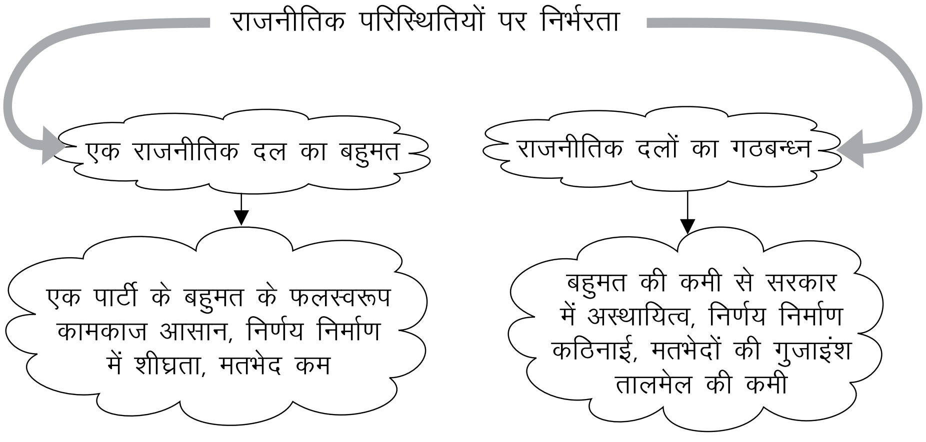

प्रधानमंत्री एवं मंत्रीपरिषद

प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यता-

1. वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो।
2. बहुमत का समर्थन प्राप्त हो।
3. यदि प्रधानमंत्री बनने के लिए समय वह संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो छः महीने के भीतर उसे संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होना अनिवार्य होगा। यही स्थिति मंत्रीयों पर भी लागू होगी।

प्रधानमंत्री पद की शक्तियो में आए बदलावः-

1. प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ी है।
2. राजनीतिक सहयोगियों से परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी है।
3. प्रधानमंत्री के विशेषाधिकारों पर अंकुश लगा है।
4. सहयोगी दलों के साथ बातचीत तथा समझौते के बाद ही नीतियां बनती है।

राज्यों में कार्यपालिका का स्वरूपः-

- राज्यों में एक राज्यपाल होता है जो (केन्द्रीय सरकार की सलाह पर) राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है।
- मुख्यमंत्री विधान सभा में बहुमत दल का नेता होता है।
- बाकी सभी सिद्धांत वही है जो केन्द्र सरकार में संसदीय व्यवस्था होने के कारण लागू है।

स्थायी कार्यपालिका (नौकरशाही)ः-

कार्यपालिका में मुख्यतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिगण और नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन, सम्मिलित होता है। इसे नागरिक सेवा भी कहते है।

- नौकरशाही में सरकार के स्थाई कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने में तथा उन्हें लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं।
- भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है लेकिन यह मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है इसका अर्थ है कि नौकरशाही राजनीतिक रूप से तटस्थ है। प्रजातंत्र में सरकारे आती जाती रहती है ऐसी स्थिति में, प्रशासनिक मशीनरी की यह जिम्मेदारी है कि वह नई सरकारों को अपनी नीतियां बनाने में और उन्हें लागू करने में मदद करें।

- नौकरशाही के सदस्यों का चुनावः नौकरशाही में अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी एवं प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित है। भारत में सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया का कार्य संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) को सौंपा गया है।

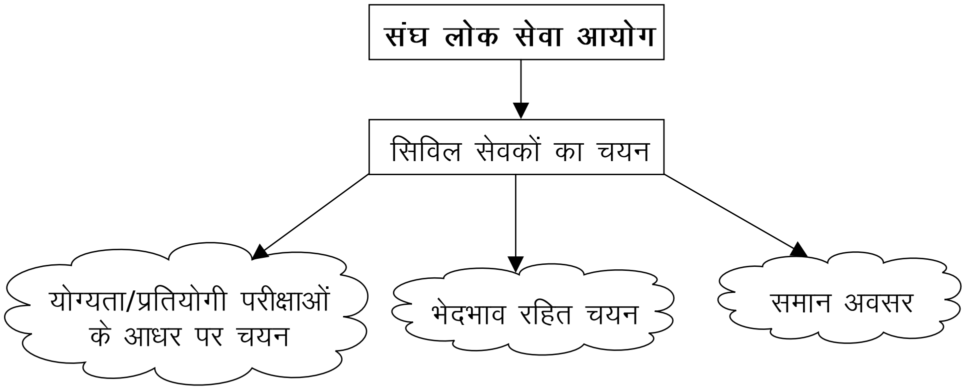

- ऐसा ही लोकसेवा आयोग राज्यों में भी बनाए गए है जिन्हें राज्य लोक सेवा आयोग कहा जाता है।
- लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता हैं उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा की गई जांच के आधार पर ही निलंबित या अपदस्थ किया जा सकता है।
- लोक सेवकों की नियुक्ति दक्षता व योग्यता को आधार बनाकर की जाती हैं संविधान ने पिछड़े वर्गों के साथ-साथ समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकरशाही बनने का मौका दिया है इसके लिए संविधान दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है।

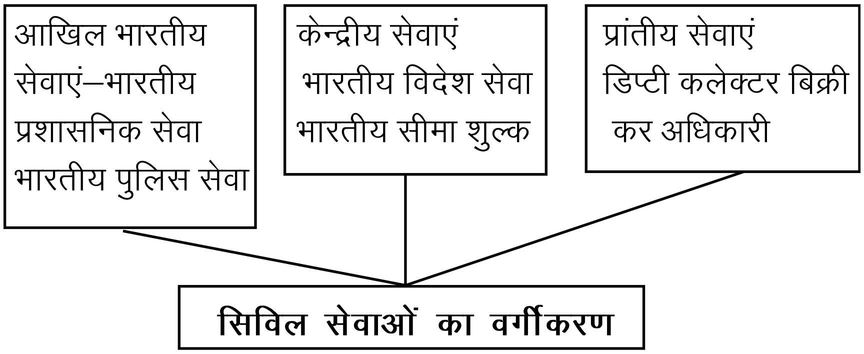

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस) तथा भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.) के उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। किसी जिले का जिलाधिकारी (कलेक्टर) उस जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है और ये समान्यतः आई ए एस स्तर का अधिकारी होता है।

नोटः- पॉकेट वीटो (Pocket Veto) - जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता है और संविधान के अनुच्छेद 3 के अन्तगत पुर्नविचार को भी नहीं लौटाता है ऐसी स्थिति में वो पॉकेट वोटो का प्रयोग करता है।

प्रश्नावली

एक अंकीय प्रश्नः-

1. अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति होता हैं।
   (क) राज्य का प्रधान
   (ख) सरकार का प्रधान
   (ग) राज्य व सरकार दोनों का प्रधान
   (घ) इनमें से कोई नहीं।

2. प्रधानमन्त्री पद के लिए आयु निर्धारित हैं।
   (क) कम से कम 20 वर्ष
   (ख) कम से कम 25 वर्ष
   (ग) कम से कम 30 वर्ष
   (घ) निर्धारित नहीं

3. सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्वान्त आधारित है
   (क) राज्य सभा के सदस्यों की एक जुटता पर आधारित
   (ख) लोकसभा सदस्यों की एक जुटता के सिद्वान्त पर आधारित
   (ग) मन्त्रिपरिषद की एक जुटता के सिद्वान्त पर आधारित
   (घ) उपरोक्त में से कोई नही

4. राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का नाम है।
   (क) अभियोग (ख) अभियुक्ति
   (ग) महाभियोग (घ) सभी

5. अमेरिका में कौन सी शासन प्रणाली हैं?
   (क) ससंदात्मक (ख) अध्यक्षात्मक
   (ग) मिश्रित (घ) साम्यवादी

अभिकथन कारणः- (आधारित प्रश्न)

1. अभिकथन: संविधान के 91वे संविधान संशोधन द्वारा मंत्रीपरिषद के सदस्यों की संख्या को सुनिश्चित किया गया है।

   कारणः मंत्रीपरिषद को कार्य-स्तर के आधार पर तीन प्रकार से विभाजित किया जाता है।

   (क) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता हैं।

   (ख) कथन एवं कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है।

   (ग) कथन गलत है एवं कारण सही हैं।

   (घ) कथन सही है कारण गलत है।

2. अभिकथन: अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में व्यक्तित्व पूजा का खतरा बना रहता है।

   कारणः अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में उत्तरदायित्व को अपेक्षा स्थायित्व पर बल दिया जाता है।

   (a) कथन A तथा R दोनों सही है तथा R कथन A की सही व्याख्या है

   (b) दोनों कथन A और R सही है लेकिन R कथन R की सही व्याख्या नहीं है

   (c) A गलत है और R सही है

   (d) A सही है लेकिन R गलत है

6. भारत में लोक सेवकों की नियुक्ति का आधार है।

   (a) राजनीतिक योग्यता (b) दक्षता एवं योग्यता

   (c) मात्र निर्वाचन (d) कोई नहीं

7. राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं

   (a) संसद के दोनों सदनों के सदस्य

   (b) संसद एवं राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य

   (c) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य

   (d) संसद एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य

8. संविधान के 91 वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधान को सम्मिलित किया गया है..........

9. राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का नाम है..........

10. राज्यसभा का पदेन सभापति .... होता है।

11. राष्ट्रपति का निर्वाचन .... प्रणाली द्वारा होता है।

12. भारतीय विदेश सेवा .... सेवाओं के अंतर्गत आती हैं।

निम्नलिखित कथन को सही करके पुनः लिखें।

13. वीटो शक्ति से अभिप्राय है राष्ट्रपति संसद से पारित विधेयकों पर अपनी स्वीकृति तुरंत देता है।

14. मंत्रीपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

15. अध्यक्षात्मक कार्यलालिका में राज्य का प्रमुख तथा सरकार का प्रमुख अलग-अलग होता है।

16. भारत में अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया गया है।

निम्नलिखित कथन बताएं सही है या गलत।

17. संघ लोक सेवा आयोग का कार्य है राष्ट्रपति को चुनना।

18. भारत में निर्वाचित नौकरशाही का सिद्धांत अपनाया गया है।

19. भारत में राज्य प्रमुख राष्ट्रपति है।

20. संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है। उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा की गई जांच के आधार पर ही हटाया जा सकता है।

संक्षिप्त प्रश्नों के उत्तर दें।

21. कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है?

22. कार्यपालिका में मुख्यतः किन-किन लोगों को शामिल किया जाता है?

23. भारत और इंग्लैंड की कार्यपालिका में प्रमुख अंतर क्या है?

24. अध्यक्षात्मक कार्यपालिका किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए।

25. भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त एक स्वविवेकीय शक्ति है का उल्लेख करें।

26. राष्ट्रपति को विशेषाधिकार की शक्ति से क्या अभिप्राय है?

27. कार्यपालिका तथा राजनीतिक कार्यपालिका में कोई एक अंतर बताएं।

28. पॉकेट वीटो से आप क्या समझते हैं?

29. सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है?

30. राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?

31. जिला कलेक्टर सामान्यतः किस स्तर का अधिकारी होता है?

32. लोक सेवा में दक्षता योग्यता के साथ ही समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले। इसके लिए संविधान में क्या प्रावधान सुनिश्चित किया है।

33. लोकसभा में बहुमत दल का नेता क्या कहलाता है?

34. निम्नलिखित अवतरण को पढ़ें तथा प्रश्नों के उत्तर दें:

कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। कार्यपालिका प्राय नीति निर्माण में भाग लेती है। सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन जो लोग रोज-रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें स्थाई कार्यपालिका कहते हैं।

1. राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहते हैं?

   (A) सरकार का प्रमुख (B) केवल मंत्री
   (C) सरकार का प्रमुख तथा मंत्रीपरिषद् (D) उपर्युक्त में कोई नहीं

2. स्थायी कार्यपालिका में शामिल किया जाता है?

   (A) मंत्री (B) नौकरशाही
   (C) प्रधान मंत्री (D) उपर्युक्त सभी

3. कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या है?

   (A) कानून निर्माण (B) न्यायिक निर्णय
   (C) नीतियों व कानूनों को लागू करना (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

4. राजनीतिक कार्यपालिका का उदाहरण है-

   (A) प्रधान मंत्री (B) मंत्री
   (C) प्रधान मंत्री तथा उसकी मंत्रीपरिषद (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

35. राष्ट्रपति सरकार का औपचारिक प्रधान है। उसे औपचारिक रूप से बहुत-सी कार्यकारी, विधायी, आपात शक्तियां प्राप्त है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है और वही वास्तविक कार्यकारी हैं। अधिकतर मामलों में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी होती है।

1. भारतीय संसदात्मक व्यवस्था में राज्य का प्रमुख कौन है ?

   (A) प्रधान मंत्री (B) राष्ट्रपति
   (C) राज्यपाल (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

2. राष्ट्रपति की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है?

   (A) स्पीकर (B) मंत्री
   (C) प्रधान मंत्री (D) कार्यपालिका

3. लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है?

   (A) राष्ट्रपति (B) प्रधान मंत्री
   (C) वित्त मंत्री (D) स्पीकर

4. 'डी फैक्टो' कार्यपालिका का अर्थ है-

   (A) वास्तविक कार्यपालिका (B) नाममात्र की कार्यपालिका
   (C) नाममात्र व वास्तविक कार्यपालिका (D) उपर्युक्त सभी

दो अंकीय प्रश्नः-

1. कार्यपालिका के किन्हीं दो रूपों का वर्णन करों।
2. एकजुटता के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं?
3. राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से क्या अभिप्राय है?
4. 'राष्ट्रपति एक अलंकारिक प्रधान है' स्पष्ट करो?
5. "मंत्रीगण एक साथ तैरते है तथा एक साथ डूबते हैं" इस कथन का क्या आशय है?
6. प्रधानमंत्री की शक्तियां किन परिस्थितियों पर निर्भर करती है। कैसे?
7. "राज्यपाल केन्द्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है"। कैसे?
8. "भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है" स्पष्ट करें।

9. ‘समाज के सभी वर्ग नौकरशाही का हिस्सा बन सकें’ इस उद्देश्य के लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए है?

10. “नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोक हितकारी नीतियां जनता तक पहुंचती है” क्या आप इस कथन से सहमत है?

चार अंकीय प्रश्नः-

1. राजनीतिक कार्यपालिका तथा स्थाई कार्यपालिका में चार अंतर बताएं।
2. संसदीय कार्यपालिका की चार विशेषताओं का वर्णन करें जो उसे विशिष्ट बनाती है।
3. “अध्यक्षात्मक सरकार में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है” कैसे?
4. राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियों का वर्णन करो।
5. राष्ट्रपति के ऐसे कौन से विशेषाधिकार है जो राष्ट्रपति की शक्त् कि प्रभावी बनाते हैं।
6. “प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपनी मर्जी नहीं चला सकता।” क्यों?
7. “प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तथा संसद के बीच एक सेतु का काम करता है”, स्पष्ट करों।
8. गठबंधन के युग के कारण प्रधानमंत्री की शक्तियों पर अंकुश लगा है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं?

चार अंकीय प्रश्नः-

(क) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो- कार्टून आधारित अभ्यास प्रश्न

(1) चित्र में सबसे आगे कौन नजर आ रहा हे? उसके सबसे आगे होने का क्या अभिप्राय है? (1)

(2) किन्हीं दो नेताओं को पहचाने उनके नाम लिखे। (1)

(3) प्रधानमंत्री के शक्तिशाली होने के दो कारण लिखे। (2)

ख. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो-

(1) विश्वास मत से क्या अभिप्राय है?

(2) सामूहिक उत्तरदायित्व से क्या अभिप्राय है?

(3) "विश्वास मत जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री की परेशानियां समाप्त नहीं होती, इस कथन का क्या अभिप्राय है।

छः अंकीय प्रश्नः-

1. राष्ट्रपति की स्थिति तथा कार्यों का वर्णन करों।
2. क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है'' तीन उचित तर्क दीजिए।
3. जब संसद में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता तब प्रधानमंत्री किस व्यक्ति को बनाया जाता है? ऐसे में प्रधानमंत्री की शक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है?
4. आमतौर पर देखा गया है कि संसदीय कार्यपालिका वाले देशों में प्रधानमंत्री बहुत प्रभावशाली तथा शक्तिशाली बन जाता है। ऐसा किन कारणों से होता है?
5. नौकरशाही राजनीतिक कार्यपालिका की किस प्रकार से सहायता करती है?
6. गठबंधन सरकारों के दौर में राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियां बढ़ जाती है इसक कथन की तर्क सहित पुष्टि करें।
7. स्वतन्त्र भारत मे अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का आधार दक्षता, प्रशासनिक योग्यता एवं समान अवसर की सुनिश्चितता को ध्यान में रखकर किया गया। ऐसा क्यों?
8. नौकरशाही ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही अपनी दृढ़ मौजूदगी एवं प्रशासनिक कुशलता का परिचय दिया है। व्याख्या करें।

उत्तरमाला

एक अंकीय प्रश्न के उत्तरः-

1. (ग)
2. (ख)
3. (ग)
4. (ग)
5. (ख)
6. (b) दक्षता एवं योग्यता
7. (d) संसद एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य

अभिकथन-कारण आधारित प्रश्नों के उत्तर

1. ख   2. क

8. मंत्री परिषद का आकार
9. महाभियोग

10. उपराष्ट्रपति
11. एकल संक्रमणीय मत प्रणाली
12. केंद्रीय सेवाओं
13. संसद से पारित विधेयकों पर स्वीकृति को लंबित करना
14. कुल सदस्य संख्या के 10: से अधिक नहीं
15. राज्य प्रमुख तथा सरकार प्रमुख एक ही
16. संसदात्मक प्रणाली को अपनाया गया है
17. गलत
18. गलत
19. सही
20. सही
21. सरकार का वह अंग जो कानूनों को लागू करता है।
22. कार्यपालिका में मुख्यतः प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद व राष्ट्रपति को शामिल किया जाता है।
23. भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ अध्यक्ष है जबकि इंग्लैंड की रानी राजतंत्र अतिथि के द्वारा बनी अध्यक्ष है।
24. जहां राष्ट्रपति कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों का ही अध्यक्ष होता है।
25. जब लोकसभा में किसी राजनतिक दल को बहुमत प्राप्त ना हो तब प्रधानमंत्री का चुनाव करना।
26. सदन को पुनर्विचार के लिए बिल लौट आना।
27. स्थाई कार्यपालिका में दिन प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदाई कर्मचारी सम्मिलित होते हैं वही कार्यपालिका में सरकार के प्रधान तथा उनके मंत्रियों को शामिल किया जाता है।
28. जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता है और पुनर्विचार को भी लौट आता है तो ऐसी स्थिति में वह पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है।
29. जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्यागपत्र देना होता है इसका मतलब यही है कि यदि किसी एक मंत्री के विरूद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है।
30. राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है
31. भारतीय प्रशासनिक सेवा

32. आरक्षण का प्रावधान

33. प्रधानमंत्री

34. 1. (C) सरकार का प्रमुख तथा मंत्री परिषद

2. (B) नौकरशाही

3. (C) कार्यपालिका का मुख्य कार्य विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियां तथा कानूनों को लागू करने

4. (C) राजनीतिक कार्यपालिका का एक उदाहरण है प्रधानमंत्री तथा उनके मंत्री

35. 1. (D) भारतीय संसदात्मक व्यवस्था में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति है।

2. (C) प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद

3. (B) प्रधानमंत्री

4. (A) राज्य का प्रमुख व सरकार प्रमुख अलग-अलग

2 अंकीय प्रश्नों के उत्तर:-

1. संसदीय कार्यपालिका, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका (संक्षिप्त वर्णन)
2. अध्यक्षात्मक कार्यपालिका जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्याग पत्र देता पड़ता है।
3. जब संसद का अधिवेशन न चल रहा हो तो राष्ट्रपति

   (1) अध्यादेश जारी कर सकता है।

   (2) यदि देश पर आक्रमण हो जाए।

   (3) यदि देश में वित्तीय संकट आ जाए।
4. क्योंकि वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद करती है।
5. यदि एक मंत्री किसी प्रश्न का उत्तर न दे पाएं तो प्रधानमंत्री उससे त्यागपत्र देने को कहता है यदि वह त्यागपत्र न दें तो प्रधानमंत्री स्वंय अपना त्याग पत्र दे देता है और सरकार गिर सकती है।
6. जब सदन में पूर्ण बहुमत होता है तो प्रधानमंत्री बहुत प्रभावशाली हो जाता है परंतु जब बहुमत नहीं होता तो उसे सभी काम सहयोगी दलों के नेताओं से सलाह करके करने पड़ते है।
7. क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है इसीलिए संबंधित राज्य में राज्यपाल केन्द्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है।

8. भारत में लोकसेवक प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी होते है वे अपने-अपने विषय में पारंगत होते है इसलिए नीतियों को बनाने और लागू करने में राजनीतिज्ञों की सहायता करते है।
9. संविधान में दलित तथा आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है बाद में महिलाओं और अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण दिया गया।
10. हाँ, क्योंकि नौकरशाही के सदस्य दक्ष और निपुण होते है और वे राजनीतिज्ञों को नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने में सहायता करते है ।

4 अंकीय प्रश्नों के उत्तरः-

1. राजनीतिक कार्यपालिका - 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है, समय से पहले भी हटाई जा सकती है। अपने कार्यों में निपुण नहीं होते । स्थाई कार्यपालिका - रिटायरमेंट की आयु तक काम करते है अपने कार्यों में दक्ष और निपुण होने के कारण राजनीतिक कार्यपालिका को मदद करते है ।
2. - सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री
   - राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति या राजा या रानी
   - विधायिका में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री
   - विधायिका के प्रति उत्तरदायी
3. अध्यक्षात्मक - देश का प्रमुख, सरकार का प्रमुख, जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से निर्वाचन, विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होना ।
4. विधायी कार्यपालिका, न्याय संबंधी, तीनो सेनाओं का सेनापति ।
5. (1) वीटो (2) गठबंधन की सरकार के समय प्रधानमंत्री का चुनाव
6. क्योंकि केवल लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। गठबंधन के समय भी जिस व्यक्ति को सदन का विश्वास प्राप्त होता है उसे ही प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है।
7. प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है, सदन की कार्यवाहियों से अवगत कराता है और सदन को राष्ट्रपति का संदेश देता है । राजनीतिक सहयोगियों से विचार विमर्श बढ़ा है।
8. - मंत्रियों का चयन अपनी इच्छा से नहीं कर सकता
   - नीतियों और कार्यक्रम अकेले तय नहीं कर सकता
   - मध्यस्थ की भूमिका बन गई है।

5 अंकीय प्रश्नों के उत्तर-

1. (क) 1. पं. जवाहर लाल नेहरू क्योंकि वो प्रधानमंत्री है। (1)
   2. अध्यापक की सहायता से पहचानें व उत्तर दें। (1)
   3. - क्योंकि वह बहुमत दल का नेता है। (2)
      - वह वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है। -

   (ख) 1. सदन में बहुमत (1)
   2. संसद के प्रति उत्तरदायी (1)
   3. क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति यदि दल छोड़ दें तो फिर से वहीं संकट आ जाएगा। (2)

छः अकीय प्रश्नों के उत्तरः

1. स्थितिः राष्ट्र का अध्यक्ष, तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति, नामपात्र की शक्तियां।
2. हां, क्योंकि:-

   (1) संविधान में ऐसा प्रावधान है अनुच्छेद 74 (1)

   (2) क्योंकि राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित प्रधान नहीं है ।

   (3) प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यकारी है।.

   तब राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है जो सदन में बहुमत प्राप्त कर लेता है प्रधानमंत्री की एकाधिकारवादी शक्तियां कम हो जाती है और विचार-विर्मश अधिक हो जाता है।

4. -मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण
   - अधिकारी वर्ग पर अधिपत्य
   - लोकसभा का नेतृत्व
   - मीडिया तक पहुंच
   - चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व का उभार,
   - अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि
   - विदेशी यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि

5. नौकरशाही मंत्रियों को नीतियों को बनाने तथा उन्हें लागू करने में सहायक, नीतियों पर विचार करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं (कोई अन्य)।

6. गठबन्धन के दौर में राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्ति का बढ़ना-

   (क) प्रधानमंत्री का चयन (यदि किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता।) उदाहरणों के साथ व्याख्या करें।

   (ख) किसी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिलने पर राष्ट्रपति पर निर्णय लेने की अधिक जिम्मेदारी।

7. दक्षताः ताकि कुशल एवं निपुण कार्यपालिका कार्यों को भली-भांति कर सके।

   प्रशासनिक योग्यताः लोकतान्त्रिक मूल्यों का संवर्द्धन तथा ही सम्भव जब सबको समान अवसर उपलब्ध है।

8. नीतियों का वास्तविक क्रियान्वयन नौकरशाही द्वारा ही सम्भव। दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए उत्तरदायी सामाजिक समस्याओं को कुशलतापूर्वक निपटाने में सक्षम। सूचना के अधिकार जैसे कदमों ने नौकरशादी को अधिक पारदर्शी व उत्तरदायी बनाया।

अध्याय-5

विधायिका

अध्याय के मुख्य बिंदु

हमें विधायिका की आवश्यकता क्यों है। सदनों की आवश्यकता, लोकसभा, राज्यसभा,कानून निर्माण, संसदीय समितियां, संसदीय नियंत्रण

विधायिका

- संसद की आवश्यकता
  - राजनीतिक प्रक्रियाओं का मंच
  - प्रतिनिधि लोकतन्त्र का आधार
  - नीति निमार्ण
  - वाद–विवाद का खुला मंच
  - लोकतांत्रिक सहभागिता का आधार
- दो सदनों की आवश्यकता
  - समाज के सभी वर्गो की भागीदारी
  - दूसरे सदन में पुनर्विचार सम्भव
  - जल्दबाजी में निर्णय नहीं
- लोकसभा
  - निर्वाचन
    - प्रत्यक्ष
    - भौगोलिक आधार पर प्रतिनिधित्व
    - सदस्योंः कार्यकाल निश्चित
    - अस्थायी सदन
  - लोकसभाः शक्तियां
    - कानून निर्माण
    - संविधान संशोधन
    - राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का चुनाव
    - प्रश्न पूछना, प्रस्ताव पारित करना व अविश्वास प्रस्ताव
    - समितियों व आयोग का गठन

राज्यसभा

निर्वाचन
- अप्रत्यक्ष
- राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व
- सदस्य–6 वर्ष के लिए निर्वाचित
- स्थायी सदन

राज्यसभाः शक्तियां
- कानून निर्माण एवं पुनर्विचार
- संविधान संशोधन
- राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी
- कार्यपालिका पर नियन्त्रण
- राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना

विधेयक
- सरकारी
- निजी
- गैर वित्त विधेयक
  - सामान्य विधेयक
  - संविधान संशोधन विधेयक
- वित्त विधेयक

संसदीय नियन्त्रण के साधन
- बहस व चर्चा
- कानूनों की स्वीकृति/अस्वीकृति
- वित्तीय नियन्त्रण
- अविश्वास प्रस्ताव

विधायिका:-

- संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है, यह राष्ट्रपति और दो सदन, जो राज्य सभा और लोक सभा कहलाते है, से बनती है। राज्यों की विधायिका को विधानमंडल या विधानसभा कहते हैं।
- लोकतंत्रीय शासन में विधायिका का महत्व बहुत अधिक होता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनायी गयी है जो कि ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित हैं।

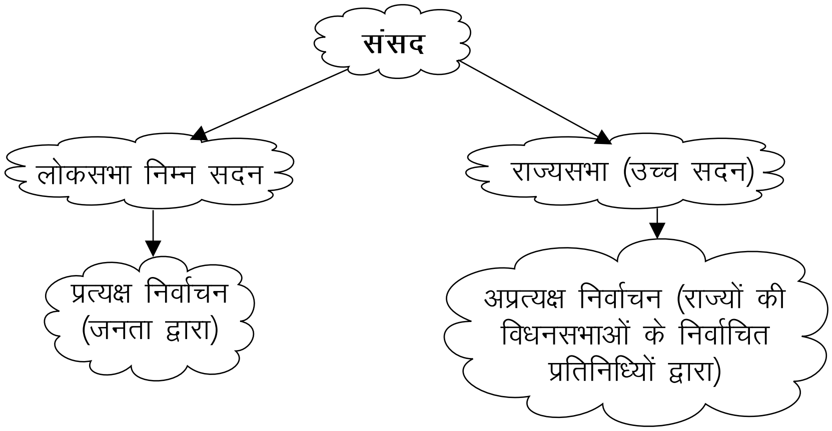

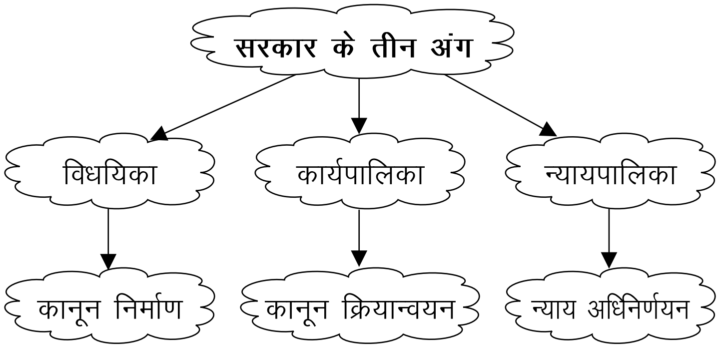

संसद के दो सदनों की आवश्यकता

- विधायिका का चुनाव जनता द्वारा होता है। इसलिए यह जनता का प्रतिनिधि बनकर कानून का निर्माण करता है। इसकी बहस विरोध, प्रदर्शन, बहिर्गमन, सर्वसम्मति, सरोकार और सहयोग आदि अत्यंत जीवन्त बनाए रखती है।

- संविधान के अनुसार भारतीय संसद में दो सदनों के साथ-साथ राष्ट्रपति को भी सम्मिलित किया जाता हैं।
- द्वि-सदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका का पहला लाभ समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सकें। दूसरा लाभ संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो।
- भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा हैं इसके अधिकतम 250 सदस्य होते है जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत और 238 स्दस्य राज्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित होते हैं। इनका निर्वाचन 6 वर्ष के लिए किया जाता है। राज्य सभा एक स्थायी सदन है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसमें एक तिहाई सदस्यों का चुनाव होता है। मनोनीत सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, समाजसेवा, खेल आदि क्षेत्रों से लिये जाते है।
- अमेरिका के द्वितीय सदन (सीनेट) में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है भारत में अधिक जनसंख्या वाले राज्य को अधिक व कम जनसंख्या वाले राज्य को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है।
- राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं-

  (1) वह भारत का नागरिक हो।

  (2) 30 वर्ष की आयु का हो।

  इनका निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है।
- 1951 के जन-प्रतिनिधि कानून के अनुसार राज्यसभा या लोक सभा के उम्मीदवार का नाम किसी न किसी संसदीय निर्वाचक क्षेत्र में पंजीकृत होना आवश्यक है-

राज्यसभा की विशेष शक्तियांः-

(1) वित्त विधेयक पर राज्यसभा 14 दिन तक विचार कर सकती है।

(2) संविधान-संशोधन संबंधी शक्तियां।

(3) प्रशासनिक शक्तियां- मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न राज्यसभा में जो पूछे जा सकते है।

(4) अन्य शक्तियाँः चुनाव, महाभियोग, आपात स्थिति की घोषणा न्यायधीश को उसके पद से हटाया जाना इत्यादि पर दोनों सदनों पर अनुमति जरूरी है।

- लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है। इसमे अधिकतम 550 सदस्य हो सकते है। वर्तमान में लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता हैं इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है परंतु उसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है।
- भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण लोकसभा अधिक शक्तिशाली है क्योंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसे कार्यपालिका को हटाने को शक्ति भी प्राप्त है।

संसद के प्रमुख कार्यः-

(1) कानून बनाना।
(2) कार्यपालिका पर नियंत्रण।
(3) वित्तीय कार्यः बजट पारित करना
(4) संविधान संशोधन।
(5) निर्वाचन संबंधी कार्य।
(6) न्यायिक कार्य।
(7) प्रतिनिधित्व।
(8) बहस का मंच।
(9) विदेश नीति पर नियन्त्रण
(10) विचारशील कार्य

- लोकसभा की विशेष शक्ति धन विधेयक प्रस्तुत करना उसे संशोधित व अस्वीकार कर सकती है।
- मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।

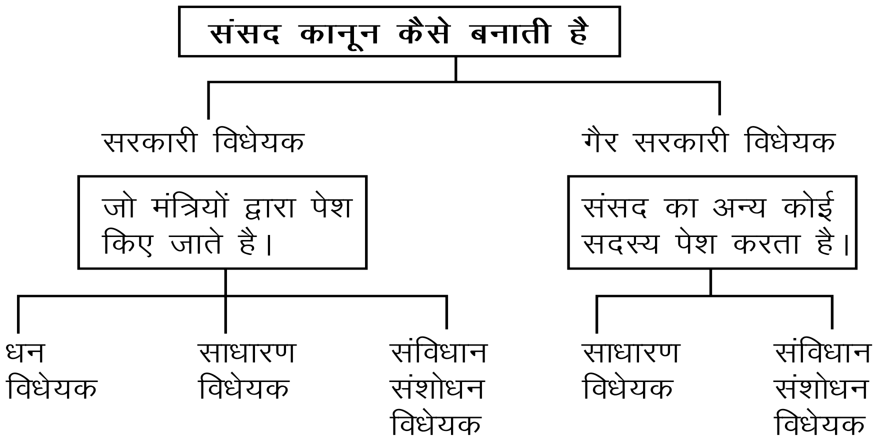

प्रक्रियाः-

(1) प्रथम वाचन।
(2) द्वितीय वाचन (समिति स्तर)
(3) समिति की रिपार्ट पर चर्चा
(4) तृतीय वाचन।
(5) दूसरे सदन में प्रक्रिया।
(6) राष्ट्रपति की स्वीकृति।

संसदीय नियंत्रण के साधनः-

(1) बहस और चर्चा- प्रश्न काल, शून्य काल, स्थगन प्रस्ताव।
(2) कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति।
(3) वित्तीय नियंत्रण।
(4) अविश्वास प्रस्ताव, निन्दा प्रस्ताव।

संसदीय समितियां तथा कार्यः-

- विभिन्न विधायी व दैनिक कार्यों के लिए समितियों का गठन संसदीय कामकाज का एक जरूरी पहलू है। ये विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श करती है और प्रशासनिक कार्यों पर निगरानी रखती है।

वित्तीय समितियांः-

(1) लोक लेखा समिति- भारत सरकार के विभिन्न विभागों का खर्च नियमानुसार हुआ है या नहीं।

(2) प्राकलन समिति- खर्च में किफायत किस तरह की जा सकती है।

(3) लोक उपक्रम- सरकारी उद्योगों की रिपोर्ट की जांच करती है कि उद्योग या व्यवसाय कुशलता पूर्वक चलाया जा रहे है या नहीं।

विभागीय स्थायी समितियांः-

(1) नियमन समिति।
(2) विशेषाधिकार समिति।
(3) कार्य-मंत्रणा समिति।
(4) आश्वासन समिति।

तदर्थ समितियांः-

- विशिष्ट विषयों की जांच-पड़ताल करने तथा रिपोर्ट देने के लिए समय-समय पर गठन किया जाता है। समितियों द्वारा दिये गए सुझावो को संसद शायद ही नामंजूर करती है।

संसद स्वयं को किस प्रकार नियंत्रित करती है-

(1) संसद का सार्थक व अनुशासित होना।

(2) सदन का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही के मामलों में सर्वोच्च अधिकारी होता है।

(3) दल बदल निरोधक कानून द्वारा 1985 में 52 वां संशोधन किया गया। 91 वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया गया।

यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद-सदन में उपस्थित न हो या दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करें अथवा स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्यागपत्र दें उसे 'दलबदल' कहा जाता है। अध्यक्ष उसे सदन की सदस्यता के अयोग्य ठहरा सकता है।

(4) भारतीय संघात्मक सरकार में 28 राज्य 8 केंद्र शासित इकाईयों को मिलाकर भारत में संघीय शासन की स्थापना करती है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया हैं

(5) भारत के प्रत्येक राज्य में विधानमंडल की व्यवस्था एक समान नहीं है। कुछ राज्यों में एक सदनीय तथा कुछ राज्यों में द्वि-सदनीय व्यवस्था है।

(6) राज्यों में कानून निर्माण का कार्य विधानमंडलों को दिया गया है-

   (i) निम्न सदन को विधानसभा।

   (ii) उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है।

द्विसदनीय राज्यः-

- उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक व आन्ध्र प्रदेश, छः राज्य बाकी सभी राज्य एक सदनीय है।

   (1) विधानसभा की शक्तियां-

      (i) विधायी कार्यशक्ति।

(ii) वित्तीय शक्तियां।

(iii) कार्यपालिका शक्तियां।

(iv) चुनाव संबंधी कार्य।

(v) संविधान संशोधन सबंधी शक्तियां।

(2) विधान परिषद की शक्तियां-

(i) विधायी शक्तियां।

(ii) वित्तीय शक्तियां।

(iii) कार्यपालिका शक्तियां।

दोनों सदन राज्य विधानपालिका के आवश्यक अंग होते हुए भी संविधान ने विधानसभा को बहुत शक्तिशाली व प्रभावशाली स्थित प्रदान की है।

प्रश्नावली

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?

(क) प्रधानमंत्री (ख) मुख्यमंत्री

(ग) राष्ट्रपति (घ) लोकसभा

2. राजनीतिक कार्यपालिका का कार्य काल होता हैः

(क) निश्चित
(ख) 4 वर्ष
(ग) लोकसभा में बहुमत रहने तक
(घ) कोई नहीं।

3. भारतीय संसद का ऊपरी सदन हैः

(क) लोकसभा
(ख) राज्य सभा
(ग) लोकसभा व राज्यसभा दोनों
(घ) कोई नहीं

4. वित्त विधेयक को राज्यसभा द्वारा रोका जा सकता है।

(क) 14 दिन (ख) 18 दिन

(ग) 20 दिन (घ) कोई नहीं

5. अमेरिका के द्वितीय सदन का नाम हैंः

(क) प्रतिनिधि सभा (ख) सीनेट

(ग) काग्रेस (घ) राज्यसभा

अभिकथन एवं तर्क:

1. अभिकथनः- भारत में अधिक जनंसख्या वाले राज्य को अधिक व कम जनसंख्या वाले राज्य को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है।

तर्क: भारत में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा में समान सीटों का आवंटन किया गया है।

2. अभिकथनः संसद की समितियों को लघु विधायिकाये कहा जाता है।

कारण: संसदीय समितियां विधेयक पर जीवंत तथा तर्कपूर्वक विचार-विमर्श करती है।

(i) कथन A तथा R दोनों सही है तथा R कथन A की सही व्याख्या है

(ii) दोनों कथन A और R सही है लेकिन R कथन A की सही व्याख्या नहीं है

(iii) A गलत है और R सही है

(iv) A सही है लेकिन R गलत है

2. अभिकथनः संसद की समितियों को लघु विधायिकायें कहा जाता है।

कारण: संसदीय समितियां विधेयक पर जीवंत तथा तर्कपूर्वक विचार-विमर्श करती है।

(i) कथन A तथा R दोनों सही है तथा R कथन A की सही व्याख्या है।

(ii) दोनों कथन A और R सही है लेकिन R कथन A की सही व्याख्या नहीं है।

(iii) A गलत है और R सही है।

(iv) A सही है लेकिन R गलत है।

एक अंकीय प्रश्न

1. राज्यसभा के सदस्यों के लिए आयु निर्धारित की गई है।

    (i) 30 वर्ष
    (ii) 35 वर्ष
    (iii) 40 वर्ष
    (iv) 45 वर्ष

2. कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करने का अधिकार है।

    (i) राष्ट्रपति
    (ii) लोकसभा अध्यक्ष
    (iii) प्रधानमंत्री
    (iv) उपराष्ट्रपति

3. भारत में मंत्री परिषद किस सदन के प्रति उत्तरदाई है?

    (i) राष्ट्रपति
    (ii) लोकसभा
    (iii) राज्यसभा
    (iv) लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों

4. राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है।

    (i) प्रधानमंत्री
    (ii) राष्ट्रपति
    (iii) उपराष्ट्रपति
    (iv) मुख्यमंत्री

5. राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जिन्हें विशेषज्ञता प्राप्त होती है।

    (i) कला, साहित्य खेल एवं विज्ञान
    (ii) कला, साहित्य, रंगमंच एवं सामाजिक सेवा
    (iii) कला, साहित्य, राजनीति एवं समाज सेवा
    (iv) कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा

6. विधेयक को राज्यसभा पुनर्विचार के लिए रख सकती है।

   (i) 10 दिन
   (ii) 14 दिन
   (iii) 3 महीने
   (iv) 6 महीने

7. राज्यसभा प्रतिनिधित्व करती है।

   (i) भारत के राज्यों का
   (ii) संघ एवं राज्यों का
   (iii) संघ का
   (iv) कोई नहीं

8. यदि भारत सरकार कोई नया कर लगाना चाहती है तो उसे सहमति लेनी होगी।

   (i) राज्यसभा
   (ii) लोकसभा
   (iii) लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों
   (iv) राष्ट्रपति

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें:

9. राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल .... होता है।
10. लोक सभा के पहले अध्यक्ष .... थे।
11. संविधान का 52वां संविधान संशोधन .... से संबंधित है।
12. विधायक द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक...................... कहलाता है।
13. लोकसभा व राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता .... करता है।
14. संविधान की चौथी अनुसूची में राज्य सभा के सदस्यों की संख्या .... सुनिश्चित की गई है।

निम्नलिखित कथन बताएं सही है या गलत।

15. संसद में राज्यसभा लोकसभा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है।
16. संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।

17. मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।

18. गैर सरकारी विधेयक वह हैं जो संसद के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं।

19. संयुक्त राज्य अमेरिका में द्वितीय सदन सीनेट के सदस्यों को राज्यों में समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है।

20. लोक लेखा समिति यह देखती है कि सरकारी उद्योग या व्यवसाय कुशलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं या नहीं।

निम्नलिखित कथनों को सही करके लिखें।

21. राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रति 2 वर्ष के पश्चात कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं।

22. संविधान संशोधन विधेयक यदि दूसरे सदन में पारित नहीं होता है तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान संविधान में उल्लेखित है।

23. सरकार के विभिन्न विभागों का खर्च नियमानुसार हुआ है या नहीं यह कार्य लोक उपक्रम समिति का है।

24. विभिन्न विधाएं तथा दैनिक कार्यों के लिए संसदीय समिति का गठन किया जाता है। यह विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श करती है। इनकी संस्तुतियों का पालन करना संसद के लिए अनिवार्य है।

25. भारतीय संघ में राज्यों की विधानसभाओं में दो सदनों की व्यवस्था अनिवार्य है।

26. कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित ना हो या मतदान ना करें या स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे तो उसे लोकसभा का नियंत्रण कहा जाता है।

28. संसद का किन्हीं दो समितियों के नाम लिखो।

अति संक्षिप्त प्रश्नों के उत्तर दें।

29. भारतीय संसद का कौन-सा सदन अधिक शक्तिशाली है?

30. वर्तमान में किस नए राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका है?

31. संसद के कौन-से तीन सत्र होते हैं?

32. संसद के किसी एक न्यायिक कार्य का उल्लेख करें।

33. द्विसदनीय विधायिका का कोई एक लाभ समझाएं।

34. भारतीय संविधान में कितनी सूचियों का उल्लेख किया गया है?

35. संसदीय नियंत्रण के किन्हीं दो साधनों का उल्लेख करें?

36. अनुच्छेद 312 में क्या प्रावधान है?

37. कोई एक तर्क प्रस्तुत करें जिससे राज्यसभा की प्रासंगिकता का महत्व पता चलता है।

38. राज्यसभा किसी सामान्य विधेयक को अपने पास कितने समय तक रख सकती है?

दो अंकीय प्रश्न-

1. दि-सदनात्मक विधायिका के पक्ष में दो तर्क दीजिए?
2. भारत के किन्हीं चार राज्यों के नाम लिखिए जिनमें द्वि-सदनात्मक विधायिका है?
3. राज्यसभा की संरचना स्पष्ट कीजिए?
4. लोकसभा की दो विशेष शक्तियों का उल्लेख कीजिए?
5. वित्त विधेयक और गैर विधेयक में अंतर है स्पष्ट करें।
6. मिलान करो-

(क) राज्य सभा में मनोनीत सदस्य	(1) राज्यसभा
(ख) निम्न सदन	(2) लोकसभा
(ग) ऊपरी सदन	(3) शून्य
(घ) लोकसभा में मनोनीत सदस्य	(4) 12

7. दलबदल में क्या अभिप्राय है?
8. राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए दो योग्यताएं कौन-सी है?
9. राज्यसभा की दो विशेष शक्तियों का वर्णन कीजिए?
10. किन परिस्थितियों में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है?

चार अंकीय प्रश्न-

1. विधायिका/संसद सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण केन्द्र है। स्पष्ट करें।
2. लोकसभा किस प्रकार भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रतिबिम्ब है चार तर्क दीजिए।

3. लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए?

4. यह नहीं है कि लोकसभा महत्वपूर्ण सदन है लेकिन राज्यसभा के पास ऐसी महत्वपूर्ण शक्तियां है जो उसे विशिष्ट बनाती है क्या आप इस कथन से सहमत है?

5. भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया के कोई चार चरण बताइए?

6. निम्नलिखित अवतरण का पढ़ तथा प्रश्ना के उत्तर द ।

   विधायिका केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है यह सभी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का केन्द्र है। सदन का इसके तहत विरोध, प्रदर्शन, सर्वसम्मति, सरोकार और सहयोग इत्यादि अत्यंत जीवंत बनाए रखते हैं। दरअसल वास्तविक प्रतिनिधित्व वाली कुशल तथा प्रभावी विधायिका के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा कसती। विधायिका जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है।

6. अवतरण आधारित प्रश्न

6.1 कानून बनाने वाली संस्था है।

(क) विधायिका (ख) कार्यपालिका
(ग) न्यायपालिका (घ) नौकरशाही

6.2 भारतीय सांसदत्मक व्यवस्था में विधायिका है।

(क) विरोध प्रदर्शन का केंद्र
(ख) लोकतांत्रिकप्रक्रियाओं का केंद्र
(ग) मात्र कानून बनाने का केंद्र
(घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

6.3 क्या सदन को जीवंत रखते हैं?

(क) विरोध व प्रदर्शन
(ख) सर्वसम्मति
(ग) सरोकार तथा सहयोग
(घ) उपरोक्त सभी

6.4 भारतीय संविधान में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाने का कारण है?

(क) बहुलता को प्रतिनिधित्व मिलसकना संभव
(ख) दोहरा नियंत्रण
(ग) क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व
(घ) उपरोक्त सभी

7. निम्नलिखित अवतरण का पढ़े तथा प्रश्नों के उत्तर दें:

विधेयकों पर विचार विमर्श अधिकांशतः संसदीय समितियों में होता है। समिति की सिफारिशें को सदन में भेज दिया जाता है। इन समितियों में सभी संसदीय दलों का प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इसी कारण इन समितियों का लघु विधायिका भी कहते है। यह कानून निर्माण की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। तीसरे और अंतिम चरण में विधेयक पर मतदान होता है। जब कोई सामान्य विधेयक एक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरा सदन भी इसी प्रक्रिया से गुजरता है।

7. अवतरण आधारित प्रश्न

7.1 लघु विधायिका को कहा जाता है।

(क) सांसद (ख) लोकसभा
(ग) राज्यसभा (घ) संसदीय समितियां

7.2 विधेयक संसदीय समितियां के समक्ष जाता है।

(क) पहले चरण में (ख) दूसरे चरण में
(ग) तीसरे चरण में (घ) कभी भी

7.3 तीसरे चरण में विधेयक पर होता है।

(क) विचार (ख) पुनर्विचार
(ग) मतदान (घ) अन्य कुछ

7.4 संसदीय समितियों में सदस्य होते है।

(क) लोकसभा के मात्र (ख) राजसभा के मात्र
(ग) लोकसभा व राज्यसभा के (घ) मंत्रीपरिषद के

8 चार अंकीय प्रश्न – मानचित्र आधारित प्रश्न

भारत के मानचित्र में द्वि सदनात्मक विधायिका वाले कोई चार राज्यों का नाम लिखें।

8. कार्टून आधारित प्रश्न

9. (अभ्यास हेतु) उपरोक्त कार्टून के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

   (i) सदन से वॉक आऊट करना क्या एक उचित तरीका है? स्पष्ट करें। (1)

   (ii) अध्यक्ष सदस्यों को सदन से किस आधार पर आऊट कर सकते है? (1)

   (iii) सदस्यगण वॉक आऊट जैसा व्यवहार क्यों करते हैं? अपना विचार प्रस्तुत करें। (2)

छः अंकीय प्रश्न-

1. लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रण में रख सकती है।

2. लोकसभा कार्यपालिका पर कारगर ढंग से नियंत्रण रखने की नहीं बल्कि जन भावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है। क्या आप इससे सहमत है? कारण सहित उत्तर दें।

3. केवल कानून निर्माण ही नहीं, अपितु संसद अनेक महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं की सहभागिता का हिस्सा है, इस कथन को स्पष्ट करते हुए संसद के कार्यो का उल्लेख करें।
4. संसदीय नियन्त्रण के वे कौन-से कारक है जो कार्यपालिका को अपने नियन्त्रण में रखते हैं।
5. प्रश्नकाल प्रशासनिक एवं कार्यकारी एजेन्सी पर नियन्त्रण का महत्वपूर्ण एवं प्रभावी साधन है। स्पष्ट करें।

उत्तरमाला

बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तरः-

1. (ग) राष्ट्रपति
2. (ग) लोकसभा में बहुमत रहने तक
3. (ख) राज्यसभा
4. (क) 14 दिन
5. (ख) सीनेट

अभिकथन एवं तर्क

1. (घ)
2. (क)

एक अंकीय प्रष्नों के उत्तरः-

1. (a) 30 वर्ष
2. (b) लोकसभा अध्यक्ष
3. (b) लोकसभा
4. (b) राष्ट्रपति
5. (d) कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा
6. (b) 14 दिन
7. (a) भारत के राज्यों का
8. (b) लोकसभा
9. 6 वर्ष
10. जीवी मावलंकर

11. दलबदल
12. गैर सरकारी विधेयक
13. लोकसभा अध्यक्ष
14. दसवीं अनुसूची
15. गलत
16. गलत
17. सही
18. सही
19. सही
20. गलत
21. एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं
22. संविधान संशोधन के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है यह सामान्य विधेयक पर होता है।
23. लोक लेखा समिति
24. इनकी संस्तुतियों का पालन करना संसद के लिए अनिवार्य नहीं है
25. दो सदन की व्यवस्था अनिवार्य नहीं है
26. दलबदल कहा जाता है
27. तेलंगाना
28. लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति लोकसभा
29. लोकसभा अधिक शक्तिशाली है
30. द्विसदनात्मक राज्य राज्य आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक ,महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश
31. 3 सत्रः बजट सत्र, मॉनसून सत्र, शीतकालीन सत्र
32. राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया
33. विधेयक पर पुनर्विचार
34. तीन सूचियों का उल्लेख

35. प्रश्नकाल, अविश्वास प्रस्ताव

36. अनुच्छेद 312 में प्रावधान है कि राज्य सूची के विषय पर यदि परिवर्तन करना है तो राज्यसभा की सहमति लेना आवश्यक है।

37. यह सदन विधायकों पर पुनर्विचार करता है तथा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है

38. 6 महीने तक अपने पास रख सकती है।

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तरः-

1. (1) समाज के सभी वर्गों व क्षेत्रों की समुचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है।

   (2) दूसरा सदन प्रथम सदन के कार्यभार कम करता है।

2. (1) आन्ध्र प्रदेश (2) उत्तरप्रदेश (3) बिहार (4) कर्नाटक

3. राज्यसभा के कुल सदस्य 250 है जिसमें 238 राज्यों द्वारा निर्वाचित क्षेत्र और 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है।

4. (1) धन विधेयक पेश करना
   (2) मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण।

5. संविधान में संशोधन के लिए या सामान्य विधयकों को गैर वित्त विधेयक कहते है जबकि धन संबंधी विधेयकों को वित्त विधेयक कहते है जैसे कर लगाने के प्रस्ताव का बजट ।

6. मिलान करो-

   (क) (4) 12
   (ख) (2) लोकसभा
   (ग) (1) राज्य सभा
   (घ) (3) शून्य

7. जब कोई सदस्य स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्यागपत्र दें और दल की सदस्यता ग्रहण कर लें उसे दलबदल कहते है।

8. (1) वह भारत का नागरिक हो। (2) वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

9. (1) राज्य सभा, राज्य के अंतर्गत आने वाली विषयों पर राष्ट्रीय हित हेतुसंसद को कानून बनाने का अधिकार दे सकती है।

   (2) राज्यसभा किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा का राष्ट्र के हित में गठन कर सकती है।

10. जब दोनों में मतभेद हो ।

चार अंकीय प्रशनों के उत्तर-

1. (i) विधि निर्माण। (ii) बजट पारित करना।
   (iii) सरकार पर नियंत्रण। (iv) संविधान में संशोधन।

10. उत्तर के लिये पाठ्य पुस्तक का पेज नं. 110 देखे।
    (i) भारत का नागरिक।
    (ii) आयु 25 वर्ष।
    (iii) पागल व दिवालिया न हो।
    (iv) किसी लाभपद सरकारी पद पर न हो।

4. उत्तर के लिये पाठ्य पुस्तक का पेज नं. 110 देखें।

5. प्रथम वाचन
   द्वितीय वाचन
   तृतीय वाचन
   राष्ट्रपति की स्वीकृति (व्याख्या सहित)।

6. अवतरणआधारित प्रश्नों के उत्तर
   6.1 (क) 6.2 (ख) 6.3 (घ) 6.4 (घ)

7. अवतरणआधारित प्रश्नों के उत्तर
   7.1 (घ) 7.2 (ख) 7.3 (ग) 7.4 (ग)

8. चार अंकीय प्रश्नों के उत्तर - मानचित्र आधारित प्रश्न का उत्तर
   1. तेलंगाना 2. उत्तर प्रदेश 3. बिहार 4. महाराष्ट्र

9. (i) नहीं, क्योंकि सदन एक ऐसा मंच है। जहां पर वाद-विवाद चर्चा, बहस व सहमति के आधार पर किसी समस्या का समाधान खोजा जाता है। (1)
   (ii) अनुशासनहीनता पर। (1)
   (iii) विद्यार्थी स्वयं उत्तर लिखें।
   अथवा
   अनुशासनहीनता तथा सदन में अव्यवस्था फैलाने पर (2)

छः अंकीय प्रश्नों के उत्तर-

1. (i) प्रश्न, पूरक-प्रश्न, काम रोको प्रस्ताव आदि से

   (ii) अविश्वास प्रस्ताव

   (iii) मंत्रीपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी

   (iv) जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि

   (v) लोकप्रिय सदन

   (vi) सदस्य संख्या अधिक

2. (i) जनता के चुने प्रतिनिधि होने के कारण

   (ii) जनहित में कानून बनाना।

   (iii) जनआकांक्षाओं एवं भावनाओं से परिचित होना।

   (iv) चुनाव के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेही। (व्याख्या सहित)

3. कानून बनाना
   कार्यपालिका पर नियंत्रण
   बहस व चर्चा
   वित्तीय नियंत्रण व अविश्वास प्रस्ताव आदि।

4. विचार विमर्श एवं वाद-विवाद, कानून निर्माण पर सहमति या असहमति अविश्वास प्रस्ताव, आर्थिक नियन्त्रण।

5. जनता के हितों की अभिव्यक्ति सरकार के कार्यो की आलोचना का अवसर निर्वाचन क्षेत्रों की समस्याओं की प्रस्तुति।

अध्याय-6

न्यायपालिका

अध्याय के मुख्य बिंदु

स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता, संरचना, सर्वोच्च न्यायालयका क्षेत्राधिकार, न्यायपालिका व अधिकार, न्यायपालिका तथा सांसद

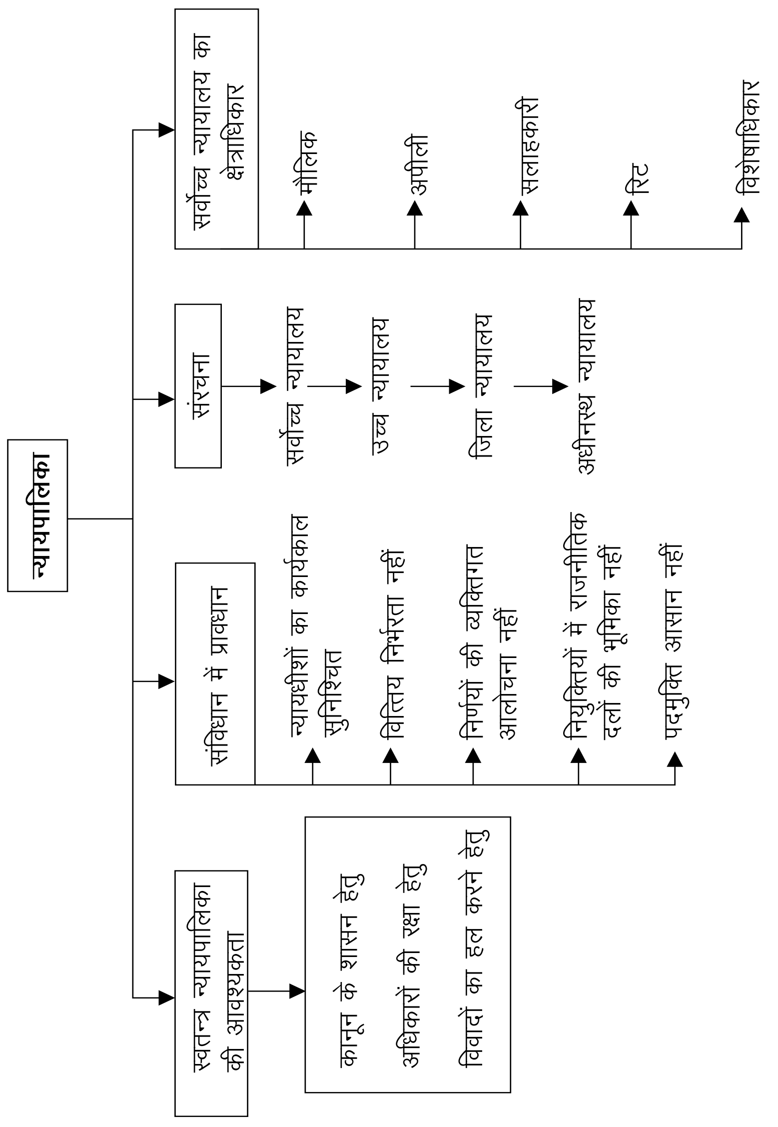

स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता:-

- न्यायपालिका सरकार का महत्वपूर्ण तीसरा अंग है जिसे विभिन्न व्यक्तियों या निजी संस्थाओं ने आपसी विवादों को हल करने वाले पंच के रूप में देखा जाता है कि कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करें। इसके लिये यह जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर स्वतंत्र निर्णय ले सकें। न्यायपालिका देश के संविधान लोकतांत्रिक परम्परा और जनता के प्रति जवाबदेह है।
- विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न पहुँचाए और न्यायपालिका ठीक प्रकार से कार्य कर सकें।
- न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सकें।
- न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। इनका निश्चिति कार्यकाल होता है। ये सेवा निवृत्त होने तक अपने पद पर बने रहते है। विशेष स्थितियों में न्यायधीशों को हटाया जा सकता है।
- न्यायपालिका, विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है।

न्यायधीश की नियुक्ति एवं हटाना:-

- मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायधीश- ये सभी न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करते है।
- मुख्य न्यायधीश की नियुक्ति के संदर्भ में यह परम्परा भी है कि सर्वोच्च न्यायलय के सबसे वरिष्ठ न्यायधीश को मुख्य न्यायधीश चुना जाता है किन्तु भारत में इस परम्परा को दो बार तोड़ा भी गया है।
- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायलय के अन्य न्यायधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायधीश की सलाह से करता है। ताकि न्यायलय की स्वतंत्रता व शक्ति संतुलन दोनों बने रहे।
- विशेष परिस्थितियों में ही न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है।

न्यायपालिका की पिरामिड रूपी सरंचनाः-

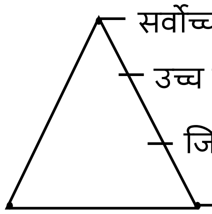

सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार-आरम्भिक क्षेत्राधिकार

- मौलिक अधिकारः केन्द्र व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा।
- रिटः मौलिक अधिकारों का संरक्षण, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव सम्बन्धित विवाद।

अपीलीय

- दीवानी फौजदारी व संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायलयों के मुकदमों पर अपील सुनना।

सलाहकारी

- जनहित के मामलों तथा कानून के मसलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना।

विशेषाधिकार

- किसी भारतीय अदालत के दिये गये फैसले पर स्पेशल लाइव पिटीशन के तहत अपील पर सुनवाई।
- भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जन हित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका रही है।
- 1979-80 के बाद जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता के द्वारा न्यायधीश ने उन मामलें मे रूचि दिखाई जहां समाज के कुछ वर्गों के लोग आसानी से अदालत की सेवाएँ नहीं ले सकते। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु न्यायलय ने जन सेवा की भावना से भरे नागरिक, सामाजिक संगठन और वकीलों को समाज के जरूरतमंद और गरीब लोगों की ओर से-याचिकाएं दायर करने को इजाजत दी।
- न्यायिक सक्रियता ने न्याय व्यवस्था को लोकतंत्रिक बनाया और कार्यपलिका उत्तरदायी बनने पर बाध्य हुई।

- चुनाव प्रणाली को भी ज्यादा मुक्त ओर निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया।
- चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की अपनी संपति आय और शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में शपथ पत्र देने का निर्देश दिया, ताकि लोग सही जानकारी के आधार पर प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें।

सक्रिय न्यायपालिका का नकरात्मक पहलूः-

- न्यायपालिका में काम का बोझ बढ़ा
- न्याायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यो के बीच अंतर करना मुश्किल हो गया जैसे-वायु और ध्वनि प्रदूषण दूर करना, भ्रष्टाचार की जांच व चुनाव सुधार करना इत्यादि विधायिका की देखरेख में प्रशासन को करना चाहिए।
- सरकार का प्रत्येक अंग एक-दूसरे की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का सम्मान करें।

न्यायिक पुनराक्लोकन का अधिकार

- न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायलय किसी भी कानून की संवैधानिक जांच कर सकता है यदि यह संविधान के प्रावधानों के विपरित हो तो उसे गैर-संवैधानिक घोषित कर सकता है।
- संघीय संबंधी (केंद्र-राज्य संबंध) के मामलें में भी सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है।
- न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या करती हैं तथा प्रभावशाली ढंग से संविधान की रक्षा करती है।
- नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है।
- जनहित याचिकाओं द्वारा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा ने न्यायपालिका की शक्ति में बढ़ोतरी की है।

न्यायपालिका और संसद/ न्यायपालिका व संसद-

- भारतीय संविधान में सरकार के प्रत्येक अंग का एक स्पष्ट कार्यक्षेत्र है। इस कार्य विभाजन के बावजूद संसद व न्यायपालिका तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव भारतीय राजनीति की विशेषता रही है।
- संपत्ति का अधिकार।

- ससद की संविधान को संशोधित करने की शक्ति के संबंध में।
- इनके द्वारा मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता।
- निवारक नजरबंदी कानून।
- नौकरियों में आरक्षण संबंधी कानून।

1973 में सर्वोच्च न्यायलय के निर्णय

- संविधान का एक मूल ढांचा है और संसद सहित कोई भी इस मूल ढांचें से छेड़-छाड़ नहीं कर सकता। संविधान संशोधन द्वारा भी इस मूल ढँाचें केा नहीं बदला जा सकता।
- संपत्ति के अधिकार के विषय में न्यायलय ने कहा कि यह मूल ढाँचें का हिस्सा नहीं है उस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
- न्यायलय ने यह निर्णय अपने पास रखा कि कोई मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं यह निर्णय संविधान की व्याख्या करने की शक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है।
- संसद व न्यायपालिका के बीच विवाद के विषय बने रहते है। संविधान यह व्यवस्था करती है कि न्यायधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती लेकिन कुछ अवसरों पर न्यायपालिका के आचरण पर उंगली उठाई गई है। इसी प्रकार न्यायपालिका ने भी कई अवसरों पर विधायिका की आलोचना की है।
- लोकतंत्र में सरकार के एक अंग का दूसरे अंग की सत्ता के प्रति सम्मान बेहद जरूरी है।

प्रश्न

1. कौनसे न्यायालय द्वारा जारी निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है।

    (i) उच्च न्यायालय (ii) जिलान्यायालय

    (iii) सैनिक न्यायालय (iv) कोई नहीं

2. जनहित याचिका किस देश द्वारा अपने संविधान में शामिल की गयी?

    (i) अमेरिका (ii) दक्षिण अफ्रीका

    (iii) भारत (iv) जापान

3. भारत का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर बना रह सकता है।

(i) 60 वर्ष (ii) 62 वर्ष

(iii) 65 वर्ष (iv) 70 वर्ष

4. न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता का उल्लेख मिलता है।

(i) संविधान के अनुच्छेद 134 में

(ii) संविधान के अनुच्छेद 224 में

(iii) संविधान के अनुच्छेद 226 में

(iv) संविधान के अनुच्छेद 27 में

5. निम्नलिखित में से कौन-सी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यकता नहीं है

(i) वह भारत का नागरिक हो।

(ii) वह लोकसभा की नजर में माननीय न्यायधीश हो।

(iii) वह हाईकोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव।

(iv) हाईकोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक रहा है।

6. अपील का सबसे बड़ा न्यायालय है।

(i) सर्वोच्च न्यायालय (ii) उच्च न्यायालय

(ii) उच्च न्यायालय (iv) जिला नयायालय

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें।

7. न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते भारत सरकार की ……………….निधि से प्रदान किए जाते हैं।

8. उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशो को व्यक्तिगत आलोचना से ……………… प्रदान की गई है।

9. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति ………………. करता है।

10. सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान संविधान के …………. संविधानिक अनुच्छेद में निहित है।

11. भारत का सर्वोच्च न्यायालय ……………… स्थित है।

निम्नलिखित कथन बताएं कि सही है या गलत।

12. भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर की जाती है।
13. न्यायिक पुनरावलोकन का सर्वप्रथम अमेरिका में मिलता है।
14. सवाच्च न्यायालय की सलाहकार शक्तिया राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है।
15. न्यायिक पुनरावलोकन का सर्वप्रथम उल्लेख ब्रिटेन के संविधान में मिलता है।
16. सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी नहीं हैं।
17. भारतीय संविधान, एकीकृत न्याय प्रणाली की स्थापना करता है।

निम्नलिखित कथनों को सही करके लिखो।

18. उच्च न्यायालय के फैसले भारतीय भूभाग के अन्य सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है।
19. सर्वोच्च न्यायालय के आरम्भिक अधिकार से अभिप्राय है दीवानी फौजदारी से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमे पर अपील सुनना।
20. भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली को अपनाया नहीं गया है।

अति संक्षिप्त प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

21. सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकारिता से आप क्या समझते हैं?
22. कानून के शासन से क्या अभिप्राय है?
23. सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किन आधारों पर उनके पद से हटाया जा सकता है।
24. सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार शक्ति से आप क्या समझते हैं।
25. अभिलेख न्यायालय से क्या अभिप्राय है।
26. न्यायिक पुनरावलोकन की परिभाषा दीजिए।
27. न्यायिक सक्रियता किस प्रकार न्यायालय को अधिक सक्रिय ,वं क्रियाशील बना रही है
28. जनहित याचिका से क्या अभिप्राय है
29. भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं
30. वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों का प्रावधान है
31. भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है।
32. भारत के मुख्य न्यायाधीशों को किस प्रकार उनके पद से हटाये का हटाया जा सकता है।

निम्नलिखित अवतरण को पढ़े तथा प्रश्नों के उत्तर दे।

I. न्यायिक सक्रियता का हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ा इससे न केवल व्यक्तियों बल्कि विभिन्न समूहों को भी अदालत जाने का अवसर मिला। इसने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया तथा कार्यपालिका उत्तरदाई बनने पर बाध्य हुई। चुनाव प्रणाली भी कहीं अधिक मुक्त और निष्पक्ष बनी। न्यायालय ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपनी संपत्ति, आय और शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में शपथपत्र देने का निर्देश दिया ताकि लोग सही जानकारी के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें।

1. न्यायिक सक्रियता है-

   (A) न्यायिक व्यवस्था का लोकतांत्रिकरण (B) अनेक दुष्प्रभाव है

   (C) अनिवार्य दिशानिर्देश (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

2. न्यायिक सक्रियता, कार्यपालिका को बनाती है-

   (A) गैर जिम्मेदार (B) उत्तरदायी

   (C) अनुत्तरदायी (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

3. निम्नलिखित में से क्या एक रिट का प्रकार है?

   (A) अधिकार विहिनता (B) गैर न्यायिकता

   (C) अधिकार (दृच्छा पृच्छा) (D) समाजिकता

4. न्यायपालिका का कौनसा अधिकार क्षेत्र मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है?

   (A) अपीलीय अधिकारक्षेत्र (B) रिट अधिकारक्षेत्र

   (C) सलाहकारी अधिकारक्षेत्र (D) उपर्युक्त सभी

दो अंकीय प्रश्नः -

1. जनहित याचिका कब व किसके द्वारा आरम्भ की गई?
2. जनहित याचिका में क्या परिवर्तन किया गया?
3. जनहित याचिका से किसको लाभ पहुंचता है?
4. न्यायिक पुनरावलोकन का क्या अर्थ है ?
5. सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही फैसले बदलने की इजाजत क्यों दी जाती है?

6. न्यायपलिका अनुच्छेद 32 का प्रयोग किस प्रकार करती है।
7. अनुच्छेद 226 जारी करने का अधिकार किसका है तथा कैसे?
8. कौन-सी दो शक्तियां सर्वोच्च न्यायलय को शक्तिशाली बना देती है?
9. कानून के शासन का क्या अर्थ है?
10. न्यायिक पुनरावलोकन तथा रिट में क्या अन्तर है?

चार अंकीय प्रश्नः-

1. मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन-सी रिटें जारी कर सकता है, उल्लेख करें।
2. परामर्श दात्री क्षेत्राधिकार से सरकार को क्या लाभ है।
3. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों की पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन करो।
.4. सामूहिकता के सिद्धान्त का क्या अर्थ है?
5. सर्वोच्च न्यायलय किस प्रकार अपील का सबसे बड़ा न्यायालय है। वर्णन करें।

चार अंकीय प्रश्नः- अभ्यास प्रश्न हेतु

1.

(1) उपरोक्त चित्र में न्यापालिका किस विषय पर हस्तक्षेप कर रही हैं। 1

(2) न्यायपालिका के हस्तक्षेप से क्या लागू हुआ। 2

(3) हस्तक्षेप करते हुए न्यायपालिका ने क्या निर्णय दिया? 2

2. नागरिकों का एक समूह जनहित याचिका के माध्यम से न्यायालय जाकर प्रार्थना करता है कि वह शहर की नगरपालिका के अधिकारियों को झुग्गी झोपड़ियों हटाने और शहर को सुंदर बनाने का काम करने के आदेश दें, ताकि शहर में पूंजी निवेश करने वाले को आकर्षित किया जा सके। उनका तर्क है कि ऐसा करना जनहित में है। झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाला का पक्ष है कि ऐसा करने पर उनके 'जीवन के अधिकार' का हनन होगा। उनका तर्क है कि जनहित के लिए साफ-सुथरे शहर के अधिकार से ज्यादा जीवन का अधिकार महत्वपूर्ण है। कल्पना करें कि आप एक न्यायधीश है। आप एक निर्णय लिखें और तय करें कि इस 'जनहित याचिका में जनहित का मुद्दा है या नहीं?

अवतरण आधारित प्रश्न

2.1 जनहित याचिका में मुख्य मुद्दा होता है।

(क) व्यक्तिगत हित (ख) संस्था का हित
(ग) जनहित (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

2.2 जनहित याचिका सर्वोत्तम उदाहरण है:

(क) न्यायिक पुनरावलोकन का (ख) न्यायिक सक्रियता का
(ग) संविधान संशोधन का (घ) न्यायिक निर्णय का

2.3 झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के अधिकार का हनन हो रहा है?

(क) धार्मिक स्वतंत्रता का (ख) घूमने फिरने का
(ग) जीवन के अधिकार का (घ) संस्कृति का

2.4 जनहित याचिका का मुद्दा संबंधित है?

(क) मूल कर्तव्यों के हनन से (ख) मूल अधिकारों के हनन से
(ग) नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन से (घ) उपरोक्त सभी से

छः अंकीय प्रश्नः -

1. भारतीय न्यायपालिका की सरंचना पिरामिड के आकार की है वर्णन करो ?
2. सर्वोच्च न्यायलय के क्षेत्राधिकार का वर्णन करो?
3. जनहित याचिका किस प्रकार गरीबों की मदद कर सकती है ?
4. जनहित यचिकाओं को न्यायपालिका के लिए नकरात्मक पहलू क्यों माना जाता है?
5. भारतीय संविधान में न्यायपालिका को किस प्रकार स्वतंत्र बनाया गया है ?
6. न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है क्या आप इस कथन से सहमत है?
7. न्यायिक सक्रियता के फलस्वरूप न्यायपालिका पर बोझ बढ़ा है। इस कथन को जांचकर तर्कसहित उत्तर दे।
8. लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुचारू एवं गतिशील बनाने में न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण स्तम्भ है, समझाये।

उत्तरमाला

एक अंकीय प्रश्नों के उत्तरः-

1. (c) सैनिक न्यायालय
2. (a) अमेरिका
3. 65 वर्ष
4. संविधान के अनुच्छेद 134 में
5. वह लोकसभा की नजर में माननीय न्यायधीश हो।
6. सर्वोच्च न्यायालय
7. संचित निधि
8. सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालय के जजों को व्यक्तिगत आलोचना से उन्मुक्ति प्रदान की गई है।
9. राष्ट्रपति
10. अनुच्छेद 124
11. दिल्ली

12. सही
13. सही
14. गलत
15. गलत
16. गलत
17. सही
18. उच्चतम न्यायालय के फैसले
19. केंद्र व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा
20. एकीकृत न्याय प्रणाली को अपनाया गया है।
21. दीवाली, फौजदारी, वैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों पर अपील सुनना।
22. कानून की नजर में सभी लोग समान है तथा सभी पर समान रूप से लागू होगा।
23. कदाचार साबित होने अथवा अयोग्यता की दशा में।
24. जनहित के मामलों तथा कानून के मसलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना।
25. सर्वोच्च न्यायालय के दिए गए निर्णय भविष्य में भी अन्य न्यायिक निर्णयों के लिए कारगर होंगे।
26. सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिक ताकि जांच कर सकता है।
27. न्यायालय ने न्यायिक किसी भी कानून की संवैधानिक ताकि जांच कर सकता है।
28. जनहित से संबंधित मुकदमों में एक व्यक्ति विशेष ही नहीं अपितु एक समूह भी जनहित याचिका दायर कर सकता है।
29. 30 . 1
30. 24 . 1
31. 2.8 Lakh
32. न्यायाधीशों के विरूद्ध आरोपों पर
33. संसद के एक विशेष बहुमत की स्वीकृति आवश्यक है।

अवतरण आधारित उत्तर

1. (A) न्यायिक व्यवस्था का लोकतांत्रिक
2. (B) उत्तरदाई
3. (C) अधिकार पृच्छा
4. (B) रिट अधिकारक्षेत्र

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तरः-

1. 1970 ने न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती तथा बी. के. कृष्णअय्यर द्वारा।
2. अखबारों के समाचार तथा डाक द्वारा प्राप्त शिकायत की भी जनहित याचिका माना जाने लगा।
3. गरीबों, असहाय, असक्षम निरक्षर लोगों की शीघ्र न्याय दिलवाने के लिए।
4. न्यायपालिका द्वारा अपने द्वारा दिए गए निर्णय की पुनः जांच करना।
5. न्यायपालिका से भी चूंक हो सकती है। व्यक्ति को सही न्याय प्राप्त हो।
6. न्यायपालिका रिट जारी करके बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश जारी करती है ताकि सभी को जीने का अधिकार तथा सूचना का अधिकार प्राप्त हो। मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित किया जा सकता है।
7. उच्च न्यायलय रिट जारी कर सकती है।

   किसी कानून की गैर संवैधानिक घोषित कर सकती है उसे लागू होने से रोक सकती है।
8. (1) रिट जारी करने की शक्ति (2) न्यायिक पुनरावालोकन शक्ति
9. गरीब अमीर, स्त्री और पुरूष, अगडे और पिछड़े सभी वर्गों के लोगों पर एक समान कानून लागू हो।
10. - न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या कर सकती है।
    - मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायलय जोआदेशजारी करती है रिट कहलाती है।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तर-

1. बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पृच्छा, उत्प्रेषण वर्णन।

2. (i) सरकार को छूट मिल जाती हैं
   (ii) अदालती राय जानकर कानूनी विवाद से बचा जा सकता है
   (iii) विधेयक में संशोधन कर सकती है
   (iv) समस्या का समाधान विद्वान व्यक्तियों के द्वारा।

3. (i) महाभियोग द्वारा
   (ii) अयोग्यता का आरोप लगने पर
   (iii) विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित
   (iv) दोनो सदनों में बहुमत के बाद

4. (i) सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा।
   (ii) न्यायाधीश की नियुक्ति नई व्यवस्था के माध्यम से
   (iii) नई व्यवस्था में भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य चार वरिष्ठतम् न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति को सामूहिकता का सिद्धान्त कहते हैं।

5. (i) उच्च न्यायालयो के निर्णय के विरूद्ध
   (ii) उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित कानूनी व्याख्या से सम्बन्धित
   (iii) किसी अपराधी के अपराध मुक्ति के निर्णय को बदल कर पुनः फांसी की सजा, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय से मंगवा कर पुनः निरीक्षण कर सकता है।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तर-

1. (i) डाक हडताल 1
   (ii) जनता को सुविधा 1
   (iii) सार्वजनिक हित से सम्बन्धित विभागों को हडताल नहीं करनी चाहिए। 2

छः अंकीय प्रश्नों के उत्तर-

1. सर्वोच्च

   उच्च

   जिला न्यायालय

   अधिनस्थ

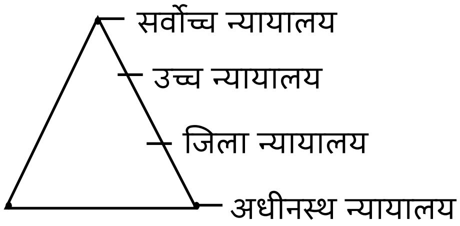

2. प्रारम्भिक (मौलिक, अपीलीय, परामर्शदाता, रिट जारी करना, वर्णन)

3. किसी व्यक्ति, संस्था की शिकायत, अखबार में समाचार, डाक द्वारा शिकायत के आधार पर।

4. (i) न्यायपालिका पर काम का बोझ बढ़ना।

   (ii) विधानपालिका के कार्यों का न्यायपालिका के द्वारा किया जाता।

   (iii) न्यायापलिका के पास समय का अभाव

   (iv) न्यायाधीशों की कमी।

5. (i) न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु निश्चित

   (ii) अच्छा वेतन

   (iii) न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णयों को चुनौती नहीं

   (iv) दिए गए निर्णयों के लिए न्यायाधीशों को जीवन सुरक्षा प्रदान करना।

   (v) राजसत्ता द्वारा न्यायाधीशों के कार्यों में बाधा न पहुंचाना

   (vi) न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधानपालिका का हस्तक्षेप नहीं।

6. मौलिक अधिकारों की रक्षक

   न्यायिक पुनरावलोकन

   न्यायिक सक्रियता

   सामाजिक एवं आर्थिक न्याय

   का महत्वपूर्ण निर्धारक

7. कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में न्यायपालिका का हस्तक्षेप, न्यायपालिका के इस कार्य के फलस्वरूप कार्यबोझ अवश्य बढ़ा है लेकिन न्यायपालिका संविधान की संरक्षक भी है।

8. न्यायपालिका महत्वपूर्ण स्तम्भ है, क्योंकि
   (a) लोकतान्त्रिक मूल्यों के संवर्द्धन में सहायक
   (b) सामाजिक आर्थिक न्याय को सुगम बनाना
   (c) मौलिक अधिकारों का संवर्द्धन
   (d) न्यायिक सक्रियता

अध्याय-7

संघवाद

सरकार के 2 स्तर

- पूरे देश के लिए एक सरकार → संघ सरकार
- राज्यों की अलग–अलग सरकारें → राज्य सरकार

संघवाद की विशेषता

- दो या तीन स्तरीय सरकार
- संविधान द्वारा सरकारों का गठन
- हर स्तर का अपना न्यायपालिका होती है
- परिवर्तन करना हो तो प्रत्येक स्तर की सहमति आवश्यक
- वित्तीय स्वायत्तता
- दोहरा उद्देश्य
- स्वतंत्र न्यापालिका

भारत एक संघ राज्य

तीन स्तरीय सरकार	तीन सूचियां	कौन कानून बनाता है	उदाहरण
1. केन्द्र सरकार	1. संघ सूची	केंद्रीय कानून बनाता है	रक्षा, उर्जा
2. राज्य सरकार	2. राज्य सूची	राज्य कानून बनाता है	पुलिस, भूमि
3. स्थानीय सरकार	3. समवर्ती सूची	दोनों कानून बनाते हैं	शिक्षा

अध्याय के मुख्य बिन्दुः संघवाद का अर्थ, भारतीय संघवाद की विशेषता भारतीय संविधान में संघात्मक लक्ष्ण, भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण, भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव, केन्द्र-राज्य संबंध।

संघावाद का अर्थ → संघवाद से आशय संगठित रहने के विचार से हैं (दो या दो से अधिक राज्यों के एक साथ संगठित रहने को ही संघवाद कहते हैं संघीय राज्य की सर्वप्रथम शुरूआत अमेरिका से हुई थी।

संघवाद एक संस्थागत प्रणाली हैं जिसमें दो प्रकार कि राजनीतिक व्यवस्था समाहित होती हैं इसमें एक केंद्रीय स्तर की और दूसरी प्रांतीय स्तर की राजनीतिक व्यवस्था शामिल होती हैं प्रत्येक स्तर की राजनीतिक व्यवस्था अपने आप में स्वायत्त होती हैं।

केंद्रीय या संघीय सरकार का कार्यक्षेत्र पूरा देश होता हैं और उसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं संघ सूची के विषयों पर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती हैं दूसरी और प्रांतीय सरकारों का कार्य क्षेत्र अपना प्रान्त होता हैं और राज्य सूची के विषयों पर ही ये कानून बनाते हैं केंद्र व राज्य के मध्य टकराव रोकने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होती हैं।

भारत में संघवाद

भारत के सर्विधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया हैं।

राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान अनेक नेता यह चाहते थे कि भारत जैसे विशाल देश पर शासन करने के लिए शक्तियों या विषयों को केंद्रीय व प्रांतीय स्तरों में बांटना जरूरी होगा भारतीय समाज में क्षेत्रीय व भाषायी विविधता हैं अतः प्रत्येक क्षेत्र के लोगों को स्वशासन का अवसर मिलना चाहिए।

भारतीय संघवाद के अनुसार भारत में एक संघीय (केंद्रीय) सरकार, 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें अपने अपने विषयों पर कार्य करती हैं भारतीय संविधान में सभी की शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा दिया हुआ हैं।

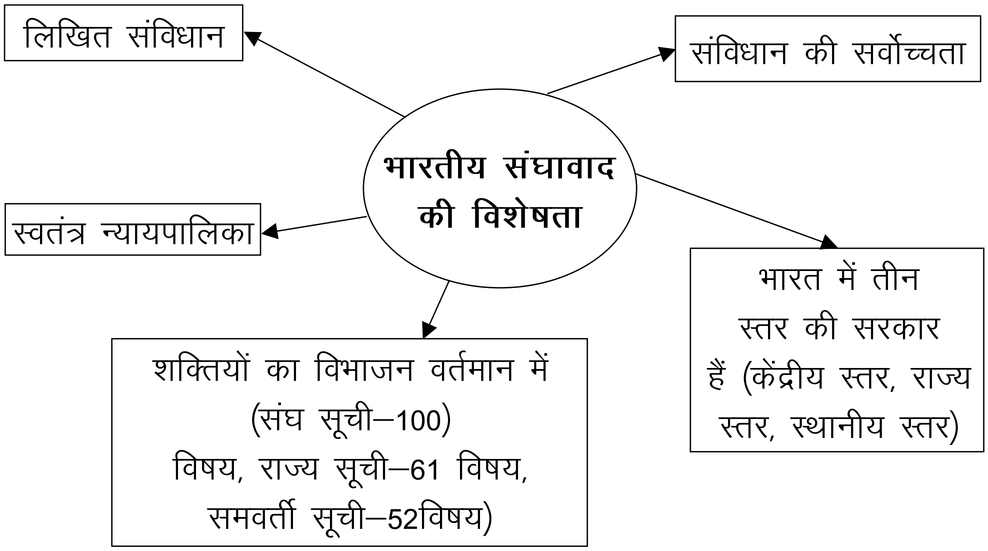

शक्ति विभाजन

भारत के संविधान में दो तरह की सरकारों का वर्णन किया गया हैं पहली केंद्रीय सरकार जिसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण देश होता हैं दूसरी सरकार राज्य स्तर की सरकार होती हैं जिसका कार्यक्षेत्र केवल राज्य तक ही सीमित होता हैं दोनों ही संवैधानिक सरकारें हैं और इसके कार्यक्षेत्रों का स्पष्ट वर्णन किया गया हैं।

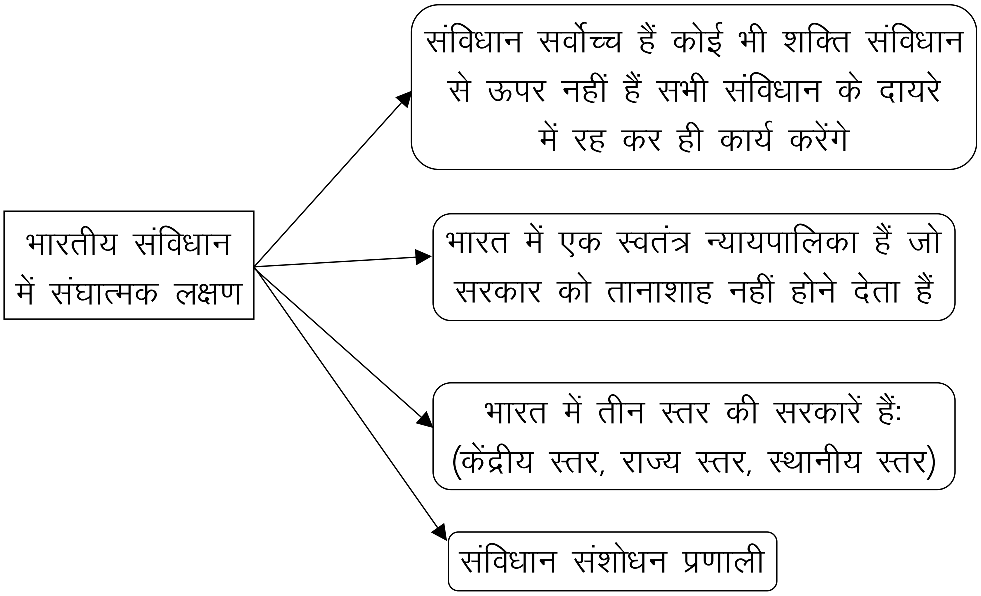

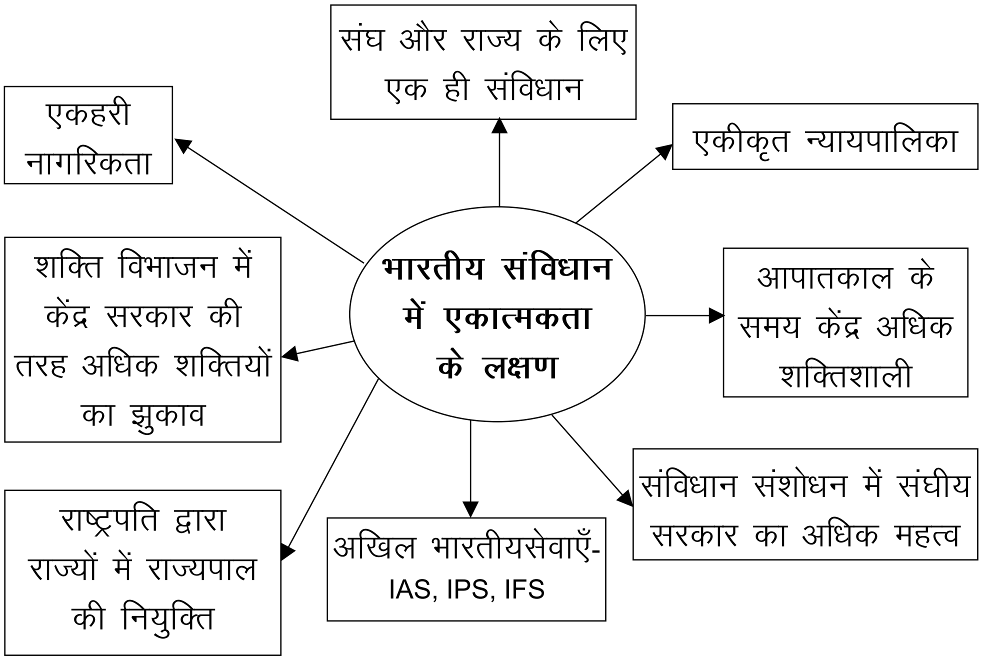

भारतीय संघ में सशक्त केंद्रीय सरकार क्यों?

भारत एक विशाल एवं विविधताओं से भारा हुआ देश हैं संविधान निर्माताआं को यह आशा थी कि इतने विशाल देश को सशक्त केंद्रीय सरकार द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता हैं देश में आजादी के समय 500 से अधिक देशी रियासतें थी जिनका विलय सक्त केंद्रीय सरकार द्वारा ही किया जा सका था।

भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव-

भारत के संविधान ने केंद्र सरकार को बहुत अधिक शक्तियां प्रदान की हैं जबकि राज्यों में शासन चलाना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी हैं इस वजह से समय समय पर राज्य अधिक स्वायत्ता व शक्तियों की मांग करते रहते हैं इस वजह से केंद्र व राज्यों में तनाव व संघर्ष उत्पन्न होता हैं।

केन्द्र-राज्य संबंध

1. राज्य समय-समय पर केंद्र सरकार और अधिक अधिकारों व स्वायत्ता की मांग करते रहते हैं जो निम्न रूपों में हैंः
   (क) वित्तीय स्वायत्ताः राज्यों के आय के साधन सीमित हैं और संसाधनों पर नियंत्रण भी सीमित ही हैं अतः राज्य सरकार आय के मामलों में और अधिक स्वायत्ता की मांग करते रहते हैं।

(ख) प्रशासनिक स्वायत्ताः राज्य सरकार दैनिक प्रशासन के मामलों में और अधिक स्वायत्ता चाहते हैं राज्य केंद्र सरकार से और अधिकार व शक्तियां चाहते हैं।

(ग) सांस्कृतिक और भाषाई मुद्देः काफी राज्य हिंदी भाषा का विरोध करते हैं तथा उनके राज्य में प्रचलित भाषा या स्थानीय को ही प्रोत्साहन देते हैं।

2. राज्यपाल की भूमिका तथा राष्ट्रपति शासनः

(क) राष्ट्रपति राज्य सरकारों से परामर्श किये बिना ही राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कर देता हैं जो राज्यों के दैनिक कार्यों में कई बार अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं।

(ख) केंद्र सरकार राज्यपाल पर दबाव डालकर राज्यों में अनुच्छेद 356 के माध्यम से अनुचित राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है।

3. नए राज्यों की मांगः भारतीय संघीय व्यवस्था में समय-समय पर नवीन राज्यों की मांग उठती रहती हैं जिसे राजनैतिक कारणों से संघ व राज्यों में तनाव बढ़ता है।

4. अन्तर्राज्यीय विवादः

(क) संघीय व्यवस्था में दो या दो से अधिक राज्यों में विवाद होता रहता हैं जैसे बेलगांव को लेकर कर्नाटक व महाराष्ट्र में सीमा विवाद।

(ख) दो या दो से अधिक राज्यों में नदियों के पानी के बंटवारें को लेकर विवाद होता रहता हैं, जैसे-कर्नाटक व तमिलनाडु में कावेरी नदी जल विवाद चल रहा है।

5. विशिष्ट प्रावधानः संविधान के अनुच्छेद 371(क) से 371 (झ) तक में नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्रप्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को विशेष दर्जा दिया गया हैं।

प्रश्नावली

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. भारत में किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है?

   (i) दोहरी नागरिकता

   (ii) बहु नागरिकता

   (iii) एकल नागरिकता

   (iv) उपरोक्त में से कोई नहीं

2. केन्द्र-राज्य संबंधी की समीक्षा के लिए किस आयोग को नियुक्त किया गया था?

   (i) शाह आयोग

   (ii) सरकारिया आयोग

   (iii) गोस्वामी आयोग

   (iv) उपरोक्त में से कोई नहीं

3. राज्य विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है?

   (i) मुख्यमंत्री

   (ii) प्रधानमंत्री

   (iii) उच्च न्यायालय

   (iv) राज्यपाल

4. अंतरराज्यी विवादों को सुलझाने की शक्ति किसके पास है?

   (i) राज्यपाल

   (ii) संसद

   (iii) सुप्रीम कोर्ट

   (iv) राष्ट्रपति

अभिकथन और कारण प्रश्न

1. अभिकथन (A): भारत के राज्यों का किसी भी समय विलय किया जा सकता है।

   कारण (R): संसद के पास भारत राज्यों का विलय करने की शक्ति है।

   (ए) A और R दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या है।

   (बी) A और R दोनों सही हैं, लेकिन R A की सही व्याख्या नहीं है

   (सी) A सही है, लेकिन R गलत है।

   (डी) A गलत है, लेकिन R सही है।

2. अभिकथन (A): भारत में सरकार के तीन स्तर हैं।

   कारण (R): भारत में संघीय व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका से अपनाई गई है

   (ए) A और R दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या है

   (बी) A और R दोनों सही हैं, लेकिन R A की सही व्याख्या नहीं है

   (सी) A सही है, लेकिन R गलत है

   (डी) R गलत है, लेकिन R सही है।

प्रश्न संख्या 1 से 5 में खाली स्थान भरिएः

1. भारतीय संविधान में संघवाद के लिए .... शब्द का प्रयोग किया गया है।
2. संघवाद का अर्थ .... हैं।
3. केंद्र व राज्यों के मध्ये उठे विवादों का समाधान .... द्वारा किया जाता है।
4. समवर्ती सूची पर कानून बनानें का अधिकार .... हैं।

प्रश्न संख्या 6 से 10 में सही या गलत वाक्य पहचानों

6. जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हैं।
7. विश्व में संघवाद सबसे पहले अमेरिका ने अपनाया था।
8. भारत के संविधान में केंद्र सरकार की अपेक्षा राज्यों को अधिक अधिकार दिए हुए हैं।
9. संसद भारत में नए राज्यों का निर्माण कर सकती हैं।
10. भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान हैं।

दो अंकीय प्रश्नः-

1. मैसूर तथा मद्रास को किस राज्य में विलय किया गया?
2. संघवाद से भारत की विविधता में एकता किस प्रकार सहायक हुई?
3. अनुच्छेद-1 क्या दर्शाता है?
4. शक्ति विभाजन का क्या अर्थ है?
5. अवशिष्ट शक्तियां कौन-सी है?
6. राज्य स्वायतता की मांग किस आधार पर करते है?
7. सरकारिया आयोग में मुख्य प्रावधान क्या रखा गया है?
8. अन्तराज्यीय विवादो के दो उदाहरण दीजिए।
9. सरकारिया आयोग कब व किसके द्वारा गठित किया गया।

चार अंकीय प्रश्नः-

1. ज्यादा स्वायतता पाने की चाह में प्रदेशों ने कौन-कौन सी मांग उठाई?
2. भारतीय संविधान की चार संघात्मक विशेषताएं बताइये?
3. भारत संविधान की चार एकात्मक विशेषताएं लिखे?
4. बहुत से राज्य राज्यपाल की भूमिका को लेकर खुश क्यों नहीं है?
5. राज्यों में राष्ट्रपति शासन के प्रावधान का उल्लेख कीजिए।

Source Based Question

6. राज्यपाल की भूमिका केन्द्र और राज्यों के बीच हमेशा ही विवाद का विषय रही है राज्यपाल निर्वाचित पदाधिकारी नहीं होता अधिकतर राज्यपाल सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी लोक सेवक या राजनीतिज्ञ हुए हैं फिर राज्यपाल की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा होती है अतः राज्यपाल के फैसलों को अक्सर राज्य सरकार के कार्यो में केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है।

   6.1. राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?

   6.2. राज्यपाल का चुनाव कैसे होता है।

   6.3. राज्यपाल किसका एजेण्ट होता है।

   6.4. राज्य का प्रमुख कौन होता है।

7. दिए गए अवतरण को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो-

   जहाँ एक ओर राज्य अधिक स्वायतता और आय के स्रोतों पर अपनी हिस्सेदारी के सवाल पर केन्द्र के साथ विवाद की स्थिति में रहते है, वही दूसरी ओर संघीय व्यवस्था में सीमाओं से अधिक राज्यों में आपसी विवाद के भी अनेक उदाहरण मिलते है। यह सच है कि कानूनी विवादों में न्यायपालिका पंच की भूमिका निभाती है। लेकिन इन विवादों का स्वरूप मात्र कानूनी नहीं होता। इन विवादों के राजनीतिक पहलू भी होते है अतः इनका सर्वोतम समाधान केवल विचार-विमर्श और पारस्परिक विश्वास के आधार पर ही हो सकता है।

7. (i) केन्द्र तथा राज्यों में किस कारण से विवाद रहता है?

   (क) आपातकाल को लेकर (ख) वित्त को लेकर

   (ग) भाषा को लेकर (घ) धर्म को लेकर

7. (ii) राज्यों में आपसी विवाद का कोई एक कारण बताइए।

   (क) सीमा को लेकर (ख) जाति को लेकर

   (ग) धर्म के कारण (घ) वित्त के कारण

7. (iii) कानूनी विवादों का कौन हल कर सकता है?

   (क) सांसद (ख) सांसद

   (ग) प्रधानमंत्री (घ) न्यायपालिका

7. (iii) जल विवाद को कौन हाल करता है?

(क) राज्य (ख) सांसद

(ग) राष्ट्रपति (घ) न्यायपालिका

8. कार्टून का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर देः-

(i) राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?

(A) प्रधानमंत्री (B) राष्ट्रपति

(C) संसद (D) मुख्यमंत्री

(ii) कार्टून के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति से क्या आशय है?

(A) राष्ट्रपति की मर्जी (B) परीक्षा के द्वारा

(C) योग्यता आधारित (D) चुनाव द्वारा

(iii) क्या राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा इसी प्रकार होती है?

(A) हाँ (B) नहीं

(C) कभी-कभी (D) कभी नहीं

(iv) राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है?

(A) 5 वर्ष (B) 6 वर्ष

(C) 8 वर्ष (D) 4 वर्ष

9. मानचित्र को ध्यानपूर्वक देखें और पूछे गये प्रश्नों के उत्तर दें-

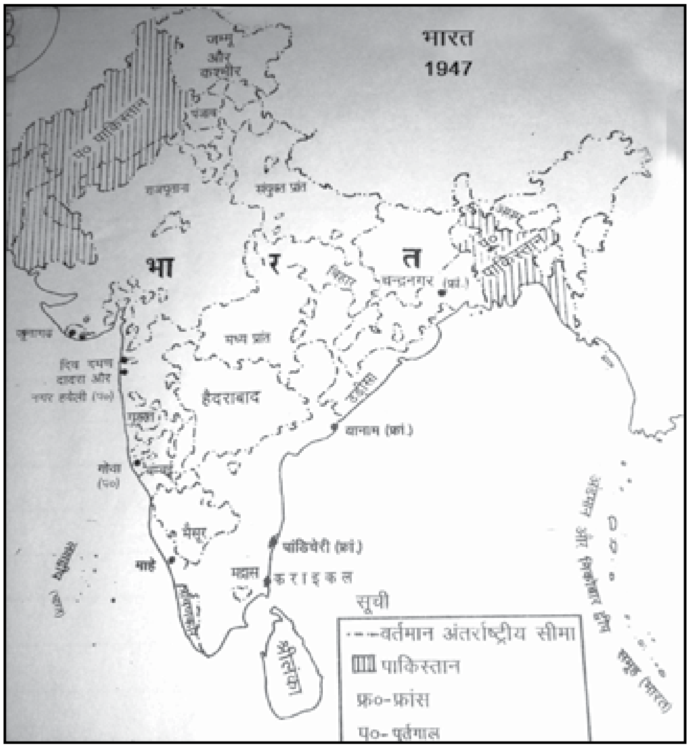

(i) भारत के मानचित्र में दो रियासतों के नाम लिखों-

(A) भोपाल, त्रावणकोर (B) जयपुर, राजस्थान

(C) चंडीगढ़, हरियाणा (D) पंजाब, हिमाचल

(ii) दो राज्यों के नाम लिखो जिनका जन्म नए राज्य के रूप में हुआ है?

(A) हिमाचल, मैसूर (B) मद्रास, मैसूर

(C) हिमाचल, जम्मू (D) उत्तराखण्ड, झारखण्ड

(iii) एक गैर हिन्दी भाषी राज्यों का नाम लिखो -

(A) आन्ध्रप्रदेश (B) हरियाणा

(C) पंजाब (D) हिमाचल

(iv) भारत की एक रियासत जिसका विलय 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ

(A) दिल्ली (B) जम्मू एवं कश्मीर

(C) जयपुर (D) बिकानेर

(v) भारत की एक रियासत जिसमें सैन्य कार्रवाई द्वारा विलय हुआ-

(A) हैदराबाद (B) जूनागढ़

(C) पंजाब (D) हरियाणा

छः अंकीय प्रश्नः-

1. भारतीय संवधान का स्वरूप संघात्मक है लेकिन वास्तव में एकात्मक इसकी आत्मा है।
2. संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन करो।
3. स्वायतता और अलगाववाद का क्या अर्थ है ।

उत्तरमाला

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. (iii) एकल नागरिकता
2. (ii) सरकारिया आयोग
3. (iv) राज्यपाल
4. (iii) सुप्रीम कोर्ट
5. गलत
6. सही
7. गलत
8. सही
9. गलत

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तरः-

1. कर्नाटक, तमिलनाडु
2. केन्द्र तथा राज्य सरकारो का अपना क्षेत्र अधिकार ।
3. भारत राज्यों और केन्द्र प्रशासित राज्यों का एक संघ (यूनियन) है।
4. (i) कार्यपालिका की शक्तियों का बँटवारा, विधानपालिका, न्यायपालिका का अपना अधिकार क्षेत्र है।

   (ii) संघ, राज्य, समवर्ती सूची में अपने विषय है जिसे केन्द्र तथा राज्य सरकार बनाते है
5. वे विषय जिनका उल्लेख किसी सूची में नही दिया गया।
6. राज्य स्वायतता की मांग भाषा, आय, वित्तीय शक्ति, प्रशासकीय शक्ति।
7. केन्द्र, राज्य, सम्बन्धों से सम्बन्धित शक्ति संतुलन पर।
8. सीमा विवाद नदी जल बंटवारा विवाद, जैसे- पंजाब, हरियाणा।
9. जून 1983 सर्वोच्च न्यायालय से सेवा निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजिन्दर सिंह सरकारिया द्वारा।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तरः-

1. - नदी जल बंटवारा

   - सीमा विवाद, नए राज्यों की मांग -

   - आर्थिक वित्तीय स्वतंत्रता, संसाधनों पर अधिकार -
2. (i) शक्तियों का विभाजन

   (ii) स्वतंत्र न्यायपालिका

   (iii) द्विसदनीय विधायिका

   (iv) संविधान

3. (i) इकहरी नागरिकता

(ii) केन्द्र के पास अधिक सर्वोच्चता

(iii) एकीकृत न्यायपालिका आर्थिक दृष्टि से भी राज्य दुर्बल ।

4. राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, केन्द्र सरकार के लिए कार्य राष्ट्रपति शासन लगवाने का अधिकार, विधेयक को कानून बनाने पर विवाद, केन्द्र के ऐजेन्ट के रूप में कार्य।

5 अनुच्छेद 356, सरकार के पास बहुमत न रहने पर।

6. 6.1 राष्ट्रपति के द्वारा

6.2 जब चाहे जिसे राज्यपाल बना दे जब चाहे हटा दे

6.3 या दूसरे स्थान पर भेज दे

6.4 हां राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति की इच्छा तथा केंद्र सरकार की इच्छा से की जाती है

7. (i) (A) आपातकाल

(ii) (A) सीमा को लेकर

(iii) (D) न्यायपालिका

(iv) (D) न्यायपालिका

8. (i) (B) राष्ट्रपति

(ii) (A) राष्ट्रपति की मर्जी

(iii) (A) हाँ

(iv) (A) 5 वर्ष

9. (i) (a) भोपाल त्रावणकोर

(ii) (d) उत्तराखंड, झारखंड

(iii) (a) आंध्र प्रदेश

(iv) (b) जम्मू कश्मीर

छः अंकीय प्रश्नों के उत्तर:-

1. इकहरी नागरिकता, शक्तियों का विभाजन, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, राज्यों पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग आदि ।

2. (i) संघ सूची - राष्ट्रीय महत्त्व के विषय इसमें लगभग 100 विषय हैं, जैसे - रक्षा, विदेष, रेल, बन्दरगाह, बैंक, खनिज आदि ।

   (ii) राज्य सूची - साधारणतय क्षेत्रिय महत्त्व के विषय लगभग 61 विषय है, जैसे- पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य आदि।

   (iii) समवर्ती सूची - लगभग 52 है, जैसे- फौजदारी, विधि प्रक्रिया, सामाजिक सुरक्षा आदि।

3. (i) स्वायतता अधिक अधिकार प्राप्त करना, अलगाववाद - केन्द्र सरकार द्वारा भेदभाव पूर्ण व्यवहार

   (ii) राज्यों के द्वारा कार्य करते समय केन्द्र सरकार का हस्तक्षेप न करना।

   (iii) अलगाववाद केन्द्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता न देना, विकास संबंधी योजनाएं न बनाना।

अध्याय-8

स्थानीय शासन

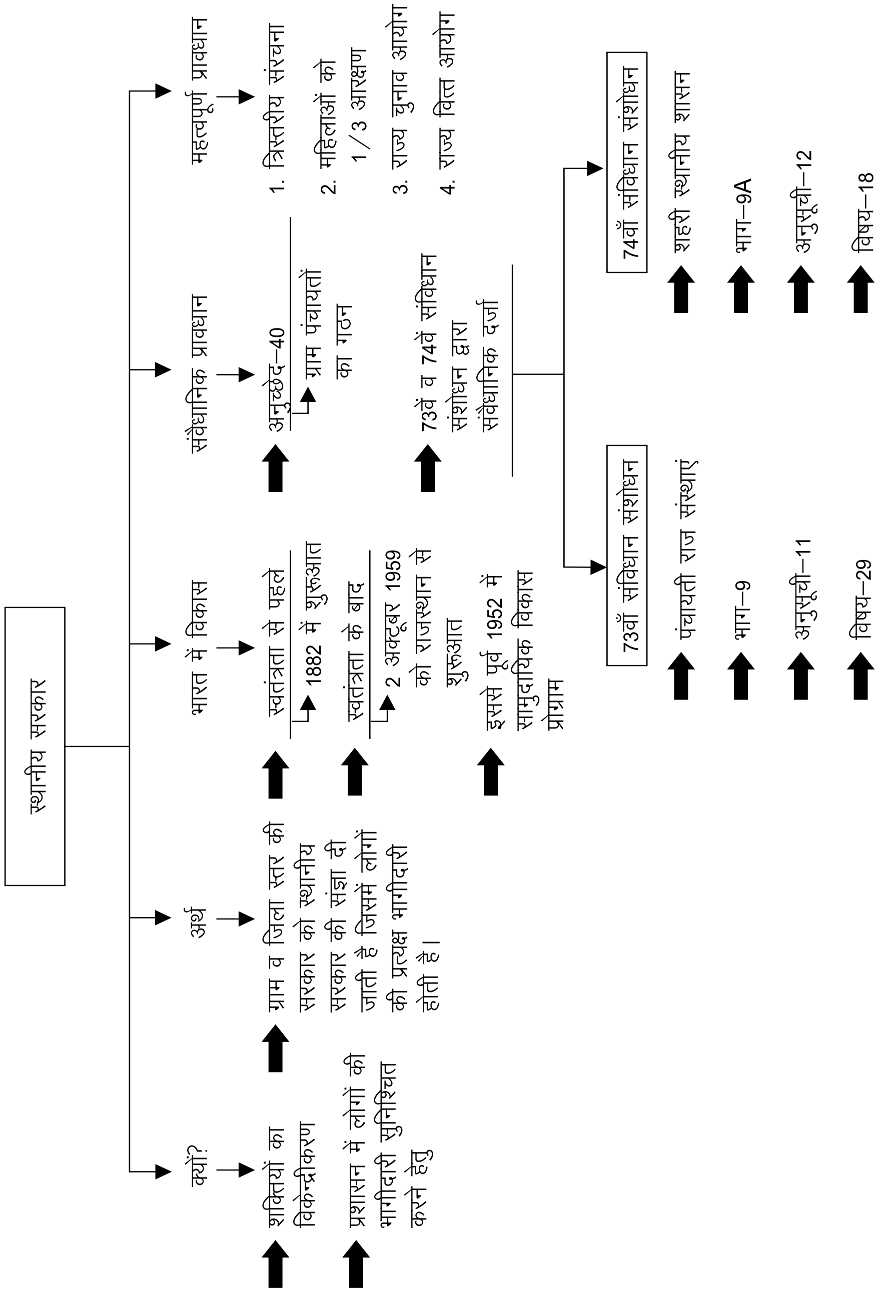

मुख्य बिन्दुः

- हमें स्थानीय सरकार की आवयश्कता क्यों?
- भारत में स्थानीय सरकार का विकास
- 73वें तथा 74वें संवैधानिक संशोधन।
- 73वें तथा 74वें संवैधानिक संशोधनों का क्रियान्वयन और चुनौतियां
    - **स्थानीय शासनः** गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। यह आम आदमी के सबसे नजदीक का शासन है। इसमें जनता की प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान बहुत तेजी से तथा कम खर्च में हो जाता है। इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है।
    - **लोकतंत्र का अर्थ है** सार्थक भागीदारी तथा जवाबदेही। जीवंत और मजबूत स्थानीय शासन सक्रिय भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। जो काम स्थानीय स्तर पर किए जा सकते हैं वे काम स्थानीय लोगों तथा उनके प्रतिनिधियों के हाथ में रहने चाहिए।
    - आम जनता राज्य, सरकार या केन्द्र सरकार से कहीं ज्यादा स्थानीय शासन या स्थानीय सरकार से परिचित होती है।

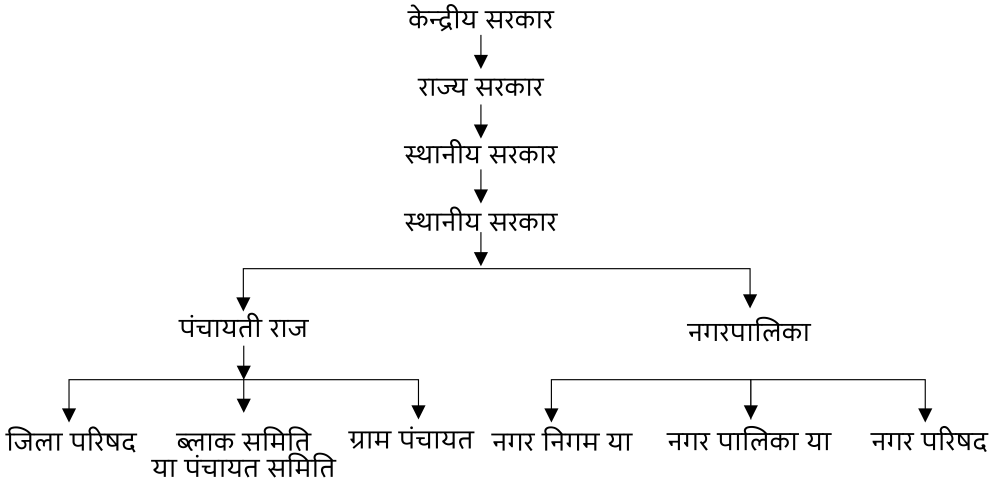

हमें स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों?

- मजबूत लोकतान्त्रिक व्यवस्था कायम करने के लिये।
- स्थानीय स्तर की राजनीतिक आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु।
- सामान्य नागरिकों की प्रतिनिधियों तक पहुंच हेतु।
- कार्य को सफल व तीव्र गति से करने हेतु (जन कल्याणकारी कार्य)
- आपसी सामन्जस्य व सफल प्रशासन हेतु।

भारत में स्थानीय शासन का विकासः प्राचीन भारत में अपना शासन खुद चलाने वाले समुदाय, ''सभा'' के रूप में मैजूद थे। आधुनिक समय में निर्वाचित निकाय सन् 1882 के बाद अस्तित्व में आए। उस वक्त उन्हें ''मुकामी बोर्ड'' कहा जाता था। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के बनने पर अनेक प्रांतो में ग्राम पंचायते बनी।

जब संविधान बना तो स्थानीय शासन का विषय प्रदेशों को सौंप दिया गया। संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी इसकी चर्चा है।

महात्मा गांधी जी ने भी ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने व सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात की व इसको एक कारगर साधन बताया।

स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासनः संविधान के 73 वे और 74वें संशोधन के बाद स्थानीय शासन को मजबूत आधार मिला। इससे पहले 1952 का "सामुदायिक विकास कार्यक्रम" इस क्षेत्र में एक अन्य प्रयास था इस पृष्ठभूमि में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरूआत 1959 की बी० आर मेहता समिति की सिफारिश पर की गई। ये निकाय वित्तीय मदद के लिए प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकार पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। सन् 1987 के बाद स्थानीय शासन की संस्थाओं के गहन पुनरावलोकन की शुरूआत हुई।।

- सन् 1989 में पी.के. थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की।
- ब्राजील के संविधान में प्रांत, संघीय जिले तथा नगरपाकिा परिषद् की व्यवस्था है।
- **संविधान का 73वां और 74 वां संशोधनः** सन् 1992 में ससंद ने 73वां और 74 वां संविधान संशोधन पारित किया।

- 73वां संवैधानिक संशोधन गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा है। इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। 74वां संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है।
- 73वां संशोधन- 73वें संविधान संशोधन के कुछ प्रावधानः-

(1) **त्रि-स्तरीय ढांचाः** अब सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का त्रि-स्तरीय ढांचा है।

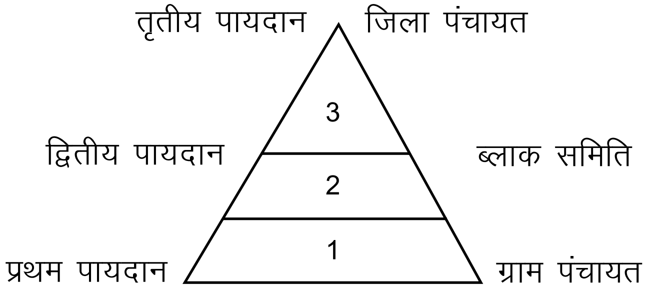

(2) **चुनावः** पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों के चुनाव सीधे जनता करती है। हर निकाय की अवधि पांच साल की होती है।

(3) **आरक्षणः**

- महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान है।
- यदि प्रदेश की सरकार चाहे तो अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) को भी सीटों में आरक्षण दे सकती है।

  इस आरक्षण का लाभ हुआ कि आज महिलाएं सरपंच के पद पर कार्य कर रही हैं।

- भारत के अनेक प्रदेशों के आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 73 वें संशोधन के प्रावधानों से दूर रखा गया परन्तु सन् 1996 में एक अलग कानून बना कर पंचायती राज के प्रावधानों में इन क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया गया।
- **राज्य चुनाव आयुक्तः** प्रदेशों के लिए यह जरूरी है कि वे एक राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करें। इस चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की होगी।

- **राज्य वित्त आयोगः** प्रदेशों की सरकार के लिए जरुरी है कि वो हर पांच वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनायें। यह आयोग प्रदेश में मौजूद स्थानीय शासन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति की जानकारी रखेगा।

- **74वां संशोधनः** 74वें संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय शासन से है अर्थात् नगरपालिका से।

- **शहरी इलाका:** (1) ऐसे इलाके में कम से कम 5000 की जनसंख्या हों (2) कामकाजी पुरूषों में कम से कम 75% खेती बाड़ी से अलग काम करते हों (3) जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो।

- **विशेषः** अनेक रूपों में 74 वें संविधान संशोधन में 73वे संशोधन का दोहराव है लेकिन यह संशोधन शहरी क्षेत्रों से संबंधित है। 73 वें संशोधन के सभी प्रावधान मसलन प्रत्यक्ष चुनाव, आरक्षण, विषयों का हस्तांतरण, प्रादेशिक चुनाव आयुक्त और प्रादेशिक वित्त आयोग 74 वें संशोधन में शामिल हैं तथा नगर पालिकाओं पर लागू होते हैं।

- **73वें और 74वें संशोधनों का क्रियान्वयनः** (1994-2023) इस अवधि में प्रदेशों में स्थानीय निकायों के चुनाव अनेकों बार हो चुके हैं। स्थानीय निकायों के चुनाव के कारण निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की संख्या में निरंतर भारी बढोतरी हुई है। महिलाओं की शक्ति और आत्म विश्वास में काफी वृद्धि हुई।

- **विषयों का स्थानांतरणः** संविधान के इन संशोधनों ने 29 विषयों को स्थानीय शासन के हवाले किया है। ये सारे विषय स्थानीय विकास तथा कल्याण की जरूरतों से संबंधित हैं।

स्थानीय शासन के विषय-

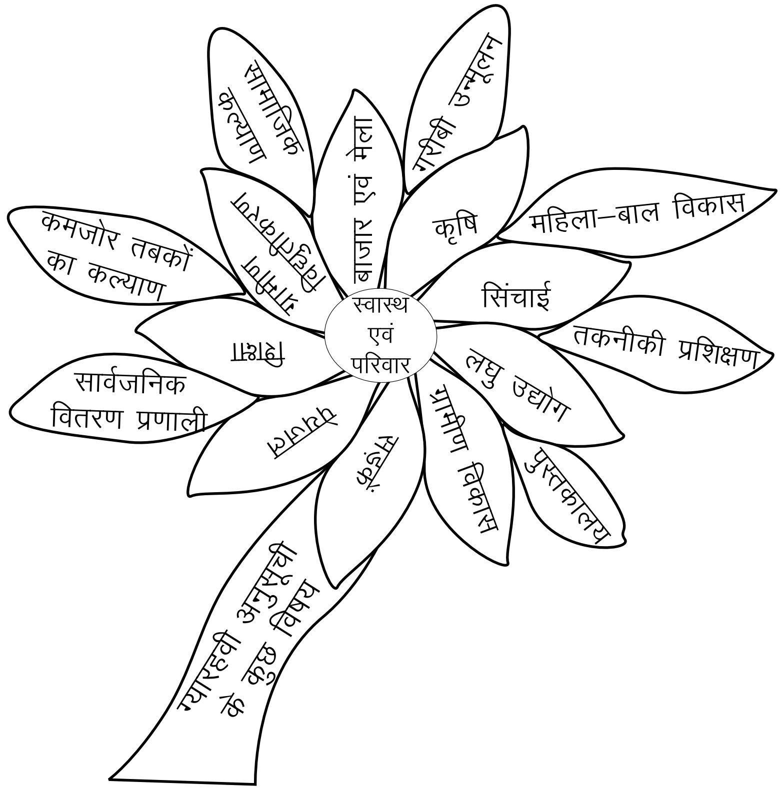

स्थानीय शासन के समक्ष समस्याएं-

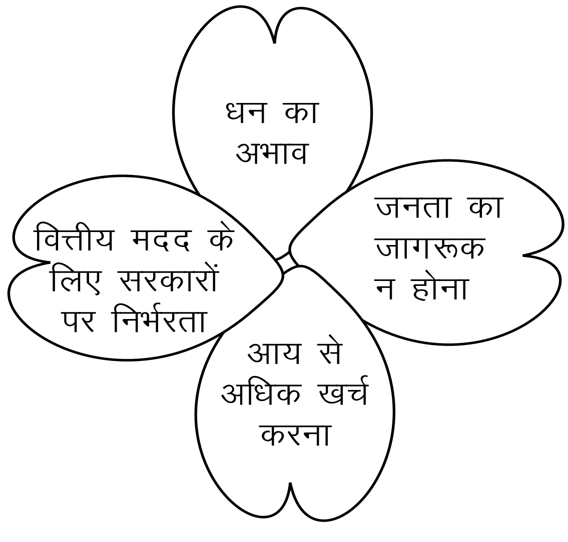

प्रश्नावली

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरूआत किस राज्य से हुई?

   (अ) आंध्रप्रदेश (ब) राजस्थान

   (स) बिहार (द) उड़ीसा (ओड़िशा)

2. राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता हैं?

   (अ) 10 अप्रैल (ब) 14 अप्रैल

   (स) 24 अप्रैल (द) 20 अप्रैल

3. पंचायती राज से सम्बंधित कौन सा अनुच्छेद है?

   (अ) अनुच्छेद 243 (ब) अनुच्छेद 324

   (स) अनुच्छेद 124 (द) अनुच्छेद 73

4. पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है?

   (अ) कृषि उत्पादन में वृद्वि

   (ब) विकास शील प्रशासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना

   (स) आर्थिक विकास

   (द) लोगों को राजनितिक रूप से जागरूक करना

5. भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई?

   (अ) कलकत्ता या कोलकाता (ब) मद्रास या चेन्नई

   (स) बोम्बे या मुंबई (द) दिल्ली

6. शहरी स्थानीय शासन से सम्बंधित कौनसा संविधान संशोधन है?

   (अ) 73 वाँ (ब) 74 वाँ

   (स) 92 वाँ (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

7. निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है?

(अ) नागालैण्ड (ब) राजस्थान

(ब) बिहार (द) तमिलनाडु

8. जिला परिषद व ग्राम पंचायत के मध्य निम्नलिखित में से क्या स्थित है?

(अ) मण्डल पंचायत (ब) ब्लॉक समिति

(स) ग्राम सभा (द) नगरपालिका

9. निम्नलिखित में से किसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है?

(अ) ग्राम पंचायत (ब) ब्लॉक पंचायत

(स) अ व ब दोनों (द) खंड विकास अधिकारी

10. निम्नलिखित कथनों में कौनसा कथन सही है?

(अ) ग्राम पंचायत का अध्यक्ष सरपंच होता है।

(ब) पंचायत समिति की अध्यक्षता चैयरमैन द्वारा की जाती है

(स) जिला परिषद की अध्यक्षता चैयरमैन द्वारा की जाती है।

(द) सरपंच व चैयरमैन का चुनाव लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है।

11. ग्राम पंचायतों के आय स्रोतों में निम्नलिखित में कौन सा नहीं है?

(अ) सरकारी अनुदान (ब) संपत्ति कर

(स) आय कर (द) भूमि पर स्थानीय कर

12. किस समूह के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 (एक तिहाई) आरक्षण का प्रावधान है?

(अ) अन्य पिछड़ा वर्ग (ब) अनुसूचित जाति

(स) अनूसूचित जनजाति (द) महिला

13. पचांयती राज चुनावों में भाग लेने के लिए कितनी न्युनतम आयु की आवश्यकता होती है?

(अ) 21 वर्ष (ब) 18 वर्ष

(स) 25 वर्ष (द) 30 वर्ष

14. 73 वाँ संविधान संशोधन लागू होने के बाद पंचायतों के प्रत्यक्ष चुनाव किस राज्य में सर्वप्रथम हुए?

(अ) आन्ध्र प्रदेश (ब) राजस्थान

(स) मध्य प्रदेश (द) कर्नाटक

15. पंचायती राज संस्थाओं की आय का मुख्य स्त्रोत क्या है?

(अ) स्वैच्छिक अनुदान (ब) सम्पति कर

(स) स्थानीय कर (द) सरकारी अनुदान

16. 73 वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची शामिल की गई ?

(अ) 6 वीं (ब) 7 वीं

(स) 9 वीं (द) 11 वीं

17. स्थानीय सरकार के विकास में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई?

(अ) विलियम बैंटिक (ब) लॉर्ड रिपन

(स) लॉर्ड डफरिन (द) लॉर्ड मेयो

18. 1989 में पी. के थुंगन समिति ने निम्नलिखित में से किसे संवेधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी?

(अ) स्थानीय शासन (ब) चुनाव आयोग

(स) लोकपाल (द) वित्त आयोग

19. स्थानीय शासन कौन से स्तर पर कार्य नहीं करता?

(अ) राज्य स्तर (ब) जिला स्तर

(स) ब्लॉक स्तर (द) ग्राम स्तर

20. स्थानीय स्वशासन का प्रमुख उदेश्य क्या है?

(अ) राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढाना

(ब) लोगों को वित्त उपलब्ध कराना

(स) शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करना

(द) (अ) तथा (स) दोनों

एक अंकीय प्रश्नः-

1. स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश किस समिति ने तथा कब की? सही विकल्प चुनिए।

   (क) पंचायत समिति, 1979 (ख) ग्राम समिति 1969

   (ग) थुंगन समिति, 1989 (घ) अशोक मेहता समिति 1977

2. भारत में स्थानीय शासन की विचारधारा का विचार किस देश से ग्रहण किया गया?

3. संविधान का 73वां तथा 74वां संवैधानिक संशोधन संसद में कब पारित हुआ तथा इसे कब लागू किया गया?

रिक्त स्थान को भरिए

4. स्थानीय शासन संविधान की .... सूची का विषय है?

5. पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे से क्या अभिप्राय है?

6. ग्राम सभा का सदस्य कौन व्यक्ति होता है?

7. ग्राम पंचायतों व नगरपालिकाओं के चुनाव कितने वर्षों के लिए किए जाते हैं?

8. पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है?

9. संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा ग्यारहवीं अनुसूची के विषय प्रांतीय सरकारे पंचायतों को दे सकती हैं? सही विकल्प चुनिए-

   (क) अनुच्छेद 243 (ख) अनुच्छेद 143

   (ग) अनुच्छेद 75 (ग) अनुच्छेद 150

10. पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की जिम्मेदारी किस अधिकारी को दी गई है? सही विकल्प चुनिए-

    (क) मुख्य चुनाव आयुक्त (ख) प्रधानमंत्री

    (ख) सरपंच (घ) राज्य के चुनाव आयुक्त

11. नगर निगम के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए?

12. निम्नलिखित को सही करके लिखिये-

(i) 73वें संवैधानिक संशोधन का सम्बन्ध केन्द्र के स्थानीय शासन से जुड़ा है।

(ii) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के लिए उनकी मांग के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान है।

(iii) 74वें संवैधानिक संशोधन का सम्बन्ध गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा है।

13. 'सही' व 'गलत' का चयन कीजिए व रिक्त स्थान भरिए:

(i) कृषि व सिंचाई ग्यारहवीं अनुसूची के विषय हैं (..................)

(ii) शिक्षा, ग्रामीण विद्युतीकरण ग्यारहवीं अनुसूची के विषय में नहीं आते। (............................)

(iii) सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था में त्रि-स्तरीय ढांचा हैं (..........)

(iv) धन का अभाव स्थानीय शासन के समक्ष एक समस्या है। (..................)

दो अंकीय प्रश्नः- (उत्तर 50 से 60 शब्द)

1. भारत में स्थानीय शासन के अधिक मजबूत न होने के दो कारण लिखिए।
2. ''शहरी इलाका'' शब्द से क्या अभिप्राय है?
3. ग्राम पंचायतों के क्या-क्या कार्य हैं? किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए।
4. पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है उससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति में क्या बदलाव आया है? स्पष्ट कीजिए।
5. स्थानीय शासन से आम नागरिकों को क्या लाभ हैं?
6. स्थानीय शासन अपना कार्य उतनी दक्षता से नहीं कर पाता, जिसके लिए उसकी स्थापना हुई थी क्यों?
7. राज्य का वित्त आयोग कितने वर्ष के लिए बनाया जाता है तथा उसका मुख्य कार्य क्या है?
8. यदि अभी हाल ही में नगर निगम के कुछ रिक्त स्थानों पर चुनाव हुए हो तो आप के विचार से ये चुनाव कराए जाने का क्या कारण रहा होगा?

9. पंचायती निकायों की व्यवस्था हमारे देश में प्राचीनकाल में भी थी। वर्तमान समय में इनकी कार्यप्रणाली में क्या सुधार हुए हैं?

10. नगर - निगम के मुखिया को किस पद नाम से जाना जाता है?

चार अंकीय प्रश्नः- (उत्तर 100 से 120 शब्द)

1. स्थानीय शासन का क्या महत्व है?

2. नगर निगम तथा नगरपालिकाओं के कोई चार लिखिए।

3. महापौर किसे कहते हैं?

4. पिछले दिनों तक दिल्ली में कितने नगर निगम थे? इतने निगमों के बनाए जाने का क्या कारण था?

5. नगर निगम आम जनता की समस्याओं का समाधान करने में कहां तक सफल रहे हैं?

6. पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष कौन-कौन सी समस्याएं हैं?

7. "स्थानीय संस्थाएं स्वायत्त नहीं हैं इसीलिए ये कुशलता पूर्वक कार्य नहीं कर पातीं"आपके विचार से क्या यह कथन सत्य है? कैसे?

8. "लोकतंत्र तभी सफल होता है जब नागरिकों की सक्रिय भागीदारी होती है" इस कथन को स्पष्ट कीजिए।

9. "स्थानीय शासन में महिला आरक्षण का लाभ वास्तव में पुरूष सत्तात्मक समाज ले रहा है"। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क दीजिए।

10. "जब भी लोकतंत्र को ज्यादा सार्थक बनाने और ताकत से वंचित लोगों को ताकत देने की कोशिश होगी तो समाज में संघर्ष और तनाव का होना तय है।" क्या आप इस विचार से सहमत हैं? स्पष्ट कीजिए।

स्रोत/कार्टून/मानचित्र आधारित प्रश्नः-

1. "गांधी जी का मानना था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना सत्ता के विकेन्द्रीकरण का कारगर साधन है। विकास के हर पहलू में स्थानीय लोगों की भागीदारी होनी चाहिए ताकि यह सफल हो सके। समूचे भारत की आजादी की शुरूआत सबसे नीचे से होनी चाहिए। इस तरह हर राज्य एक गणराज्य होगा।"

(क) "सत्ता के विकेंद्रीकरण" से क्या अभिप्राय है?

(A) ग्राम पंचायतों का मजबूत होना

(B) स्थानीय लोगों की विकास कार्यों में भागीदारी होना

(C) सत्ता का जनता तक पहुंचना

(D) उपरोक्त सभी

(ख) गणराज्य से क्या अभिप्राय है?

(A) राज्य के मुखिया जनता द्वारा चुना जाना

(B) राज्य के मुखिया का चयन वंशानुगत होना

(C) राज्य का मुखिया तानाशाह होना

(D) उपरोक्त सभी

(ग) पंचायतों को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है ?

(A) उन्हें धन की कमी नहीं होनी चाहिए।

(B) राज्य व केंद्र का सहयोग मिलना चाहिए।

(C) जनता को जागरूक होना चाहिए।

(D) उपरोक्त सभी।

(घ) "आजादी की शुरुआत सबसे नीचे से होना चाहिए" यह कथन किसका है।

(A) महात्मा गांधी

(B) पंडित नेहरू

(C) सरदार पटेल

(D) नेताजी सुभाष चंद्र बोस

अभ्यास हेतु अतिरिक्त प्रश्न:-

इस चित्र को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

(1) इस चित्र में जो लिखा है उससे आप क्या समझ पा रहे हैं? 1

(2) स्थानीय शासन की मदद से क्या इस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है? कैसे? 1

(3) इस उद्देश्य की प्राप्ति में किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं? 2

छः अंक वाले प्रश्न- (उत्तर 180 से 200 शब्द)

1. स्थानीय शासन से क्या अभ्रिपाय है तथा इसका नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है?
2. पंचायती राज व्यवस्था से क्या अभिप्राय है? यदि आप जिला कलैक्टर होते तो आप गांवों की किन-किन समस्याओं का समाधान करते?
3. यदि स्थानीय निकाय न होते तो नागरिकों की दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान हो पाता या नहीं? कारण भी बताइए।
4. नगर निगम को आय कहां से प्राप्त होती है? क्या यह धन नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त होता है? स्पष्ट कीजिए।
5. यदि आप अपने गांव की सरपंच होतीं तो आपके कार्यों में किस प्रकार की बाधाए भी उत्पन्न हो सकती थीं? तब आप उन बाधाओं से कैसे छुटकारा पातीं?

उत्तरमाला

बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर-

1. (ब) राजस्थान
2. (स) 24 अप्रैल
3. (अ) अनुच्छेद 243
4. (ब) लोगों की प्रशासन में भागीदारी बढ़ाना
5. (ब) मद्रास (चेन्नई)
6. (ब) 74वां संविधान संशोधन
7. (अ) नागालैण्ड
8. (ब) ब्लॉक समिति
9. (अ) ग्राम पंचायत
10. (अ) ग्राम पंचायत का अध्यक्ष सरपंच होता है
11. (द) स्थानीय भूमिकर
12. (द) महिला
13. (अ) 21 वर्ष
14. (अ) आन्ध्रप्रदेश
15. (द) सरकारी अनुदान
16. (द) 11वीं अनुसूची
17. (द) लॉर्ड मेयो
18. (अ) स्थानीय सरकार (शासन)
19. (अ) राज्य स्तर
20. (द) अ तथा स दोनों

एक अंकीय प्रश्नों के उत्तरः-

1. थुंगन समिति, 1989
2. ब्राजील
3. 1992, 1993
4. राज्य सूची
5. ग्राम पंचायतें निचले स्तर पर, ब्लॉक समिति मध्य स्तर पर और जिला परिषद ऊपरी स्तर पर
6. वे सभी जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के चुनाव में वोट डालने के अधिकारी हैं।
7. 5 वर्षों
8. 1 तिहाई
9. अनुच्छेद 243
10. राज्य के चुनाव आयुक्त
11. 21 वर्ष
12. (i) 73वें संवैधानिक संशोधन का सम्बन्ध गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा है।
    (ii) अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान है
    (iii) 74वें संवैधानिक संशोधन का सम्बन्ध शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है।
13. (i) सही (ii) गलत
    (iii) सही (iv) सही

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तरः-

1. जातिवाद, गुटबाजी, सांप्रदायिकता आदि।
2. (i) जनसंख्या कम से कम 5000, (ii) 75% से अधिक कामकाजी पुरूष खेती बाडी से अलग काम करते हों, (iii) जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो।

3. सफाई, बिजली, पानी की व्यवस्था, सड़कों का निर्माण, जन्म तथा मृत्यु का पंजीकरण आदि।

4. आज अनेकों महिलाएं सरपंच तथा मेयर जैसे पदों पर आसीन हैं उनमें पहले से ज्यादा शक्ति तथा आत्मविश्वास आया है। महिलाओं की राजनीतिक समझ में वृद्धि हुई है।

5. नागरिकों की समस्याओं के समाधान बहुत तेजी से तथा कम खर्च में हो जाते हैं। नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ती है।

6. धन का अभाव रहता है। आय के अनुपात में खर्च अधिक है इसलिए राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के अनुदान पर निर्भर रहना पड़ता है।

7. 5 वर्ष के लिये स्थानीय शासन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाना।

8. ये स्थान कई कारणों से रिक्त हुए होंगे।

   - किसी निगम पार्षद की मृत्यु के कारण

   - किसी निगम पार्षद का दल बदल लेने के कारण

   - किसी निगम पार्षद का विधायक बन जाने के कारण

9. प्राचीनकाल में भी स्थानीय संस्थाएं थीं परन्तु वे जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थीं। आज ये संस्थाएं अधिक उत्तरदायी हैं और जनता के प्रति जवाबदेह भी।

10. मेयर या महापौर, 1 वर्ष

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तरः-

1. स्थानीय शासन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यदि स्थानीय विषय स्थानीय प्रतिनिधियों के पास रहते हैं तो नागरिकों के जीवन की रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान तीव्र गति से तथा कम खर्च में हो जाते हैं।

2. सफाई का प्रबंध, बिजली का प्रबंध, पेयजल की व्यवस्था, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, सड़कों का निर्माण व मरम्मत, शमशान घाटों की व्यवस्था आदि।

3. नगर निगम के सदस्यों का मुखिया होता है।

4. तब दिल्ली में तीन नगर निगम थे, उत्तरी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली तथा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम। क्योंकि दिल्ली की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उनकी समस्याएं भी। एक नगर निगम सबकी समस्याओं का समाधान उतनी कुशलता से नहीं कर पा रहा था जितना तीन नगर निगम कर पा सकते।

5. नगर निगम जनता की समस्याओं का समाधान उस हद तक नहीं कर पा रहे जितना वो कर सकते हैं। आज भी सड़कें टूटी रहती हैं कूड़े के ढेर जगह-जगह देखे जा सकते हैं। पानी, बिजली की समस्या का समाधान किया जा चुका है परंतु फिर भी गर्मी के दिनों में इन दोनों से ही आम नागरिकों को जूझना पड़ता है।

6. धन की समस्या, जनता का जागरूक न होना, राजनीतिक हस्तक्षेप, आय से अधिक व्यय होना,।

7. हाँ, यदि ये संस्थाएं स्वायत्त हो जाएं तो नागरिकों की समस्याएं जल्दी सुलझेंगी और ये संस्थाएं जनता के प्रति उत्तरदायी भी होंगी।

8. नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी लोकतंत्र की सफलता के लिए अनिवार्य है। जागरूक नागरिक ही लोकतंत्र में सार्थक भागीदारी कर सकता है। तभी सरकार जवाबदेह होगी।

9. अनेक मामलों में यह देखा गया है कि महिलाएं अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में असफल रही हैं या महिला को पद पर आसीन करा कर परिवार का मुखिया या पुरूष उसके बहाने फैसले लेता रहता है।

10. हाँ, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को संविधान ने अनिवार्य बना दिया था इसके साथ ही, अधिकांश प्रदेशों ने पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान बनाया। इससे स्थाानीय निकायों की सामाजिक बुनावट में भारी बदलाव आए। कभी-कभी इससे तनाव पैदा होता है और सत्ता के लिए संघर्ष तेज हो जाता है।

स्रोत/ चित्र /मानचित्र/कार्टून आधारित प्रश्न का उत्तर:-

1. (क) (D) उपरोक्त सभी

   (ख) (A) गणराज्य से अभिप्राय है जहां राज्य का प्रमुख जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होता है यदि स्थानीय शासन को स्थानीय जनता तक पहुंचाया जाएगा तो हर ग्राम एक गणराज्य बन जाएगा

   (ग) (D) उपरोक्त सभी

   (घ) (A) महात्मा गांधी

2. (क) इसका अर्थ है कि यह हमारा गांव है और इसमें हमारा राज होना चाहिए।

(ख) हां क्योंकि स्थानीय प्रतिनिधि स्थानीय समस्याओं का समाधान अच्छे प्रकार से कर सकते हैं क्योंकि वे समस्याओं से अवगत होते हैं।

(ग) कभी-कभी धन की समस्या, सरकार का हस्तक्षेप, आय से अधिक व्यय होने के कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

छः अंकीय प्रश्नों के सांकेतिक उत्तरः-

1. स्थानीय शासन स्थानीय मामलों की देखभाल करती है नागरिकों की दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान तेजी से तथा कम खर्च में कर सकती है। इससे नागरिक सामाजिक तथा राजनीतिक रूप से भागीदार बनता है।
2. गांवों के स्थानीय शासन को पंचायती राज कहा जाता है। इसके तीन स्तर हैं। (विद्यार्थीअपने विवेक से उत्तर देंगे)
3. विद्यार्थी अपने विवेक से उत्तर देंगे।
4. नगर निगम बहुत से कर लगाता है जैसे गृहकर, जल कर, साप्ताहिक बाजारों में सामान बेचने वालों पर कर, आदि राज्यों से अनुदान प्राप्त करके भी नगर निगम धन प्राप्त करते हैं। नहीं, क्योंकि आय से अधिक व्यय किया जाता है और राज्य सरकारों से अनुदान प्राप्त करने के लिए बहुत देर हो जाती है।
5. विद्यार्थी अपने विवेक से उत्तर देंगे।

अध्याय-9

संविधान : एक जीवंत दस्तावेज

मुख्य बिंदुः

- क्या संविधान अपरिवर्तनीय होते हैं?
- संविधान संशोधन की प्रक्रिया
- संविधान में इतने संशोधन क्यों किए गए हैं
- संशोधनों की विषय वस्तु
- संविधान की मूल संरचना तथा उसका विकास
- संविधान एक जीवंत दस्तावेज
- न्यायपालिका का योगदान
- राजनीतिज्ञों की परिपक्वता

संविधान समाज की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिम्ब होता है। यह एक लिखित दस्तावेज़ है जिसे समाज के प्रतिनिधि तैयार करते हैं। संविधान का अंगीकरण 26 नवम्बर 1949 को हुआ और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।

संविधान में जीवंतता है क्योंकि -

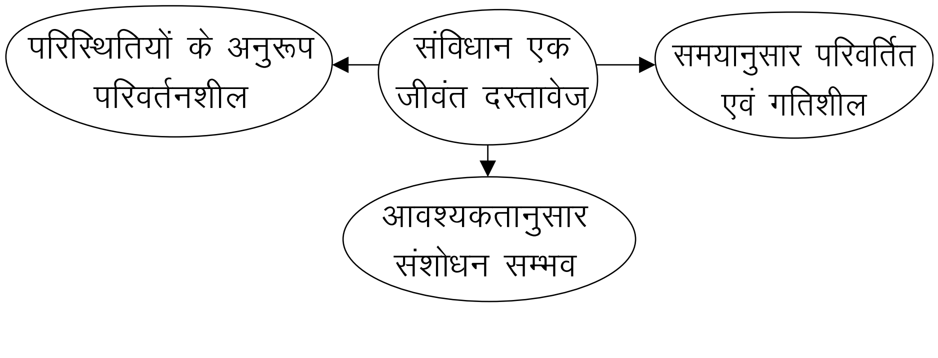

संविधान में संशोधन-

1. संशोधन की प्रक्रिया केवल संसद से ही शुरू होती है।
2. संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है।
3. संशोधनों का अर्थ यह नहीं कि संविधान की मूल सरंचना परिवर्तित हो।
4. संशोधनों के मामलें में भारतीय संविधान लचीलेपन व कठोरता का मिश्रण।
5. 1950 में संविधान के लागू होने से अब तक लगभग 103 संशोधन किये जा चुके हैं। इसके लिए 124 संविधान संशोधन विधेयक पारित हुए हैं 124 वॉ संविधान संशोधन बिल के अनुसार सामान्य वर्ग के आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लोगो को 10% आरक्षाण देने का प्रावधान है।
6. संविधान संशोधन विधेयक के मामलें में राष्ट्रपति को पुर्नविचार के लिए भेजने का अधिकार नहीं है।

संविधान में संशोधन के तरीके

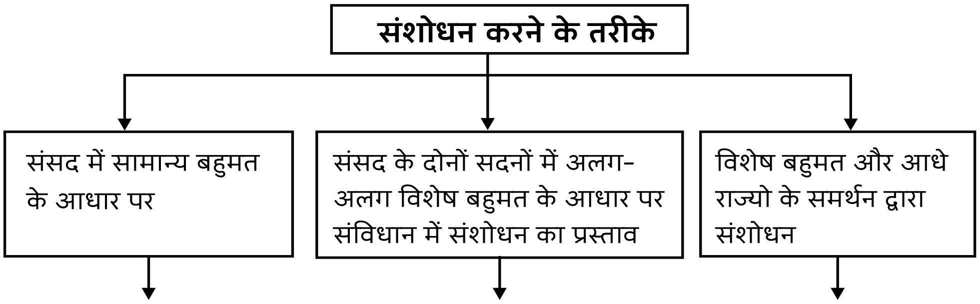

प्रावधान/उदाहरण
- नए राज्यों का निर्माण
- राज्यों की सीमाओं व नामों में परिवर्तन
- राज्यों में उच्च सदन (विधान परिषद) का सृजन या समाप्ति
- नागरिकता की प्राप्ति व समाप्ति
- सर्वोच्च न्यायलय का क्षेत्राधिकार बढ़ाना

प्रावधान/उदाहरण
- मौलिक अधिकार (राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत)
- अन्य प्रावधान जो की पहली व तीसरी श्रेणी में आते हों आदि

प्रावधान/उदाहरण
- राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका
- केन्द्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण
- संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व आदि

संविधान में इतने संशोधन क्यों?

- हमारा संविधान द्वितीय महायुद्ध के बाद बना था उस समय की स्थितियों में यह सुचारू रूप से काम कर रहा था पर जब स्थिति में बदलाव आता गया तो संविधान को सजीव यन्त्र के रूप में बनाए रखने के लिए संशोधन किए गए। इतने (लगभग 105) अधिक संशोधन हमारे संविधान में समय की आवश्यकतानुसार लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए किए गए।

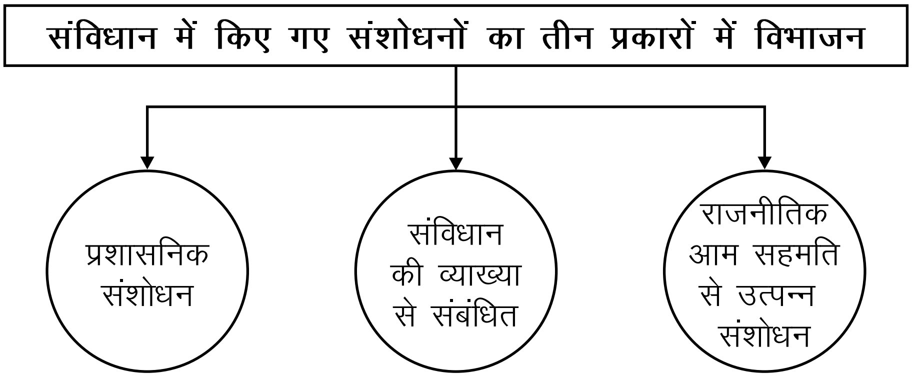

विवादास्पद संशोधन-

- वे संशोधन जिनके कारण विवाद हो। संशोधन 38वां, 39वां 42वां विवादस्पद संशोधन माने जाते हैं। ये आपातकाल में हुए संशोधन इसी श्रेणी में आते हैं। विपक्षी सांसद जेलों में थे और सरकार को असीमित अधिकार मिल गए थे।

संविधान की मूल संरचना का सिद्धान्त-

- यह सिद्धान्त सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में 1973 में दिया था। इस निर्णय ने संविधान के विकास में निम्नलिखित सहयोग दिया-
    1. संविधान में संशोधन करने की शक्तियों की सीमा निर्धारित हुई।
    2. यह संविधान के विभिन्न भागों के संशोधन की अनुमति देता है पर सीमाओं के अंदर।
    3. संविधान की मूल सरंचना का उल्लंघन करने वाले किसी संशोधन के बारे में न्यायपालिका का फैसला अंतिम होगा।

संविधान एक जीवंत दस्तावेज:-

- संविधान एक गतिशील दस्तावेज है।
- भारतीय संविधान का अस्तित्व 73 वर्षों से है इस बीच यह संविधान अनेक तनावों से गुजरा है। भारत में इतने परिवर्तनों के बाद भी यह संविधान अपनी गतिशीलता और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य के साथ कार्य कर रहा है।
- परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तनशील रह कर नई चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए भारत का संविधान खरा उतरता है यहीं उसकी जीवतंता का प्रमाण है।
- समयानुसार परिस्थितियों के बदलनें पर संविधान में परिवर्तन किये जाते हैं, जो किसी जीवंत दस्तावेज मे ही मुमकिन है।

न्यायपालिका का योगदान:-

संविधान की समझ को बदलने में न्यायिक व्याख्याओं की अहम भूमिका रही है। शिक्षा, जीवन, स्वतंत्रता अल्पसंख्यक समूह संबंधी उपबंधों में अनौपचारिक रूप से कई संशोधन न्यायपालिका द्वारा किए गए हैं। भारत के संवैधानिक ढांचे को बचाए रखने में भी न्यायिक सक्रियता द्वारा योगदान दिया गया है।

राजनीतिज्ञों की परिपक्वता

पिछले 73 वर्षों की संवैधानिक विकास यात्रा के दौरान भारत के राजनेताओं ने संविधान के मूल उद्देश्यों और आदर्शों के प्रति अनेक विरोधाभासों के बावजूद संविधान के सम्मान और महत्व के प्रति सहमति व्यक्त की है।

प्रश्नावली

एक अंकीय प्रश्न

1. गतिशील संविधान से क्या अभिप्राय है?
2. भारतीय संविधान कब अपनाया गया और कब लागू किया गया?
3. भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है?
4. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक संशोधन की चर्चा करता है?

   (अ) 366 (ब) 367 (स) 368 (द) 369
5. संविधान का 15 व संशोधन किससे संबधित है?
6. निम्नलिखित वाक्य को सही करके पुनः लिखिए।

   "मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष संविधान के 68वें संशोधन के द्वारा की गई"?
7. भारतीय संविधान का42 वां संशोधन वर्ष __________में लागू हुआ।
8. संविधान के पुर्नरावलोकन में किस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए?
9. किस मामले में (मुकदमें) के द्वारा भारतीय संविधान की मूल संरचना का विकास हुआ?

   (अ) बोगई मुकदमा (ब) मिनर्वा मिल मुकदमा

   (स) केशवानंद भारती मुकदमा (द) इनमें से कोई नहीं
10. आज तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए जा चुके हैं?
11. भारतीय संविधान को लागू हुए कितने वर्ष हो चुके हैं?

    (अ) 50 (ब) 56 (स) 73 (द) 80
12. सही या गलत बताइए

    (i) संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए नहीं भेजा जाता।

    (ii) संशोधन विधेयक को केवल लोकसभा में पारित करने की आवश्यकता होती है।

    (iii) संविधान में संशोधन करने के लिए दो प्रकार के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।

    (iv) संशोधन विधेयक विशेष बहुमत के बिना भी पारित किया जा सकता है।

13. संविधान की समीक्षा आयोग सन् 2000 (श्री वेंकटचलैया आयोग) ने किस बात पर विश्वास जताया?

14. "मूल संरचना" की अवधारणा मुख्यतः किसके द्वारा विकसित की गई?

(अ) कार्यपालिका (ब) विधायिका

(स) न्यायपालिका (द) इनमें से कोई नहीं

15. अभिकथन (A): भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है।

कारण (R): यह समय की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित किया जा सकता है।

(क) A और R दोनों सही हैं तथा (R) (A) की सही व्याख्या है।

(ख) A और R दोनों सही हैं लेकिन (R) (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(ग) A सही है पर R गलत है।

(घ) R सही है पर A गलत है।

दोअंकीय प्रश्न

1. कोई दो उदाहरण/प्रावधान दीजिए। जिनमें भारतीय संसद अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया को अपनाएं बिना ही संविधान में संसद कर सकती है?
2. भारतीय संविधान निर्माताओं ने किन आदर्शों को ध्यान में रखकर वह संविधान बनाया जो आज भी बरकरार है?
3. यदि भारतीय संसद के दोनों सदनों में किसी संशोधन प्रस्ताव पर आपसी सहमति ना बन पाए तो क्या होगा?
4. "भारतीय संविधान कठोर और लचीलेपन का समिश्रण" है क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तर्क दीजिए?
5. "न्यायिक पुनर्वालोकन" क्या है?
6. संविधान को जीवन दस्तावेज क्यों कहा जाता है?
7. भारतीय संविधान में इतने अधिक संशोधनों के क्या कारण हैं?
8. केशवानंद भारती मुकदमे की दो उपलब्धियां/ महत्व बताइए?
9. कोई दो कारण लिखिए की क्यों भारत का संविधान इतने दिनों से काम करता आ रहा है?

10. संविधान में संशोधन करने के लिए किन दो प्रकार के "विशेष बहुमतों" की आवश्यकता होती है?

चार अंकीय प्रश्न

1. किन विषयों पर भारतीय संविधान साधारण कानून द्वारा भी संशोधित किया जा सकता है?
2. भारतीय संविधान में निम्नलिखित संशोधनों को करने के लिए कौन सी बहुमत प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए?
   (क) चुनाव आयोग संबंधी
   (ख) राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन
   (ग) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
   (घ) केंद्र सूची में परिवर्तन
3. साधारण बहुमत और विशेष बहुमत में क्या अंतर है?
4. संविधान संशोधन के लिए न्यायपालिका की क्या भूमिका है?
5. भारतीय संविधान के विवादस्पद संशोधन कौन से कहे जाते हैं और क्यों?
6. भारतीय संविधान के संशोधनों में गठबंधन की राजनीति के काल 2001-2003 का क्या योगदान है?
7. भारतीय संविधान में राजनीतिक आम सहमति से हुए कुछ संशोधनों का वर्णन कीजिए?
8. संविधान संशोधनों में भारतीय राजनीतिज्ञों की परिपक्वता को स्पष्ट कीजिए?

स्रोत/मानचित्र/कार्टून आधारित प्रश्न

पाठ्य पुस्तक के निम्न अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उसके नीचे दिए प्रश्नों के उचित विकल्प चुनिए-

जून 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा की गई। ये तीन संशोधन इसी पृष्ठभूमि से निकले थे। इन संशोधनों का लक्ष्य संविधान के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में बुनियादी परिवर्तन करना था। वास्तव में संविधान का 42 वां संशोधन एक बड़ा संशोधन है।इसने संविधान को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। एक प्रकार से यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद

भारती मामले में दिए गए निर्णय को भी चुनौती थी। यहां तक इसके तहत लोकसभा की अवधि को भी 5 वर्ष से बढाकर 6 वर्ष कर दिया गया। मूल कर्तव्यों को भी संविधान में इसी संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यह कहा जाता है कि इस संशोधन के द्वारा संविधान के एक बड़े मौलिक हिस्से को नए सिरे से लिखा गया।

1. (i) देश में आपातकाल की घोषणा कब की गई?

(क) जून 1965 (ख) जून 1975

(ग) जून 1977 (घ) जून 1985

(ii) किस संशोधन को एक बड़ा संशोधन माना जाता है?

(क) 42 वां संशोधन (ख) 44 वां संशोधन

(ग) 46 वां संशोधन (घ) 48 वां संशोधन

(iii) 42 वें संशोधन के तहत लोकसभा की अवधि को -

(क) बढ़ाया गया (ख) घटाया गया

(ग) वही रखा गया (घ) इनमें से कोई नहीं

(iv) किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया?

(क) 38वें (ख) 39वें

(ग) 42वें (घ) 44वें

छः अंकीय प्रश्न

1. संविधान संशोधन के तरीकों का विस्तृत वर्णन कीजिए?
2. क्या संविधान एक जीवंत दस्तावेज है? किन्ही तीन सहायक तर्कों के साथ अपनी राय दीजिए।
3. भारत में संविधान संशोधनों द्वारा किए गए कुछ परिवर्तनों का वर्णन कीजिए।
4. केसवानंद भारती मुकदमे के बारे में इंटरनेट तथा अपने विषय अध्यापक की सहायता से पढ़ कर व समझ करके एक नोट लिखिए।

उत्तरमाला

एक अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. ऐसा संविधान जिसे विभिन्न परिस्थितियों में परिवर्तित किया जा सके।
2. 26 नवंबर 1949 तथा 26 जनवरी 1950
3. लचीला तथा कठोर
4. (स) 368
5. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्तिआयु 60 वर्ष से बढ़कर 62 वर्ष करना।
6. मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष संविधान के 61वें संशोधन के द्वारा की गई।
7. 1976
8. संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन ना हो।
9. (स) केशवानंद भारती मुकदमा
10. 105 (100 से भी अधिक)
11. (स) 73
12. (i) गलत (ii) गलत (iii) सही (iv) गलत
13. संविधान की बुनियादी संरचना (मूल ढांचे) पर।
14. (स) न्यायपालिका
15. (क) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R) (A) की सही व्याख्या है।

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. अनुच्छेद 2 नए राज्यों की स्थापना/गठन
   अनुच्छेद तीन राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना
2. व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता, सामाजिक और आर्थिक एकता, राष्ट्रीय एकता व अखंडता।
3. प्रस्ताव निरस्त हो जाएगा। प्रस्ताव दोनों सदनों में स्वतंत्र रूप से पारित होना चाहिए।

4. हां। कुछ संवैधानिक उपबंधों को परिवर्तित करने के लिए कठोर संशोधन प्रक्रिया है जैसे दो-तिहाई विशेष बहुमत, आधे राज्यों का अनुमोदन आदि। जबकि कुछ भाग केवल सामान्य कानून (विधि द्वारा) भी बदले जा सकते हैं।

5. विधायिका द्वारा बनाए कानूनों की न्यायपालिका द्वारा पुनर्समीक्षा।

6. किसी भी समय परिस्थिति अनुरूप संशोधन किए जा सकते हैं।

7. (i) लचीलापन (ii) परिस्थितियां
   (iii) विभिन्न वर्गों की संतुष्टि हेतु (iv) सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों हेतु

8. (i) 38वें और 39वें संशोधनों को चुनौती।
   (ii) सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के विरुद्ध राज्य की धारणा का प्रतिपादन किया।

9. (i) समय की जरूरत देखते हुए इसके अनुकूल संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं।
   (ii) संविधान के व्यवहारिक कामकाज में इस बात की पर्याप्त गुंजाइश रहती है कि किसी संवैधानिक बात की एक से ज्यादा व्याख्याएँ हो सकें।

10. (i) संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या सदन के कुल सदस्यों की संख्या की कम से कम आधी होनी चाहिए।
    (ii) संशोधन का समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या मतदान में भाग लेने वाले सभी सदस्यों की दो तिहाई होनी चाहिए।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. (क) नए राज्यों का गठन
   (ख) राज्य के नाम में परिवर्तन
   (ग) राज की सीमाओं में परिवर्तन
   (घ) सांसदों के विशेष अधिकारों संबंधी संशोधन

2. (क) विशेष बहुमत
   (ख) साधारण बहुमत
   (ग) विशेष बहुमत
   (घ) विशेष बहुमत और आधे राज्यों द्वारा अनुमोदन

3. साधारण बहुमत के लिए आधे से एक अधिक (50% +1) मतों की आवश्यकता होती है। जबकि विशेष बहुमत के लिए सदन के कुल सदस्यों का दो तिहाई 2/3 मत प्राप्त करना आवश्यक होता है।

4. (i) संविधान की समझ को बदलने में न्यायिक व्याख्याओं की अहम भूमिका रही है।

   (ii) आरक्षण संबंधी फैसले।

   (iii) शिक्षा, जीवन, स्वतंत्रता अल्पसंख्यक समूहों संबंधी उपबंधों में अनौपचारिक रूप से कई संशोधन किए गए हैं।

   (iv) यह सुनिश्चित किया कि संसद की सर्वोच्चता व संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक मूल ढांचे के अंतर्गत ही होने चाहिए।

5. (i) 1971-76 के काल के संशोधन जैसे 38वां, 39वां और 42वां संशोधन।

   (ii) विपक्षी दल इन संशोधनों को संदेह की दृष्टि से देखते थे उनका मानना था कि इन संशोधनों के माध्यम से सत्तारूढ़ दल संविधान के मूल स्वरूप को बिगाड़ना चाहता है।

   (iii) ये तीनों संशोधन जून 1975 की आपातकाल की घोषणा की पृष्ठभूमि में से निकले थे।

   (iv) इन संशोधनों (38, 39, 42वें) के माध्यम से जो परिवर्तन किए गए थे उनमें से अधिकांश को 43वें, 44वें संशोधन द्वारा नई सरकार ने निरस्त कर दिया।

6. (i) 2001-2003 केवल 3 वर्षों में भी 10 संशोधन किए गए।

   (ii) यह गठबंधन राजनीति का काल था और विभिन्न राज्यों में अलग-अलग दलों की सरकारें काम कर रही थीं।

   (iii) यद्यपि विरोधी दलों व भाजपा के बीच कटु प्रतिद्वंद्विता थी पर यह संशोधन समय की जरूरत के अनुसार किए गए ना कि सत्ताधारी दल की राजनीतिक सोच या पार्टी के बहुमत के आधार पर।

   (iv) ये संशोधन राजनीतिक आम सहमति का परिणाम थे।

   (v) ये संशोधन तत्कालीन राजनीतिक दर्शन और समाज की आकांक्षाओं को समाहित करने के लिए व्यापक आम सहमति द्वारा किए गए।

7. (i) 52वां तथा 91वां (ii) 61वां (iii) 73वां (iv)74वां

आदि (अन्य कोई संक्षिप्त वर्णन सहित)

8. (i) 1967 से 1973 के दौरान पैदा हुए कटु विरोधाभासों के दौर में संसद तथा कार्यपालिका ने एक संतुलित तथा दीर्घकालीन समाधान की आवश्यकता को महसूस किया।

   (ii) राजनीतिक दलों, राजनेताओं, सरकार तथा संसद सभी ने मूल संरचना के संवेदनशील विचार को स्वीकृति प्रदान की।

   (iii) केशवानंद निर्णय की संविधान की व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका व स्वीकार्यता।

   (iv) संविधान की समीक्षा का विचार भी मूल संरचना के सिद्धांत द्वारा निर्धारित सीमाओं के परे नहीं।

   (v) संविधान के बुनियादी मूल्यों व आदर्शों का सदैव सम्मान व महत्व।

स्रोत/मानचित्र/कार्टून आधारित उत्तर

1. (i) (ख) जून 1975

   (ii) (क) 42वां संशोधन

   (iii) (क) बढ़ाया गया

   (iv) (ग) 42वें

छः अंकीय उत्तर

1. (क) संसद के साधारण बहुमत द्वारा

   (ख) संसद के दोनों सदनों में स्वतंत्र रूप से विशेष बहुमत के द्वारा

   (ग) दोनों सदनों में स्वतंत्र विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के अनुमोदन के द्वारा। (वर्णन सहित)

2. (क) संविधान एक गतिशील व जीवंत दस्तावेज है।

   (ख) एक जीवित व्यक्ति की तरह अनुभवों से सीखता है।

   (ख) भविष्य की चुनौतियों के समाधान के लिए समर्थ होना आवश्यक है अतः संशोधन आवश्यक हैं।

3. (i) 1951 संपत्ति के अधिकार का संशोधन संविधान में नौवीं अनुसूची जोड़ी गई।

(ii) 1969 -सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कि संसद संविधान संशोधन नहीं कर सकती यदि उनके चलते मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो।

(iii) प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा 'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवादी' शब्दों को जोड़ना

(iv) दल-बदल विरोधी (52वां संशोधन 1985)

(v) मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना (61वां संशोधन 1989)

(vi) स्थानीय सरकार (73वां व 74वां संशोधन 1992)

(vii) उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण (93वां संशोधन 2005)

4. विद्यार्थी स्वयं करेंगे।

अध्याय-10

संविधान का दर्शन

मुख्य बिंदु

- संविधान के दर्शन से क्या अभिप्राय है?
- लोकतांत्रिक परिवर्तन के एक साधन के रूप में संविधान।
- संविधान सभा की ओर जाने की आवश्यकता क्यों?
- हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है?
- व्यक्तिगत स्वतंत्रता
- सामाजिक न्याय
- विविधता और अल्पसंख्यक अधिकारों का आदर
- धर्मनिरपेक्षता/पंथनिरपेक्षता
- सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार
- संघवाद
- राष्ट्रीय पहचान
- प्रक्रियागत उपलब्धियां
- आलोचना
- सीमाएँ

भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन

संविधान का सार -प्रस्तावना

भारत का संविधान प्रस्तावना
हम भारत के लोग...

प्रस्तावना हमारे संविधान
की आत्मा है।

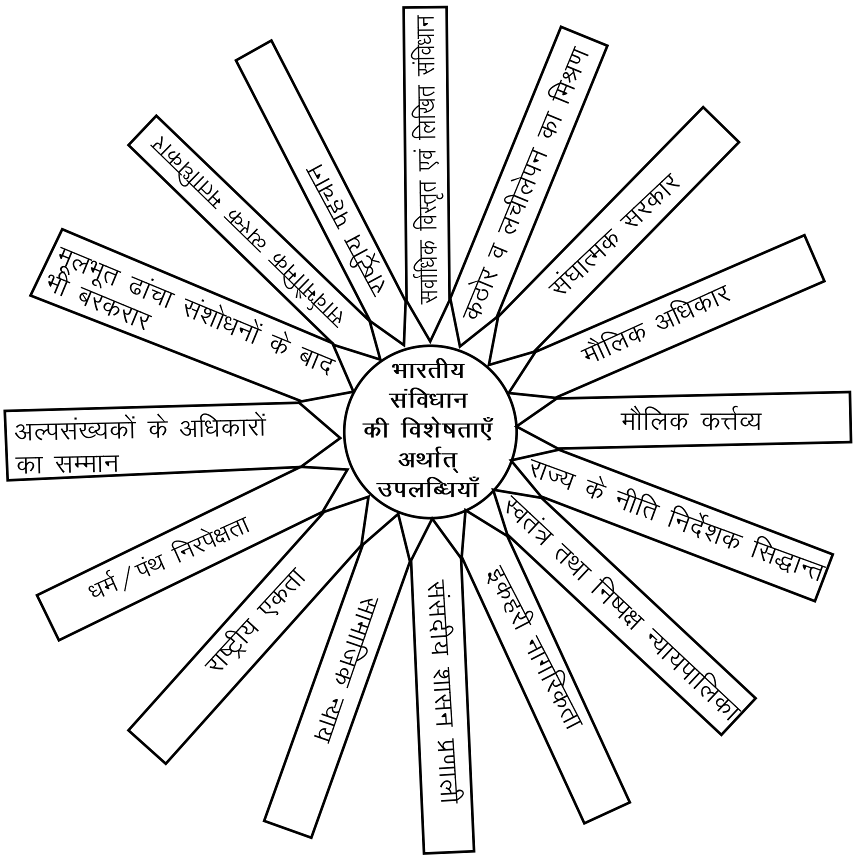

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक [1][**संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य**] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन **सब में**

व्यक्ति की गरिमा और [2][**राष्ट्र की एकता और अखंडता**] सुनिश्चित करने वाली **बंधुता**

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. को **एतदद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

---

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

संविधान का राजनीतिक दर्शन:-

- संविधान के दर्शन से अभिप्राय संविधान की बुनियादी अवधारणाओं से है जैसे अधिकार, नागरिकता, लोकतंत्र आदि।
- संविधान में निहित आदर्श जैसे समानता, स्वतंत्रता हमें संविधान के दर्शन करवाते हैं।
- हमारा संविधान इस बात पर जोर देता है कि उसके दर्शन पर शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाए तथा उन मूल्यों को जिन पर नीतियां बनी हैं, इन नैतिक बुनियादी अवधारणाओं पर चल कर उद्देश्य प्राप्त करें।

संविधान का मुख्य सार- संविधान की प्रस्तावना

प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है

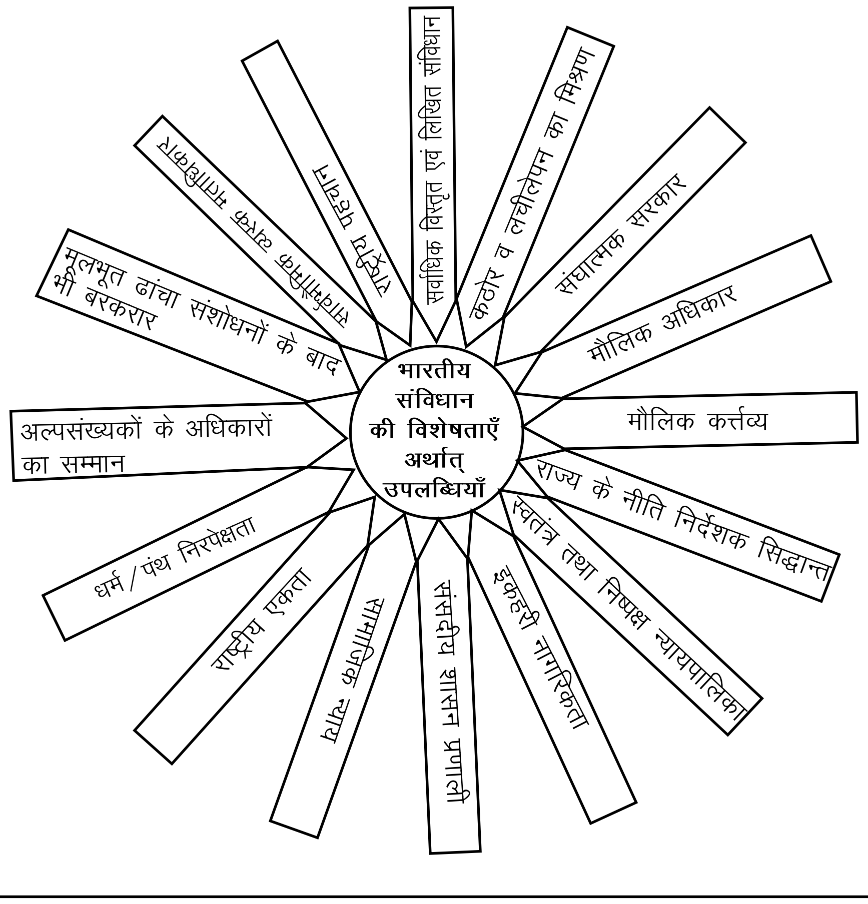

जवाहर लाल नेहरू के अनुसार-''भारतीय संविधान का निर्माण परंपरागत सामाजिक ऊँच नीच के बंधनों को तोड़ने और स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय के नए युग में प्रवेश के लिए हुआ। यह कमजोर लोगों को उनका वाजिब हक सामुदायिक रूप में हासिल करने की ताकत देता है।''

प्रक्रियागत उपलब्धिः-

- संविधान का विश्वास राजनीतिक विचार विमर्श से है। संविधान सभा असहमति को भी सकारात्मक रूप से देखती है।
- संविधान सभा किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला बहुमत से नहीं, सबकी अनुमति से लेना चाहती थी। वे समझौतों को महत्व देते थे। (शिक्षक कक्षा में बहुमत व सर्व अनुमति को स्पष्ट करेंगे।)

  संविधान सभा जिन बातों पर अडिग रही वही हमारे संविधान को विशेष बनाती है।

संविधान की आलोचना के बिंदुः-

- बहुत लंबा तथा विस्तृत-मूल 395 अनुच्छेद संशोधन के बाद 448 अनुच्छेद, 22 भाग 8 अनुसूचियाँ।
- पश्चिमी देशों के संविधानों से इसके प्रावधान लिए गए हैं।
- संविधान के निर्माण में सभी समूहों के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे।

संविधान में दिखने वाली मुख्य सीमाएँः-

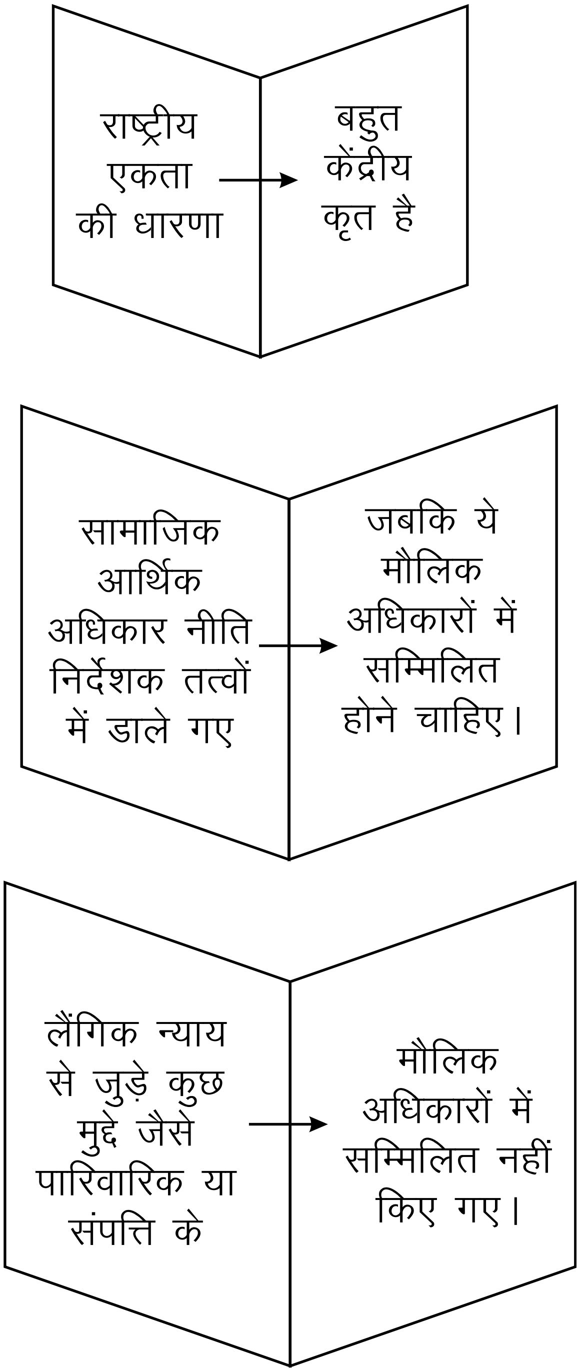

एक अंकीय प्रश्न

1. भारतीय संविधान का दर्शन वस्तुतः संविधान के किस भाग में है?

   (क) प्रस्तावना (ख) राज्य के नीति निर्देशक तत्व

   (ग) मूल अधिकार (घ) इनमें से कोई नहीं

2. भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं?

   (क) छः (ख) आठ

   (ग) दस (घ) बारह

3. किस देश के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है?

   (क) चीन (ख) भारत

   (ग) जापान (घ) अमेरिका

4. भारतीय संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे?

   (क) पंडित नेहरू (ख) सच्चिदानंद सिन्हा

   (ग) डॉ राजेंद्र प्रसाद (घ) डॉ भीमराव अंबेडकर

5. संविधान का पालन करना निम्न में से किस में शामिल है?

   (क) मौलिक अधिकार (ख) मौलिक कर्तव्य

   (ग) राज्य के नीति निर्देशक तत्व (घ) इनमें से कोई नहीं

6. भारत में मत देने की न्यूनतम आयु कितनी है?

   (क) 18 वर्ष (ख) 20 वर्ष

   (ग) 25 वर्ष (घ) 35 वर्ष

7. वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं?

   (क) 445 (ख) 448

   (ग) 450 (घ) 455

8. भारतीय संविधान के अनुसार अंतिम सत्ता किस में निहित है?

(क) प्रधानमंत्री (ख) राज्यपाल

(ग) राष्ट्रपति (घ) जनता

9. सही या गलत बताइए-

(i) निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के समान वैधानिक शक्ति प्रदान की गई है।

(ii) अनुच्छेद 370 का संबंध उत्तर पूर्वी राज्यों से था।

(iii) भारत में मतदान के लिए एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत है।

(iv) रौलेट एक्ट द्वारा गिरफ्तारी के विरुद्ध स्वतंत्रता का हनन हुआ।

(v) राम मोहन राय ने व्यक्ति के अधिकार विशेष कर महिलाओं के अधिकारों पर जोर दिया।

10. कथन कारण प्रश्न

कथन (A) - हमारा संविधान सामाजिक न्याय से संबंधित है।

कारण (R)- अनुसूचित जाति औरअनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान इसका सर्वोत्तम उदाहरण है।

(क) कथन A और कारण R दोनों सही हैं और करण कथन की सही व्याख्या करता है।

(ख) कथन A और कारण R दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता।

(ग) कथन A सही है पर कारण R गलत है।

(घ) कथन A गलत है पर कारण R सही है।

दो अंकीय प्रश्न

1. संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है?
2. 'सर्वभौम व्यस्क मताधिकार' का क्या अर्थ है?
3. 'राष्ट्रीय पहचान' से क्या अभिप्राय है?
4. संविधान सभा की बहसों (CAD) के बारे में आप क्या जानते हैं?
5. धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में 'पारस्परिक निषेध' के क्या मायने हैं?

चार अंकीय प्रश्न

1. संविधान की कोई चार विशेषताओं का वर्णन कीजिए?
2. संविधान की प्रस्तावना में स्थित/ वर्णित किन्हीं चार मूल्यों/आदर्शों का वर्णन कीजिए?
3. 'व्यक्ति की स्वतंत्रता' व 'सामाजिक न्याय' का स्पष्टीकरण कीजिए।
4. नीचे दिए गए अवतरण का अध्ययन करके उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए-

   कानूनी प्रावधान एवं संस्थानिक व्यवस्था समाज की जरूरत तथा समाज द्वारा अपनाए गए दर्शन पर निर्भर है। इस पुस्तक में हमने जिस संस्थानिक व्यवस्था का अध्ययन किया है उसके मूल में है भविष्य के प्रति एक दृष्टि। इस दृष्टि को सब की सहमती प्राप्त है। यह दृष्टि ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्पन्न हुई। संविधान सभा ने इस दृष्टि का परिष्कार किया और उसे विधिक संस्थानिक रूप प्रदान किया। इस तरह संविधान में यह दृष्टि रूपायित हुई। बहुत से लोगों का कहना है कि इस दृष्टि अथवा संविधान के दर्शन का सर्वोत्तम सार संक्षेप संविधान की प्रस्तावना में है।

   (i) "भविष्य के प्रति दृष्टि" से क्या अभिप्राय है?
      (क) संविधान की सीमाएं
      (ख) संविधान की आलोचना
      (ग) संविधान के मूल्य व दर्शन
      (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

   (ii) संविधान के दर्शन की उत्पत्ति कब हुई?
      (क) आजादी से पहले
      (ख) स्वतंत्रता संग्राम के दौरान
      (ग) वर्तमान में
      (घ) कभी भी नहीं

   (iii) इस दृष्टि का परिष्कार किसके द्वारा किया गया?
      (क) संविधान सभा द्वारा
      (ख) लोक सभा द्वारा
      (ग) राज्य सभा द्वारा
      (घ) विधान सभा द्वारा

(iv) संविधान के दर्शन का सर्वोत्तम सार संक्षेप किस में है?

(क) मौलिक अधिकारों में

(ख) मौलिक कर्तव्यों में

(ग) नीति निर्देशक सिद्धांतों में

(घ) संविधान की प्रस्तावना में

छः अंकीय प्रश्न

1. संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शत के नजरिए से क्या अभिप्राय है?
2. हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शत क्या है?
3. भारतीय संविधान की किन्ही तीन आलोचनाओं का वर्णन कीजिए?
4. भारतीय संविधान की सीमाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए?
5. यदि आप किसी संविधान सभा के सदस्य बन जाए तो क्या योगदान देना चाहेंगे?
6. भारत के संविधान की प्रतिलिपि देखने का प्रयास करें। इसे देखकर प्राप्त हुई अनुभूति को अपने शब्दों में लिखिए?
7. विषय अध्यापक की अथवा अभिभावकों की मदद से भारतीय संसद के पुस्तकालय जाकर संविधान सभा की बहसों के कुछ अंश पढ़िए तथा उनका सार अपने शब्दों में लिखिए?
8. दिल्ली के सिविल लाइन स्थित 'डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल' में शैक्षिक भ्रमण हेतु जाइए तत्पश्चात संविधान के निर्माण व प्रमुख विशेषताओं पर एक नोट लिखिए?

उत्तरमाला

एक अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. (क) प्रस्तावना
2. (क) छः
3. (ग) जापान
4. (ख) सच्चिदानंद सिन्हा
5. (ख) मौलिक कर्तव्य
6. (क) 18 वर्ष
7. (ख) 448
8. (घ) जनता
9. (i) गलत (ii) गलत (iii) सही (iv) सही (v) सही
10. (क) कथन A और कारण R दोनों सही हैं और कारण, कथन की सही व्याख्या करता है।

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. भारतीय संविधान विभिन्न लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र सामाजिक न्याय तथा राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिबद्ध है।
2. किसी भी व्यस्क व्यक्ति (18 वर्ष व अधिक) को बिना किसी जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण लिंग आदि के भेदभाव के मतदान देने का अधिकार है।
3. बिना किसी धार्मिक मतभेद के राष्ट्रीय एकता की धारणा को अपनाना।
4. संविधान बनने के दौरान हुई वाद-विवाद तथा विभिन्न दृष्टिकोण जिनका संकलन कई खंडों में है तथा यह संसदीय पुस्तकालय में देखे जा सकते हैं।
5. धर्म और राज्य एक दूसरे के अंदरूनी मामले से दूर रहेंगे।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. (i) मौलिक अधिकार (ii) मौलिक कर्तव्य

   (iii) संघवाद (iv) पंथनिरपेक्षता

   (कोई भी अन्य चार वर्णन सहित)

2. समानता, स्वतंत्रता, न्याय बंधुत्व आदि (कोई चार वर्णन सहित)

3. व्यक्ति की स्वतंत्रता-भारतीय संविधान का चरित्र मजबूत उदारवादी बुनियाद पर प्रतिष्ठित है। जैसे की मौलिक अधिकार आदि का वर्णन।

   सामाजिक न्याय-समता के अधिकार कानूनों व आरक्षण द्वारा समाज के सभी वर्गों को बिना भेदभाव के न्याय प्रदान करना।

4. (i) (ग) संविधान के मूल्य व दर्शन (ii) (ख) स्वतंत्रता संग्राम के दौरान

   (iii) (क) संविधान सभा द्वारा (iv) (घ) संविधान की प्रस्तावना में

छः अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. (i) संविधान की अवधारणाओं की व्याख्या आवश्यक है।

   (ii) समाज व शासन व्यवस्था इन अवधारणाओं पर स्थित हो।

   (iii) संविधान को संविधान सभा की बहसों के साथ जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए।

2. स्वतंत्रता संग्राम के दौरान संजोये गए आदर्शों व मूल्यों को लोकतांत्रिक व शांतिपूर्ण ढंग से अपनाना, सम्मान करना, महत्त्व देना और संजोये रखना।

3. (क) अस्त व्यस्त संविधान

   (ख) सब का प्रतिनिधित्व नहीं

   (ग) भारतीय परिस्थितियों के विपरीत (कोई अन्य वर्णन सहित)

4. (क) राष्ट्रीय एकता की धारणा बहुत केंद्रीकृत।

   (ख) लिंगगत न्याय (परिवार संबंधी मुद्दों आदि) पर कम ध्यान।

   (ग) कुछ बुनियादी सामाजिक आर्थिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा।

5. विद्यार्थी स्वयं सोच कर लिखेंगे।

6. विद्यार्थी अध्यापकों या अभिभावक की मदद से स्वयं करेंगे।

7. विद्यार्थी स्वयं करेंगे।

8. अध्यापकों या अभिभावक की मदद से स्वयं करेंगे।

अध्याय-11

राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय

दो मामलों में अद्वितीय

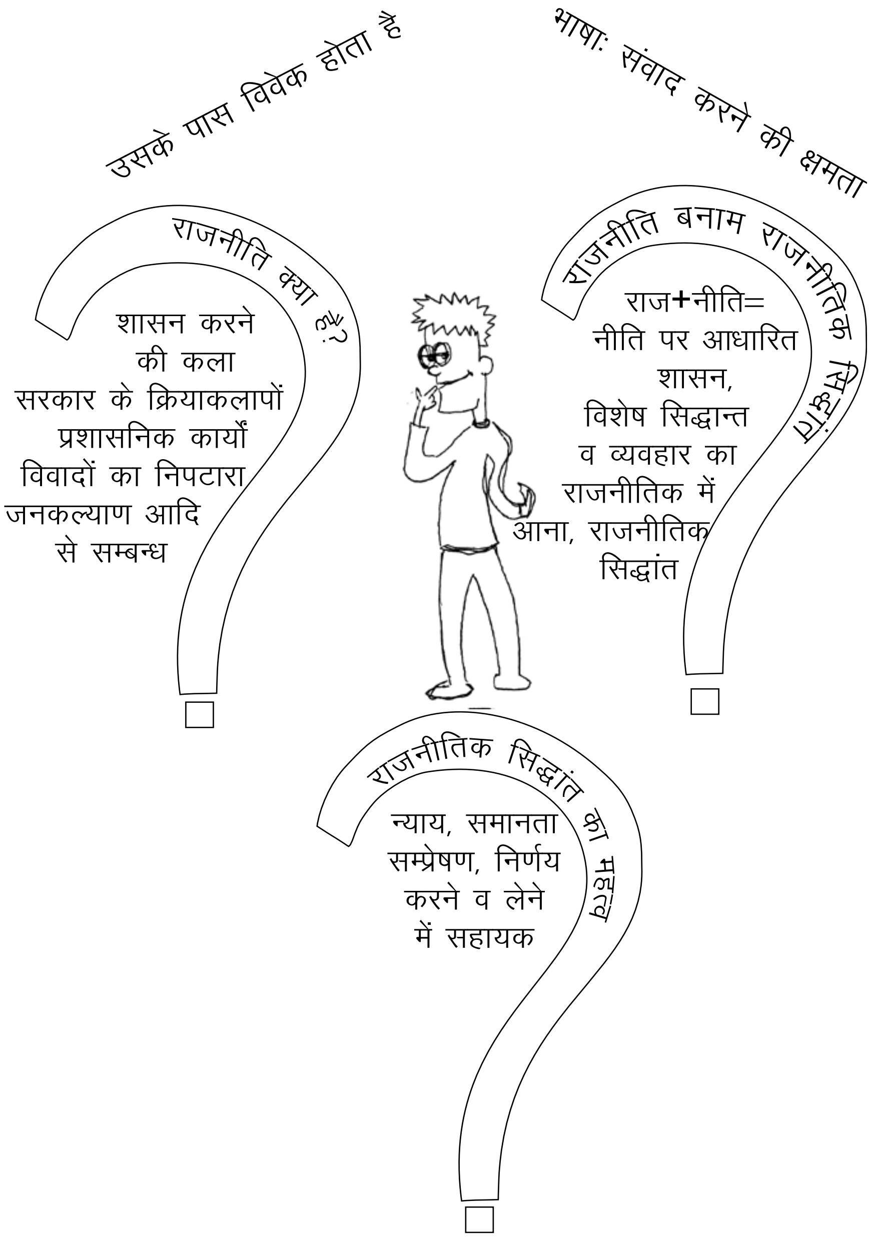

मुख्य बिन्दुः

- राजनीति क्या है?
- राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं?
- राजनीतिक सिद्धान्तों को व्यवहार में उतारना।
- हमें राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों करना चाहिए?
- राजनीति बनाम राजनीतिक सिद्धांत।
- राजनीतिक सिद्धांत का महत्त्व।

राजनीति क्या है?

- राजनीति को परिभाषित करने के लिए विद्वानों के अलग-अलग मत है। सामान्य तौर पर-
  - (i) राजनीति शासन करने की कला है।
  - (ii) राजनीति सरकार के क्रियाकलापों को ठीक से चलाने की सीख देती है।
  - (iii) राजनीति प्रशासन संचालन के विवादों का हल प्रस्तुत करती है।
  - (iv) राजनीति भागीदारी करना सिखाती है लेकिन आम व्यक्ति का सामना राजनीति की परस्पर विरोधी छवियों से होता है, आज राजनीति का संबंध निजी स्वार्थ साधने से जुड़ गया है।
  - (v) जनकल्याण से इसका सम्बन्ध है।
  - (vi) राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण व अविभाज्य अंग है।

राजनीतिक सिद्धान्त में हम क्या पढ़ते है?

- राजनीतिक सिद्धान्त में हम जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते है जैसे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान, आजादी, समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्म निरपेक्ष आदि।
- निश्चित मूल्यों व सिद्धान्तों को पढ़ते है जिनके द्वारा नीतियां निर्देशित होती है।

राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना-

- राजनीति का स्वरूप समय के साथ साथ बदलता रहा, राजनीतिक सिद्धांतों जैसे कि स्वतंत्रता/आजादी और समानता को व्यवहार में उतारने का काम बहुत मुश्किल है। हमें अपने पूर्वाग्रहों का त्याग कर, इन्हें अपनाना चाहिए, राजनीतिक सिद्धांत

के अध्ययन के द्वारा हम राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में अपने विचारों तथा भावनाओं का परीक्षण कर सकते है, हम यह समझ सकते है कि सचेत नागरिक ही देश का विकास कर सकते है, राजनीतिक सिद्धांत कोई वस्तु नहीं है यह मनुष्य से संबधित है उदाहरण के लिए समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर है फिर भी महिलाओं, वृद्धों या विकलांगों के लिए अलग व्यवस्था की गई है अतः हम कह सकते है कि पूर्ण समानता संभव नहीं है, भेदभाव का तर्क संगत आधार जरूरी है।

हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए?

1. भविष्य में आने वाली समस्याओं के समय एक उचित निर्णय लेने वाला नागरिक बनने के लिए।
2. बुनियादी व सामान्य ज्ञान के लिए।
3. एक अधिकार संपन्न एवं जागरूक नागरिक बनने के लिए, राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए।
4. मत देने के लिए।
5. समाज से पूर्वाग्रहों को समाप्त करने एवं एकता कायम करने के लिए।
6. आन्दोलनों को प्रेरणा व सही दिशा देने के लिए।
7. वाद-विवाद, तर्क-वितर्क, लाभ-हानि का आंकलन करने के बाद सही निर्णय लेने की कला सीखने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए।
8. शासन व्यवस्था की जानकारी के लिए।
9. नीति बनाने के लिए।
10. लोकतंत्र की उपयोगिता का ज्ञान प्राप्त करने हेतु।
11. अधिकार एंव कर्तव्यों को समझने के लिए।
12. भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए।
13. अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग को बढ़ावा देने के लिए।
14. विभिन्न शासन प्रणालियों के अध्ययन हेतु।
15. एक छात्र होने के नाते।

राजनीति बनाम राजनीतिक सिद्धांत

राजनीति व राजनीतिक सिद्धान्त दो अलग-अलग धारणाएं है।

राजनीति दो शब्दों से मिलकर बना है। राज . नीति अर्थात नीति पर आधारित शासन, नागरिक या व्यक्तिगत स्तर पर किसी विशेष सिद्धांत अथवा व्यवहार का प्रयोग राजनीति के अंतर्गत आता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया सरकार बनाने की प्रक्रिया सत्ता प्राप्त करने की प्रक्रिया आदि।

राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विषय राज्य व सरकार है। यह आजादी, समानता, न्याय व लोकतंत्र जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य- नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्क संगत ढंग से सोचने और सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीकें से आंकने का प्रशिक्षण देना है। गणित के विपरीत जहां त्रिभुज या वर्ग की निश्चित परिभाषा होती है- राजनीतिक सिद्धांत में हम 'समानता', 'आजादी' या न्याय की अनेक परिभाषाओं से रूबरू होते है।

ऐसा इसलिए है कि समानता, न्याय जैसे शब्दों का सरोकार किसी वस्तु के बजाय अन्य मनुष्यों के साथ हमारे संबंधों से होता है। राजनीतिक सिद्धांत हमें राजनीतिक चीजों के बारे में अपने विचार व व्यवहार से भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है।

दूसरी ओर राजनीति विज्ञान व राजनीति भी दो अलग-अलग धारणाएं है। राजनीति विज्ञान का जन्म राजनीति से पूर्व हुआ है, यह नैतिकता पर आधारित है जबकि राजनीति अवसर व सुविधा पर आधारित है। इतना होने पर भी इन्हें सिक्के के दो पहलू के रूप में माना जा सकता है।

राजनीतिक सिद्धांत का महत्व-

- न्याय व समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच का विकास
- तर्कसंगत व प्रभावी ढंग से सम्प्रेषण
- कुशल व प्रभावी राजनीति निर्णय लेने में सहायक
- अन्तर्राष्ट्रीय जगत की सूचना प्राप्त करने हेतु।

प्रश्नावली

बहुविकल्पीय प्रश्नः- एक अंकीय प्रश्न

1. कथनः राजनीति विज्ञान व राजनीति दो अलग-अलग विचारधारा हैं।

   कारणः राजनीति विज्ञान का जन्म राजनीति से पहले हुआ यह नैतिकता पर आधारित है। राजनीति अवसर व सुविधा पर आधारित है।

   (i) कथन व कारण दोनों गलत है।

   (ii) कथन सही है, कारण भी सही है। कारण, कथन की सही व्याख्या कर रहा है।

   (iii) कथन सही कारण गलत है।

   (iv) कथन व कारण दोनों सही है परन्तु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा।

2. कथनः प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में राजनीतिक सिद्धांत का महत्व है।

   कारणः राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन से न्याय समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच का विकास होता है।

   (i) कथन सही कारण गलत है।

   (ii) कथन गलत, कारण सही है।

   (iii) कथन व कारण दोनों सही हैं। कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा।

   (iv) कथन व कारण दोनों सही हैं कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है।

3. राजनीति क्या है?

   (i) शासन करने की कला

   (ii) सरकार के क्रियाकलापों को ठीक से चलाने की सीख देती है

   (iii) प्रशासनिक संचालन के विषयों को हल देती है

   (iv) उपरोक्त सभी

4. राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विषय क्या है?

   (i) सरकार व नागरिक

   (ii) नागरिक व मतदाता

   (iii) राज्य व सरकार

   (vi) उपरोक्त में से कोई नहीं

5. व्यवहारपरक राजनीतिक सिद्धांत किस शताब्दी की उपज है?

(i) 18वीं शताब्दी

(ii) 20वीं शताब्दी

(iii) 16वीं शताब्दी

(iv) 21वीं शताब्दी

6. 'रिपब्लिक' पुस्तक किसने लिखी?

(i) अरस्तु

(ii) महात्मा गांधी

(iii) अंबेडकर

(iv) प्लेटो

7. 'थ्योरी' (Theory) शब्द का उद्भव (Theoria) शब्द से हुआ यह किस भाषा का शब्द है?

(i) संस्कृत

(ii) लैटिन

(iii) यूनानी

(iv) फ्रेंच

8. मनुष्य अद्वितीय हैं क्योंकि वेः

(i) राजनीति में भाग लेते हैं

(ii) वे आपस में लड़ते हैं

(iii) उनके पास एक-दूसरे के साथ संवाद करने के लिए विवेक और भाषा है

(iv) उपरोक्त में से कोई नहीं

9. राजनीतिक सिद्धांत क्या है? समझाइए।

10. गांधी जी की पुस्तक 'हिन्द-स्वराज' में किस विषय पर प्रकाश डाला गया है?

11. राजनीति के विषय में आम लोगों की विचारधारा क्या है?

12. राजनीतिक विज्ञान व राजनीति में कोई एक अन्तर लिखें?

13. हमें राजनीतिक सिद्धान्त क्यों पढ़ना चाहिए?
14. राजनीतिक सिद्धान्त का मुख्य विषय क्या है?
15. राजनीति क्या है? (निम्न में से सही को अंकित करें)
    (i) राजनीति शासन करने की कला है।
    (ii) राजनीति प्रशासन संचालन के विवादों का हल प्रस्तुत करती है।
    (iii) राजनीति जन कल्याण से संबंधित है।
    (iv) उपरोक्त सभी
16. राजनीतिक सिद्धांत में हम अध्ययन करते हैं ...., ..., ... तथा ....। (कोई चार पहलू लिखें)।
17. वाक्य कों सही करके लिखें-

    लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना जरूरी नहीं है।
18. राजनीति व राजनीतिक सिद्धांत दो अलग-अलग धारणाएं हैं। (सही/गलत)
19. राजनीतिक सिद्धांत भावी राजनीतिक निर्णय लेने में सहायक है? (सही/गलत)

दो अंकीय प्रश्नः-

1. 'राजनीति' का अर्थ स्पष्ट करें।
2. राजनीतिक सिद्धांत के किन्हीं दो क्षेत्रों को समझाइए। वर्णन कीजिए।
3. किन्हीं चार राजनैतिक विद्वानों के नाम लिखिए।
4. राजनीतिक सिद्धांत में हम जीवन के किन-किन पहलुओं का अध्ययन करते हैं?
5. हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए? कोई दो कारण लिखिए।

चार अंकीय प्रश्नः-

1. 'राजनीति विज्ञान, विज्ञान है भी और नहीं भी।' इस तथ्य को स्पष्ट कीजिए।
2. किसी देश में लोकतंत्रिक सरकार के सफल संचालन के लिए राजनीतिक सिद्धांत आवश्यक है। कैसे?
3. 'राजनीति मनुष्य के दैनिक जीवन को कदम-कदम पर प्रभावित करती है। स्पष्ट कीजिए।

4. चार अंकीय प्रश्नः- अवतरण आधारित प्रश्न

राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे मूल्य के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। अतीत और वर्तमान के कुछ प्रमुख राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखकर इन अवधारणाओं की मौजूदा परिभाषाओं को स्पष्ट करता है। वर्तमान परिभाषाएं कितनी उपयुक्त हैं और कैसे वर्तमान नीतियों के अनुपालन को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए उनका परिमार्जन किया जाएँ। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने और सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आँकने का प्रशिक्षण देना है।

4.1. राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले मूल्य कौन-कौन से हैं?

(A) शिक्षा, नैतिकता (B) आदर्श, सत्यता, ईमानदारी

(C) स्वतंत्रता, समानता और न्याय (D) समानता, धर्मनिरपेक्षता, मित्रता

4.2. राजनीतिक सिद्धांत किस को आंकने का प्रशिक्षण देता है?

(A) आर्थिक व राजनीतिक घटनाओं को

(B) शैक्षिक व विदेशी घटनाओं को

(C) सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं को

(D) विदेशनीति व सामाजिक नीतियों को

4.3. नागरिकों को तर्क संगत ढंग से सोचने, सामाजिक, राजनीतिक घटनाओं को आंकने का प्रशिक्षण देना किसका उद्देश्य है?

(A) राजनीतिक सिद्धांत का (C) राल्स के न्याय सिद्धांत का

(B) आर्थिक सिद्धांत का (D) सामाजिक न्याय के सिद्धांत का

4.4. मौजूदा परिभाषाओं को स्पष्ट करने के लिए किन-किन राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखा जाता है।

(A) वर्तमान के सभी चिन्तक (B) आर्थिक क्षेत्र के प्रमुख चिन्तक

(C) भूतकाल (अतीत) के चिन्तक (D) अतीत और वर्तमान के प्रमुख चिन्तक

छः अंकीय प्रश्नः -

1. राजनीतिक सिद्धान्त में हम क्या - क्या पढ़ते है ? लिखिए।
2. राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं लिखिए।
3. हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए? सविस्तार समझाइए।
4. 'राजनीतिक सिद्धांत समानता व स्वतंत्रता से संबंधित प्रश्नों को हल करने में बहुत प्रासंगिक है।" कैसे ? तर्क सहित सिद्ध कीजिए।

उत्तरमाला

एक अंकीय प्रश्नों के उत्तरः-

1. (B) कथन सही है, कारण भी सही है। कारण, कथन की सही व्याख्या कर रहा है।
2. (D) कथन व कारण दोनों सही हैं। कारण, कथन की सही व्याख्या कर रहा है।
3. (D) उपरोक्त सभी
4. (C) राज्य व सरकार
5. (B) 20वीं शताब्दी
6. (D) प्लेटो
7. (C) यूनानी
8. उसके पास एक-दूसरे के साथ संवाद करने के लिये विवेक और भाषा है।
9. राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों के व्यवस्थित रूप को प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है।
10. स्वराज के अर्थ की विवेचना पर।
11. आम लोग राजनीति को अच्छा नहीं मानते
12. राजनीतिक विज्ञान निश्चित आदर्शों पर आधारित है जबकि राजनीति स्वार्थ व अवसरवादिता पर आधारित है।
13. इससे राजनीतिक नियमों / सिद्धांतों, समानता, स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र का ज्ञान होता है। जो लोकतंत्र के लिये आवश्यक है।
14. राज्य व सरकार

15. (4) उपरोक्त सभी।

16. स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र (पाठ में वर्णित अन्य)

17. लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना जरूरी है।

18. सही।

19. सही।

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तरः-

1. राजनीति शब्द की उत्पति ग्रीक शब्द पोलिस से हुई है, जिस का शाब्दिक अर्थ नगर राज्य होता है।

2. (i) राज्य और सरकार का अध्ययन।

   (ii) शक्ति और राजनीतिक विचारधराओं का अध्ययन।

3. अरस्तु, प्लेटो, रूसों, कौटिल्य, कार्ल मार्क्स, एवं डॉ. अम्बेडकर।

4. राजनीतिक सिद्धांत में मुख्यतः सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान, स्वतंत्रता समानता न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता आदि का अध्ययन किया जाता है।

5. 1. शासन व्यवस्था की जानकारी के लिए।

   2. अधिकार एवं कर्तव्य को समझने के लिए। (अन्य कोई पॉइंट)

चार अंकीय प्रष्नों के उत्तरः-

1. **राजनीतिक विज्ञान, विज्ञान है-** जो विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं उनका तर्क है कि विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान होता है और राजनीति विज्ञान का अध्ययन भी क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। इसमें प्रयोग संभव है। इसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता है तथा इतिहास एवं समस्त विश्व इसकी प्रयोगशाला के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं।

   राजनीति विज्ञान, विज्ञान नहीं है- जो लोग इसे विज्ञान नहीं मानते उनका कहना है कि राजनीति विज्ञान के सिद्धान्त स्पष्ट नहीं हैं। राजनीति में समान कारण होते हुए भी राजनीति विज्ञान में परिणाम एक जैसे नहीं निकलते। इसमें प्रयोग करना भी संभव नहीं है। इसकी कोई वास्तविक प्रयोगशाला भी नहीं होती। इसके अध्ययन में वैज्ञानिक विधि को अपनाया जाना सम्भव नहीं।

2. राजनीति सिद्धान्त उन विचारों पर चर्चा करते हैं जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाएँ बनती हैं। राजनीति सिद्धान्त विभिन्न धर्मों के अंतर्संबंधों की व्याख्या करते हैं। ये समानता और स्वतंत्रता जैसी अवधारणाओं के अर्थ की व्याख्या करते हैं।

3. दैनिक जीवन में व्यक्ति कदम-कदम पर स्वतंत्रता एवं समानता के लिए संघर्ष करता नजर आता है। उदाहरण कही पानी के लिए सार्वजनिक नल पर पानी भरना हो चाहे समान रूप से मंदिर में प्रवेश को लेकर हो

4.1. (A) स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्य।

4.2 (B) सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं को।

4.3 (C) नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने और सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आँकने का प्रशिक्षण देता है।

4.4. (D) अतीत और वर्तमान के प्रमुख राजनीतिक चिंतक।

छः अंकीय प्रष्नों के उत्तरः- (सांकेतिक उत्तर)

1. राजनैतिक सिद्धान्त में हम-समाज में आए परिवर्तनों, आन्दोलनों, विकास तथा विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन करते है तथा अन्य कारण।

2. स्वतंत्रता, समानता पूर्वाग्रहों का त्याग करना, देश का विकास, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास के मार्ग निर्देशन देना आदि। अन्य कारण।

3. (i) जागरूक बनाने के लिए।

   (ii) भविष्य की समस्याओं के सफल समाधान कर्ता तैयार करने के लिए।

   (iii) समाज में एकता कायम करने के लिए।

   (iv) तर्क संगत निर्णय लेने के लिए तैयार करना, आदि।

4. राजनैतिक सिद्धान्त स्वतंत्रता व समानता से संबंधित प्रश्नों के सरल एवं सहज उत्तर प्रस्तुत करता है। यह सम्पूर्ण मानव समाज के विकास एव सभ्यता के उदाहरण प्रस्तुत करतो हुए सभ्य मानव बनने का मार्ग सुझाता है तथा गलत रास्ते पर जाने के परिणामों से अवगत करता है।

   यह स्वतंत्रता एवं समानता को अपनाने वाले राष्ट्रों की समृद्धि एवं सफलता की कहानी के माध्यम से सम्पूर्ण विश्व से गुलामी एवं असफलता को समाप्त करने का रास्ता दिखाता है।

अध्याय-12

आजादी

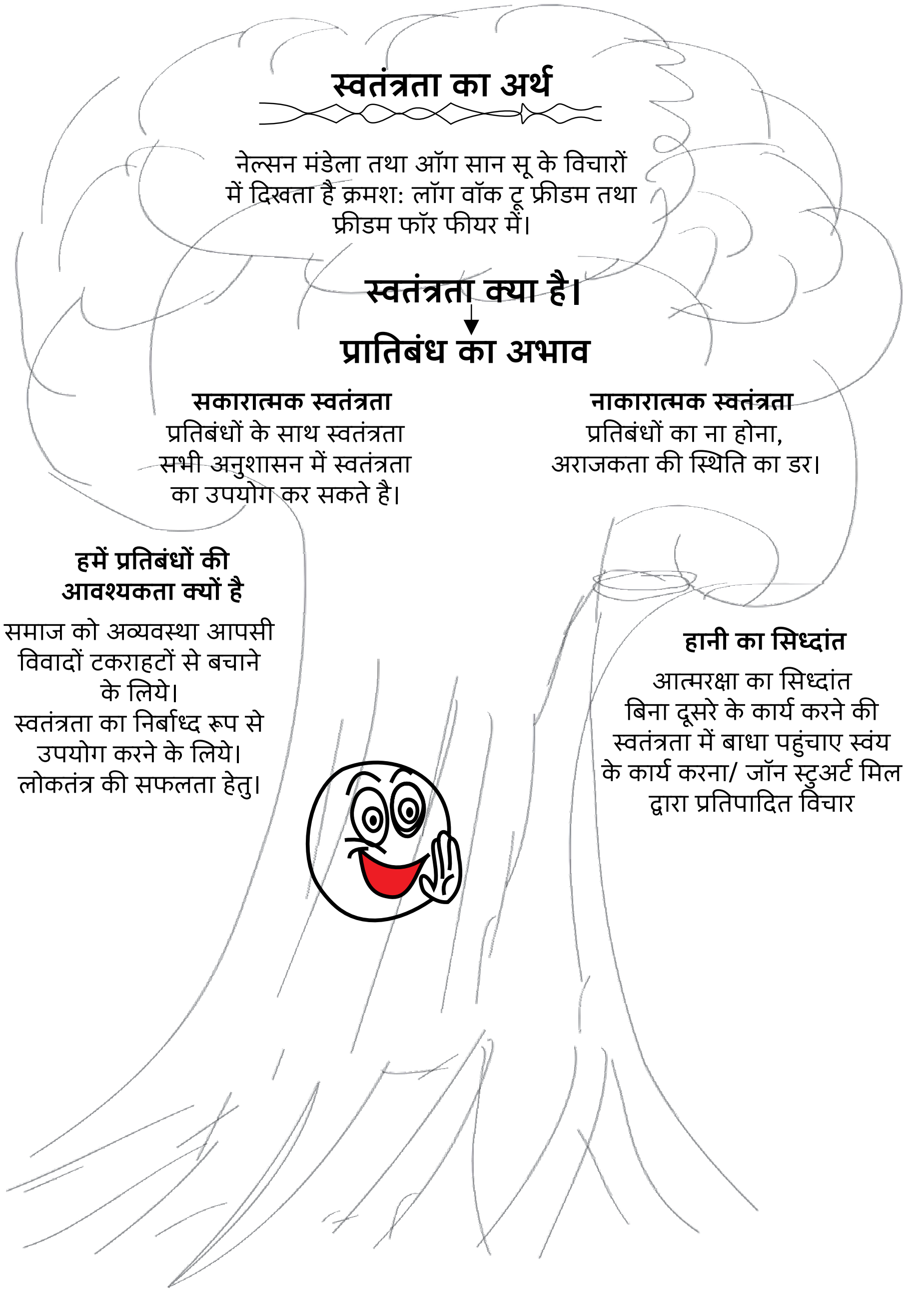

स्वतंत्रता का अर्थ
नेल्सन मंडेला तथा ऑग सान सू के विचारों में दिखता है क्रमशः लॉग वॉक टू फ्रीडम तथा फ्रीडम फॉर फीयर में।
स्वतंत्रता क्या है।
प्रातिबंध का अभाव
सकारात्मक स्वतंत्रता
प्रतिबंधों के साथ स्वतंत्रता सभी अनुशासन में स्वतंत्रता का उपयोग कर सकते है।
नाकारात्मक स्वतंत्रता
प्रतिबंधों का ना होना, अराजकता की स्थिति का डर।
हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है
समाज को अव्यवस्था आपसी विवादों टकराहटों से बचाने के लिये।
स्वतंत्रता का निर्बाध्द रूप से उपयोग करने के लिये।
लोकतंत्र की सफलता हेतु।
हानी का सिध्दांत
आत्मरक्षा का सिध्दांत बिना दूसरे के कार्य करने की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाए स्वंय के कार्य करना/ जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा प्रतिपादित विचार

आज़ादी/स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में वर्णित है।

मुख्य बिन्दुः

- स्वतंत्रता का आदर्श
- स्वतंत्रता क्या है?
- बाधाओं के स्रोत
- बधाओ की आवश्यकता क्यों है?
- हानि का सिद्धांत।
- स्वतंत्रता (लिबर्टी) बनाम स्वतंत्रता (फ्रीडम)
- नकारात्मक एवं सकारात्मक स्वतंत्रता। (दो आयाम)
  (भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार का विश्लेषण)

स्वतंत्रता का आदर्शः

नेल्सन मंडेला की पुस्तक 'वाक टू फ्रीडम' तथा आँग सान सू की पुस्तक 'फ्रीडम फ्रॉम फीयर' में स्वतंत्रता के आदर्श की शक्ति को देख सकते हैं। गरिमामय जीवन जीने के लिए भय मुक्त होना जरूरी है।

स्वतंत्रता क्या है?

- सामान्यतः स्वतंत्रता को प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अभाव के रुप में माना जाता है। इसे मानव के 'जो चाहे सो करे' के अधिकार का पर्यायवाची समझा जाता है। (बाहरी प्रतिबंधों का अभाव)
- हाब्स ने इसे अर्थात ' जो चाहों सो करो' की स्थिति को स्वच्छंदता की स्थिति कहा है जो प्राकृतिक अवस्था में उपलब्ध होती है।
- दूसरे शब्दों में, स्वतंत्रता का अर्थ है मानव को उस कार्य को करने का अधिकार जो वह करने के योग्य है। व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना तथा ऐसी परिस्थितियों का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें।
- वार्कर के अनुसार, 'व्यक्तियों की स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं के साथ जुड़ी हुई है।
- स्वतंत्रता व्यक्तित्व विकास की सुविधा तर्कसंगम बंधन।

- बीसवीं शताब्दी में महात्मा गांधी, नेल्सन मण्डेला तथा आंग सान सू, की आदि व्यक्तियों ने शासन में भेदभाव, शोषणात्मक व दमनात्मकारी नीतियों का विरोध कर स्वतंत्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाया।

स्वतंत्रता के प्रकार

प्राकृतिक स्वतंत्रता	व्यक्तिगत स्वतंत्रता	राजनीतिक स्वतंत्रता	आर्थिक अधिकार
–व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार सब कुछ करने की पूर्ण स्वतंत्रता	– निजी मामलों में विकल्प की स्वतंत्रता	–राज्य के कार्यों में भाग लेने का अधिकार	–कोई लाभकारी पद पाने या कारोबार करने का अधिकार
–मानव के कार्यों पर किसी भी प्रकार का बंधन न हो।	–जीवन की सुरक्षा	–मतदान का अधिकार	–अभाव से मुक्ति का अधिकार
	–विचार, अभिव्यक्ति तथा आस्था की स्वतंत्रता	–स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव लड़ने का अधिकार	–वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण करने का अधिकार
		– शासन की नीतियों तथा कार्यों का समर्थन अथवा विरोध करने का अधिकार	

उदारवादी बनाम मॉर्क्सवादी धारणाः-

- ऐतिहासिक रूप से उदारवाद ने मुक्त बाजार और राज्य की न्यूनतम का पक्ष लिया है। हालांकि अब वे कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करते है और मानते है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने वाले उपायों की जरूरत है।
- सकारात्मक उदारवादी (हॉब्स लॉक तथा लास्की) समर्थन करते है कि कानून व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करता हैं। सार्वजनिक हित में व्यक्तियों को सर्वोत्तम विकास के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उचित प्रतिबंधों का समर्थन।
- उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे मूल्यों से अधिक वरीयता देते है। वे आमतोर पर राजनीतिक सत्ता को भी संदेह की नजर से देखते है।
- माक्र्सवादी (समाजवादी) सामाजिक जीवन के ढांचे में उपलब्ध आर्थिक स्वतंत्रता को महत्व देते है।

- स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा सभी लोगों के लिए इसके समान हितों की कामना करती है। वर्गों के बोझ से दबे बुर्जुआ समाज में उसके निहितार्थ भिन्न वर्गों के लिए भिन्न होते है। इसलिए जब तक पूंजीवादी व्यवस्था के स्थान पर समाजवादी व्यवस्था नहीं आ जाती तब तक वास्तविक स्वतंत्रता संभव नहीं है।

प्रतिबंधों के स्रोत

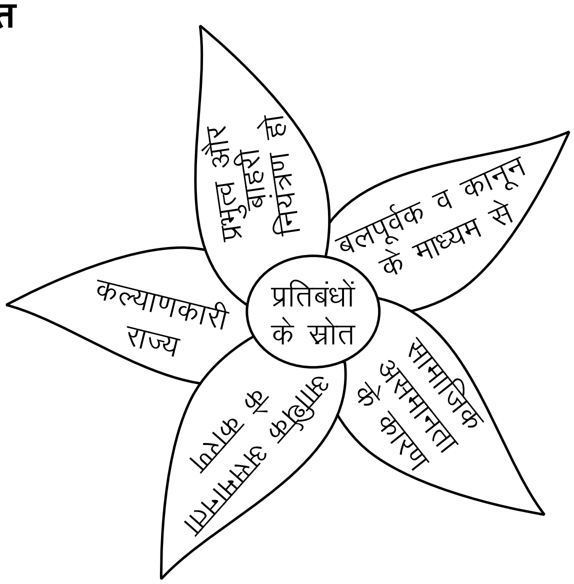

हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है?

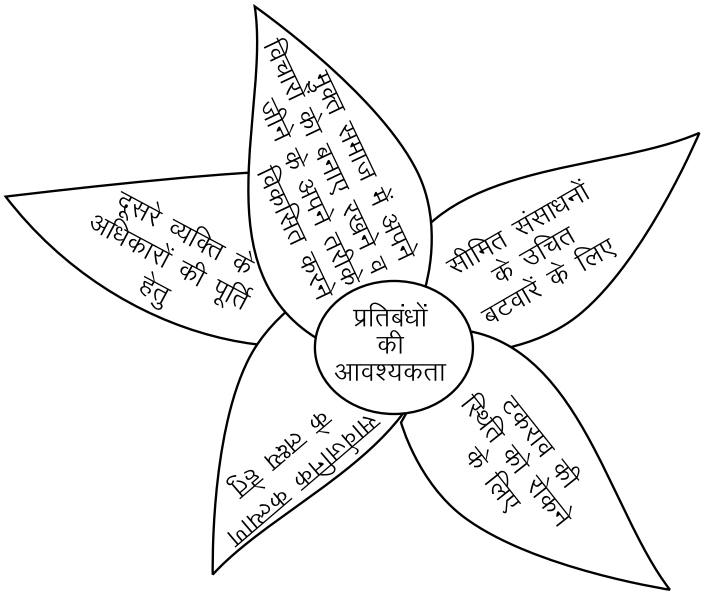

हानि सिद्धांतः

''किसी के कार्य करने के स्वतत्रंता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है।''

जे. एस. मिल ने यहां एक महत्वपूर्ण विभेद को सामने रखा 'स्वसंबंध' और 'परसंबंध' के रूप में। स्वसंबंध जिसका प्रभाव केवल कार्य करने वाले व्यक्ति के उपर पड़ता है। 'परसंबंध जिसमें करने वाले कार्य का प्रभाव अन्य बाहरी व्यक्तियों के ऊपर भी पड़ता है। यदि उन कार्यों से दूसरों को कोई बड़ी हानि पहुंच रही हो तो ऐसी परिस्थिति में राज्य उनके ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है।

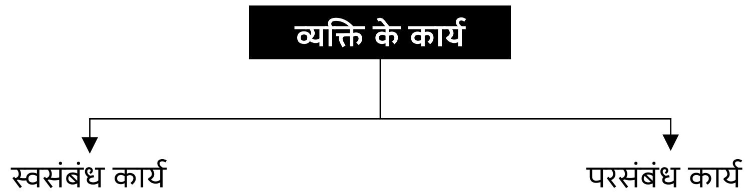

राज्य का किसी व्यक्ति के कार्यों व इच्छा के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य किसी को हानि से बचाना होता है।

स्वतंत्रता (लिबर्टी) बनाम स्वतंत्रता (फ्रीडम)

स्वतंत्रता (लिबर्टी) बनाम स्वतंत्रता (फ्रीमड) हम प्रायः स्वतंत्रता की संकल्पना को फ्रीडम तथा लिबर्टी के समानार्थक शब्दों के रूप में प्रयोग होते हुए देखते हैं परंतु इन दोनों संकल्पनाओं के मध्य कुछ मूलभूत अंतर है जिन्हें समझना आवश्यक है। लिबर्टी लैटिन शब्द से आया है जिसका अर्थ है 'मुक्त व्यक्ति की स्थिति'। जबकि स्वतंत्रता (लिबर्टी) अंग्रेजी शब्द फ्रीडम से बना है जिसका अर्थ है 'मुक्त राज्य'।

(लिबर्टी) व्यक्ति की स्वतंत्रता की इच्छा के अनुसार कार्य करने तथा स्वयं को अभिव्यक्त करने की शक्ति है, जबकि फ्रीडम किसी के कार्य को निश्चित करने की शक्ति होती है। फ्रीडम, लिबर्टी से अधिक ठोस संकल्पना है। फ्रीडम व्यक्ति के राज्य के साथ अन्य व्यक्तियों के साथ एवं परिस्थितियों के साथ संबंध संकल्पना है। राज्य लिबर्टी के माध्यम से अपने नागरिकों को फ्रीडम की गारंटी प्रदान करता है।

स्वतंत्रता (फ्रीडम)

- एक मुक्त व्यक्ति की स्थिति
- कार्य करने की शक्ति
- कुछ करने के लिए स्वतंत्रता

स्वतंत्रता (लिबर्टी)

- स्वतंत्र इच्छा की अवस्था।
- निर्णय लेने की शक्ति।
- किसी से स्वतंत्र।

इन दोनों संकल्पना के मध्य एक सामान्य विशेषता यह है कि यह दोनों संबंधित हैं, अर्थात एक-दूसरे की प्राप्ति में बाधा मुक्त हैं। इसके अतिरिक्त दोनों अपने बोध के संदर्भ में नैतिक अनुरूपता का पालन करते हैं।

नकारात्मक स्वतंत्रता एवं सकारात्मक स्वतंत्रता:-

- नकारात्मक स्वतंत्रता- नकरात्मक भाव में इसका यह निहितार्थ है कि जहां तक संभव हो प्रतिबंधों का अभाव हो। क्योंकि प्रतिबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती करते है। इसलिए इच्छानुसार कार्य करने की छूट हो और व्यक्ति के कार्यों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध न हो।
- समर्थक है जॉन स्टुअर्ट मिल और एफ.ए. हायक आदि।
- सकारात्मक स्वतंत्रता
  - नियमों व कानूनों के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था जिससे मनुष्य अपना विकास कर सकें।
  - यदि राज्य सार्वजनिक कल्याण का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो प्रतिबन्ध अनिवार्य है।
  - मानव समाज मे रहता है, उसके कार्य अन्य लोगों की स्वतंत्रता को प्रभावित करते है। इसलिए इसका जीवन बंधनों द्वारा विनियमित होना चाहिए।
  - तर्कयुक्त बंधनों की उपस्थिति।
  - समर्थक है टी.एच.ग्रीन व प्रो. ईसाह बर्लिन'।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताः-

- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा अहस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र से जुड़ा है।
- जान स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक 'आन लिबर्टी' में सबल तर्क रखते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें भी होनी चाहिए जिनके विचार आज की स्थितियों में गलत और भ्रामक लग रहे हो।
- चार सबल तर्कः-
    1) कोई भी विचार पूरी से गलत नहीं होता। उसमें सच्चाई का भी कुछ अंश होता है।
    2) सत्य स्वंय से उत्पन्न नहीं होता बल्कि विरोधी विचारों के टकराव से पैदा होता है।
    3) जब किसी विचार के समक्ष एक विरोधी विचार आता है तभी उस विचार की विश्वसनीयता सिद्ध होती है।
    4) आज जो सत्य है, वह हमेशा सत्य नही रह सकता। कई बार जो विचार आज स्वीकार्य नही है वह आने वाले समय के लिए मूल्यवान हो सकते है।
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कई बार प्रतिबंध अल्पकालीन रूप में समस्या का समाधान बन जाते है तथा तत्कालीन मांग को पूरा कर देते है लेकिन समाज में स्वतंत्रता के दूरगामी संभावनाओं की दृष्टि से यह बहुत खतरनाक है।
- स्वतंत्रता विकल्प चुनने के सामर्थ्य और क्षमताओं में छुपी होती है

स्वतंत्रता की रक्षा के उपायः-

- लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था
- मौलिक अधिकरों का प्रावधान
- कानून का शासन
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता
- शक्तियों का विकेन्द्रीकरण
- शक्तिशाली विरोधी दल
- आर्थिक समानता
- विशेषाधिकार न होना
- जागरूक जनमत

प्रश्नावली

एक अंकीय प्रश्नः-

1. कथनः- किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा के लिये अधिकार जरूरी होते हैं।

   कारणः- भारतीय संविधान नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है।

   (A) कथन गलत है कारण सही हैं।

   (B) 'कथन' व 'कारण' दोनों सही हैं कारण, कथन की सही व्याख्या कर रहा है।

   (C) कथन सही कारण गलत

   (D) उपरोक्त सभी सही

2. 'लिबर्टी' शब्द की उत्पत्ति, किस भाषा के शब्द से मानी जाती है?

   (A) स्पेनिश

   (B) ग्रीस

   (C) लैटिन

   (D) फ्रेंच

3. नकारात्मक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है?

   (A) प्रतिबंधों के साथ स्वतंत्रता

   (B) प्रतिबंधों का अभाव

   (C) प्रतिबंधों की अधिकता

   (D) उपरोक्त सभी

4. सकारात्मक स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं?

   (A) प्रतिबंधों के साथ स्वतंत्रता

   (B) परिस्थिति के अनुसार प्रतिबंध

   (C) राजनीतिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध

   (D) आर्थिक व सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर रोक

5. 'लिबर' (Liber) शब्द का क्या अर्थ है?

(A) वैश्विक स्वतंत्रता

(B) आर्थिक स्वतंत्रता

(C) राजनीतिक स्वतंत्रता

(D) पूर्ण स्वतंत्रता

6. स्वतंत्रता के दो आयाम कौन-कौन से हैं?

(A) एकात्मकता तथा नकारात्मकता

(B) सकारात्मकता तथा बहुलवाद

(C) नकारात्मक तथा सकारात्मक

(D) उपरोक्त सभी

7. स्वतंत्रता (लिबर्टी) का अर्थ है?

(A) स्वतंत्रता की अवस्था

(B) निर्णय लेने की शक्ति

(C) किसी से स्वतंत्र

(D) उपरोक्त सभी

8. निम्नलिखित का मिलान करें (1+1+1+1+1)

(A) नेल्सन मंडेला	(i) हिन्द स्वराज
(B) आंग सान सू की	(ii) रामायण रिटोल्ड
(C) गांधी जी	(iii) लाँग वॉक टू फ्रीडम
(D) जॉन स्टुअर्ट मिल	(iv) फ्रीड़म फार फीयर
(E) ओब्रे मेनन	(v) आन लिबर्टी

9. स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है?

10. प्रतिबंधों के स्रोत क्या है?

11. नकारात्मक स्वतंत्रता से आप क्या समझते है?

12. एक व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है?

13. जान स्टुअर्ट मिल ने व्यक्ति के कार्यों को कितने भागों में विभाजित किया है?

14. नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक क्या है?

15. आंग सान सू ने किस देश में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया।

16. उदारवादियों के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ लिखिए।

17. भारतीय राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता की समानार्थी अवधारणा क्या है?

18. ''तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता परन्तु मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा।'' यह कथन किसका है और इसमें किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात कहीं गई है?

19. स्वतंत्रता संबंधी नेताजी सुभाष चन्द्र जी के विचार क्या है?

20. 'स्वराज' शब्द से क्या अभिप्राय है?

21. स्वतंत्रता की एक विशेषता का वर्णन कीजिए?

22. लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य के बारे में क्या कहा था?

23. सलमान रुश्दी की .... पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया गया?

24. निम्नलिखित में से स्वतंत्रता की रक्षा के कौन-कौन से उपाय हैं?

    (क) कानून का शासन (ख) आर्थिक समानता

    (ग) जागरूक जनमत (घ) उपरोक्त सभी

25. कथन को सही करके लिखेंः गरिमामय जीवन जीने के लिए भय मुक्त होना जरूरी नहीं है।

26. प्रतिबंधों के निम्नलिखित स्रोत हैंः

    (क) कल्याणकारी राज्य

    (ख) प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण हो

    (ग) बलपूर्वक व कानून के माध्यम से

    (घ) सामाजिक असमानता तथा सभी

27. राज्य का किसी व्यक्ति के कार्यों में इच्छा के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य किसी को हानि से बचाना होता है। (सही/गलत बताइये)

28. 'हानि के सिद्धांत' का संबंध हैः

    (क) प्लेटो (ख) अरस्तु

    (ग) जे एस मिल (घ) कार्ल माक्र्स

दो अंकीय प्रश्नः-

1. व्यक्तिगत स्वतंत्रता से आप क्या समझते है?
2. राजनीतिक स्वतंत्रता पर अपने विचार प्रकट कीजिए?
3. राष्ट्रीय स्वतंत्रता पर अपने विचार दीजिए?
4. नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ बताइए?
5. आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ स्पष्ट कीजिए?
6. स्वतंत्रता से आपका क्या अभिप्राय है?
7. फिल्म निर्माता दीपा मेहता को काशी में विधवाओं पर फिल्म बनानें से किस आधार पर रोका गया? यह किस स्वतंत्रता का उल्लंघन था?

चार अंकीय प्रश्नः-

1. नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या अंतर है?
2. सामाजिक प्रतिबंधों से क्या अभिप्राय है? क्या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है?
3. स्वतंत्रता के चार लक्षणों का वर्णन करो?
4. जॉन स्टुअर्ड मिल के 'हानि सिद्धान्त' का वर्णन करो?

अवतरण आधारित प्रश्नः-

1. निम्नलिखित अवतरण को पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिएः

   सकारात्मक स्वतंत्रत के पक्षधरों का मानना है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्रत हो सकता है, समाज से बाहर नहीं और इसलिए वह समाज को ऐसा बनाने का प्रयास करते है जो व्यक्ति के विकास का रास्ता साफ करें। दूसरी ओर नकारात्मक स्वतंत्रता का सरोकार अहस्तक्षेप के अनुलंधनीय क्षेत्र से है, इस क्षेत्र से बाहर समाज की स्थितियों से नही। नकारात्मक स्वतंत्रता अहस्तक्षेप के इस छोटे क्षेत्र का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहेगी। हालांकि ऐसा करने में वह समाज के स्थायित्व को ध्यान रखेगी। आमतौर पर दोनों तरह की स्वतंत्रताएं साथ-साथ चलती है और एक-दूसरे का समर्थन करती है लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि निरंकुश शासन सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्कों का सहारा लेकर अपने शासन को न्यायोचित सिद्ध करने की कोशिश करे।

5.1 सकारात्मक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है?

(A) प्रतिबन्धों का होना | (C) अराजकता

(B) प्रतिबन्धों को न मानने की स्वतंत्रता | (D) सरकार की स्वतंत्रता

5.2 नकरात्मक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है?

(A) राज्य की संप्रभुत्ता | (C) सबकी मनमानी

(B) आपसी सामन्जस्य | (D) प्रतिबन्धों का अभाव

5.3 क्या दोनों स्वतंत्रताएं आमतौर पर साथ-साथ चलती हैं ('हाँ' अथवा 'ना')

(A) हाँ | (B) ना

5.4 सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधरों का मानना है कि व्यक्ति केवल-में ही स्वतंत्र हो सकता है ।

(A) घर में | (C) समाज में

(B) देश में | (D) कार्यस्थल में

छः अंकीय प्रश्नः-

1. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे? उदाहरण सहित बताइये।

2. हमें प्रतिबंधों की आदत को विकसित क्यों नहीं होने देना चाहिए? ऐसा आदत किस प्रकार से स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकती है? व्याख्या कीजिए।

उत्तरमाला

1. (B) कथन व कारण दोनों सही हैं, कारण, कथन की सही व्याख्या कर रहा है।
2. (C) लैटिन
3. (B) प्रतिबन्धों का अभाव।
4. (A) प्रतिबन्धों के साथ स्वतंत्रता
5. (D) पूर्ण स्वतन्त्रता
6. (C) नकारात्मक तथा सकारात्मक
7. (D) उपरोक्त सभी
8. (A-iii) (B-iv) (C-i) (D-v) (E-ii)
9. अगर स्वतंत्रता पर प्रतिबंध न होंगे तो समाज अव्यवस्था की गर्त में पहुंच जाएगा। लोगों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
10. कानून द्वारा, बल के आधार पर,
11. एक ऐसा क्षेत्र जिसमें व्यक्ति अबाधित रूप से व्यवहार कर सके।
12. आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना तथा प्रतिभा का विकास करना।
13. दो भागों में - स्वसंबद्ध कार्य, परसबंद्ध कार्य
14. 'लॉग वाक टू फ्रीडम' (स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा)
15. म्यांमार में
16. उदारवादियों के अनुसार स्वतंत्रता का केन्द्र बिंदु व्यक्ति है। व्यक्ति को अधिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता पर बल तथा राज्य की कल्याणकारी भूमिका को बढ़ावा देना।
17. स्वराज की अवधारणा।
18. यह कथन 'वाल्तेयर' का है और इसमें 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता'की बात कही गयी है।

19. ऐसी सर्वांगीण स्वतंत्रता से है- जो व्यक्ति और समाज की हो, अमीर और गरीब की हो, स्त्रियो और पुरूषों की हो तथा सभी लोगों और सभी वर्गों की हो।

20. स्वराज का अर्थ 'स्व' का शासन भी हो सकता है और 'स्व' के उपर शासन भी हो सकता है। स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं है बल्कि ऐसी संस्थाओं से मुक्ति भी है, जो मनुष्य को उसकी मनुष्यता से वंचित करती है।

21. उचित बंधनों का होना।

22. ''स्वाराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा''।

23. 'द सेटानिक वर्सेस'

24. उपरोक्त सभी

25. गरिमामय जीवन जीने के लिए भय मुक्त होना जरूरी है।

26. सामाजिक असमानता तथा सभी।

27. सही

28. (ग) जे एस मिल

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तरः-

1. मनुष्यों का व्यक्तिगत मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्रता होनी चाहिए। भोजन, वस्त्र, शादी-विवाह, रहन-सहन आदि मामलों में राज्य को दखल नहीं देना चाहिए।

2. राज्य के नागरिकों को-
   - अपनी सरकार में भाग लेना।
   - मताधिकार का प्रयोग करना।
   - चुनाव लड़ना आदि।

3. राष्ट्र को विदेशी नियंत्रण से स्वतंत्रता प्राप्त होती है। एक स्वतंत्र राष्ट्र ही अपने नागरिकों को अधिकार तथा स्वतंत्रता प्रदान कर सकता है। जिससे नागरिकों अपना सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक तथ राजनैतिक विकास कर सके।

4. एक व्यक्ति को किसी राज्य का नागरिक होने के कारण मिलती है। ऐसी स्वतंत्रता को राज्य के माध्यम से दिया जाता है। राज्य के संरक्षण में ही व्यक्ति इस स्वतंत्रता का प्रयोग अपने विकास के लिए करता है, बिना किसी की स्वतंत्रता को बाधित किए हुए।

5. - अपनी रूचि व योग्यातानुसार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता।
   - देश में उद्योग-धंधों को चलाने की स्वतंत्रता।
   - धन का उत्पादन व वितरण ठीक ढंग से हो।
   - बेरोजगारी न हो।

6. स्वतंत्रता से अभिप्राय व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है। इसका आशय व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना भी है, जिसमें व्यक्ति की रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास हो सकें।

7. - भारत की दशा का बुरा चित्रण होना।
   - विदेशी पर्यटकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
   - काशी नगरी की बदनामी होना।

   यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन था।

चार अंकीय प्रष्नों के उत्तरः-

1. नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ उस स्वतंत्रता से है जिनके अंतर्गत व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कार्य करता है। हॉब्स के अनुसार ''ऐसी स्वतंत्रता का अर्थ है- सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव।'' जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता नियमों, उपनियमों तथा कानूनों के अंतर्गत प्राप्त स्वतंत्रता। संक्षेप में कहा जाए तो नकरात्मक स्वतंत्रता के समर्थक राज्य के कम से कम हस्तक्षेप के पक्ष में थे ताकि मनुष्य पर किसी प्रकार का नियंत्रण न हो जबकि सकरात्मक स्वतंत्रता के पोषक राज्य को अधिक से अधिक कार्य देने के पक्ष में हैं। उनके अनुसार इससे व्यक्तियों पर नियंत्रण नहीं होता बल्कि राज्य व्यक्तियों के विकास के लिए उचित परिस्थितियों को प्रदान करता है।

   नकारात्मक स्वतंत्रता पूर्ण स्वतंत्रता है जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता नियंत्रित स्वतंत्रता है।

नकारात्मक स्वतंत्रता में सभी प्रकार के बंधनों का अभाव होता है जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता में अनुचित बंधनों का अभाव तथा उचित बंधनों का अस्तित्व है।

नकारात्मक स्वतंत्रता 18वीं तथा 19वीं शताब्दियों की स्वतंत्रता है जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता वर्तमान शताब्दी की स्वतंत्रता है।

नकारात्मक स्वंतत्रता में एक व्यक्ति कुछ कह सकता है, परन्तु सकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्ति सीमा में रहकर ही कुछ कर सकता है।

2. सामाजिक प्रतिबंध - सामाजिक प्रतिबंध का आषय है कि समूह, समुदाय या राज्य के द्वारा व्यक्ति को चयन, निर्णय या काम करने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना है। ऐसे प्रतिबंध जो जरूरी हों, जिनसे व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित हो। बिना प्रतिबंधों के स्थिति अराजकता की हो जाएगी, अव्यवस्था की स्थिति हो जाएगी।

   सभी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक नहीं है। जो प्रतिबंध जोर-जबरदस्ती यानी बलपूर्वक लगाए जाते हैं, जिसमें शासक वर्ग के हितों की पूर्ति हो, वे प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक नहीं, हैं जैसे- तानाशाही शासन व्यवस्था में। जबकि लोकतांत्रिक देशों में सरकार द्वारा लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रतिबंध लगाना लोगों को उचित परिस्थितियाँ देना है। अतः वह सामाजिक प्रतिबंध जो व्यक्ति को चयन, निर्णय या काम करने की स्वतंत्रता देता है, स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। वे प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक हैं जो व्यक्तिगत समूहों तथा राष्ट्र के बीच के संबंधों पर लागू होते हैं।

3. स्वतंत्रता के लक्षण निम्नलिखित हैं-

   (i) स्वतंत्रता सभी व्यक्तियों को समान रूप से मिलती है।

   (ii) करने योग्य कार्य को करने की शक्ति ही स्वतंत्रता है।

   (iii) स्वतंत्रता नियंत्रण से मुक्ति ही नहीं दिलाती बल्कि व्यक्तित्व के विकास के अवसर प्रदान करती है।

   (iv) स्वतंत्रता समाज में मिल सकती है, समाज के बाहर नहीं।

   (v) स्वतंत्रता का प्रयोग समाज के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है।

4. सिद्धान्त यह है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देष्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। अतः हानि पहुँचाने वाले कार्यो पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसे ही हानि का सिद्धान्त कहते हैं।

अवतरण आधारित प्रश्न के उत्तर

5.1 (A) प्रतिबन्धों का होना

5.2 (D) प्रतिबन्धों का अभाव

5.3 (A) हाँ

5.4 (C) समाज में

छः अंकीय प्रश्नों के उत्तर:-

1. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता - अपने विचारों को प्रकट करने की आजादी ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। व्यक्ति अपने विचारों को कहकर, लिखकर या किसी माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध हैं। कोई भी स्वतंत्रता बंधनों के अभाव में नहीं रह सकती। प्रतिबंधों के कारण ही लोगों की स्वतंत्रता कायम रह सकती है। यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करता है परन्तु वह किसी व्यक्ति का अपमान नहीं कर सकता या किसी को अपशब्द नहीं कह सकता। व्यक्ति अपनी इच्छानुसार स्वतंत्रतापूर्वक कार्य तो कर सकता है परन्तु वह अपनी मनमानी नहीं कर सकता। परन्तु राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह देष की अखण्डता, सुरक्षा, शांति, नैतिकता आदि को ध्यान में रखते हुए इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है।"

   राज्य यह भी ध्यान रखता है कि प्रतिबंध इतने भी न हो कि स्वतंत्रता ही नष्ट हो जाए। लोकतांत्रिक राज्यों में सरकार लोगों का स्वतंत्रता की रक्षक हैं।

2. विद्यार्थी स्वयं अपने विवेक से उत्तर देंगे।

अध्याय-13

समानता

- समानता
  - बिना भेदभाव के सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना
    - समानता के प्रकार
      - राजनीतिक समानता → सभी को समान नागरिकता, मतदान का अधिकार
      - आर्थिक समानता → सबको समान अवसर उपलब्ध कराना
      - सामाजिक समानता → समाज में सभी लोगों को निवार्य या बुनियादी जरूरतों उपलब्ध कराना

- समानता को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है
  - विभेदक बर्ताव द्वारा समानता → विशेष आवश्यकताओं वालों लोगों को विशेष सुविधाएं देना जैसे दिव्यांगों के लिए विद्यालयों में रेम्प बनाना
  - सकारात्मक कार्यवाही → असमानता की खाई को कम करने के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाना, जैसे–SC/ST के लिए छात्रवृति, आरक्षण

मुख्य बिन्दुः

- समानता का महत्व।
- समानता क्या है?
- समानता के विभिन्न आयाम।
- हम समानता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं?

समानता का महत्व (महत्वपूर्ण क्यों?)

समानता मौलिक अधिकारों में अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है। समानता का दावा है कि समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और सम्मान के अधिकारी है। यही धारणा सार्वभौमिक मानवाधिकार की जनक भी है। मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए भी समानता अत्यंत महत्वपूर्ण है।

समानता क्या है?

सबके साथ बराबरी अर्थात एक जैसा व्यवहार करना बिना किसी भेद-भाव के।

सबको विकास के समान अवसर प्रदान करना तथा विशेष अधिकारों का अभाव ही वास्तव में समानता है।

- अनेक देशों के कानूनों में समानता को शामिल किए जाने के बावजूद भी समाज में धन, सम्पदा, अवसर, कार्य, स्थिति व शक्ति की भारी असमानता नजर आती हैं।
- समानता के अनुसार, व्यक्ति को प्राप्त अवसर या व्यवहार, जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होने चाहिए।

  अवसरों की समानता सभी मनुष्य अपनी दक्षता और प्रतिभा को विकसित करने के लिए तथा अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समान अधिकार और अवसरों के हकदार हैं।

प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं

- प्राकृतिक समानताएंलोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं और प्रतिभाओं के कारण तथा समाज जनित असमानताएं अवसरों की असमानता व शोषण से पैदा होती हैं।
- प्राकृतिक असमानताएंलोगों कीजन्मगत विशेषताओं और योग्यताओं का परिणाम मानी जाती है माना जाता है कि इन्हें बदला नहीं जा सकता।
- सामाजिक असमानताएं वह हैं जिनको समाज ने बनाया है इनको बदला जा सकता है।

समानता के तीन आयाम:-

राजनीतिक समानता - सभी नागरिकों को समान नागरिकता प्रदान करना राजनीतिक समानता में शामिल है। समान नागरिकता अपने साथ मतदान का अधिकार संगठन बनाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि का अधिकार भी लाती है।

- **समाजिक समानता-** राजनीतिक समानता व समान अधिकार देना इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम था साथ ही समाज में सभी लोगों के जीवनयापन के लिये अनिवार्य चीजों के साथ पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, पोषक आहार व न्यूनतम वेतन की गारण्टी को भी जरूरी माना गया है। समाज के वंचित वर्गों और महिलाओं को समान अधिकार दिलाना भी राज्य की जिम्मेदारी होगी।
- **आर्थिक समानता -** आर्थिक समानता का लक्ष्य धनी व निर्धन समूहों के बीच की खाई को कम करना है यह सही है कि किसी भी समाज में धन या आमदनी की पूरी समानता शायद कभी विद्यमान नहीं रही किंतु लोकतांत्रिक राज्य समान अवसर की उपलब्धि कराकर व्यक्ति को अपनी हालत सुधारने का मौका देती हैं।
- असमानता और विशेषाधिकारों की समाप्ति करके समानता की स्थापना का प्रयास किया गया है।
- विभेदक बर्ताव अर्थात लोगों के बीच अंतर को ध्यान रखकर कुछ विभेदक बर्ताव (आरक्षण) की नीति बनाई गई है जिससे समाज के सभी वर्गों की अवसरों तक समान पहुंच हो सके। कुछ देशों में इसे सकारात्मक कार्यवाही की नीति का नाम दिया गया है।
- समाजवाद व मार्क्सवाद के अनुसार आर्थिक असमानताएं सामाजिक रूत्वे या विशेषाधिकार जैसी असमानाताओं को बढ़ावा देती है इसीलिए समान अवसर से आगे जाकर आर्थिक संसाधनों पर निजी स्वामित्व न होकर जनता का नियंत्रण सुनिश्चित करने की जरूरत है।

  उदारवादी समाज में संसाधनों के वितरण के मामले में प्रतिद्वंद्विता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं और राज्य के हस्तक्षेप को अनिवार्य समझते है।
- स्त्रियों द्वारा समान अधिकारों के लिए संघर्ष मुख्यतः नारीवादी आंदोलन से जुड़ा है। मातृत्व अवकाश जैसे विशेषाधिकार नारी समाज के लिये अत्यंत आवश्यक हैं।
- विभेदक बर्ताव या विशेषाधिकार का उद्देश्य न्यायपरक व समानता मूलक समाज को बढ़ावा देना है समाज में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को फिर से खड़ा करना नहीं है।

समानता के प्रमुख प्रकारः

- प्राकृतिक समानता
- नागरिक समानता
- सामाजिक समानता कानूनी समानता
- राजनीतिक समानता
- आर्थिक समानता
- शिक्षा की समानता
- अवसर की समानता
- सांस्कृतिक समानता आदि

हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं?

- औपचारिक समानता की स्थापना करके।
- सरकार और 'कानून' द्वारा असमानता की व्यवस्था को संरक्षण देना बंद करके।
- विशेष अधिकारों की औपचारिक व्यवस्था को भी समाप्त करना होगा।
- दुनिया भर में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक असमानता स्थापित करने वाली कानूनी व्यवस्था और रीति-रिवाजों को समाप्त करना होगा।
- महिलाओं को बहुत सारे व्यवसाय और गतिविधियों में भाग लेने की इजाजत दे कर।

विभेदक बर्ताव द्वारा समानता।

समानता के सिद्धांत को यथार्थ में बदलने के लिए औपचारिक समानता या कानून के समक्ष समानता आवश्यक तो है लेकिन पर्याप्त नहीं कभी-कभी यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोग समान अधिकारों का उपयोग कर सकें उनसे अलग-अलग बर्ताव करना जरूरी हो जाता है। उदाहरण के लिए दिव्यागों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए उनके साथ बर्ताव बनाया जाता है।

सकारात्मक कार्यवाही कार्यवाई

जो कानून बना दिए गए हैं उन्हें सही रूप में लागू करना । असमानता की गहरी खाई को भरने के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए।

दलित, वंचित समुदायों, महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति तथा होस्टल जैसी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए ।

नौकरियों तथा शिक्षण संस्थानों में सभी वर्गों के लिये विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए।

विशेष सहायता को उपलब्ध कराने हेतु राज्य अर्थात सरकार को समानता लाने वाली सामाजिक नीतियां बनानी चाहिए।

प्रश्नावली

एक अंकीय प्रश्नः-

1. कथनः कानून के समक्ष समानता भारत के राष्ट्रपति पर लागू नहीं होती है।

   कारणः भारत के राष्ट्रपति को संविधान के तहत विशेष शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त हैं।

   (A) कथन और कारण दोनों सही है, कारण, कथन की सही व्याख्या कर रहा है।

   (B) कथन सही, कारण गलत है।

   (C) थन और कारण दोनेां सही हैं, कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है।

   (D) दोनों गलत हैं।

2. समानता के तीन प्रमुख आयाम हैं?

   (A) राजनीतिक समानता

   (B) आर्थिक समानता

   (C) सामाजिक समानता

   (D) उपरोक्त सभी

3. '''पुरुष', 'स्त्री' से शक्तिशाली है''। यह किसका उदाहरण है?

   (A) सामाजिक असमानता का

   (B) अवसर की समानता का

   (C) शैक्षिक असमानता का

   (D) आर्थिक असमानता का

4. धर्म, जन्म, भाषा, जाति आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना होना कहलाता है?

   (A) नैतिक समानता

   (B) राजनीतिक समानता

   (C) सामाजिक समानता

   (D) इनमें से कोई नहीं

5. न्यूनतम आवश्यकतआं की पूर्ति से अभिप्राय है किः

   (A) सामाजिक समानता

   (B) आर्थिक समानता

   (C) प्राकृतिक समानता

   (D) सांस्कृतिक समानता

6. सभी व्यवस्कों को बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार किस समानता में आता है?

   (A) राजनीतिक समानता

   (B) धार्मिक समानता

   (C) शैक्षिक समानता

   (D) अवसर की समानता

7. समानता का महत्व लिखिए।
8. क्या समानता का मतलब व्यक्ति से हर स्थिति में समान बर्ताव करना है?
9. 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था?
10. क्या समाज मे समानता के साथ-साथ असमानता अधिक नजर आती है?
11. भारतीय समाज में व्याप्त एक साधारण असमानता का उल्लेख कीजिए?
12. नारीवाद से आप क्या समझते है?
13. वंचित समूहों से क्या अभिप्राय है?

14. समानता भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है?

    (क) 19 से 22 (ख) 14 से 18

    (ग) 10 से 12 (घ) इनमें से कोई नहीं

15. भारत सरकार ने विकलांगता अधिनियम किस वर्ष में पास किया?

    (क) 1975 (ख) 1875

    (ग) 1895 (घ) 1995

16. कथन को सही करके लिखेंः

    समानता के तीन आयाम, सांस्कृतिक समानता, आर्थिक समानता व नैतिक समानता है।

17. सही वह गलत का निशान लगाएः

    1. सबके साथ बराबरी अर्थात एक जैसा व्यवहार की समानता है। ( )

    2. सबको विकास के समान अवसर प्रदान करना समानता है। ( )

    3. विशेष अधिकारों का अभाव ही वास्तव में समानता है। ( )

    4. जैसा जो चाहे वैसा करने के लिए स्वतंत्र होना ही समानता है। ( )

18. मनुष्य के .... विकास के लिए भी समानता अत्यंक महत्वपूर्ण है।
19. समानता को बढ़ावा देने वाले कोई दो कारक लिखिए।
20. किसी एक असमानता को लिखिए जो आपने स्वयं अनुभव की हो।
21. क्या आर्थिक असमानता समाप्त करना संभव है? यदि हां तो किस प्रकार से?

दो अंकीय प्रश्नः-

1. न्यायपूर्ण व अन्यायपूर्ण असमानता से आप क्या समझते है?
2. आर्थिक समानता का अर्थ लिखिये।
3. समानता के आदर्श से क्या तात्पर्य है?
4. कुछ विभिन्नताएं जन्मजात न होकर भी जन्मजात बना दी गई है? इस संबंध में अपने विचार लिखिये।
5. प्राकृतिक व समाज-जनित असमानताओं से आप क्या समझते है?
6. क्या हमारा समाज समानता पर आधारित समाज का उदाहरण हो सकता हैं?

7. क्या आपके अनुसार सामाजिक समानता भारत में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है? क्यों?
8. मार्क्सवाद से आप क्या समझते है?
9. समाजवाद की अवधारणा समझते हुए भारत के प्रमुख समाजवादी चिंतक का नाम बताइये।
10. ''विभेदक बर्ताव (आरक्षण) समानता स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है'' कैसे?

चार अंकीय प्रश्नः-

1. "क्या प्राकृतिक विभिन्नताएं सदैव अपरिवर्तनीय होती है? इस सम्बन्ध में अपने विचार उदाहरण के साथ लिखिये।
2. मार्क्सवाद व उदारवाद में समानता की अवधारण को ध्यान में रखकर अंतर स्पष्ट कीजिए।
3. हम समानता को बढ़ावा किस प्रकार दे सकते है?
4. "राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता के बिना धोखा मात्र है"। प्रयुक्त वाक्य को ध्यान में रखकर अपने विचार प्रकट कीजिये।
5. संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल के आधार पर असमानता से निपटने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये? क्या यह कारगर सबित हुए।
6. "एक अध्यापक और एक फैक्ट्री मजदूर के वेतन के अंतर को आप असमानता मानते है"। यदि नही तो क्यों?
6. अवतरण आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिये।

   समानता के उद्देश्य से जुड़े बहुत से मुद्दे नारीवादी आंदोलनों द्वारा उठाए गए। उन्नीसवीं सदी में स्त्रियों ने समान अधिकरों के लिए संघर्ष किया। उदाहरण के लिए उन्होंने मताधिकार, कॉलेज-यूनिवर्सिटी में डिग्री पाने का अधिकार और काम के लिए अधिकार की उसी प्रकार मांग की जैसे अधिकार पुरूषों को हासिल थे। हालांकि जैसे ही उन्होंने नौकरियों में प्रवेश किया उन्हें महसूस हुआ कि स्त्रियों को इन अधिकारों को उपयोग में लाने के लिए विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए उन्हें मातृत्व अवकाश और कार्यस्थल पर बालवाड़ी जैसे प्रावधानों की आवश्यकता थी। इस प्रकार के विशेष बरताव के बिना वे न तो गंभीरतापूर्वक स्पर्धा में भाग ले सकेंगी और न ही सफल व्यवसायिक और निजी जीवन का आनंद उठा सकेंगी दूसरे शब्दों में पुरूषों के समान अधिकारों के उपयोग के लिए उन्हें कई बार एक विशेष बरताव की जरूरत होती थी।

7.1. नारीवाद से क्या तात्पर्य है?

(A) महिला अधिकारों पर बल देना (B) महिला-पुरुष समानता स्थापित करना

(C) महिला सशक्तिकरण (D) उपरोक्त सभी

7.2. पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त होने के बावजूद महिलाओं को विशेषाधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी?

(A) महिलाओं की वंचित स्थिति के कारण

(B) राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्र में न्यून महिला भागीदारी के कारण

(C) (A) तथा (B) दोनों

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

7.3 महिलाओं को दिया गया विशेषाधिकार समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है या नहीं?

(i) हां (ii) नहीं

7.4 उपरोक्त गद्यांश सिद्धांत किस विषय से संबंधित है?

(A) महिलाओं से (B) पुरुषों से

(C) बच्चों से (D) संपूर्ण समाज से

छः अंकों वालों प्रश्नः

1. "मानव जीवन के सम्मानपूर्वक संचालन के लिये समानता आवश्यक व अनिवार्य है"। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए समानता के तीनों आयामों पर प्रकाश डालिये।
2. क्या विभेदक बर्ताव (आरक्षण) समानता की विरोधी अवधारणा है? आपके अनुसार इस सम्बंध में क्या सुझाव या सुधार होने चाहिये।

उत्तरमाला

एक अंकीय उत्तर

1. A- कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण, कथन की सही व्याख्या कर रहा है।
2. D- उपरोक्त सभी
3. A - सामाजिक असमानता का
4. C- सामाजिक समानता

5. B-आर्थिक समानता

6. A- राजनैतिक समानता

7. समानता के कारण सभी व्यक्ति महत्व व सम्मान के अधिकारी है। इसी धारणा ने सर्वभौमिक मानावधिकार जैसी धारणा को जन्म दिया।

8. नहीं वरन व्यक्ति की प्रतिभा व क्षमताओं को ध्यान में रखकर अवसर की समानता मुहैया कराना है।

9. स्वतंत्रता, समानता व भाईचारा।

10. हाँ। आलीशान कॉलोनियों के साथ झुग्गियां भोजन की बर्बादी के साथ भुखमरी समाज में आसानी से देखी जा सकती है।

11. स्त्री पुरूष असमानता जिसके चलते कन्या भ्रूण हत्या का पाप समाज में हुआ है।

12. नारीवाद स्त्री पुरूष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत है।

13. लम्बे समय से असमानता व शोषण के शिकार व्यक्ति जिनपर जन्म व जातिगत विभिन्नताओं के चलते अत्याचार होते रहे है।

14. अनुच्छेद (14-18)

15. वर्ष 1995

16. समानता के तीन आयाम राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता व सामाजिक समानता है ।

17. 1. (✓) सही
    2. (✓) सही
    3. (✓) सही
    4. (×) गलत

18. सर्वांगीण

19. 1. औपचारिक समानता की स्थापना करके

2. महिलाओं को बहुत सारे व्यवसाय और गतिविधियों में भाग लेने की इजाजत दे करके।

20. विद्यार्थी अपने अनुभव के आधार पर उत्तर लिखें।

21. अवसर की समानता द्वारा।

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. व्यक्ति के काम के महत्व के आधाार पर असमानता न्यायपूर्ण कहीं का सकती है जैसे देश के प्रधानमंत्री व सेना के जनरल को विशेष दर्जा या सम्मान जबकि व्यक्ति के जन्म व जाति पर आधारित असमानता अन्यायपूर्ण होगी जैसे मंदिर व सार्वजनिक स्थल में प्रवेश पर रोक।

2. अमीर व गरीब के बीच व्याप्त खाई को कम करना तथा अवसरों से समानता की उपलब्धि

3. व्यक्ति को प्राप्त अवसर या व्यवहार जन्म या समाजिक परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होने चाहिए।

4. जब समाज में कुछ विभिन्नताएं लम्बे समय तक विद्यमान रहती है तो वह प्राकृतिक विभिन्नताओं पर आधारित लगने लगती है जैसे प्राचीन समय से ही महिलाओं को अबला व पुरूषों के मुकाबले में डरपोक मानकर उन्हें समान अधिकारों से वंचित करना, न्यायसंगत मान लिया गया था।

5. प्राकृतिक असमानताएं व्यक्तियों की क्षमता व प्रतिभा से जुड़ी होती है जबकि समाजजनित असमानताएं अवसरों की असमानता व शोषण से जुड़ी होती है।

6. यद्यपि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में समानता वर्णित है किंतु फिर भी समाज में अमीर गरीब, स्त्री पुरूष व जातिगत असमानताओं के उदाहरण प्रतिदिन देखने को मिलते है।

7. हां क्योंकि भारतीय समाज जातिगत विभिन्नताओं में बंटा है। जन्म के आधार पर फैली असमानता को समाप्त करने के लिय डॉ. भीम राव अम्बेडकर ने आरक्षण सम्बधी प्रावधानों का जिक्र किया था।

8. सामाजिक व आर्थिक असमानताओं को मिटाने का उपाय निजी स्वामित्व को समाप्त करके आर्थिक संसाधानों पर जनता का स्वामित्व होना चाहिए।

9. समाजवाद का अर्थ असमानताओं को न्यूनतम करके संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा करना है। भारत के प्रमुख समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया।

10. हाँ, क्योंकि समानता व विकास की दौड़ में पीछे रह गई नीतियों को विशेषाधिकारों की आवश्यकता है।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. नहीं! यह परिवर्तनीय हो सकती है चिकित्सा तकनीक व कम्प्यूटर अक्षमता के निराकरण में सहायक हो सकते है। प्रसिद्ध भौतिकविद स्टीफन हॉकिन्स का चलने व न बोल पाने के बावजूद भी विज्ञान में योगदान सराहनीय है।

2. मार्क्सवाद आर्थिक संशोधन पर जनता का नियंत्रण करके समानता की स्थापना करने के प्रयास में विश्वास रखते है जबकि उदारवादी खुली प्रतिस्पर्धा द्वारा सभी वर्गो से योग्य व्यक्तियों को बाहर निकालने में यकीन रखते हैं।

3. विशेषाधिकार वर्ग की समाप्ति तथा विभेदक बर्ताव द्वारा समानता लाने का प्रयास।

4. न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के अभाव में व्यक्ति अपने राजनीतिक अधिकारों के महत्व को नहीं समझ सकता जिससे राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।

5. 1964 में Civil Right Act सरकार द्वारा पास किया गया जिसमें रंग, नस्ल व धर्म के आधार पर समानता की स्थापना का प्रयास था। एक अश्वेत व्यक्ति बराक हुसैन ओबामा अमेरिका के सबसे गरिमा मय पद पर दो बार आसीन हो चुके हैं। जो रंगभेद की नीति को नकारे जाने का उदाहरण है किंतु फिर भी समाज में समय -समय पर अश्वेतों के विरूद्व हिंसा की गूंज सुनाई पड़ जाती है।

6. समानता के अनुसार समान कार्य का समान वेतन होना चाहिए था कार्य बौद्विक व शारीरिक अलग अलग है।

7 (7.1) B. महिला-पुरुष समानता

(7.2) C. A तथा B दोनों

(7.3) B. नहीं

(7.4) A. महिलाओं से

छः प्रश्नीय अंकों के उत्तर

1. (1) राजनीतिक समानता (व्याख्या सहित)

   (2) सामाजिक समानता (व्याख्या सहित)

   (3) आर्थिक समानतानहीं (व्याख्या सहित)

2. -आरक्षण की अवधारणा समानता के विरुद्ध नहीं है। यह तो समानता की स्थापना के लिए आवश्यक है। लंबे समय शोषण व पीड़ित बिना विशेषाधिकार व आरक्षण के विकास के दौड़ में साथ नहीं आ सकते थे।

   -आरक्षण न केवल जातीय जन्म के आधार पर अपितुआर्थिक, शैक्षिक पिछड़ेपन आदि के आधार पर भी होना चाहिए

अध्याय-14

सामाजिक न्याय

''न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करें।–डॉ. बी आर अंबेडकर	सामाजिक न्यायः व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन को व्यवस्थित करने के नियम और तरीके, सामाजिक लाभ और सामाजिक कर्तव्यों का उचित बंटवारा सामाजिक न्याय कहलाता है।	''न्याय में ऐसा कुछ अंतर्निहित है जिसे करना न सिर्फ सही है और न करना सिर्फ गलत, बल्कि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष हमसे दावा जता सकता है।'' –जे.एस.मिल

न्याय के सिद्धांत

1. समान लोगों के प्रति समान बर्ताव
2. समानुपातिक न्याय
3. विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल

न्यायपूर्ण बंटवाराः नियम कानूनों को निष्पक्षता से लागू करवाना तथा वस्तुओं और सेवाओं का न्यायोचित बंटावारा।

जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांतः तर्क-1: निष्पक्ष और न्याय संगत नियम यह है कि यदि हम खुद को ऐसी स्थिति में होने की कल्पना करते हैं जिसमें हमें यह निर्णय लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाना चाहिए अर्थात ''अज्ञानता के आवरण में सोचना।''

तर्क-2: नैतिकता नहीं बल्कि विवेकाशील चिंतन हमें समाज में लाभ और भार के वितरण के मामले में निष्पक्ष होकर विचार करने की ओर प्रेरित करता है।

सामाजिक न्याय का अनुसरणः समाज में व्याप्त अमीर और गरीब के बीच स्थाई विभाजन को समाप्त करना।

मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेपः

1. समर्थकों का मानना है कि यदि बाजारों को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त छोड़ दिया जाए तो बाजार के लेनदेन का योग समाज में लाभो और कर्तव्यों के समग्र वितरण को सुनिश्चित करेगा। हालांकि कुछ समर्थक राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार करते हैं ताकि समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा हो सके।
2. निजी एजेंसियों को सेवाएं मुहैया कराने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। राज्य की नीतियां इन सेवाओं को खरीदने के लिए लोगों को सशक्त बनाने की कोशिश करें।

मुख्य बिन्दुः

1. न्याय क्या है?
2. न्याय के विभिन्न आयाम
3. सामाजिक न्याय की स्थापना के तीन सिद्धांत
   (i) समान लोगों के प्रति समान बरताव।
   (ii) समानुपातिक न्याय।
   (iii) विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल।
4. न्यायपूर्ण बंटवारा
5. रॉल्स का न्याय सिद्धांत
6. सामाजिक न्याय का अनुसरण
7. मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप
8. भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए उठाये गए कदम।
   - न्याय का संबंध हमारे जीवन व सार्वजनिक जीवन से जुड़े नियमों से होता है। जिसके द्वारा सामाजिक लाभ, कर्तव्यों का बंटवारा किया जाता है।
   - प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुडा था, जिसकी स्थापना राजा का परम कर्तव्य था।
   - चीनी दार्शनिक कन्फ्युशियस के अनुसार गलत करने वालों को दण्डित व भले लोगों को पुरस्कृत करके न्याय की स्थापना की जानी चाहिये।

- प्लेटों ने अपनी पुस्तक 'द रिपब्लिक' में न्याय की चर्चा की है।
- सुकरात के अनुसार यदि सभी अन्यायी हो जायेगे तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा।
- साधारण शब्दों में हर व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना न्याय है।
- जर्मनी दार्शनिक इमैनुएल के अनुसार हर व्यक्ति का प्राप्य उसकी प्रतिभा या विकास के लिये अवसरों की प्राप्ति है।

न्याय क्या है?

न्याय का अर्थ-न्याय को अंग्रेजी भाषा में ''जस्टिस'' (JUSTICE) कहा जाता है। ''जस्टिस'' (JUSTICE) लेटिन भाषा के शब्द jus सेबना है, जिसका अर्थ है-''बंधन'' या ''बांधना'' (Bouind or Tie) इसका अर्थ है कि ''न्याय'' उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से जुड़ा होता है। अतः न्याय समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के उसका ''उचित'' हक देने से संबंध रखता है।

प्लेटो के अनुसार-''न्याय वह गुण है जो अन्य गुणों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है।''

न्याय के विभिन्न आयाम

1. **विधिक न्याय:** यह न्याय की एक संकीर्ण अवधारणा है तथा समाज में विधिक प्रक्रिया के रूप में विद्यमान है। कोर्ट ऑफ लॉ विधि की व्याख्या करता है तथा विवाद में सम्मिलित वादियों के पक्ष विपक्ष सुनने के पश्चात इसे अधिनियमित करता है। यहां, न्याय विधि न्यायालय द्वारा प्रशासित है तथा न्यायाधीश की व्याख्या को न्याय का प्रतीक माना जाता है।

2. **राजनीतिक न्यायः** किसी भी लोकतांत्रिक समाज में राजनीतिक न्याय का अर्थ है समान राजनीतिक अधिकारों को प्रेरित करना। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक क्षेत्र में लोगों की स्वतंत्र तथा निष्पक्ष सहभागिता के लिए है। सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार राजनीतिक न्याय की अभिव्यक्ति है। सार्वजनिक कार्यालयों में निर्वाचित होने के लिए अवसर की समानता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता राजनीतिक न्याय के महत्वपूर्ण स्तंभ है।

3. **सामाजिक न्यायः** इसका अर्थ है सभी प्रकार की सामाजिक विषमताओं को समाप्त करना तथा जीवन के समस्त क्षेत्रों में प्रत्येक नागरिक को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा समान

राजनीतिक अधिकारों का प्रावधान करना। सामाजिक न्याय की अवधारणा इस विश्वास पर आधारित है कि सभी मनुष्य समान हैं तथा उनसे जाति, धर्म, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

4. **आर्थिक न्यायः** इसका अर्थ है सभी को जीवन यापन के लिए समान अवसर प्रदान करना। इसका आज से ऐसे लोगों की सहायता करना भी है, जो कार्य करने तथा अपनी जीविका अर्जित करने में सक्षम नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की मौलिक आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, आश्रय तथा शिक्षा की पूर्ति होनी चाहिए। यह समान कार्य के लिए समान वेतन, समान आर्थिक अवसर, संसाधनों का उचित वितरण आदि प्रावधानों के माध्यम से आजीविका के पर्याप्त साधनों का आश्वासन देता है।

   जहां राजनीतिक न्याय की अवधारणा स्वतंत्रता के आदर्श के साथ घनिष्ठ रूप से संबंद्ध है, वहीं आर्थिक व कानूनी न्याय ''समानता'' तथा सामाजिक न्याय ''भ्रातृत्व'' के साथ संबंधित है। इन सभी का संयोजन न्याय के चारों आयामों को प्राप्त करने में सहायक होगा।

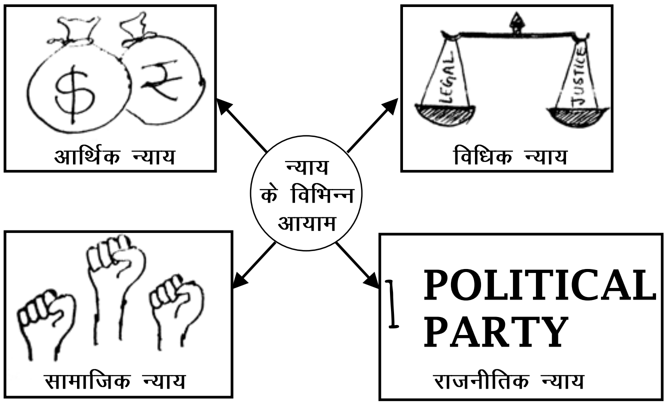

सामाजिक न्याय की स्थापना के तीन सिद्धांतः-

- **समान लोगों के प्रति समान बर्तावः** सभी के लिये समान अधिकार तथा भेदभाव की मनाही है। नागरिकों को उनके वर्ग जाति नस्ल या लिंग के आधार पर नहीं बल्कि उनके काम व कार्यकलापों के आधार पर जांचा जाना चाहिये। अगर भिन्न जातियों के दो व्यक्ति एक ही काम कर रहें हो तो उन्हें समान पारिश्रमिक मिलना चाहिए।

- **समानुपातिक न्यायः** कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हो सकती है जहां समान बर्ताव अन्याय होगा, जैसे परीक्षा में बैठने वाले सभी छात्रों को एक जैसे अंक दिये जायें। यह न्याय नहीं हो सकता अतः मेहनत, कौशल व संभावित खतरे आदि को ध्यान में रखकर अलग-अलग पारिश्रमिक दिया जाना न्याय संगत होगा।

- विशेष जरूरतों का विशेष ख्यालः जब कत्त्र्तव्यों व पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाये तो लोगों की विशेष जरूरतों का ख्याल रखा जाना चाहिए। जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं है उनके साथ भिन्न ढंग से बर्ताव करके उनका ख्याल किया जाना चाहिए।

न्यायपूर्ण बंटवाराः-

- सामाजिक न्याय का अर्थ वस्तुओं और सेवाओं के न्यायपूर्ण वितरण से भी है। यह वितरण समाज के विभिन्न समूहों और व्यक्तियों के बीच होता है ताकि नागरिकों को जीने का समान धरातल मिल सकें, जैसा भारत में छुआछूत प्रथा का उन्मूलन आरक्षण की व्यवस्था तथा कुछ राज्य सरकारों द्वारा उठाये गये भूमि सुधार जैसे कदम है।

रॉल्स का न्याय सिद्धांतः-

- ''अज्ञानता के आवरण'' द्वारा रॉल्स ने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यदि व्यक्ति को यह अनुमान न हो, कि किसी समाज में उसकी क्या स्थिति होगी? और उसे समाज को संगठित करने का कार्य तथा नीति निर्धारण करने को दिया जाये तो वह अवश्य ही ऐसी सर्वश्रेष्ठ नीति बनायेगा, जिसमें 'समाज के प्रत्येक वर्ग को सुविधाएं दी जा सकेगी।

सामाजिक न्याय का अनुसरणः-

- सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए अमीर गरीब के दरम्यान गहरी खाई को कम करना, समाज के सभी लोगों के लिये जीवन की न्यूनतम बुनियादी स्थितियां- आवास, शुद्ध पेयजल, न्यूनतम-मजदूरी, शिक्षा व भोजन मुहैया कराना आवश्यक है।

मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेपः-

- मुक्त बाजार, खुली प्रतियोगिता द्वारा योग्य व सक्षम व्यक्तियों को सीधा फायदा पहुंचाना, ये राज्य के हस्तक्षेप के विरोधी है। ऐसे में यह बहस तेज हो जाती है कि क्या अक्षम और सुविधा विहीन वर्गों की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिये? क्योंकि मुक्त बाजार के अनुसार ये प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते।

भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिये उठाये गये कदमः-

- निशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा।
- पंचवर्षीय योजनाएं।
- अन्तयोदय योजनाएं।
- वंचित वर्गो को आर्थिक सामाजिक सुरक्षा।
- मौलिक अधिकारों में प्रावधान।
- राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रयास।
- प्रधानमंत्री उज्जवला योजना।
- किसान फसल बीमा योजना।
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।

प्रश्नावली

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (एक अंकीय प्रश्न)

1. समस्य समाज को बराबर की अहमियत मिले और प्रतिभा के विकास के लिए समान अवसर मिलने की स्थिति को क्या कहते हैं?

   (a) समानता (b) स्वतंत्रता

   (c) धर्म (d) न्याय

2. प्राचीन भारतीय समाज में न्याय के साथ किसको जोड़कर देखा जाता था?

   (a) शिक्षा (b) धर्म

   (c) संस्कृति (d) समुदाय

3. प्राचीन भारतीय समाज में न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था कायम रखना किसका प्राथमिक कर्तव्य माना जाता था।

   (a) न्यायालय (b) राजा

   (c) मंत्री (d) सेना

4. गलत करने वालों को दंडित और भले लोगों को पुरस्कृत कर राजा को न्याय कायम रखना चाहिए। यह कथन किसका है?

   (a) प्लेटो (b) कन्फ्यूशियस

   (c) सुकरात (d) अरस्तु

5. ''द रिपब्लिक'' पुस्तक के लेखक थे?

   (a) अरस्तु (b) सुकरात

   (c) प्लेटो (d) लॉक

6. निम्न में से कौन सुकरात का शिष्य था?

   (a) अरस्तु (b) लास्की

   (c) रूसो (d) ग्लाउकॉन

7. प्लेटो का संबंध .... से था।

(a) ईरान (b) इराक

(c) यूनान (c) लेबनान

8. यदि एक स्कूल में पुरुष शिक्षक को महिला शिक्षक से ज्यादा वेतन मिलता है, तो यह किस सिद्धांत के विरूद्ध है?

(a) स्वतंत्रता के विरूद्ध

(b) समान लोगों के प्रति समान बर्ताव के विरूद्ध

(c) समकक्षों के साथ समान बर्ताव सिद्धांत के विरूद्ध

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

9. किसी काम कें लिए वांछित मेहनत, कौशल और संभावित खतरे आदि कारकों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग पारिश्रमिक का निर्धारण कहलायेगा?

(a) अन्याय संगत

(b) न्याय संगत

(c) समान लोगों के प्रति समान बर्ताव के विरूद्ध

(d) उपरोक्त में कोई नहीं

10. जिन लोगों में शारीरिक विकलांगता हो, या जिन तक अभी अच्छी शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंची, उनको न्याय किस माध्यम से दिया जा सकता है?

(a) समान लोगों के प्रति समान बर्ताव द्वारा

(b) समानता के अधिकार द्वारा

(c) विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल द्वारा

(d) उपरोक्त सभी

11. भारती संविधान में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के प्रयासः

(a) छुआछुत की प्रथा का उन्मूलन

(b) भूमि सुधार कानून लागू करना

(c) उपरोक्त (a) और (b) दोनों

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

12. भारत में सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए शैक्षिक संस्थाओं में या सरकारी नौकरी में सीट आरक्षण का प्रस्ताव किस आयोग ने दिया था?

(a) सरकारिया आयोग (b) मंडल आयोग

(c) शाह आयोग (d) जैन आयोग

13. सुकरात कौन था?

(a) राजनीतिज्ञ (b) राजा

(c) दार्शनिक (c) अर्थशास्त्री

14. न्याय के सिद्धांत हैं-

(a) समानुपातिक न्याय

(b) समान लोगों के प्रति समान बर्ताव

(c) उपरोक्त (a) और (b) दोनों

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

15. ''न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करें।'' उपरोक्त कथन किसका है?

(a) महात्मा ज्योति राव फूले (b) महात्मा गांधी

(c) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (d) डॉ. बी आर अंबेडकर

16. जॉन रॉल्स ने .... का सिद्धांत दिया।

(a) समानता का (b) न्याय का

(c) संपत्ति का (d) स्वतंत्रता का

17. जहां तक संभव हो व्यक्तियों को संपत्ति अर्जित करने के लिए दूसरों के साथ अनुबंध और समझौतों में शामिल होने के लिए स्वतंत्र रहना चाहिए। उपरोक्त विचार है.....

(a) मुक्त बाजार के समर्थकों का (b) समाजवादियों का

(c) उपरोक्त (a) और (b) दोनों (d) उपरोक्त में से कोई नहीं।

18. समाज में बेहिसाब धन दौलत रखने वालों एवं वंचितों के बीच गहरी खाई किस बात का प्रतीक है?

(a) अवसर का अभाव (b) सामाजिक न्याय का अभाव

(c) समानता का अभाव (d) उपरोक्त कोई नहीं

19. अभिकथनः भारत में सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है।

कारणः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना के साथ-साथ जनसामान्य की भलाई को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।

(a) अभिकरण और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है।

(b) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।

(c) अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है।

(d) अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है।

20. अभिकथनः न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है।

कारणः निष्पक्ष और पारदर्शी न्याय देने के लिए न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है।

(a) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है।

(b) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।

(c) अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है

(d) अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है।

21. न्याय (JUSTICE) शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई?

(a) यूनानी भाषा (b) जापानी भाषा

(c) लेटिन भाषा (c) अरबी भाषा

22. ''न्याय वह गुण है जो अन्य गुणों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है।'' न्याय की यह परिभाषा किसने दी है?

(a) लास्की
(b) प्लेटो
(c) अरस्तु
(d) रूसो

23. ''न्याय पूर्ण कानून का निर्माण'' किस न्याय का पहलू है?

(a) राजनीतिक न्याय
(b) सामाजिक न्याय
(c) आर्थिक न्याय
(d) कानूनी न्याय

24. जॉन रॉल्स ने वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का वर्णन अपनी किस पुस्तक में किया है?

(a) द थ्योरी ऑफ जस्टिस
(b) द रिपब्लिक
(c) द डेमोक्रेसी
(d) द पॉलिटिक्स

25. भारत में पिछड़ों/दलितों के शोषण का उदाहरण किस प्रकार के अन्याय का है?

(a) आर्थिक अन्याय
(b) सामाजिक अन्याय
(c) सामाजिक अन्याय
(d) धार्मिक अन्याय

26. सुकरात ने कहा है कि न्याय ने तमाम लोगों की .... निहित रहती है।

27. सत्य और स्वतंत्रता न्याय के आधारभूत .... में शामिल हैं।

28. वितरणात्मक न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन .... ने किया।

29. भारत के संविधान का अनुच्छेद .... कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा।

30. ''न्याय पूर्ण समाज वह है, जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करें। इस कथन के लेखक कौन है?

31. ''न्याय में ऐसा कुछ अंतर्निहित है, जिसे करना न सिर्फ सही है और न करना सिर्फ गलत, बल्कि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष हमसे दावा जता सकता है।'' इस कथन के लेखक का नाम लिखिए।

32. निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें।

मुक्त बाजार के समर्थकों का मानना है कि जहां तक संभव हो, व्यक्तियों को संपत्ति अर्जित करने के लिए तथा मूल्य, मजदूरी और मुनाफे के मामले में दूसरें के साथ प्रतिद्वंदिता करने की छूट होनी चाहिए। यह मुक्त बाजार का सरल चित्रण है। मुक्त बाजार के समर्थक मानते हैं कि अगर बाजारों को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया जाए, तो बाजारी कारोबार का योग कुल मिलाकर समाज में लाभ और कर्तव्यों का न्याय पूर्ण वितरण सुनिश्चित कर देगा।

बहुविकल्पीय प्रश्नः-

32.1 "मुक्त बाजार" से क्या आशय है?

(A) उद्यमों को प्रोत्साहित करना

(B) उद्यमों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना

(C) उद्यमों को सरकारी नियंत्रण में रखना

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

32.2 बाजारों में अधिक से अधिक लाभ कब प्राप्त किया जा सकता

(A) जब बाजारों पर नीजी क्षेत्र के लिए प्रतिबंध हो

(B) जब बाजारों पर राज्य / सरकार का प्रतिबंध हो

(C) जब बाजारों पर राज्य / सरकार का प्रतिबंध कम से कम होगा

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

32.3 मुक्त बाजार का सरल चित्रण क्या होता है ?

(A) बाजारों को लाभ की अधिकतम मात्रा हासिल करने हेतु

(B) बाजारों को लाभ की न्यूनतम मात्रा हासिल करने हेतु

(C) बाजारों में काम करने वाले मजदूरों को अधिकतम लाभ हो

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

32.4 बाजारों को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त कर देने से क्या लाभ होगा?

(A) बाजारों में दुकानदारों को अधिक नुकसान होगा

(B) बाजारों में वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएगी ।

(C) समाज में लाभ और कर्त्तव्यों का न्यायपूर्ण वितरण होगा

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

33.1 “मुक्त बाजार” से क्या आशय है?

33.2 बाजारों में अधिक से अधिक लाभ कब प्राप्त किया जा सकता हैं?

33.3 मुक्त बाजार का सरल चित्रण क्या होता है?

33.4 बाजारों को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त कर देने से क्या लाभ होगा?

34. निम्नलिखित कथन को सही करके पुनः लिखिए।
प्राचीन भारतीय समाज में न्याय अधर्म के साथ जुड़ा था।

35. निम्नलिखित प्रत्येक कथन के आगे सही अथवा गलत लिखिए–

(i) तमाम संस्कृतियों और परंपराओं को न्याय के प्रश्न से जूझना पड़ा है। [ ]

(ii) प्लेटों ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की है। [ ]

(iii) न्याय के लिए जरूरी है कि तमाम व्यक्तियों को समुचित और बराबर की अहमियत दें। [ ]

(iv) संसद में एक प्रस्ताव विचाराधीन है कि संसद की कुल सीटों में से दो तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाए। [ ]

(v) राल्स ने न्याय का सिद्धांत दिया है। [ ]

35. प्राचीन भारतीय समाज में न्याय संबंधी अवधारणा क्या थी?

36. साधारण शब्दों में न्याय का अर्थ समझाइए।

37. न्याय को बढ़ावा देने का तरीका क्या हो सकता है?

38. समान लोगों के प्रति समान व्यवहार या बर्ताव से क्या अभिप्राय है?

39. न्यूनतम आवश्यकताओं की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी?

40. सरकारी नौकरियों में आरक्षण के प्रस्ताव के विरोध में जो आंदोलन चला उसका क्या नाम था ?

41. भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए किस भारतीय दार्शनिक का योगदान सर्वोपरि है?

42. भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए किस भारतीय दार्शनिक का योगदान सर्वोपरि है?

43. व्यक्ति के जीवन के लिए बुनियादी आवश्यकताएं कौन-कौन सी होती हैं ?

44. भारत में बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच न होने के कारण, कौन से समुदायों को सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान किया गया है?

दो अंकीय प्रश्नः -

1. सामाजिक न्याय ....व.......................... का सामंजस्य है।
2. रॉल्स के अज्ञानता के आवरण का तात्पर्य समझाइये।
3. समानता व सामाजिक न्याय के मध्य संबंध स्पष्ट कीजिये।
4. न्यायपूर्ण वितरण से क्या अभिप्राय है?
5. न्यायपूर्ण समाज की अवधारणा क्या अपेक्षा की जाती है ?
6. संयुक्त राष्ट्र संघ की इकाईयों ने न्यूनतम आवश्यकताओं में किन सुविधाओं की गणना की है?
7. मुक्त बाजार से क्या अभिप्राय है?

चार अंकीय प्रश्नः-

1. 'न्याय में देरी होना अंधेर होना है।' उपरोक्त वाक्य का अर्थ समझाइये।
2. न्याय अपने आप में सम्पूर्ण प्रक्रिया है फिर भारत में सामाजिक न्याय पर विशेष बल क्यों दिया गया है?
3. मुक्त बाजार के पक्ष व विपक्ष में तर्क दीजिये।
4. हर किसी को उसका प्राप्य देने का मतलब समय के साथ कैसे बदला है?
5. न्याय के संबंध में जर्मन दार्शनिक इमनुएल कांट के विचार लिखिये।

चार अंकीय कार्टून आधारित प्रश्न

1. प्रस्तुत कॉर्टून पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

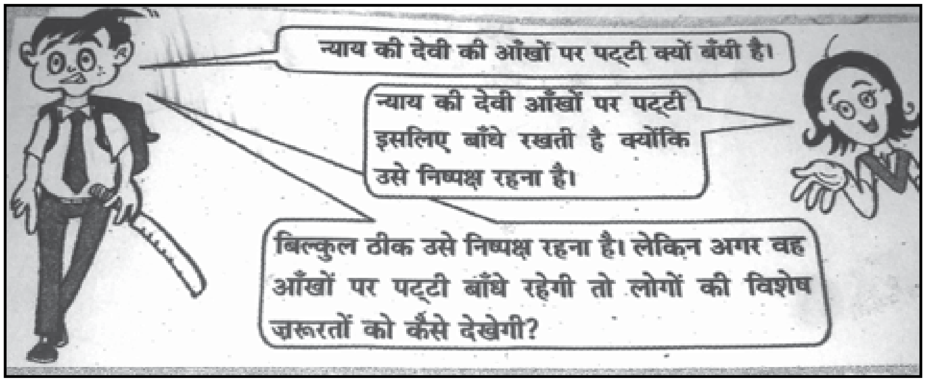

1.1 न्याय से क्या तात्पर्य है?

(A) हर व्यक्ति को उसका जायज हिस्सा मिलना

(B) हर व्यक्ति को उपहार देना

(C) हर व्यक्ति को निःशुल्क आवास देना

(D) हर व्यक्ति को निःशुल्क पानी, बिजली देना

1.2 विशेष जरूरतों से क्या अभिप्राय है?

(A) जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान है। उनके साथ भिन्न ढंग से बर्ताव किया जाए ।

(B) जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं है। उनके साथ भिन्न ढंग से बर्ताव किया जाए ।

(C) जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में महत्वपूर्ण हो उन्हें सम्मान दिया जाएग

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

1.3. क्या विशेष जरूरतों का सिद्धांत न्याय के मार्ग में अवरोध पैदा करता है?

(A) हाँ (B) नहीं

(C) (A) और (B) (D) उपरोक्तस में से कोई नहीं

1.4 भारत में न्याय की देवी से संबंधित सरकार का अंग है?

(A) कार्यपालिका (B) न्यायपालिका

(C) विधायिका (D) उपरोक्त सभी

छः अंकीय प्रश्नः-

1. सामाजिक न्याय की स्थापना के लिये सरकार द्वारा लागू किये जाने वाले तीन सिद्धांत पर प्रकाश डालिये।
2. राल्स के न्याय सिद्धांत की व्याख्या कीजिये।
3. मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप से क्या तात्पर्य है। विस्तार से समझाइये।
4. न्याय के विभिन्न आयामों का सविस्तार वर्णन कीजिए।

उत्तरमाला

वस्तुनिष्ठ/एक अंकीय प्रश्नों के उत्तरः

1. (d) न्याय
2. (b) धर्म
3. (b) राजा
4. (b) कन्फ्यूशियस
5. (c) प्लेटो
6. (d) ग्लाउकॉन
7. (c) यूनान
8. (c) समकक्षों के साथ समान बर्ताव सिद्धांत के विरूद्ध
9. (b) न्याय संगत
10. (c) विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल द्वारा
11. (c) उपरोक्त (a) और (b) दोनों
12. (b) मंडल आयोग
13. (c) दार्शनिक
14. (c) उपरोक्त (a) और (b) दोनों
15. (d) डॉ. बी आर अम्बेडकर

16. (b) न्याय का
17. (a)मुक्त बाजार के समर्थकों का
18. (b) सामाजिक न्याय का अभाव
19. (a) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है।
20. (a) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है।

एक अंकीय प्रश्नों के उत्तरः-

21. (c) लेटिन भाषा
22. (b) प्लेटो
23. (d) कानूनी न्याय।
24. (c) प्लेटो
25. (a) द थ्यारी ऑफ जस्टिस
26. (b) सामाजिक अन्याय
27. भलाई
28. तत्वों
29. जॉन रॉल्स
30. तत्वों
31. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
32. जे.एस. मिल

    32.1 (B) मुक्त बाजार से आशय यह है कि उद्यमों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त रखा जाए।

    32.2 (C) जब बाजारों पर राज्य/सरकार का प्रतिबंध कम से कम होगा।

    32.3 (A) बाजारों को लाभ की अधिकतम मात्रा हासिल करने हेतु एक-दूसरे के साथ प्रतिद्वंदिता करने की छूट होनी चाहिए। यह मुक्त बाजार का सरल चित्रण है।

    32.4 (C) अगर बाजारों को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया जाए, तो बाजारी कारोबार का योग कुल मिलाकर समाज में लाभ और कर्तव्यों का न्याय पूर्ण वितरण सुनिश्चित कर देगा।

33. प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा था।

34. (i) सही (ii) गलत (iii) सही (iv) गलत (v) सही

35. प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा हुआ था और न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था कायम रखना राजा का कर्तव्य था।

36. साधारण शब्दों में न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित हक/हिस्सा दिया जाए।

37. पारिश्रमिक और कर्तव्यों का वितरण करते समय लोगों की विशेष जरूरतों का ख्याल सिद्धांत न्याय को बढ़ावा देने का तरीका माना जा सकता है।

38. समान लोगों के प्रति समान व्यवहार या बर्ताव से अभिप्राय है कि लोगों के साथ वर्ग, जाति, नस्ल या ंलिंग के आधार पर भेदभाव में किया जाए।

    भिन्न-भिन्न वर्गों के दो व्यक्ति यदि एक ही काम करते हैं तो उन्हें समान परिश्रमिक मिलना चाहिए।

39. न्यूनतम आवश्यकताओं की अवधारणा पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974- 1979) में लाई गई थी।

40. मंडल कमीशन विरोधी आंदोलन-1990।

41. डॉ. बी आर अंबेडकर।

42. न्याय पूर्ण बंटवारे से अभिप्राय है कि लोगों में वस्तुओं और सेवाओं का न्यायपूर्ण वितरण हो।

43. व्यक्ति के जीवन के लिए बुनियादी आवश्यकताएं-भोजन, आवास, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्यूनतम आवश्यक संसाधन जरूरी है।

44. भारत में बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच न होने के कारण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया।

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तरः-

1. व्यक्तिगत अधिकारों, सामाजिक अधिकारों

2. हम खुद को ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करें जहां हमें यह फैसला लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाये और साथ ही हमें यह भी पता न हो कि समाज में हमारी जगह क्या होगी तब हम ऐसा निर्णय लेंगे जो सभी के लिये हितकर होगा।

3. दोनों में घनिष्ठ संबंध है सामाजिक न्याय द्वारा समानता तथा समानता द्वारा सामाजिक न्याय की स्थापना होती है।

4. सामाजिक न्याय का संबंध वस्तुओं और सेवाओं के न्यायोचित बंटवारे से है। यह वितरण समाज के विभिन्न समूहों व व्यक्तियों के बीच होता है जिससे उन्हें जीने के लिये समान धरातल मिल सके।

5. न्यायपूर्ण समाज को लोगों के लिये न्यूनतम बुनियादी स्थितियाँ जरूर मुहैया करानी चाहिये ताकि स्वस्थ व सुरक्षित जीवन के साथ समान अवसर के जरिये अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें।

6. भोजन, शुद्ध पानी, आवास, आय व शिक्षा।

7. मुक्त बाजार के समर्थक खुली प्रतिद्वंदिता के पक्षधर है। व्यक्ति को संम्पति अर्जित करने हेतु, मूल्य व मजदूरी के मामले में व्यक्ति की स्वतंत्रता के हामी है।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तरः-

1. न्याय मे ंदेरी वास्तव में अंधेर ही है क्योंकि यदि पीड़ित व्यक्ति न्याय के लिये लम्बे समय तक दर दर भटकता रहे तो उसका न्याय से विश्वास उठने लगता है कभी कभी तो पीड़ित इंसाफ की उम्मीद लिये दुनिया से ही चला जाता हे।

2. लम्बे समय से चली आ रही जातिगत विभिन्नताओं के कारण न्याय की प्रक्रिया कहीं न कहीं प्रभावित हुई है। इसीलिये सामाजिक ताने बाने को ध्यान में रखकर ही न्याय किया जाना चाहिए।

3. पक्षः बाजार व्यक्ति की जाति धर्म या लिंग की परवाह नहीं करता। बाजार केवल व्यक्ति की योग्यता व कौशल की परवाह करता है।

   विपक्षः मुक्त बाजार ताकतवर धनी व प्रभावशाली लोगों के हित में काम करने को प्रवृत होता है जिसका प्रभाव सुविधा विहीन लोगों के लिये अवसरों से वंचित होना हो सकता है।

4. बदलते समय व परिस्थितियों के कारण व्यक्ति की आावश्यकताओं में भी बदलाव आया है। भूमण्डलीकरण व तकनीक के विस्तार ने व्यक्ति के जीवन में महान परिवर्तन ला दिये हैं इसी के अनुसार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताएं भी बढ़ या बदल गई है।

5. इमैनुएल कांट के अनुसर हर व्यक्ति की गरिमा होती है इसलिये हर व्यक्ति का प्राप्य यह होगा कि उन्हें अपनी प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिये समान अवसर प्राप्त हो।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर (चित्र पर आधारित)

1.1 (A) हर व्यक्ति को उसका जायज हिस्सा मिलना।

1.2 (B) जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं है उनके साथ भिन्न ढंग से बर्ताव किया जाये।

1.3 (B) नहीं।

1.4 (B) न्याय पालिका

छः अंकीय प्रश्नों के उत्तरः-

1. 1) समान लोगों के बीच समान बर्ताव जरूरतमंदों के लिये जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं और अवसरों का प्रावधान।

   2) लाभ तय करते समय विभिन्न प्रयास व कौशलों को मान्यता देना (समानुपातिक न्याय)

   3) विशेष जरूरतों का विशेष ख्यालः जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं है उनके साथ भिन्न ढंग से बर्ताव करके उनका ख्याल किया जाना चाहिये।

2. रॉल्स ने न्याय प्राप्ति के लिये 'अज्ञानता के आवरण' का सिद्धान्त दिया है यदि अज्ञानता में रहकर यह निर्णय लिया जाये कि समाज में न्याय कैसा होना चाहिये किस वर्ग के लिये क्या सुविधाएं होनी चाहिए तो व्यक्ति सबसे कमजोर या निचले वर्ग के लिये भी सर्वश्रेष्ठ नीति का चयन करेगा क्योंकि उसे यह ज्ञान नहीं होगा कि इस समाज में उसका स्थान कहां होगा।

3. मुक्त बाजार के समर्थक राज्य के हस्तक्षेप के विरोधी और खुली प्रतिस्पर्धा के पक्षधर है। उनके अनुसार इससे योग्यता और प्रतिभा से लैस लोगों को अच्छा फल मिलेगा जबकि अक्षम लोगों को कम हासिल होगा।

4. न्याय के विभिन्न आयामः

(1) **विधिक न्यायः** यह न्याय की एक संकीर्ण अवधारणा है तथा समाज में विधिक प्रक्रिया के रूप में विद्यमान है। कोर्ट ऑफ लॉ विधि की व्याख्या करता है तथा विवाद में सम्मिलित वादियों के पक्ष विपक्ष सुनने के पश्चात इसे अधिनियमित करता है। यहां, न्याय, विधि न्यायालय द्वारा प्रशासित है तथा न्यायाधीश की व्याख्या को न्याय का प्रतीक माना जाता है।

(2) **राजनीतिक न्यायः** किसी भी लोकतांत्रिक समाज में राजनीतिक न्याय का अर्थ है समान राजनीतिक अधिकारों को प्र्ेरित करना। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक क्षेत्र में लोगों की स्वतंत्र तथा निष्पक्ष सहभागिता के लिए है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार राजनीतिक न्याय की अभिव्यक्ति है। सार्वजनिक कार्यालयों में निर्वाचित होने के लिए अवसर की समानता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता राजनीतिक न्याय के महत्वपूर्ण स्तंभ है।

(3) **सामाजिक न्यायः** इसका अर्थ है सभी प्रकार की सामाजिक विषमताओं को समाप्त करना तथा जीवन के समस्त क्षेत्रों में प्रत्येक नागरिकों को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना, सामाजिक सुरक्षा निश्चित करना तथा समान राजनीतिक अधिकारों अधिकारों का प्रावधान करना। सामाजिक न्याय की अवधारणा इस विश्वास पर आधारित है कि सभी मनुष्य समान हैं तथा उनसे जाति, धर्म, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

(4) **आर्थिक न्यायः** इसका अर्थ है सभी को उनके जीवन यापन के लिए समान अवसर प्रदान करना। इसका आज से ऐसे लोगों की सहायता करना भी है, जो कार्य करने तथा अपनी जीविका अर्जित करने में समक्ष नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की मौलिक आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, आश्रय तथा शिक्षा की पूर्ति होनी चाहिए। यह समान कार्य के लिए समान वेतन, समान आर्थिक अवसर, संसाधनों का उचित वितरण आदि प्रावधानों के माध्यम से आजीविका के पर्याप्त साधनों का आश्वासन देता है।

जहां राजनीतिक न्याय की अवधारणा स्वतंत्रता के आदर्श के साथ घनिष्ठ रूप से संबंद्ध है, वहीं आर्थिक व कानूनी न्याय ''समानता'' तथा सामाजिक न्याय ''भ्रातृत्व'' के साथ संबंधित है। इन सभी का संयोजन न्याय के चारों आयामों को प्राप्त करके में सहायक होगा।

अध्याय-15

अधिकार

अधिकारः किसी व्यक्ति द्वारा की गई मांग, जिसे सार्वजनिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए, समाज स्वीकार करता है और राज्य मान्यता देता है।

अधिकारों की उत्पत्ति

1. **प्राचीन युग में:** प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांतः (प्रकृति या ईश्वर प्रदत्त/जन्म से प्राप्त अधिकार) जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार।

2. **आधुनिक युग में:** प्राकृतिक अधिकार अस्वीकार्य। मानवाधिकार सामाजिक कल्याण की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण।

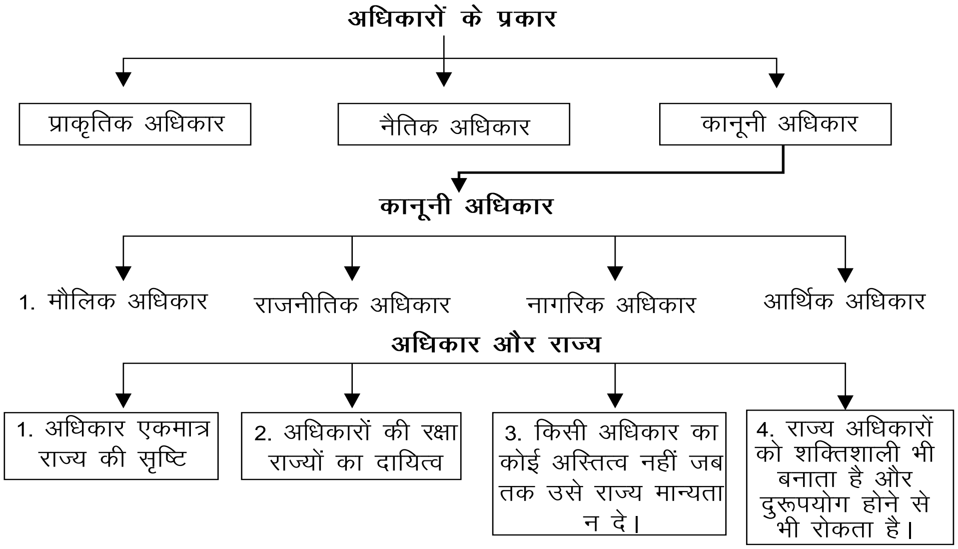

विश्व के समस्त देशों के नागरिकों को पूर्ण अधिकार दिलाने के लिए 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा ने मानव-अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार कर लागू किया।

मुख्य बिन्दुः

1. अधिकार का अर्थ/अधिकार क्या है?
2. मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा
3. अधिकारों क्यों आवश्यक है?
4. अधिकारों की उत्पत्ति/अधिकार कहाँ से आते हैं?
5. कानूनी अधिकार और राज्य सत्ता
6. अधिकारों के प्रकार
7. अधिकारों की दावेदारी
8. अधिकार एवं जिम्मेदारियां
9. अधिकार और कर्तव्य
10. कर्तव्य के प्रकार
11. मानवाधिकार

1. अधिकार का अर्थः-

- अधिकार किसी व्यक्ति द्वारा की गई 'मांग' है, जिसे सार्वजनिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए समाज स्वीकार करता है और राज्य मान्यता देता है, तो वह मांग अधिकार बन जाती है।

  समाज में स्वीकृति मिले बिना मांगे, अधिकार का रूप नहीं ले सकतीं।

2. मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणाः-

- विश्व के समस्त देशों के नागरिकों को अभी पूर्ण अधिकार नहीं मिले हैं। इसी दिशा में 10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की 'सामान्य सभा' ने मानवाधिकरों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार कर लागू किया गया है।

  मानव अधिकार दिवस - 10 दिसम्बर

3. अधिकार क्यों आवश्यक है?

- व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा के लिए।
- लोकतांत्रिक सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए।

- व्यक्ति की प्रतिभा व क्षमता को विकसित करने के लिए।
- व्यक्ति के सम्पूर्ण विकास के लिए।
- अधिकार रहित व्यक्ति, बंद पिंजड़े में पक्षी के समान है।

4. अधिकारों की उत्पत्तिः-अधिकार कहाँ से आते हैं?

1. प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत- जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति-प्राकृतिक अधिकार (17वीं और 18वीं शताब्दी)
2. आधुनिक युग में- प्राकृतिक अधिकार अस्वीकार्य

   मानवाधिकार सामाजिक कल्याण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मानव अधिकारों के पीछे मूल मान्यता यह है कि सभी लोग मनुष्य होने मात्र से कुछ चीजों को पाने के अधिकारी है।

5. **कानूनी अधिकार और राज्य सत्ता:-** कानूनी अधिकार अर्थात वे अधिकतर जिन्हें राज्य सरकार ने कानूनी मान्यता दी है। कानूनी मान्यता से यकीनन हमारे अधिकारों को समाज में एक खास दर्जा मिलता है। अधिकार यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य सत्ता वह वैयक्तिक जीवन और स्वतंत्रता की मर्यादा का उल्लंघन किए बगैर काम करें।

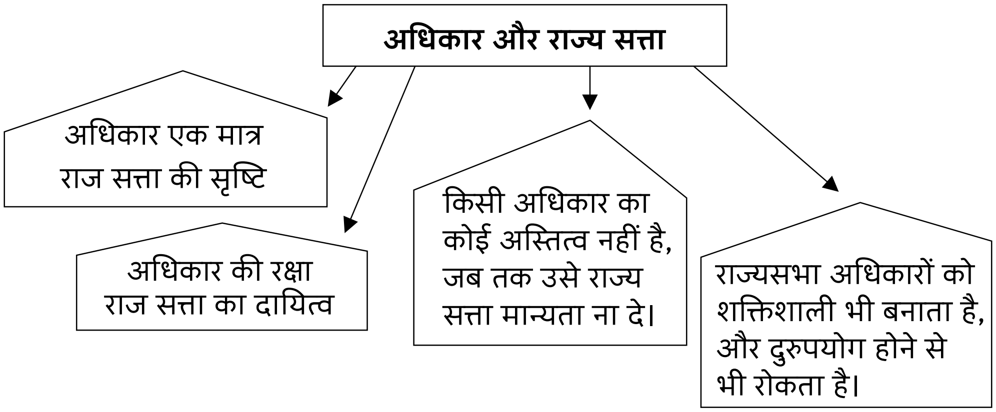

6.

अधिकारों के प्रकार

प्राकृतिक अधिकार | नैतिक अधिकार | कानूनी अधिकार

1. प्राकृतिक अधिकार : जन्म के समय मिला अधिकार
   जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति

2. नैतिक अधिकार : व्यक्ति की नैतिक भावनाओं से जुड़े अधिकार
   माता–पिता की सेवा करना, शिष्ट व्यवहार, सच्चा चरित्र, आदर का भाव

कानूनी अधिकार : जिन्हें राज्य ने कानूनी मान्यता दी है।

6.1 मौलिक अधिकार

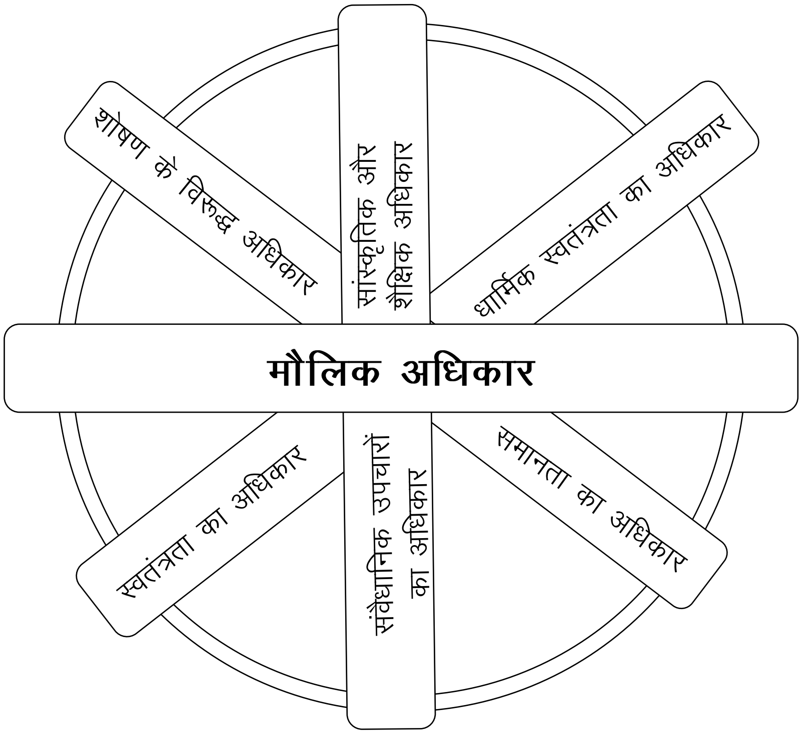

6.2 राजनैतिक अधिकारः (i) मत देने का अधिकार
(ii) निर्वाचित होने का अधिकार
(iii) सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार

6.3 नागरिक अधिकारः (i) देश में कहीं आने जाने की स्वतंत्रता
(ii) विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

6.4 आर्थिक अधिकारः (i) काम करने का अधिकार
(ii) संपत्ति खरीदने का अधिकार

7. अधिकारों की दावेदारी

- सार्वभौम अधिकार - शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

कुछ कार्यकलाप, जिन्हें अधिकार नहीं माना जा सकताः

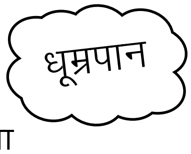

- वे कार्यकलाप जो समाज के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए नुकसानदेह हैं। जैसे नशीली या प्रतिबंधित दवाइयां का सेवन करना

8. **अधिकार और जिम्मेदारियां:-** अधिकार न केवल राजेश पर जिम्मेदारी डालते हैं कि वह खास तरीके से काम करें बल्कि हम सब पर भी जिम्मेदारी आयद करते हैं:

(i) उदाहरण के लिए टिकाऊ विकास का मामला ले, हमारे अधिकार में हमें याद दिलाते हैं कि इसके लिए न केवल राज्य को कुछ कदम उठाना उठाने हैं बल्कि हमें भी इस दिशा में प्रयास करने हैं।

(ii) अधिकार यह अपेक्षा करते हैं कि मैं अन्य लोगों के अधिकारों का सम्मान करूं।

(iii) टकराव की स्थिति में हमें अपने अधिकारों को संतुलित करना है।

(iv) नागरिकों को अपने अधिकारों पर लगाए जाने वाले नियंत्रण के बारे में चौकस रहना होगा।

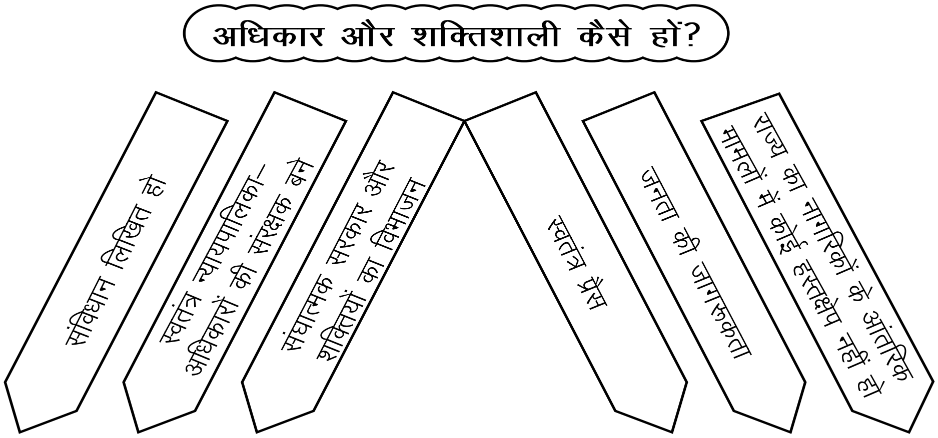

9. अधिकार और कर्तव्य

यदि राज्य अधिकारों को सुरक्षित करता हे तो उसे यह अधिकार भी प्राप्त होता है कि वह अधिकारों के दुरूपयोग को रोके इसलिए संविधान के अनुच्छेद 19(2) में मौलिक कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है।

अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह हैं। एक पहलू अधिकार है तो दूसरा पहलू कर्तव्य। समाज में हमें जो अधिकार मिलते हैं उनके बदले में हमें कुछ ऋण चुकाने पड़ते है। ये ऋण ही हमारे कत्तव्य हैं।

10. :- **कर्त्तव्य के प्रकार**

नैतिक कर्त्तव्य

- अपने परिवेश को स्वच्छ रखने का कर्त्तव्य।
- बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करना।
- माता–पिता व बुजुर्गों की सेवा करना
- सामाजिक नियमों का पालन करना
- परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ण करना

कानूनी कर्त्तव्य

- संविधान का सम्मान करना।
- राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का सम्मान करना।
- कानून व व्यवस्था बनाए रखना
- नियमित रूप से 'कर' देना
- राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा
- देश की एकता तथा अखंडता व सुरक्षा बनाए रखना।
- देश की रक्षा करना।
- प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी पूर्ण उपयोग।
- ओजोन परत की हिफाजत करना।

11. **मानवाधिकारः-**

देश में नए खतरों और चुनौतियां से उभरने के लिए मानवाधिकारों की सूचीः

1) स्वच्छ वायु, सुरक्षित पेयजल तथा टिकाऊ विकास का अधिकार
2) सूचना के अधिकार का दावा
3) महिला सुरक्षा का अधिकार
4) समाज के कमजोर लोगों के लिए शौचालयों की व्यवस्था
5) बच्चों को खाद्य, संरक्षण शिक्षा का अधिकार
6) सादा-जीवन यापन के लिए आवश्यक स्थितियाँ

मानवाधिकारों की कीमतः-

- मनुष्य की सतत् जागरूकता।
- किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता गिरफ्तारी के लिए उचित कारण जरूरी है।
- अपराधी से अपराध की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उत्पीड़न उचित नहीं।
- नागरिक के लिए यह आवश्यक है कि वह सतर्क रहें, अपनी आँखे खुली रखें, अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमेशा जागरूक रहें।

प्रश्नावली

एक अंकीय प्रश्नः-

1. अधिकार मूल रूप से एक ऐसा............ है जिसका औचित्य सिद्ध हो।

(a) दावा (b) मांग

(c) कर्तव्य (d) अधिकार

2. 17वीं-18वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांतकारों का तर्क देते थे कि हमारे लिए अधिकार .... प्रदत्त हैं।

(a) प्रकृति द्वारा (b) ईश्वर द्वारा

(c) प्रकृति या ईश्वर द्वारा (d) उपरोक्त में से कोई भी

3. हाल के वर्षों में प्राकृतिक अधिकार शब्द से ज्यादा .... अधिकार शब्द का प्रयोग हो रहा है।

(a) राजनीतिक (b) राजनीतिक

(c) आर्थिक (d) मानव

4. अधिकतर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं................... अधिकारों का घोषणा पत्र बनाने से अपनी शुरूआत करती हैं।

(a) सामाजिक (b) राजनीतिक

(c)आर्थिक (d) सांस्कृतिक

5. 10 दिसंबर .... को संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार और लागू किया।

(a) 1945 (b) 1947

(c) 1948 (d) 1960

6. आधुनिक काल में प्राकृतिक अधिकार हैंः

(a) स्वीकार्य (b) अस्वीकार्य

(c) कानूनी (d) उपरोक्त में कोई नहीं

7. मानव अधिकार सामाजिक कल्याण की दृष्टि से हैं.............

(a) महत्वपूर्ण (b) महत्वहीन

(c) सामान्य (d) विशिष्ट

8. निर्वाचित होने का अधिकार, किस श्रेणी में आता है?

(a) प्राकृतिक अधिकार (b) सामाजिक अधिकार

(c) राजनीतिक अधिकार (d) सांस्कृतिक अधिकार

9. ''काम'' का अधिकार हैः

(a) सामाजिक अधिकार (b) आर्थिक अधिकार

(c) राजनीतिक अधिकार (d) नैतिक अधिकार

10. हमें सृजनात्मकता और मौलिक होने का अधिकार कौन देता है?

(a) समानता का अधिकार | (b) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

(c) अभिव्यक्ति का अधिकार | (d) शोषण के विरूद्ध अधिकार

11. हमारी तर्कशक्ति विकसित करने में सहयोग करने वाला अधिकार है-

(a) समानता का अधिकार | (b) शिक्षा का अधिकार

(c) अभिव्यक्ति का अधिकार | (d) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

12. 17वीं, 18वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांतकारों ने मनुष्य के कौन-से अधिकारों को चिह्नित किया था-

(a) जीवन का अधिकार | (b) स्वतंत्रता का अधिकार

(c) संपत्ति का अधिकार | (d) उपरोक्त सभी

13. ''सभी लोग, मनुष्य होने मात्र से कुछ चीजों को पाने के लिए अधिकारी हैं।'' यह मूल मान्यता है-

(a) मानवाधिकारों की | (b) नैतिक अधिकारों की

(c) सामाजिक अधिकारों की | (d) राजनीतिक अधिकारों की

14. दास प्रथा के उन्मूलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है?

(a) प्राकृतिक अधिकारों की | (b) सामाजिक अधिकारों की

(c) मानवाधिकारों की | (d) राजनीतिक अधिकारों की

15. शुद्ध पर्यावरण प्राप्त करने का अधिकार, अधिकारों की किस श्रेणी में आता है?

(a) सामाजिक अधिकार | (b) आर्थिक अधिकार

(c) सांस्कृतिक अधिकार | (d) मानवाधिकारों की

16. किस सकार की लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियादी का निर्माण होता है.....

(a) नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार द्वारा

(b) नागरिक स्वतंत्रता और आर्थिक अधिकार द्वारा

(c) नागरिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अधिकार द्वारा

(d) नागरिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अधिकार द्वारा

17. अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार, अधिकारों की किस श्रेणी में आता है-

(a) स्वतंत्रता का अधिकार (b) समानता का अधिकार

(c) शोषण के विरूद्ध (d) शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार

18. लोकतांत्रिक समाज की बुनियाद का निर्माण कौन करता है?

(a) कर्तव्य (b) अधिकार

(c) दावे (d) उपरोक्त में कोई नहीं

19. प्रसिद्ध सिने तारिका और नामी अधिकारी के बीच की बातचीत पर आधारित स्टिंग ऑपरेशन को टेलीविजन पर दिखाना किस अधिकार का अतिक्रमण है?

(a) निजता के अधिकार का (b) स्वतंत्रता के अधिकार का

(c) समानता के अधिकार का (d) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार

20. अभिकथनः 18वीं सदी में जर्मनी में महान दार्शनिक ''इमैन्युएल कांट'' थे।

कारणः महान दार्शनिक ''इमैन्युएल कांट'' के अनुसार-'हमें दूसरों के साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा हम अपने लिए दूसरों से अपेक्षा करते हैं।''

(a) अभिकरण और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है।

(b) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।

(c) अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है।

(d) अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है।

21. अभिकथनः पूरी दुनिया के उत्पीड़िन जन सार्वभौम मानवाधिकारों की अवधारणा का लाभ उठा रहे हैं।

कारणः विश्व समुदाय सामूहिक रूप से गरिमा और आत्मसम्मान से परिपूर्ण जिंदगी जीना चाहता है।

(a) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है।

(b) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।

(c) अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है।

(d) अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है।

22. अभिकथनः 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने मानव-अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकर करते हुए विश्व से इनपर अमल करने की अपील की।

मानवः मानवाधिकारों के दावों की नैतिक अपील की सफलता विश्व के देशों की सरकारों एवं कानूनों पर निर्भर करती है।

(a) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है।

(b) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।

(c) अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है।

(d) अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है।

23. अभिकथनः अधिकार सिर्फ यह ही नहीं बताते कि राज्य को क्या करना है, वे यह भी बताते हैं कि राज्य को क्या कुछ नहीं करना है।

कारणः राज्य किसी व्यक्ति को सलाखों के पीछे करना चाहती है तो उसे न्यायालय के समक्ष उसके कारण बताने पड़ेंगे।

(a) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है।

(b) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।

(c) अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है।

(d) अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है।

24. अभिकथनः अधिकारों का उद्देश्य लोगों के कल्याण की हिफाजत करना होता है।

कारणः लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है।

(a) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है।

(b) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।

(c) अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है।

(d) अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है।

25. अधिकार किसे कहते हैं?

26. अधिकार किन बातों का द्योतक है?

27. 17वीं और 18वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांतकारों ने अधिकारों की उत्पत्ति कहां से बताई थी?

28. हाल के वर्षों में प्राकृतिक अधिकार शब्द से ज्यादा किस ''अधिकार-शब्द'' का प्रयोग हो रहा है?

29. मानव अधिकारों के पीछे ''मूल-मान्यता'' क्या है?

30. मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र किसने बनाया है?

31. विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है?

32. मानव के जीवन में अधिकारों का क्या महत्व है?

33. भारत के संविधान में वर्णित अधिकारों का क्या महत्व है?

34. शिक्षा के अधिकार को व्यक्ति का सार्वभौमिक अधिकार क्यों कहा जाता है?

35. कर्तव्य से आप क्या समझते हैं?

36. मौलिक अधिकारों और प्राकृतिक अधिकारों में कोई एक अंतर लिखिए।

37. कर्तव्य कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए।

38. किन्हीं दो नैतिक कर्तव्यों का नाम लिखिए।

39. ''हमें दूसरों के साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए, जैसा हम अपने लिए दूसरों से अपेक्षा करते हैं।'' अधिकार की यह नैतिक अवधारण किस दार्शनिक की है?

    (a) लास्की (b) अरस्तु

    (c) कांट (d) लॉक

40. प्राकृतिक अधिकार से अभिप्राय है?

    (a) वे अधिकार जो प्राचीनकाल में राजा के द्वारा दिए जाते थे।

    (b) वे अधिकार जो राज्य की ओर से नागरिकों को दिए जाते हैं।

    (c) वे अधिकार जो व्यक्ति को प्रकृति ने दिए हैं।

    (d) वे अधिकार जो व्यक्ति को प्रकृति ने दिए हैं।

41. प्राकृतिक अधिकार का समर्थन क्या हैः

(a) कार्ल मार्क्स ने (b) लॉक ने

(c) अरस्तु ने (d) मैक्यावली ने

42. जीवन का अधिकारः

(a) सामाजिक अधिकार (b) आर्थिक अधिकार

(c) राजनीतिक अधिकार (d) सांस्कृतिक अधिकार

43. ''अधिकार उन समाजिक व्यवस्थाओं का नमा है जिनके बिना कोई व्यक्ति पूर्ण रूप में विकास नहीं कर सकता''। यह कथन किसका है

(a) मैक्यावली (b) अरस्तु

(c)आइंस्टीन (d) लास्की

44. मतदान करने का अधिकार हैः

(a) सामाजिक अधिकार (b) राजनीतिक अधिकार

(c) आर्थिक अधिकार (d) नैतिक अधिकार

खाली स्थान भरोः

45. .... सामाजिक जीवन की भी अनिवार्य परिस्थितियां हैं, जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है।

46. काम का अधिकार .... अधिकार है।

47. भारत में राजनीतिक अधिकार .... वर्ष की आयु अथवा उससे अधिक आयु के नागरिकों को प्राप्त होता है।

48. किसान कृषि कानूनो के खिलाफ सरकार की आलोचना .... अधिकार के तहत कर रहे हैं।

49. .... दिसंबर .... को संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने मानवधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया।

50. निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें।

''आज संयुक्त राष्ट्र महासभा, मानवाधिकारों की विश्व-जननीय घोषणा पत्र को सभी सभ्यताओं तथा देशों के लिए उपलब्धि के सर्वमान्य मानदंड के रूप में एतदर्थ घोषित करती है कि-प्रत्येक व्यक्ति तथा समाज का प्रत्येक अंग इस घोषणा-पत्र का सदा विचार रखते हुए इन अधिकारों तथा स्वतंत्रता, स्वतंत्रताओं की मर्यादा को अध्यापन तथा शिक्षा के माध्यमों द्वारा प्रोत्साहित करेगा तथा विकास की ओर उन्मुख राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय साधनों द्वारा इनकी सर्व-देशिक तथा सशक्त स्वीकृति आने वाले प्रदेशों की जनता के बीच स्थापित करेगा।''

50.1. संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी?

(a) 1940 (b) 1945 (c) 1950 (d) 1955

50.2 ''मानवाधिकारों के विश्व-जननीय घोषणा पत्र को'' संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने घोषित किया...........

(a) यूनिसेफ (b) सुरक्षा परिषद ने

(c) यूनेस्को ने (d) महासभा ने

50.3 संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों को प्रोत्साहित करने के लिए किस माध्यम को उचित समझा........

(a) मीडिया द्वारा (b) आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा

(c) शिक्षा द्वारा (d) पत्राचार द्वारा

50.4 संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों को किसके बीच स्थापित करने का आह्वान किया..................

(a) सदस्य देशों के बीच (b) गैर सदस्य देशों के बीच

(c) शिक्षा द्वारा (d) उपरोक्त में कोई नहीं

51. निम्नलिखित कथन को सही करके पुनः लिखिए।

(a) शिक्षा प्राप्ति का अधिकार एक सामाजिक अधिकार है।

(b) काम प्राप्ति का अधिकार एक सांस्कृतिक अधिकार है।

(c) भाषण का अधिकार एक आर्थिक अधिकार है।

(d) चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है।

(e) सम्मान के साथ रहने के लिए व्यक्ति को काम का अधिकार प्राप्त होना आवश्यक है

दो अंकीय प्रश्नः-

1. राजनीतिक अधिकारों में कौन-कौन से अधिकार शामिल है?
2. अधिकारों की सुरक्षा के कोई दो उपाय सुझाइए।
3. नागरिक के राज्य के प्रति किन्हीं दो कर्तव्यों को लिखिए।
4. एक नागरिक को कौन-कौन से आर्थिक अधिकार प्राप्त है?
5. निम्नलिखित का मिलान कीजिए-

a) आर्थिक अधिकार	मत देने का अधिकार
b) नागरिक अधिकार या सामाजिक अधिकार	स्वतंत्रता का अधिकार
c) राजनीतिक अधिकार	न्यूनतम भत्ता
d) सांस्कृतिक अधिकार	मातृभाषा में शिक्षा पाने का अधिकार

चार अंकीय प्रश्नः-

1. कर्तव्यों व अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? क्या आप इससे सहमत हैं? समझाइए।
2. नागरिक के किन्हीं चार राजनीतिक अधिकारों का वर्णन करो।
3. अधिकार राज्य की सत्ता पर कुछ सीमाएं लगातें है? उदाहरण देकर समझाइए।

वस्तुनिष्ठ (चित्र आधारित प्रश्न)

1. निम्नलिखित चित्र और वार्तालाप को पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो

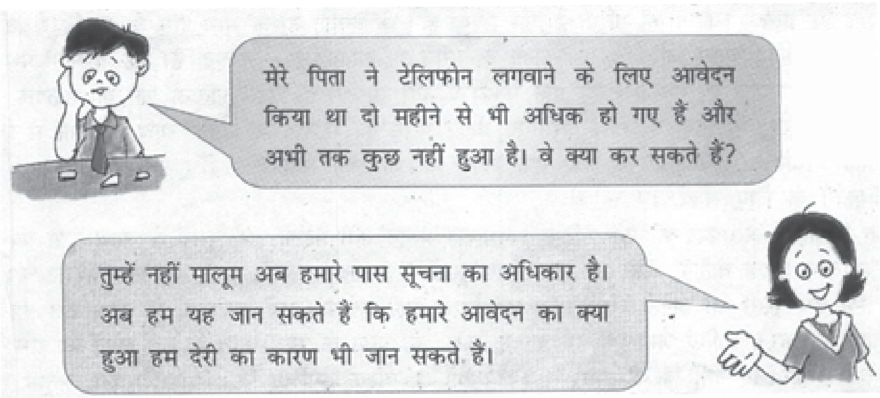

1.1 उपरोक्त चित्र किस अधिकार का दावा कर रहा है?

(A) काम का अधिकार

(B) सूचना का अधिकार

(C) सम्पत्ति का अधिकार

(D) मानव अधिकार

1.2 समाज में किसी भी कार्य में देरी से आहत व्यक्ति को राहत कौन देता है ?

(A) कार्यपालिका

(B) व्यवस्थापिका

(C) न्यायपालिक

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

1.3 सूचना का अधिकार है-

(A) किसी भी विषय पर जानकारी इकट्ठा करना

(B) किसी भी विषय पर आंकड़े मिलान

(C) किसी भी विषय पर संशय की प्रस्तुति में

(D) इनमें से कोई नहीं

1.4 समाज मेंकिसी भी कार्य में देरी से आहत व्यक्ति क्या महसूस करता है

(A) असुरक्षित

(B) सुरक्षित

(C) रहता

(D) उपयुक्त में से कोई नहीं

छः अंकीय प्रश्नः-

1. कर्तव्य किसे कहते हैं? एक अच्छे नागरिक के कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए।
2. अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण देकर समझाइए।
3. अधिकार तथा कर्तव्यों में क्या संबंध है?
4. अधिकार व दावे में अंतर लिखो?

उत्तरमाला

वस्तुनिष्ठ (एक अंकीय प्रश्नों के उत्तर)

1. (a) दावा
2. (c) प्रकृति या ईश्वर द्वारा
3. (d) मानव
4. (b) राजनीतिक
5. (c) 1948
6. (b) अस्वीकार्य
7. (a) महत्वपूर्ण
8. (c) राजनीतिक अधिकार
9. (b) आर्थिक अधिकार
10. (c) अभिव्यक्ति का अधिकार
11. (b) शिक्षा का अधिकार
12. (d) उपरोक्त सभी
13. (a) मानवाधिकारों की
14. (c) मानवाधिकारों की
15. (d) मानवाधिकारों की
16. (a) नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार द्वारा
17. (d) शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार
18. (b) अधिकार
19. (a) निजता के अधिकार का

20. (a) अभिकथन और कारण दोनेां सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है।

21. (a) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।

22. (b) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।

23. (a) अभिकथन और कारण दोनेां सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है।

24. (b) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।

25. अधिकार किसी व्यक्ति द्वारा की गई मांग या दावा है, जिसे सार्वजनिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए समाज स्वीकार करता है और राज्य मान्यता देता है, तो वह मांग ''अधिकार'' बन जाती है।

26. अधिकार उन बातों का द्योतक है जीने में और अन्य लोग सम्मान ओर गरीमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं।

27. 17 मई और 18वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांत कार तर्क देते थे कि हमारे लिए अधिकार प्रकृति या ईश्वर प्रदत्त हैं।

28. हाल के वर्षों में प्राकृतिक अधिकार शब्द से ज्यादा ''मानवाधिकार-शब्द'' का प्रयोग हो रहा है।

29. मानव अधिकारों के पीछे मूल मान्यता यह है कि सभी लोग, मनुष्य होने मात्र से कुछ चीजों को पानी के अधिकारी हैं। एक मानव के रूप में हर आदमी विशिष्ट और समान महत्व का है।

30. मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ ने बनाया है।

31. प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को।

32. मानव के सर्वागीण विकास हेतु अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है।

33. भारत के संविधान में वर्णित अधिकारों को ''मौलिक-अधिकार'' कहा जाता है।

34. क्योंकि शिक्षा व्यक्ति के सभी क्षेत्रों के विकास में सहयोगी होती है, इसलिए इस अधिकार को सार्वभौमिक अधिकार कहा जाता है।

35. अधिकार प्राप्त करने के बदले निभाई जाने वाली जिम्मेदारीयों को कर्तव्य कहते हैं।

36. मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं जबकि प्राकृतिक अधिकार जन्म से प्राप्त होते हैं।

37. कर्तव्य मुख्यतः दो प्रकार के होते हैंः

    (i) नैतिक कर्तव्य और (ii) कानूनी कर्तव्य

38. नैतिक कर्तव्य हैंः

    (i) सामाजिक नियमों का पालन करना (ii) बुजुर्गों की देखभाल करना।

39. (c) कांट

40. (c) वे अधिकार जो व्यक्ति को प्रकृति ने दिए हैं।

41. (b) लॉक ने

42. (a) सामाजिक अधिकार

43. (d) लास्की

44. (b) राजनीतक अधिकार

खाली स्थान भरो के उत्तर-

45. अधिकार

46. आर्थिक अधिकार

47. 18 वर्ष की आयु

48. राजनीतिक अधिकार

49. 10 दिसम्बर 1948

50. (i) (b) 1945

(ii) (d) महासभा ने।

(iii) (c) शिक्षा द्वारा

(iv) (c) सदस्य देशों की जनता के बीच

51. ''आजकल प्राकृतिक अधिकार से ज्यादा मानव अधिकार शब्द का प्रयोग हो रहा है।

52. निम्नलिखित प्रत्येक कथन के आगे सही अथवा गलत लिखिएः-

(a) सही (b) गलत (c) गलत (d) सही (e) सही

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तरः-

1. (i) मत देने का

(ii) निर्वाचित होने का

2. (i) राज्य द्वारा

(ii) स्वतंत्रत न्यायपालिका द्वारा

3. (i) संविधान का सम्मान

(ii) कानून व व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग

4. (i) व्यवसाय चुनने, काम करने का अधिकार।

(ii) सम्पत्ति खरीदने का अधिकार।

5. (i) आर्थिक अधिकार - न्यूनतम भत्ता

(ii) सामाजिक अधिकार - स्वतंत्रता का अधिकार

(iii) राजनीतिक अधिकार - मत देने का अधिकार

(iv) सांस्कृतिक अधिकार - मातृभाषा में शिक्षा पाने का अधिकार

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तरः-

1. अधिकार व कत्र्तव्य का नजदीकी संबंध अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्ण नहीं कर सकते जब तक व्यक्ति समाज के प्रति अपने कत्र्तव्य नहीं निभाता। कत्र्तव्य एक दायित्व है जो दूसरों को अपने अधिकारों को इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता देता है।

2. मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार।

3. राज्य अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकता।

जनता के हितों का ध्यान राज्य द्वारा क्योंकि जनता ही लोकतांत्रिक देशों में सरकार चुनती है।

अधिकार ही राज्य को कुछ खास तरीकों से कार्य करने का दायित्व देते हैं। अधिकार यह निश्चित करते है कि राज्य व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता की मर्यादा का उल्लंघन किए बगैर काम करें।

वस्तुनिष्ठ चित्र आधारित प्रश्न के उत्तर

1.1 (B) सूचना के अधिकार का

1.2 (C) न्यायपालिका

1.3 (c) किसी भी विषय पर संशय की परिस्थिति में जानकारी तथा आंकड़े प्राप्त करना

1.4 (A) असुरक्षित

छः अंकीय प्रश्नों के उत्तरः-

(सिर्फ Hint के लिए explanation विद्यार्थी स्वंय करें)

1. कर्तव्य एक दायित्व है। कर्तव्य हम दूसरों के प्रति निभाते हैं जिससे समाज का विकास होता है।

कर्तव्यः- (i) शरीर मन स्वस्थ रखना

(ii) शिक्षा

(iii) माता पिता की सेवा

(iv) राष्ट्र के प्रति भक्ति भावना

(v) देश की सुरक्षा

(vi) राष्ट्र ध्वज तथा गान की गरिमा

2. (i) प्राकृतिक - जीवन, स्वतंत्रता

   (ii) नैतिक - माता पिता की सेवा, बच्चों की शिक्षा

   (iii) कानूनी- मौलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक

3. गहरे रूप से जुड़े, एक ही सिक्के के दो पहलू कर्तव्य के बिना अधिकार लागू नहीं हो सकते। अपना अधिकार ही पहला कर्तव्य है।

4. (i) सभी दावे अधिकार नहीं होते परंतु सभी अधिकार दावे होते हैं।

   (ii)अधिकार दावें है जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, सभी दावों को राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होते है।

   (iii) दावे-राज्य के संविधान द्वारा गांरटी नहीं।
   मौलिक अधिकारों के राज्य के संविधान द्वारा।

अध्याय-16

नागरिकता

नागरिकताः नागरिकता से अभिप्राय एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता से है जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता।

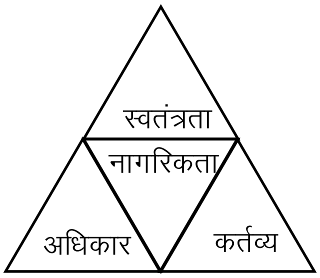

संपूर्ण और समान सदस्याता

राजकृत नागरिकता के तरीकेः

1. पंजीकरण, 2. देशीयकरण, 3. वंश परंपरा, 4. किसी भू क्षेत्र का राज्य क्षेत्र में मिलना

सार्वभौमिक नागरिकता/विश्व नागरिकता

मुख्य बिन्दुः

1. नागरिकता
2. सम्पूर्ण और समान सदस्यता
3. प्रवासी
4. प्रतिवाद के तरीके
5. नागरिक और राष्ट
6. राज्यकृत नागरिकता के तरीके
7. सार्वभौमिक नागरिकता
8. विस्थापन के कारण
9. शरणार्थी का अर्थ
10. विश्व नागरिकता
11. विश्व नागरिकता के लाभ

- भारतीय संविधान के भाग दो (अनुच्छेद 5-11) में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है।
- नागरिकता से अभिप्राय एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता से है जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता। राष्ट्रों ने अपने सदस्यों को एक सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ ही कुछ अधिकार भी दिए है। इसलिए हम सबंद्ध राष्ट्र के आधार पर स्वंय को भारतीय, जापानी या जर्मन कहते है।
- अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को अभिव्यक्ति का अधिकार, मतदान या आस्था की स्वतंत्रता, न्यूनतम मजदूरी या शिक्षा पाने का अधिकार शामिल किए जाते हैं।
- नागरिक आज जिन अधिकारों का प्रयोग करते है उन्हें उन्होंने एक लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त किया है, जैसे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, दक्षिण अफ्रीका में समान नागरिकता प्राप्त करने के लिए लंबा संघर्ष आदि।
- नागरिकता में नागरिकों के आपसी संबंध भी शामिल हैं इसमें नागरिकों के एक दूसरे के प्रति और समाज के प्रति निश्चित दायित्व सम्मिलित होते है।
- नागरिकों को देश के सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों का उत्तराधिकारी और न्यासी भी माना जाता है।

संपूर्ण और समान सदस्यताः-

- इसका अभिप्राय है नागरिकों को देश में जहां चाहें रहने, पढ़ने, काम करने का समान अधिकार व अवसर मिलना तथा सभी अमीर-गरीब नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त होना है।

प्रवासीः-

- काम की तलाश में लोग एक शहर से दूसरे शहर तथा देश से दूसरे देश की ओर की जाते है, तब वे प्रवासी कहलाते है।
- निर्धन प्रवासियों का अपने-अपने क्षेत्रों में उसी प्रकार स्वागत नहीं होता जिस प्रकार कुशल और दौलतमंद प्रवासियों का होता है।
- प्रतिवाद (विरोध) का अधिकार हमारे संविधान में नागरिकों के लिए सुनिश्चित की गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक पहलू है बशर्ते इससे दूसरें लोगों या राज्य के जीवन और संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए।

प्रतिवाद के तरीकेः-

- नागरिक समूह बनाकर, प्रदर्शन कर के, मीडिया का इस्तेमाल करके, राजनीतिक दलों से अपील करके या अदालत में जाकर जनमत और सरकारी नीतियों को परखने और प्रभावित करने के लिए स्वतंत्र है।
- समान अधिकारः शहरों में अधिक संख्या झोपड़पट्टियों और अवैध कब्जें की भूमि पर बसे लोगों की हैं। ये लोग हमारे बहुत काम के है । इनके बिना एक दिन भी नहीं गुजारा जा सकता, जैसे-सफाईकर्मी, फेरीवाले, घरेलू नौकर, नल ठीक करने वाले आदि।
- सरकार, स्वंय सेवी संगठन भी इन लोगों के प्रति जागरूक हो रहे है। सन 2004 में एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई जिससे लाखों फुटपाथी दुकानदारों को स्वतंत्र कारोबार चलाने का अधिकार प्राप्त हुआ।
- इसी प्रकार एक और वर्ग है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है वह है आदिवासी और वनवासी समूह। ये लोग अपने निर्वाह के लिए जंगल और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं।
- नागरिकों के लिए समान अधिकार का अर्थ है-नीतियाँ बनाते समय भिन्न-भिन्न लोगों की भिन्न-भिन्न जरूरतों का तथा दावों का ध्यान रखना।

नागरिक और राष्ट्रः-

- कोई नागरिक अपनी राष्ट्रीय पहचान को एक राष्ट्रगान, झंडा, राष्ट्रभाषा या कुछ खास उत्सवों के आयोजन जैसे प्रतीकों द्वारा प्रकट कर सकता है। लोकतांत्रिक देश यथासंभव समावेशी होते हैं जो सभी नागरिकों को राष्ट्र के अंश के रूप में अपने को पहचानने की इजाजत देता है। जैसे फ्रांस, जो यूरोपीय मूल के लोगों को ही नहीं अपितु उत्तर अफ्रीका जैसे दूसरे क्षेत्रों से आए नागरिकों को भी अपने में सम्मिलित करता है इसे राज्यकृत नागरिकता कहते हैं।
- राज्यकृत नागरिकता के लिए आवेदकों को अनुमति देने की शर्ते प्रत्येक देश में पृथक होती है। जैसे-इजराइल या जर्मनी में धर्म और जातीय मूल जैसे तत्वों को प्राथमिकता दी जाती है।
- भारतीय संविधान ने अनेक विविधतापूर्ण समाजों को समायोजित करने का प्रयास किया है। इसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अलग-अलग समुदायों, महिलाओं, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के कुछ सुदूरवर्ती समुदायों को पूर्ण तथा समान नागरिकता देने का प्रयास किया है।
- नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन संविधान के दूसरे खंड तथा संसद द्वारा तत्पश्चात पारित कानूनों से हुआ हैं।

राज्यकृत नागरिकता के तरीके

1) पंजीकरण
2) देशीकरण
3) वंश परंपरा
4) किसी भू क्षेत्र का राजक्षेत्र में मिलना

सार्वभौमिक नगारिकताः-

- हम यह मान लेते हैं कि किसी देश की पूर्ण सदस्यता उन सबको उपलब्ध होनी चाहिए जो सामान्यतः उस देश के निवासी है, जहां काम करते या जो नागरिकता के लिए आवदेन करते हैं किंतु नागरिकता देने की शर्ते सभी तय करते हैं। अवांछित नागरिकता से बाहर रखने के लिए राज्य ताकत का इस्तेमाल करते हैं, परंतु फिर भी व्यापक स्तर पर लोगों का देशांतरण होता है।

विस्थापन के कारणः-

- युद्ध, अकाल, उत्पीड़न एवं महामारियों, आपदाएँ।

शरणार्थी का अर्थः-

- विस्थापन के कारण जो लोग न तो घर लौट सकते है और न ही कोई देश उन्हें अपनाने को तैयार होता है, तो वे राज्यविहीन या शरणार्थी कहलाते हैं।

विश्व नागरिकताः-

- आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते है, जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। संचार के साधन, टेलिविजन या इंटरनेट ने हमारे संसार को समझने के ढंग में भारी परिवर्तन किया है। एशिया की सूनामी या बड़ी आपदाओं के पीड़ितों की सहायता के लिए विश्व के सभी भागों से उमड़ा भावोदगार विश्व समाज के उभार की ओर इशारा करता है। इसी को विश्व नागरिकता कहा जाता है। यही 'विश्व ग्राम' व्यवस्था का आधार भी है।

विश्व नागरिकता से लाभः-

- इससे राष्ट्रीय सीमाओं के दोनों तरफ उन समस्याओं का समाधान करना सरल होगा, जिसमें बहुत से देशों की सरकारों और लोगों की संयुक्त कार्यवाही जरूरी होती है। इससे प्रवासी या राज्यविहीन लोगों की समस्या का सर्वमान्य निबटान करना आसान हो सकता है।

प्रश्नावली

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (एक अंकीय प्रश्न)

1. एक राजनीतिक समुदाय की समान सदस्यता क्या कहलाती है?

   (a) राजनीतिक सदस्या (b) नागरिकता

   (c) नागरिकत अधिकार (d) सामाजिक सदस्यता

2. नागरिकता की माध्यमिक चुनौतियां हैं-

   (a) गरीबी (b) अशिक्षा

   (c) क्षेत्रवाद (d) उपरोक्त सभी

3. नागरिकता का गुण नहीं है-

(a) आत्म संयम (b) सचरित्रता

(c) कर्तव्य परायणता (d) अलगाववादी

4. यूरोप में समान नागरिकता पाने के लिए पहली क्रांति कब हुई?

(a) 1785 (b) 1789

(c) 1885 (d) 1889

5. दक्षिण अफ्रीका में समान नागरिकता पाने के लिए अफ्रीका की जनता को जिसके खिलाफ लंबा संघर्ष करना पड़ा।

(a) अफ्रीकी सेना के खिलाफ

(b) अफ्रीकी राजा के खिलाफ

(c) अफ्रीका में सत्तारूढ़ गोरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ

(d) उपरोक्त सभी

6. 17वीं शताब्दी से .... शताब्दी तक यूरोप के गोरे लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के लोगों पर अपना शासन कायम रखा।

(a) 19वीं शताब्दी (b) 20वीं शताब्दी

(c) 21वीं शताब्दी (d) उपरोक्त में कोई नहीं

7. मार्टिन लूथर किंग जूनियर का संबंध .... देश से था?

8. 1950 का दशक अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में .... और .... आबादी के बीच नागरिक अधिकार आंदोलन का साक्षी है।

(a) उत्तरी........ दक्षिणी (b) पूर्वी......... पश्चिमी

(c) गोरी .... काली (d) मैदानी .... पहाड़ी

9. वर्ष .... में फुटपाथी दुकानदारों के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की गई है।

(a) 2004 (b) 2006 (c) 2001 (d) 2008

10. अंग्रेज समाजशास्त्री टी.एच. मार्शल ने ''नागरिकता और सामाजिक वर्ग'' पुस्तक वर्ष .... में लिखी।

(a) 1960 (b) 1918 (c) 1950 (d) 1980

11. राष्ट्रीय पहचान को व्यक्त किया जा सकता है.....

(a) राष्ट्रीय गान (b) झंडा

(c) राष्ट्रभाषा (d) उपरोक्त सभी

12. समाजशास्त्री टी एच मार्शल ने नागरिकता में कौन से तीन प्रकार के अधिकारों को जरूरी मानते हैं?

(a) नागरिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार

(b) सामाजिक, शैक्षिक और नागरिक अधिकार

(c) नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार

(d) नागरिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार

13. .... फ्रांस एक......................देश है

(a) धर्मनिरपेक्ष

(b) समावेशी

(c) उपरोक्त (a) और (b) दोनों

(d)उपरोक्त में से कोई नहीं

14. ''नागरिकता'' से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है-

(a) भाग 1 (b) भाग 2

(c) भाग 3 (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

15. ''नागरिकता'' प्रदान करने में इजरायल देश में ....वरियता दी जाती है

(a) धर्म को

(b) जाति को

(c) उपरोक्त ;ंद्ध और ;इद्ध दोनों

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

16. भारत में नागरिकता............................. प्राप्त होती है

(a) जन्म से (b) वंश-परंपरा से

(c) पंजीकरण से (d) उपरोक्त सभी

17. नागरिकता देने की शर्तें अक्सर देशों के संविधान और .... में लिखी होती हैं।

(a) कानूनों (ii) शर्तों

(b) ग्रंथों (c) उपरोक्त में कोई नहीं

18. किसी एक देश के नागरिक दूसरे देश में बिना नागरिकता प्राप्त किए रहते हैं। उन्हें कहते हैं

(a) कामगार (b) शरणार्थी

(c) गुलाम (d) उपरोक्त में कोई नहीं

19. एक देश के नागरिक काम की तलाश में दूसरे देश में जाते हैं, उन्हें.......... कहते हैं

(a) शरणार्थी (b) प्रवासी

(c) नागरिक (d) उपरोक्त में कोई नहीं

20. प्रवासियों एवं राज्य-विहीन लोगों की समस्याओं का निपटारा......................... आसान हो सकता है

(a) विश्व नागरिकता देकर

(b) आर्थिक सहायता देकर

(c) रोजगार देकर

(d) सामाजिक सुरक्षा देकर

21. अभिकथनः नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों की सुस्पष्ट प्रकृति विभिन्न राष्ट्रों में भिन्न-भिन्न हो सकती है।

कारणः नागरिक आज जिन अधिकारों का प्रयोग करते हैं उन सभी को लंबे संघर्ष के बाद हासिल किया गया है।

(a) अभिकथन और कारण दोनेां सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है।

(b) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।

(c) अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है

(d) अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है

22. अभिकथन-यूरोप में 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई।

कारणः फ्रांसीसी क्रांति की तर्ज पर एशिया और अफ्रीका के अनेक उपनिवेशो में समान नागरिकता की मांग के लिए संघर्ष हुआ।

(a) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है।

(b) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।

(c) अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है

(d) अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है

23. अभिकथन-हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में कुशल और अकुशल मजदूरों के लिए बाजार विकसित हुए हैं।

कारण-सूचना एवं तकनीकी के क्षेत्र में बेंगलुरू शहर की ओर कुशल कामगार जा रहे हैं।

(a) अभिकथन और कारण दोनेां सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है।

(b) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।

(c) अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है

(d) अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है

24. अभिकथनः मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका के अश्वेत नेता थे।

कारणः मार्टिन लूथर किंग ने दलील दी है कि पृथक्करण की प्रथा गोरे समुदाय के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है।

(a) अभिकथन और कारण दोनेां सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है।

(b) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।

(c) अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है

(d) अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है

25. अभिकथन-भारत के हर शहर में बहुत बड़ी आबादी झोपड़पट्टीयों और अवैध कब्जे की जमीन पर बसे लोगों की है।

कारण-शहर की अधिकांश आबादी झोपड़पट्टी वालों को अवांछनीय मेहमान की तरह दिखती है।

(a) अभिकथन और कारण दोनेां सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है।

(b) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।

(c) अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है।

(d) अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है।

26. नागरिक अधिकारों के लिए विश्व की पहली क्रांति थी-

(a) रूसी क्रांति (b) फ्रांसीसी क्रांति (c) अमेरिकी क्रांति (d) जर्मन क्रांति

27. यूरोप के गोरे लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत लोगों पर अपना शासन कायम रखाः

(a) 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी (b) 16वीं सदी शताब्दी से 20 शताब्दी

(c) 17वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी (d) 18वीं शताब्दी से 20 शताब्दी

28. संयुक्त राज्य अमेरिका में अश्वेत और गोरी आबादी के बीच विषमताओं के खिलाफ नागरिक अधिकार आंदोलन किस दशक में चला?

(a) 1850 के दशक में (b) 1960 के दशक में

(c) 1860 के दशक में (d) 1950 के दशक में

29. निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य की नागरिकता प्राप्त करने का साधन है?

(a) दीर्घकालीन आवास (b) सरकारी नौकरी

(c) विवाह (d) उपर्युक्त सभी

30. निम्नलिखित में से कौन-सा नागरिकता खोने का साधन है?

(a) दीर्घकालीन आवास (b) लंबी अनुपस्थिति

(c) विवाह (d) सरकारी नौकरी

31. निम्नलिखित कथन को सही करके पुनः लिखिए।

''पृथक्करण कानूनों'' के खिलाफ हुए आंदोलन में अमेरिका के अब्राहम लिंकन जूनियर अग्रणी अश्वेत नेता थे।

32. निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें।

नागरिकता महज एक कानूनी अवधारणा नहीं है। इसका समानता और अधिकारों के व्यापक उद्देश्यों से भी घनिष्ठ संबंध है। इस संबंध का सर्व सम्मत सूत्री-करण अंग्रेज समाजशास्त्री टी.एच. मार्शल ने किया है। अपनी पुस्तक ''नागरिकता और सामाजिक वर्ग'' में मार्शल ने नागरिकता को ''किसी समुदाय के पूर्ण सदस्यों को प्रदत प्रतिष्ठा'' के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रतिष्ठा को ग्रहण करने वाले सभी लोग प्रतिष्ठा में अंतर भूत अधिकारों और कर्तव्यों के मामले में बराबर होते हैं। नागरिकता की मार्शल प्रदत्त कुंजी धारणा में मूल संकल्पना ''समानता'' की है। मार्शल नागरिकता में तीन प्रकार के अधिकारों को शामिल मानते हैं-नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार। मार्शल ने सामाजिक वर्ग को ''असमानता की व्यवस्था'' के रूप में चिह्नित किया है।

32.1 टी.एच. मार्शल है-

(a) अर्थशास्त्री (b) समाजशास्त्री (c) राजनीतिज्ञ (d) इतिहासकार

32.2 ''नागरिकता और सामाजिक वर्ग'' पुस्तक के लेखक हैं-

(a) टी एच ग्रीन (b) टी एच साल्वे (c) समानता (d) टी एच मार्शल

32.3 नागरिकता की मार्शल द्वारा प्रदत्त कुंजी धारणा में मूल संकल्पना हैंः

(a) नागरिक (b) सरकार (c) समानता (d) स्वतंत्रता

32.4 मार्शल नागरिकता में कितने प्रकारों के अधिकारों को शामिल करते है?

(a) दो प्रकार के अधिकार (b) तीन प्रकार के अधिकार

(c) चार प्रकार के अधिकार (d) छः प्रकार के अधिकार

खाली स्थान भरोः-

33. भारतीय संविधान के अनुच्छेद ....से .... में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है।

34. अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को .... अधिकार दिए जाते हैं।

35. काम की तलाश में लोग एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, तब वे .... कहलाते हैं।

36. राज्य नागरिकता के लिए आवेदकों को अनुमति देने की शर्तें प्रत्येक देश में....... हैं।

37. भारतीय संविधान में बहुत ही .... समाज को समायोजित करने की कोशिश की है।

38. निम्नलिखित प्रत्येक कथन के आगे सही अथवा गलत लिखिएः-

(a) नागरिक शब्द अंग्रेजी के सिटीजन शब्द का हिंदी रूपांतरण है।

(b) स्थानीय लोग ''बाहरी लोगों'' की प्रतिद्वन्दिता से नाराज होते हैं।

(c) 1960 का दशक अमेरिका में विषमताओं के खिलाफ नागरिक अधिकार आंदोलन का साक्षी था

(d) मार्टिन लूथर किंग जूनियर अग्रणी गोरे नेता थे।

(e) विश्व नागरिकता की धारणा ''वसुदेव-कुटुंबकम'' पर आधारित है।

दो अंकीय प्रश्नः-

1. एक नागरिक का दूसरे नागरिकों के प्रति क्या कर्तव्य है?
2. रंगभेद की नीति से क्या अभिप्राय है?
3. समान सदस्यता से क्या अभिप्राय है?
4. नागरिक किस प्रकार प्रतिवाद या विरोध कर सकते हैं?
5. आदिवासी तथा वनवासियों के क्या अधिकार हैं?
6. ''कई बार धार्मिक प्रतीक और रिवाज सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर जाते है'' इस कथन का आशय स्पष्ट करें।
7. नागरिकता प्राप्त करने के दो तरीके बताइए।
8. नागरिकता व्यपगत होने के दो कारण बताइए।
9. लोग विस्थापित क्यों होते है दो कारण बताइए।
10. भारत में विकास योजनाओं से विस्थापित लोगों द्वारा किए गए संघर्ष का वर्णन करों।

चार अंकीय प्रश्नः-

1. एक नागरिक तथा विदेशी में क्या अंतर है?
2. एक अच्छे नागरिक में क्या-क्या गुण होने चाहिए। अपने विचार दें।
3. सार्वभौमिक नागरिकता से क्या अभिप्राय है? कुछ शरणार्थी लोगों के उदाहरण दीजिए।
4. विश्व नागरिकता आज एक आकर्षण बनी है। कैसे?
5. भारत में एक जातिगत तथा एक पर्यावरणीय आंदोलन का वर्णन करो।
6. शरणार्थियों को किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है?
7. 'बाहरी तथा भीतरी' समस्या का वर्णन करो।
8. आज विश्व एक विश्व ग्राम की भांति बदल रहा है? कैसे?
9. नागरिक और सामाजिक अधिकार क्या है?
10. शहरी गरीबों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पांच अंकीय प्रश्न अभ्यास हेतु

दिए गए चित्र कार्टून का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे लिखे प्रश्न उत्तर लिखिए।

प्रवासी मजदूरों के बिना भारत के शहरी मध्यवर्ग के जीवन का एक दिन

(a) प्रवासी किसे कहते हैं? (1)

(b) प्रवासी लोग शहरों में कौन-कौन से काम करते हैं? (2)

(c) प्रवासियों के बिना शहरी लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हो सकता है? उदाहरण सहित समझाइए। (2)

छः अंक वाले प्रश्नः-

1. ''आज नागरिकों को जो भी अधिकार मिले हुए हैं वे उसके कड़े संघर्ष का परिणाम है''। सिद्ध करो।

2. ''समान सदस्यता मिलने का अर्थ यह नहीं कि सभी उसका समान प्रयोग कर सकें'' क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उचित तर्क दीजिए।

3. ''लोकतंत्र का यह बुनियादी सिद्धांत है कि विवादों का निदान बल प्रयोग की अपेक्षा संधि-वार्ता तथा विचार विमर्श से हो'' आपके अनुसार क्या यह तरीका विश्व नागरिकता को बढ़ावा देगा।

4. ''भारत एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य है'' कैसे।

उत्तरमाला

वस्तुनिष्ठ (एक अंकीय प्रष्नों के उत्तर)

1. (b) नागरिकता
2. (d) उपरोक्त सभी
3. (d) अलगाववादी
4. (b) 1789
5. (c) अफ्रीका में सत्तारूढ़ गोरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ
6. (b) 20वीं शताब्दी
7. (d) अमेरिका
8. (c) गोरी..... अश्वेत
9. (a) 2004
10. (c) 1950
11. (d) उपरोक्त सभी
12. (c) नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार
13. (c) उपरोक्त (a) और (b) दोनों
14. (b) भाग-2

15. (c) उपरोक्त (a) और (b) दोनों
16. (d) उपरोक्त सभी
17. (a) कानूनों
18. (b) शरणार्थी
19. (b) प्रवासी
20. (a) विश्व नागरिकता देकर
21. (b) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।
22. (b) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।
23. (a) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और अभिकथन की सही व्याख्या है।
24. (d) अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है।
25. (a) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं कारण अभिकथन की सही व्याख्या है।
26. (b) फ्रांसीसी क्रांति
27. (c) 17वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी
28. (d) 1950 का दशक
29. (d) उपर्युक्त सभी
30. (b) लंबी अनुपस्थिति
31. ''पृथक्करण कानूनों'' के खिलाफ हुए आंदोलन में अमेरिका के ''मार्टिन लूथर किंग जूनियर'' अग्रणी काले नेता थे।

32.1 (b) समाजशास्त्री

32.2 (d) टी एच मार्शल

32.3 (c) समानता

32.4 (b) तीन प्रकार के अधिकार

33. अनुच्छेद 5 से 11
34. अभिव्यक्ति का अधिकार/मतदान का अधिकार/आस्था की स्वतंत्रता का अधिकार/शिक्षा का अधिकार/न्यूनतम मजदूरी पाने का अधिकार।

35. प्रवासी

36. भिन्न-भिन्न/प्रथक-प्रथक।

37. विविधतापूर्ण (समाज)

38. (a) सही (b) सही (c) गलत (d) गलत (e) सही

दो अंकीय प्रष्नों के उत्तरः-

1. नागरिकों का कत्र्तव्य है कि वे दूसरें नागरिकों के अधिकारेां का सम्मान करें। रोजमर्रा के जीवन में उन्हें सम्मिलित होने और योगदान करने का दायित्व शामिल हैं

2. गोरे और अश्वेत लोगों के बीच भेदभाव दक्षिण अफ्रिका का उदाहरण।

3. राजसत्ता द्वारा सभी नागरिकों को चाहें वे धनी हो या निर्धन कुछ बुनियादी अधिकारों की गांरटी देना।

4. समूह बनाकर, प्रदर्शन, धरना, मीडिया का प्रयोग, राजनीतिक दलों से अपील करना या अदालत जाकर जनमत और सरकारी नीतियों को परखना और प्रभावित करना।

5. उन्हें उनके जीवन निर्वाह के लिए जंगल और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों के साथ रहने का अधिकार, अपनी संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखने का अधिकार।

6. छात्र इस प्रश्न का उत्तर अपने विवेक से दें।

7. राज्यकृत नागरिकता।

   (i) विवाह द्वारा

   (ii) नौकरी द्वारा

   (ii) आवेदन द्वारा

8. (i) देशद्रोही क्रियाकलाप द्वारा

   (ii) विवाह द्वारा

9. अकाल, बाढ़, युद्ध, सुनामी, महामारी जैसी समस्याओं से।

10. सरदार सरोवर बांध का वर्णन।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तरः-

1. नागरिक-देश के राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करता है वह मतदान, चुनाव लड़ना, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार रखता है।

   विदेशी को ये सभी अधिकार प्राप्त नहीं है।

2. छात्र इस प्रश्न का उत्तर अपने विवेक से दें।

3. किसी देश की पूर्ण सदस्यता, सभी को उपलब्ध होनी चाहिए जो सामान्यतया उस देश में रहते है और काम करते हैं तथा जो नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं। बांग्लादेशी आदि....।

4. क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इससे राष्ट्रीय सीमाओं के दोनों तरफ उन दिक्कतों का सामना करना, सरल हो सकता है जिसमें बहुत से देशों की सरकारों और लोगों की संयुक्त कार्यवाही जरूरी होती है। विजय माल्या का उदहारण।

5. जातिगत आंदोलन - दलित पैथर्स
   पर्यावरणीय आंदोलन - चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओं आंदोलन

6. (i) कोई देश उन्हें स्वीकार नहीं करता।

   (ii) वे शिवरों में या अवैध प्रवासी के रूप में रहने को विवश किए जाते है।

   (iii) वे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते या

   (iv) संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते।

7. भीतरी- जो समाज से स्वीकृति प्राप्त कर लेते हैं और सरकार से नागरिकता के अधिकार।
   बाहरी- जो समाज व राज्य से स्वीकृति प्राप्त नहीं कर पाते।

8. विश्व ग्राम- हम सब संचार के नए माध्यमों द्वारा जैसे टेलिविजन, इंटरनेट आदि से एक दूसरे से जुडाव अनुभव करते हैं आज विश्व के तमाम राष्ट्रों के लोगों में साझे सरोकर एवं भाईचारे की भावना का विकास हो रहा है।

9. नागरिक अधिकार- आस्था और स्वतंत्रता के अधिकार
   सामाजिक अधिकार- न्यूनतम मजदूरी, शिक्षा प्राप्त करने, किसी भी जगह घूमने फिरने की आजादी।

10. (i) 2004 में एक राष्ट्रीय नीति बनाई ताकि फुटपाथी दुकानदारों को पुलिस और नगर प्रशासकों का उत्पीड़न न झेलना पड़ा।

(ii) संविधान की धारा 21 में जीने के अधिकार की गांरटी दी गई है जिसमें आजीविका का अधिकार भी शामिल है।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तरः- (अभ्यास हेतु)

1. (क) काम की तलाश में लोग एक शहर से दूसरे शहर अथवा एक देश से दूसरे देश की ओर जाते हैं, उन्हें प्रवासी कहा जाता है।

(ख) प्रवासी लोग शहरों में घरेलू नौकर, सफाई, कर्मचारी, समाचार पत्र वितरक, रेहड़ी पटरी पर सामान बेचना, फेरी लगाकर सामान भेजना, रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली छोटी-छोटी वस्तुओं को साप्ताहिक बाजारों में बेचना आदि काम करते हैं।

(ग) प्रवासियों के बिना शहरी लोगों का जीवन बहुत प्रभावित हो सकता है, शहरी लोगों के रोजमर्रा के जीवन में प्रवासियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अभी कोरोनावायरस के काल में जब घरेलू नौकर/ नौकरानियाँ छूट्टी पर चली गई तथा लॉक डाउन लग गया तो शहरी लोगों का जीवन बदहाल हो गया था। शहरी लोगों के जीवन में प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, छोटे-छोटे कामों के लिए शहरी लोग प्रवासियों पर ही आश्रित होते हैं।

छः अंकीय प्रश्नों के उत्तरः-

1. (i) बहुत से यूरोपीय देशों में ऐसे संघर्ष हुए जैसे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति।

(ii) एशिया अफ्रीका में भी समान नागरिकता की मांग, संघर्ष से ही प्राप्त की।

(iii) दक्षिण अफ्रीका मे भी अश्वेत जनसंख्या को सत्तारूढ़ श्वेत अल्पसंख्यकों के विरूद्ध लम्बा संघर्ष किया।

2. अधिकांश समाजों में लोगों की योग्यताओं और सामर्थ्य के आधार पर संगठन पाया जाता है लोगों के आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण तथा मौलिक आवश्यकताओं एवं सुविधाओं की दृष्टि से अलग हो सकते है। यदि लोगों को समानता पर लाना है तो नीतियों का निर्धारण करते वक्त लोगों की भिन्न-भिन्न जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए।

3. हाँ, लोकतंत्र में जनता की भागीदारी आवश्यक है इसके लिए नागरिकों का जागरूक होना जरूरी है अगला चरण सरकार का प्रतिवाद हो सकता है परन्तु शर्त है कि अन्य नागरिकों व सरकार के जीवन व संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। विरोध की प्रक्रिया धीमी हो सकती है पर वार्ता द्वारा या संधि द्वारा समस्याओं के समाधान किए जा सकते है।

4. स्वतंत्रता आंदोलन का आधार व्यापक था और विभिन्न धर्म, क्षेत्र और संस्कृति के लोगों को आपस में संबंद्ध होकर प्रयत्न करने पड़ें। भारत में विभाजन को रोका तो नहीं जा सका परंतु स्वतंत्र भारत में धर्मनिरपेक्ष और समावेशी चरित्र को कामय रखा जाए। यह निश्चय संविधान में किया गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के कुछ सुदूरवर्ती समुदायों और कई अन्य समुदायों को पूर्ण तथा समान नागरिकता देने का प्रयास किया गया है।

अध्याय-17

राष्ट्रवाद

राष्ट्रवाद

राष्ट्रवाद का अर्थ हैं एक भोगोलिक क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों में अपनापन कि भावना होना

राष्ट्रवाद क्या हैं?

– एक राजनीतिक सिद्धांत जिसका अर्थ हैं एक देश जो किसी के अधीन नहीं हैं बल्कि स्वशासित हैं

– राष्ट्रवाद स्वयं का एक स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित करने कि बात करता हैं

– राष्ट्र का आत्मनिर्णय का एक अधिकार (केंद्रीय सिद्धांत)

– देश का स्वयं निर्माण का अधिकार (लक्ष्य)

मुख्य बिन्दुः

राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्र तथा राष्ट्रवाद, राष्ट्र के बारे में मान्यताएं, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय, राष्ट्र और बहुलवाद

राष्ट्रवाद क्या हैं? → सामान्यतः यदि जनता की राय ली जाये तो राष्ट्रवाद से आशय राष्ट्रीय ध्वज, देश भक्ति देश के लिए बलिदान जैसे बातें ही सुनने को मिलेंगी। दिल्ली में राजपथ पर देखें जाने वाली गणतंत्र दिवस परेड राष्ट्रवाद का बेजोड़ प्रतीक हैं।

राष्ट्रवाद क्या हैं?

पिछली दो शताब्दियों के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसे सम्मोहक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उभरकर सामने आया हैं जिसने इतिहास रचने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की हैं इसने गुलामी की दासता से मुक्ति दिलाने में सहायता की हैं तो इसके साथ ही यह विरोध, कटुता और युद्धों की वजह भी रहा हैं राष्ट्रवादी संघर्षो ने राष्ट्रों और साम्राज्यों की सीमाओं के निर्धारण-पुनर्निर्धारण में योगदान किया हैं।

राष्ट्रवाद ने उन्नीसवीं शताब्दी में यूरोप की कई छोटी-छोटी रियासतों का एकीकरण किया हैं जैसे जर्मनी और इटली का एकीकरण राष्ट्रवाद की भावना के कारण ही हो पाया था राष्ट्रवाद बड़े-बड़े साम्राज्यों के पतन में भी भागीदार रहा हैं बीसवीं शताब्दीं के शुरूआत में यूरोप में आस्ट्रियाई-हंगरियाई और रूसी साम्राज्य तथा इसके साथ एशिया और अफ्रीका में फ्रांसीसी, ब्रिटिश, डच और पुर्तगाल साम्राज्य के बंटवारे के मूल में राष्ट्रवाद ही थाः

राष्ट्र तथा राष्ट्रवाद → राष्ट्र बहुत हद तक एक काल्पनिक समुदाय होता हैं जो अपने सदस्यों के सामूहिक विश्वास, उम्मीदों और कल्पनाओं के सहारे एक सूत्र में बंधा होता हैं यह कुछ मान्यताओं पर आधारित होता हैं जिन्हें लोग उस समग्र समुदाय के लिए गढ़ते हैं जिससे वे अपनी पहचान कायम करते हैं ऐसा माना जाता हैं कि राष्ट्रों का निर्माण ऐसे समूहों द्वारा किया जाता हैं कुल या भाषा अथवा धर्म या फिर जातीयता जैसी कुछ पहचान का सहभागी होता हैं।

राष्ट्र के बारे में मान्यताएंः

1. **साझे विश्वासः** एक राष्ट्र का अस्तित्व तभी तक ही बना रह सकता हैं जब तक उसके सदस्यों को यह विश्वास हो कि वे एक दुसरे के साथ हैं।

2. **इतिहासः** व्यक्ति अपने आप को एक राष्ट्र मानते हैं उनके अन्दर स्थायी पहचान की भावना होती हैं देश की स्थायी पहचान का ढांचा पेश करने हेतु वे किदवंतियों, स्मृतियों तथा इतिहासिक इमारतों तथा अभिलेखों की रचना के जरिए स्वयं राष्ट्र के इतिहास के बोध की रचना करते हैं।

3. **भू-क्षेत्रः** किसी भू क्षेत्र पर काफी हद तक साथ-साथ रहना एवं उससे संबंधित साझे अतीत की स्मृतियां जन साधारण को एक सामूहिक पहचान का अनुभव कराती हैं जैसे कोई भू क्षेत्र को मातृभूमि या पितृभूमि कहता हैं।

4. **साझे राजनीतिक आदर्शः** राष्ट्र के सदस्यों की एक साझा दृष्टि होती हैं कि वे किस तरह का राज्य बनाना चाहते हैं वे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और उदारवाद जैसे मूल्यों और सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं इन शर्तों के साथ-साथ आना और रहना चाहते हैं।

5. **साझी राजनीतिक पहचानः** लोगों का मानना हैं कि राज्य के बारें में साझी राजनीतिक द्रष्टि व्यक्तियों को एक राष्ट्र के रूप में बांधने के लिए पर्याप्त नहीं होती बल्कि एक समान भाषा या जातीय वंश परम्परा जैसी राजनीतिक पहचान चाहते हैं।

राष्ट्रीय आत्मनिर्णयः

बाकि सामाजिक समूहों से अलग राष्ट्र अपना शासन अपने आप करने और अपने भविष्य को तय करने का अधिकार चाहते हैं दूसरें शब्दों में कहे तो वे आत्मनिर्णय का अधिकार चाहते हैं आत्मनिर्णय के अपने दावे में राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग करता हैं कि उसके प्रथक राजनीतिक इकाई या राज्य के दर्जे को मान्यता या स्वीकार्यता दी जाए।

उन्नीसवीं सदीं में यूरोप में एक संस्कृतिः एक राज्य की मान्यता ने जोर पकड़ा। वर्साय की संधि के बाद विभिन्न छोटे एवं नव स्वतंत्रत राज्यों का गठन हुआ इस कारण राज्य की सीमाओं में भी परिवर्तन हुए बड़ी जनसंख्या का विस्थापन हुआ कई लोग सांप्रदायिक हिंसा के भी शिकार हुए।

अलग-अलग सांस्कृतिक समुदायों को अलग-अलग राष्ट्र राज्य मिले यह ध्यान में रखकर सीमाओं को बदला गया पर ऐसा करना मुमकिन नहीं हो पाया क्योंकि एक राष्ट्र राज्य में एक से ज्यादा नस्ल व संस्कृति के लोग रहते थे।

आश्चर्य की बात हैं जिन राष्ट्र राज्यों ने संघर्षों के बाद स्वाधीनता प्राप्त की किन्तु अब वे अपने भू क्षेत्रों में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करने वाले अल्पसंख्यक समूहों का खंडन करते हैं।

आत्मनिर्णय के आन्दोलनों से कैसे निपटें:

नए राज्यों का गठन करने में समाधान नहीं हैं बल्कि राज्यों को ज्यादा लोकतांत्रिक और समतामूलक बनाने में हैं आत्मनिर्णय के आन्दोलन का समाधान यह हैं कि भिन्न-भिन्न सांस्कृतिक और नस्लीय पहचान के लोग देश में समान नागरिकों तथा मित्रों की तरह सहअस्तित्व पूर्वक रह सकें।

राष्ट्रवाद और बहुलवाद

एक संस्कृति-एक राज्य के विचार को छोड़ने के बाद लोकतांत्रिक देशों ने सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान को स्वीकार करने तथा पहचान के तरीकों की शुरूआत की हैं भारतीय संविधान में भाषायी, धार्मिक एवं सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रावधान हैं।

हालांकि ऐसा हो सकता हैं कि अल्पसंख्यक समूहों को मान्यता एवं सरंक्षण प्रदान करने के बावजूद कुछ समूह प्रथम राज्य की मांग पर अड़े रहे यह विरोधाभाषी तथ्य होगा कि जहां वैश्विक ग्राम की बातें चल रही हैं वहां अभी भी राष्ट्रीय आकांक्षाए विभिन्न वर्गों और समुदायों को उद्देलित कर रही हैं इसके समाधान के लिए संबंधित देश को विभिन्न वर्गों के साथ उदारता एवं दक्षता का परिचय देना होगा साथ ही असहिष्णु एक जातीय स्वरूपों के साथ कठोरता से पेश आना होगा।

प्रश्नावली

एक अंकीय प्रश्न-

1. कौन-सा राष्ट्रवाद में शामिल नहीं है?

    (i) सामान्य इतिहास

    (ii) सामान्य भूमि क्षेत्र

    (iii) आम धारणा

    (iv) सामान्य धर्म

2. निम्नलिखित में से किस संधि ने नए राज्यों का गठन किया?

(i) वर्साय की संधि

(ii) लंदन की संधि

(iii) पेरसि की संधि

(iv) न्यूयॉर्क की संधि

3. किसने कहा कि राष्ट्रवाद हमारा अंतिम गंतव्य नहीं हो सकता है?

(i) पंडित नेहरू

(ii) महात्मा गांधी

(iii) रविंदर नाथ ठाकुर

(iv) अरविंद घोष

4. 'नेशन (Nation)' शब्द किस भाषा से लिया गया है?

(i) ग्रीक

(ii) फ्रेंच

(iii) लैटिन

(iv) रूसी

5. राष्ट्रवाद के विकास में बाधक है

(i) मजबूत ऐतिहासिक विरासत

(ii) सांप्रदायिकता

(iii) भावनात्मक एकीकरण

(iv) सामान्य सभ्यता

अभिकथन और कारण प्रश्न

6. अभिकथन (A) इटली और जर्मनी के एकीकरण में राष्ट्रवाद मुख्य कारक था

कारण (R) इटली और जर्मनी के एकीकरण के दौरान बडी मात्रा में हिंसा देखी गई

(a) A और R दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या है

(b) A और R दोनों सही हैं, लेकिन R A की सही व्याख्या नहीं है

(c) A सही है, लेकिन R गलत है

(d) A गलत है, लेकिन R सही है।

7. अभिकथन (A): वर्तमान में समय में राष्ट्रवाद की अवधारणा अधिक महत्वपूर्ण नहीं है।

   कारण (R): पूरी दुनिया एक वैश्विक गांव की ओर बढ़ रही है

   (a) A और R दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या है

   (b) A और R दोनों सही हैं, लेकिन R A की सही व्याख्या नहीं है

   (c) A सही है, लेकिन R गलत है

   (d) A गलत है, लेकिन R सही है।

प्रश्न संख्या 8 से 12 में सही या गलत की पहचान कीजिएः

8. राष्ट्र बहुत हद तक एक काल्पनिक समुदाय होता हैं

9. पहले विश्व युद्ध के बाद राज्यों की पुनर्व्यवस्था में एक संस्कृति एक राज्य के विचार को अपनाया गया।

10. नवगठित राज्यों में एक राज्य में एक ही नस्ल के लोग रहते हैं।

11. रवीन्द्रनाथ टैगोर ओपेनिवेशिक शासन के धुर विरोधी थे।

12. राष्ट्रवाद का बड़े-बड़े राज्यों के पतन और एकीकरण में कोई योगदान नहीं रहा हैं।

दो अंकीय प्रश्नः-

1. ''राष्ट्रवाद ने लोगों को संगठित किया है साथ ही विभाजित भी किया है'' कैसे?
2. ''राष्ट्रवाद साम्राज्यों के पतन के लिए जिम्मेदार रहा है'' कैसे? कुछ उदाहरण दीजिए।
3. 'राष्ट्र' शब्द और राष्ट्रवाद में क्या अंतर है?
4. 'सांझे विश्वास' किस प्रकार राष्ट्रवाद के विकास में सहायक हैं।
5. साझी राजनीतिक पहचान से क्या अभिप्राय है?
6. क्या 'राष्ट्रीय आत्मनिर्णय' की मांग समकालीन विश्व में विरोधाभासी है?
7. राष्ट्रीय पहचान के लिए समावेशी नीति से कार्य करने का क्या अर्थ है?
8. बहुलवाद से क्या अभिप्राय है?

चार अंकीय प्रश्नः-

1. राष्ट्रवाद ने राज्यो को जोड़ा भी है और तोड़ा भी है। कैसे?
2. ''भूमंडलीकरण के दौर में आज भी राष्ट्रीय आकांक्षाए सिर उठाती रहती है'' इस समस्या का समाधान कैसे संभव है?
3. ''एक संस्कृति एक राज्य'' इस नीति से क्या अभिप्राय है? क्या यह नीति प्रयोग में लाना संभव है?
4. आत्मनिर्णय के सिद्धांत के द्वारा जिन राष्ट्रों ने स्वाधीनता प्राप्त की, आज वे ही अपने भू-क्षेत्रों में राष्ट्रीय आत्म निर्णय के अधिकार की मांग का विरोध करते है? क्यों?
5. राष्ट्रवाद के मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ कौन सी हैं?
6. 'राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है अपने शासन में अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों और संस्कृति पहचान का आदर किया जाएं'। क्या आप इस कथन से सहमत हैं?
7. राष्ट्र बहुत हद तक एक काल्पनिक समुदाय होता है जो अपने सदस्यों के सामूहिक विश्वास, आकांक्षाओं और कल्पनाओं के सहारे एवं सूत्र में बंधा होता है यह कुछ खास मान्यताओं पर आधारित होता है जिन्हें लोग उस समग्र समुदाय के लिए गठन करते हैं जिससे वे अपनी पहचान कायम करते हैं।

   प्र.1 राष्ट्रवाद क्या हैं?

   प्र.2. राष्ट्रवाद की सीमाएँ लिखिए।

   प्र.3. राष्ट्र के निर्माण में इतिहास का क्या योगदान रहा है?

   प्र.4. राष्ट्र क्या है?

8. ''यद्यपि बाहरी रूप में लोगों में विविधता और अनगिनत विभिन्नताएं थी, परंतु हर जगह एकात्मकता की वह जबर्दस्त छाप थी जिसने हमें युगों तक जोड़े रखा, चाहे हमें जो भी राजनीतिक सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य झेलना पड़ा हो''।

8.1 उपरोक्त कथन किसका है?

(A) महात्मा गाँधी	(B) रविन्द्रनाथ टैगौर
(C) पंडित नेहरू	(D) सरदार पटेल

8.2 लेखक किस विविधता और विभिन्नता की बात कर रहा है?

(A) धर्म, भाषा, जाति (B) राज्य, देश

(C) जमीन, जंगल (D) पड़ोसी देश

8.3 राजनीतिक दुर्भाग्य से लेखक का क्या अभिप्राय है?

(A) परतंत्रता (B) आजादी

(C) राष्ट्रवाद (D) विश्वग्राम

8.4 भारत में क्या विविध मात्रा में है

(A) विविधता (B) भाषाई विवाद

(C) धार्मिक विवाद (D) उपर्युक्त सभी

9. ''राष्ट्रवाद मेरी आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकती, मेरी शरण स्थली तो मानवता है। मै हीरों की कीमत पर शीशा नहीं खरीदूंगा, और जब तक मैं जीवित हूँ देशभक्ति को मानवता पर कदापि विजयी नहीं होने दूंगा।

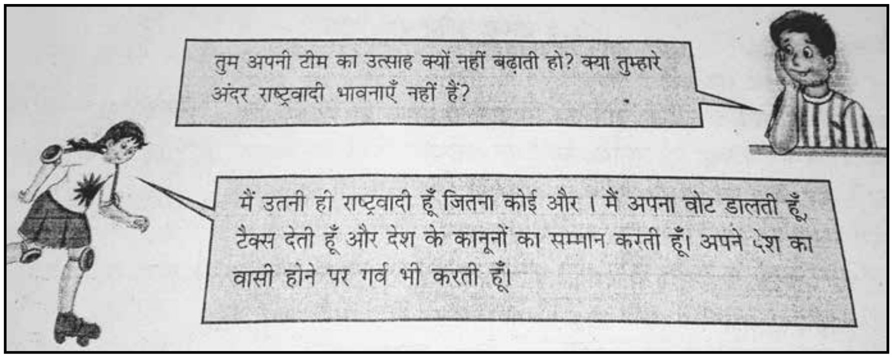

9.1 लेखक राष्ट्रवाद की बजाय मानवता को क्यों महत्व दे रहा है?

(A) मानवता भलाई के काम आती है

(B) मानवता उत्तम है

(C) मानवता भ्रष्ट है

(D) मानवता आवश्यक है

9.2 ‘देशभक्ति को मानवता पर विजयी न होने देने’ का क्या अभिप्राय है?

(A) देशभक्ति ने साम्राज्यों का पतन किया है

(B) देशभक्ति भ्रष्ट बनाती है

(C) देशभक्ति मानव को कट्टर बनाती है

(D) देशभक्ति आवश्यक नहीं है

9.3 ‘हीरों की कीमत पर शीशा नहीं खरीदूंगा इस कथन में लेखक ने हीरा और शीशा किसे कहा है?

(A) मानवता व देशभक्ति

(C) देशभक्ति व जाति

(B) धर्म व देशभक्ति

(D) देशभक्ति

9.4 राष्ट्रवाद से कौन ज्यादा प्रभावित होता है।

(A) पुरुष

(B) महिला

(C) युवा

(D) वृद्ध

छः अंक वाले प्रश्नः

1. राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाले विभिन्न तत्वों का वर्णन करो?

2. ‘‘संघर्षवादी ताकतों से निपटने में तानाशाही सरकारों की बजाय लोकतांत्रिक सरकारें अधिक कारगर सिद्ध हुई है? कैसे।

3. राष्ट्रवाद के दायरें क्या-क्या हैं। (सीमाएं)।

उत्तरमाला

क

1. (iv) सामान्य धर्म
2. (i) वर्साय की संधि
3. (iii) रवींद्र नाथ ठाकुर
4. (iii) लेटिन
5. (ii) साम्यवाद

अभिकथन और कारण उत्तरः

6. A सही है, लेकिन R गलत है
7. A और R दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या करता है
8. सही
9. सही
10. गलत
11. सही
12. गलत

दो अंकीय प्रष्नों के उत्तरः-

1. राष्ट्रवाद ने उत्कृष्ट निष्ठाओं के साथ-साथ गहरे विद्वेषों को प्रोत्साहित किया है। इसने जनता को एकत्र किया है तो विभाजित भी किया है।
2. बीसवीं शताब्दी की शुरूआत में यूरोप में अस्ट्रियाई- हंगेरियाई और रूसी साम्राज्यों के पतन तथा उनके साथ एशिया और अफ्रीका में फ्रांसीसी, ब्रिटिश, डच और पुर्तगाली साम्राज्य के बंटवारें में राष्ट्रवाद ही था।
3. राष्ट्रः- राष्ट्र जनता का कोई आकस्मिक समूह नहीं है यह परिवार से भिन्न है राष्ट्र के अधिकतर सदस्यों को प्रत्यक्ष तौर पर न कभी जान पाते हैं और न ही उनके साथ वंशानुगत संबंध जोड़ने की जरूरत पड़ती है।

   राष्ट्रवादः- राष्ट्रवाद एक भावना है, देश प्रेम की भावना जो विकसित होती है साझे विश्वास, साझां इतिहास, साझें भू क्षेत्र साझे राजनीतिक आदर्श तथा साझी राजनीतिक पहचान के द्वारा।

4. साझे विश्वासः- राष्ट्र का निर्माण विश्वास के द्वारा होता है राष्ट्र ऐसी इमारते नहीं जिन्हें हम स्पर्श कर सकें, न ही ये ऐसी वस्तुएं है जिनका लोगों के विश्वास से स्वतंत्र अस्तित्व हो। राष्ट्र की तुलना एक टीम से की जा सकती है।

5. साझी राजनीतिक पहचानः- अधिकांश समाज सांस्कृतिक रूप से विविधता से भरे हैं। एक ही भू-क्षेत्र में विभिन्न धर्म और भाषाओं के लोग मिलजुल कर रहते हैं इसलिए अच्छा होगा यदि हम राष्ट्र की कल्पना राजनीतिक शब्दावली में करे न कि सांस्कृतिक पदों में। लोकतंत्र में किसी खास नस्ल, धर्म या भाषा से संबद्धता की जगह एक मूल्य समूह के प्रति निष्ठा की आवश्यकता होती है।

6. राष्ट्रीय आत्मविश्वासः- उस वक्त विरोधाभासी लगता है जब हम उन राष्ट्रराज्यों को, जिन्होंने स्वंय संघर्षों के बल पर स्वाधीनता प्राप्त की, किंतु अब वे अपने भू-क्षेत्रों में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करने वाले अल्पसंख्यक समूहों का खंडन कर रहे हैं।

7. समावेशी नीति का आशय है जो राष्ट्र राज्य के समस्त सदस्यों के महत्व एवं अद्वितीय योगदान को मंजूरी दे सके अर्थात् अल्पसंख्यक समूहों और उनके सदस्यों की संस्कृति, भाषा और धर्म के लिए संवैधानिक संरक्षण के अधिकार।

8. बहुलवादः जब एक संस्कृति एक राज्य की अवधारणा को त्याग दिया गया तब नई व्यवस्था वह होगी जहां अनेक संस्कृतियां और समुदाय एक ही देश में फल फूल सकें। भारतीय संविधान में भाषायी, धार्मिक एवं सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तरः-

1. राष्ट्रवाद ने उन्नीसवीं शताब्दी के यूरोप में कई छोटी-छोटी रियासतों के एकीकरण से वृहत्तर राष्ट्र राज्यों की स्थापना का मार्ग दिखाया। आज के जर्मनी, इटली का गठन एकीकरण और सुदृढ़ीकरण भी इसी प्रक्रिया के माध्यम से हुआ था।

   किन्तु राष्ट्रवाद बड़े-बड़े साम्राज्यों के पतन में भी भागीदार रहा है। बीसवीं शताब्दी में यूरोप में आस्ट्रियाई-हंगेरियाई और रूसी साम्राज्य तथा इनके साथ एशिया और अफ्रीका में फ्रांसीसी, ब्रिटिश, डच एवं पुर्तगाली साम्राज्य के बंटवारे के मूल में 'राष्ट्रवाद' ही था।

2. भूमंडलीकरण का दौर चल रहा है वहीं दूसरी ओर कुछ राष्ट्रीय आकांक्षाए सिर उठाती रहती है। ऐसी मांगों से निपटने का एक मात्र तरीका लोकतांत्रिक तरीका है। इससे निपटने में संबंधित देश विभिन्न वर्गों के साथ उदारता एवं दक्षता का परिचय दें।

परंतु इसका आशय यह कदापि नहीं है कि हम राष्ट्रवाद के असहिष्णु एकजातीय स्वरूपों के साथ कोई सहानुभूति बरतें।

3. एक संस्कृति-एक राज्य की धारणा की शुरूआत 19 वीं सदी के यूरोप में सामने आई परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् राज्यों की पुर्नव्यवस्था में इस विचार को परखा गया परंतु आत्म निर्णय की सभी मांगों को संतुष्ट करना संभव नहीं था।

   आज भी इस नीति को प्रयोग में ला पाना संभव नहीं तभी बहुलवाद की प्रचलन है अर्थात् बहुत से समुदाय और संस्कृतियों के लोग एक ही देश में फल फूल सकें।

4. आत्मनिर्णयः क्योंकि इससे आबादी का देशांतरण, सीमाओं पर युद्ध और हिंसा की घटनाएं होती रहती है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जितने भी नए राष्ट्र राज्य बने उसके परिणामस्वरूप जनसंख्या का बड़ी मात्रा में विस्थापन हुआ, लाखों लोग अपने घरों से उजड़ गए और उस जगह से बाहर धकेल दिए गए जहां पीढ़ियों से उनका घर था।

5. (i) सांप्रदायिकता

   (ii) जातिवाद

   (iii) क्षेत्रवाद

   (iv) भाषावाद

   (v) नस्लवाद

6. जो राष्ट्र राज्य अपने शासन में अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान का आदरनहीं करते उसके लिए अपने सदस्यों की निष्ठा प्राप्त करना कठिन होता है।

   इसके लिए राज्यों को ज्यादा लोकतांत्रिक व समतामूलक बनना होगा ताकि भिन्न-भिन्न सांस्कृतिक और नस्लीय पहचान के लोग देश में समान नागरिक और मित्रों की तरह रह सकें।

7. 1. राष्ट्र बहुत हद तक काल्पनिक समुदाय होता है तो अपने सदस्यों के सामूहिक विश्वास, आकांक्षाओं और कल्पनाओं के सहारे एक सूत्र में बंधा होता है।

   2. राष्ट्रवाद व्यक्ति को एक क्षेत्र तक सीमित कर देता है जिससे विश्वग्राम की भावना अधूरी रह जाती है और यह भूमण्डलीकरण में संभव नहीं हैं।

   3. राष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों के अन्दर एक ऐतिहासिक पहचान की भावना होती है।

   4. एक ही समुदाय के लोग जो एक निश्चित भू-भाग में रहते हैं।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तरः-

8. 8.1 पं. जवाहर लाल नेहरू

   8.2 अपने देश विभिन्न धर्म, भाषाएं, जातियां आदि है उसके बावजूद एकता दिखाई देती है।

   8.3 राजनीतिक दुर्भाग्य का अर्थ है वह लंबा परतंत्रता का समय जो ब्रिटिश काल में भारत को झेलना पड़ा।

9. 9.1 लेखक चाहता है कि राज्यों की सीमाएं नहीं होनी चाहिए बल्कि सबको मानवता की भलाई के लिए काम करना चाहिए ताकि विश्व हमें विश्व ग्राम की तरह नजर आए।

   9.2 देशभक्ति ने बहुत साम्राज्यों का पतन किया है इसलिए मानव को प्राथमिकता दी जाए राज्य या राष्ट्र को नहीं।

   9.3 लेखक का अभिप्राय है कि हमे विश्व ग्राम को प्राप्त करने की ओर चलना चाहिए देश या राष्ट्र की सीमाएं नहीं बनानी चाहिये।

छः अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. (i) साझां इतिहास

   (ii) साझें विश्वास

   (iii) साझां भू-क्षेत्र

   (iv) साझें राजनीतिक आदर्श

   (v) साझीं राजनीतिक पहचान

2. लोकतांत्रिक सरकारें समतामूलक व समावेशी होने के लिए संघर्षवादी ताकतों से निपटने में निपुण होती है बजाय तानाशाही सरकारों के। आज संसार एक विश्व ग्राम का स्वप्न देख रहा है ऐसे में संघर्षवादी शक्तियां उस स्वप्न में बाधा उत्पन्न करती है ऐसी भागों से लोकतांत्रिक ढंग से समाधान किया जा सकता है और इसमें संबंधित देश को अपना योग्यता और दक्षता का परिचय देना होगा।

   यह आवश्यक है कि हम राष्ट्रीय पहचान के इनके दावों की सत्यता को स्वीकार करें परंतु इसका यह आशय कदापि नहीं है कि हम राष्ट्रवाद के असहिष्णु और एक जातीय स्वरूपों के साथ कोई सहानुभूति बरतें।

3. (i) क्षेत्रवाद

(ii) नैतिक मूल्यों का पतन

(iii) धार्मिक विविधता

(iv) आर्थिक विषमता

(v) भाषायी विषमता

अध्याय-18

धर्म निरपेक्षता

धर्म निरपेक्षता का अर्थ

बिना किसी भेद–भाव के सभी भारतीय नागरिकों को अपना–अपना धर्म मानने व प्रसार की स्वतंत्रता

- धर्मों के बीच वर्चस्वाद (मैं श्रेष्ठ की संस्कृति)
- धर्मों के अन्दर वर्चस्वाद (इसमें भी मैं ही श्रेष्ठ)

धर्म निरपेक्ष राज्य

राज्य का अपना कोई धर्म नहीं

धर्म निरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल

–अमेरिकी मॉडल
–यूरोपीय मॉडल
–राज्य व धर्म की पृथकता

धर्म निरपेक्षता का भारतीय मॉडल

–मौलिक अधिकारों द्वारा प्रदत्त
– 42वें संशोधन द्वारा 1976 में पथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया
–राज्य व धर्म पूर्णतः पृथक नहीं

मॉडल की आलोचना

–धार्मिक पहचान का खतरा
–परिश्चम से आयातित व अन्य तर्क

मुख्य बिन्दुः

1. धर्म निरपेक्षता का अर्थ।
2. धर्मों के बीच वर्चस्ववाद
3. धर्म के अन्दर वर्चस्ववाद
4. धर्म निरपेक्ष राज्य
5. धर्म निरपेक्षता का पश्चिमी मॉडल
6. धर्म निरपेक्षता का भारतीय मॉडल
7. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
8. भारतीय धर्म निरपेक्षता की आलोचना

धर्म निरपेक्षता का अर्थ हैः-

- बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को अपना-अपना धर्म मानने व प्रचार करने की स्वतंत्रता अर्थात् जब राज्य धर्म को लेकर कोई भेद-भाव न करें।

- भारत विविधताओं का देश है, लोकतन्त्र को बनाए रखने के लिए सभी को समान अवसर प्रदान करने का कार्य कठिन है। इसलिए भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। संविधान के घोषणा-पत्र में धार्मिक वर्चस्ववाद का विरोध करना, धर्म के अन्दर छिपे वर्चस्व का विरोध करना तथा विभिन्न धर्मों के बीच तथा उनके अन्दर समानता को बढ़ावा देना आदि की घोषणा का वर्णन है।

धर्मों के बीच वर्चस्ववादः-

- हर भरतीय नागरिक को देश के किसी भी भाग में आज़ादी और प्रतिष्ठा के साथ रहने का अधिकार है, फिर भी भेदभाव के अनेक उदाहरण पाए जाते हैं जिससे धर्मों के बीच वर्चस्ववाद बढ़ा, क्योंकि हम स्वयं के धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं लेकिन दूसरे के धर्म को हीन।

धर्म के अंदर वर्चस्ववादः-

धर्म के अंदर भी अनेक प्रकार के भेद-भाव तथा वरीयताएँ स्थित हैं। जो आपसी वैमनस्य का कारण बनती हैं।

धर्म निरपेक्ष राज्यः-

- वह राज्य जहां सरकार की तरफ से किसी धर्म को अधिकारिक (कानूनी) मान्यता न दी गई हो।
- सर्व धर्म समभाव की अवधारणा को महत्व।
- धार्मिक समूह के वर्चस्व को रोकना
- धार्मिक संस्थाओं एवं राज्यसत्ता की संस्थाओं के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए। तभी शांति, स्वतंत्रता और समानता स्थापित हो पाएगी।
- किसी भी प्रकार के धार्मिक गठजोड़ से परहेज।
- ऐसे लक्ष्यों व सिद्धान्तों के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए जो धार्मिक उत्पीड़न, भेदभाव और वर्जनाओं से आज़ादी को महत्त्व दें तथा शांति व धार्मिक स्वतंत्रता को स्थापित करें।

धर्मनिरपेक्षता का पश्चिमी मॉडलः-

- अमेरिकी मॉडल-धर्म और राज्य सत्ता के संबंधविच्छेद को पारस्परिक निषेध के रूप में समझा जाता है। राजसत्ता धर्म के मामले में व धर्म राजसत्ता के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते।
- ये संकल्पना स्वतंत्रता और समानता की व्यक्तिवादी ढंग से व्याख्या करती है।
- धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधार के लिये कोई जगह नहीं है।

धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडलः-

- भारतीय धर्म निरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देती।
- अल्पसंख्यक तथा सभी व्यक्तियों को धर्म अपनाने की आजादी है।
- भारतीय राज्य धार्मिक अत्याचार का विरोध करने हेतु, धर्म के साथ निषेधात्मक संबंध भी बना सकता है।
- भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को खुद अपनी समस्याएं खोजने का अधिकार है तथा राज्यसत्ता के द्वारा सहायता भी मिल सकती है।
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन 1976 के बाद 'पंथ निरपेक्ष' शब्द जोड़ दिया गया है।
- मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, सभी धर्मों को समान अवसर प्रदान करते हैं।

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकारः-

- अनुच्छेद 25 से 28 तक

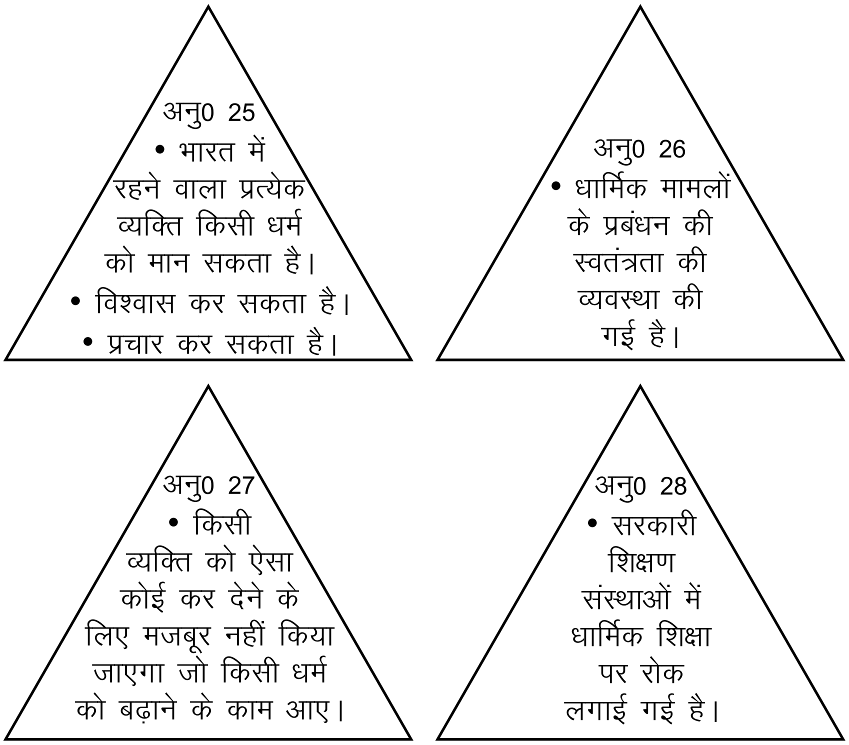

भारतीय धर्म निरपेक्षता की आलोचनाएँः

- विरोधियों के अनुसार धर्म निरपेक्षता धर्म विरोधी है तथा धार्मिक पहचान के लिए खतरा पैदा करती है।
- पश्चिम से आयातित है।
- अल्पसंख्यक अधिकारों की पैरवी करती है। अल्पसंख्यकवाद का आरोप मढ़ा जाता है।
- वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देती है।
- अतिशय हस्तक्षेपकारी क्योंकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्यसत्ता समर्थित धार्मिक सुधार की इजाजत देती है।

असंभव परियोजनाः-

- धर्म निरपेक्षता की नीति बहुत कुछ करना चाहती है परन्तु यह परियोजना सच्चाई से दूर है जो असम्भव है।
- अनेक आलोचनाओं के बाद भी भारत की धर्म निरपेक्षता की नीति भविष्य की दुनिया का प्रतिबिम्ब प्रस्तुत करती है। भारत में महान प्रयोग किए जा रहें हैं। जिसे पूरा विश्व उत्सुकता से देखता है। यूरोप अमेरिका तथा मध्यपूर्व के कुछ देश धर्म संस्कृति की विविधता से भारत जैसे दिखने लगे है।

प्रश्नावली

एक अंकीय प्रश्नः-

1. कथनः अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को किसी भी धार्मिक विश्वास को मानने और उसका प्रचार करने का अधिकार है।

   कारणः राज्य धार्मिक प्रभावों से जुड़ी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को विनियमित या प्रतिबंधित नहीं कर सकता।

   A- दोनों सही हैं तथा कारण, कथन की सही व्याख्या कर रहा है।

   B- दोनों सही हैं लेकिन कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है।

   C- कथन सही है कारण गलत।

   D- कथन गलत है कारण सही है।
2. धर्म निरपेक्षता/ पंथ निरपेक्षता क्या है?
3. धर्मनिरपेक्ष/पंथनिपेक्ष राज्य किसे कहते हैं?
4. क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष/पंथनिरपेक्ष राज्य है?
5. ''अतातुर्क'' का क्या अर्थ है?
6. ''मुस्तफा कमाल पाशा'' ने अपना नाम क्या रखा था?
7. भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था?
8. भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेदों के अंतर्गत दी गई है?

9. धर्मनिरपेक्ष/पंथ निरपेक्ष राज्य की एक विशेषता लिखिए।

10. ''सांप्रदायिकता'' से क्या अभिप्राय है?

11. भारतीय लोकतंत्र को सांप्रदायिकता से क्या खतरा है?

12. भारत किस प्रकार का राज्य है?

    (a) हिंदू राज्य (b) मुस्लिम राज्य

    (c) ईसाई राज्य (d) धर्मनिरपेक्ष/पंथ निरपेक्ष राज्य

13. भारतीय संविधान के कौन-से अनुच्छेदों द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई?

    (a) 29 से 38 (b) 25 से 28

    (c) 19 से 22 (d) 14 से 18

14. धर्मनिरपेक्ष/पंथ निरपेक्ष राज्य से क्या अभिप्राय है?

    (a) जो किसी धर्म पर आधारित न हो

    (b) जो किसी एक धर्म पर आधारित हो

    (c) जो बहुसंख्यक नागरिकों के धर्म पर आधारित हो

    (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

15. भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था?

    (a) 44वां (b) 46वां

    (c) 42वां (d) 52वां

16. धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषता हैः

    (a) राज्य का कोई धर्म नहीं होता (b) धार्मिक स्वतंत्रता

    (c) सभी धर्मों में समानता (d) उपरोक्त सभी

17. आजाद भारत में ''सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण''। यह कथन किसका है?

    (a) महात्मा गांधी का (b) डॉ बी.आर. अंबेडकर का

    (c) जवाहरलाल नेहरू का (d) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का

18. निम्न में से क्या भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना का एक कारण हैः

(a) राज्य का अपना कोई धर्म नहीं

(b) संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है

(c) अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पैरवी करती है

(d) भारतीय राज्य धार्मिक अत्याचार का विरोध करता है

19. धर्मनिरपेक्षता के मार्ग में बाधा है?

(a) अराजकतावादी तत्व (b) सांप्रदायिकता

(c) धार्मिक विद्वेष (d) उपर्युक्त सभी

20. निम्नलिखित कथन मैं रेखांकित को सही करके पुनः लिखिए-

''धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के भाग चार से संबंधित है।''

अवतरण /मानचित्र /कार्टून आधारित प्रश्न

21. निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

जवाहर लाल नेहरू जी स्वयं किसी का अनुसरण नहीं करते थे। ईश्वर में उनका विश्वास ही नहीं था लेकिन उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म के प्रति विद्वेष नहीं था। इस अर्थ में नेहरू तुर्की के अतातुर्क से काफी भिन्न थे। साथ ही, वे धर्म और राज्य के बीच पूर्ण संबंध विच्छेद के पक्ष में भी नहीं थे। उनके विचार के अनुसार, समाज में सुधार के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्य में यदि आवश्यक हो तो राज्य सत्ता धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। जातीय भेदभाव, दहेज प्रथा और सती प्रथा की समाप्ति के लिए कानून बनवाने तथा देश की महिलाओं को कानूनी अधिकार और सामाजिक स्वतंत्रता मुहैया कराने में नेहरू ने खुद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

22.1 नेहरू जी के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है?

(a) राज्य का अपना धर्म विशेष होगा

(b) राज्य द्वारा सभी धर्मों का समान संरक्षण होगा

(c) राज्य धर्म के लिए कानून बनाएगा

(d) उपरोक्त कोई नहीं

22.2नेहरू जी किस धर्म का अनुसरण करते थे?

(a) हिंदू धर्म का

(b) बौद्ध धर्म का

(c) ईसाई धर्म का

(d) स्वयं किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे

22.3नेहरू जी का तुर्की के अतातुर्क से क्या संबंध थाः

(a) अतातुर्क के अनुयाई थे

(b) अतार्तुक के सहयोगी थे

(c) अतातुर्क के विचारों से भिन्न विचार रखते थे

(d) अतातुर्क के सहपाठी थे

22.4धर्म और राज्य के बीच संबंधों को लेकर नेहरू जी के क्या विचार थेः

(a) नेहरू जी धर्म और राज्य के बीच पूर्ण संबंध विच्छेद के पक्ष में थे

(b) नेहरू जी धर्म और राज्य के बीच पूर्ण संबंध विच्छेद के पक्ष में नहीं थे

(c) नेहरू जी धर्म और राज्य को दो अलग-अलग दृष्टिकोणों से देखते थे

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

रिक्त स्थान भरिए-

22. धर्मनिरपेक्ष राज्य उसे कहते हैं, जो किसी .... पर आधारित न हो।

23. धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी लोगों को धर्म की .... प्राप्त होती है।

24. भारतीय संविधान के अनुच्छेद .... के अनुसार सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है।

25. 1976 में ....संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़कर भारत को स्पष्ट शब्दों में धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया।

26. नेहरू जी भारतीय धर्मनिरपेक्षता के .... थे।

27. निम्नलिखित प्रत्येक कथन के आगे सही अथवा गलत लिखिएः

(a) भारत एक धर्म पक्षीय राज्य है

(b) पाकिस्तान एकधर्म पक्षीय राज्य है

(c) भारत में अलग-अलग जातियों और वर्गों के साथ अलग-अलग व्यवहार किया जाता है।

(d) 1928 में नई तुर्की वर्णमाला को संशोधित लेटिन रूप में अपनाया गया

(e) सांप्रदायिकता समाज के विकास में बाधा उत्पन्न करती है

दो अंकीय प्रश्नः- (उत्तर 50 से 60 शब्द)

1. धर्म शब्द का क्या अर्थ है?
2. धर्म निरपेक्षता बनाए रखने के दो उपाय बताइए?
3. भारतीय धर्म निरपेक्षता की क्या विशेषता है?
4. धर्म से राज्य की सैद्धान्तिक दूरी से आप क्या समझते हैं?
5. धर्म निरपेक्षता की कोई दो कमियां लिखिए?
6. 20वीं शताब्दी में तुर्की में किस तरह धर्म निरपेक्षता को अपनाया गया?
7. अंतरधार्मिक वर्चस्व का अर्थ स्पष्ट कीजिए?
8. पश्चिमी धर्म निरपेक्षता का मूल मंत्र क्या है? ये वर्चस्ववाद का उदाहरण कैसे हैं?
9. किसी अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी पृथक शैक्षिक संस्था बनाने की अनुमति होना क्या धर्म निरपेक्षता है? कारण बताइए?

चार अंकीय प्रश्नः- (उत्तर 100 से 120 शब्द)

1. धर्म निरपेक्षता की भारतीय अवधारणा तथा पश्चिमी अवधारणा में क्या अन्तर है?
2. सम्प्रदायिकता का क्या अर्थ है? इसे रोकने के उपाय बताइए?
3. भारत में धर्म निरपेक्षता अपनाने के क्या कारण हैं?
4. धर्म निरपेक्ष राज्य की आलोचना क्यों की जाती है?

अवतरण /मानचित्र/ कार्टून आधारित प्रश्न

1. नीचे दिए गए चित्र का सावधानी पूर्वक अध्ययन करके उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

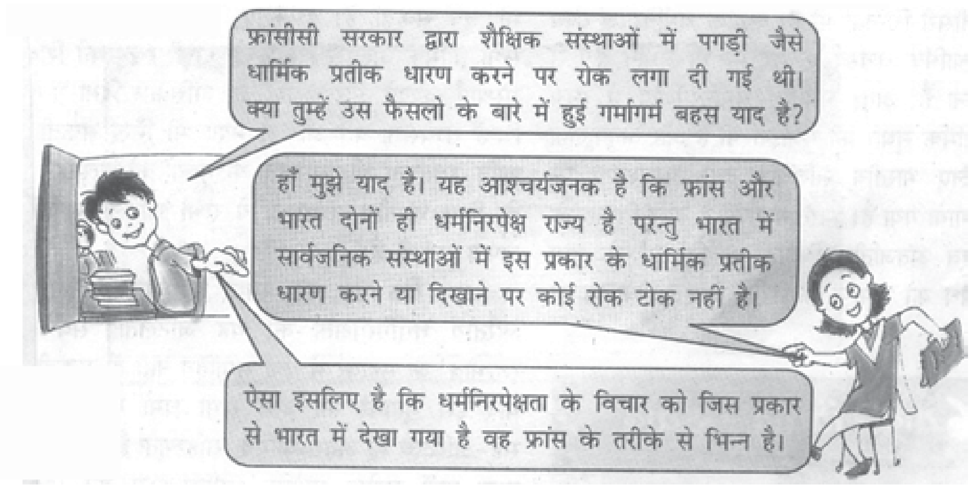

1) फ्रांसीसी सरकार ने शैक्षिक संस्थाओं पर क्या रोक लगा दी थी? (1)

2) क्या फ्रांस एक धर्म निरपेक्ष राज्य है? (1)

3) धर्मनिरपेक्षता के विचार में फ्रांस तथा भारत में क्या अन्तर है? (2)

छः अंकीय प्रश्न

1. भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए।

2. भारतीय धर्मनिरपेक्षता का जोर धर्म और राज्यों के अलगाव पर नहीं अपितु उससे अधिक कई अन्य बातों पर भी है इस कथन को समझाएं।

3. क्या धर्मनिरपेक्षता नीचे लिखी बातों के लिए न्याय संगत है?

   (i) अल्पसंख्यक समुदाय के तीर्थ स्थल के लिए आर्थिक अनुदान देना

   (ii) सरकारी कार्यालयों में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करना

उत्तरमाला

एक अंकीय प्रश्नों के उत्तरः-

1. (A) और (R) दोनों सही है तथा कारण, कथन की सही व्याख्या कर रहा है।
2. धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी विचारधारा है जिसमें सरकार/राज्य का यह कर्तव्य है कि विभिन्न धर्मों के बीच बिना भेदभाव के सभी को समान अवसर प्रदान करना।
3. धर्मनिरपेक्ष/पंथनिरपेक्ष राज्य वह होता है, जिसका अपना कोई धर्म/पंथ नहीं होता तथा जो अपने नागरिकों पर कोई धर्म/पंथ का पालन करने का दबाव नहीं डालता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य न तो धर्म-विरोधी होते हैं, और न ही किसी खास धर्म की स्थापना करते हैं।
4. हां, भारत एक धर्मनिरपेक्ष/पंथनिरपेक्ष राज्य है। इसका वर्णन आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही मिल जाता है। भारत में प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है।
5. ''अतातुर्क'' का अर्थ होता है, ''तुर्कों का पिता''।
6. मुस्तफा कमाल पाशा ने अपना नाम बदलकर ''कमाल अतातुर्क'' रख लिया था।
7. भारतीय संविधान में पंथनिपरेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था।
8. भारतीय संविधान में धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत दी गई है।
9. धर्मनिरपेक्ष राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। वह किसी धर्म विशेष का संरक्षण नहीं करता और न ही कानूनों का निर्माण धर्म के आधार पर करता है।
10. साम्प्रदायिकता से अभिप्राय मनुष्य की उस संकीर्ण सोच से है जो धर्म और सम्प्रदाय के नाम पर पूरे समाज व राष्ट्र के विरोधी तथा धर्म के हितों को महत्व देती है।
11. भारत में अराजकतावादी तत्त्वों द्वारा साम्प्रदायिक दंगे करवाये जाते हैं, तब भारत में लोकतंत्र प्रभावित होता है तथा इससे सामाजिक प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है।
12. (d) धर्मनिरपेक्ष राज्य

13. (b) 25 से 28

14. (a) जो किसी धर्म पर आधारित ना हो

15. (c) 42वां

16. (d) उपर्युक्त सभी

17. (c) जवाहरलाल नेहरू का

18. (c) अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पैरवी करती है

19. (d) उपर्युक्त सभी

20. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के भाग तीन से संबंधित है

21.1 (b) राज्य द्वारा सभी धर्मों का समान संरक्षण होगा

21.2 (d) जवाहरलाल नेहरू जी स्वयं किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे।

21.3 (c) अतातुर्क के विचारों से भिन्न विचार रखते थे।

21.4 (b) नेहरू जी धर्म और राज्य के बीच पूर्ण संबंध विच्छेद के पक्ष में नहीं थे

रिक्त स्थान भरीए के उत्तर-

22. धर्म

23. स्वतंत्रता

24. अनुच्छेद 25

25. 42वें

26. दार्शनिक/पक्षधर

सही/गलत प्रश्न के उत्तर

27. (a) गलत (b) सही (c) गलत (d) सही (e) सही।

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तरः-

1. कर्तव्य का पालन करना
   धर्म में अनेक पंथ समाहित होते हैं।

2. (i) राज्य किसी धर्म का पक्षधर न हो।

(ii) किसी धर्म की तरफदारी न करना।

3. बिना किसी धार्मिक भेदभाव के संविधान में समानता का अधिकार, सभी को अपना धर्म मानने की छूट, कानून के समक्ष समानता बगैर धर्म की परवाह के।

4. राज्य का अपना कोई धर्म नहीं।

5. (i) वोट बैंक की राजनीति।

(ii) एक असंभव परियोजना।

6. (i) मुसलमानों का एक विशेष टोपी पहनने पर रोक।

(ii) पश्चिमी पोशाक पहनने पर बल।

7. (i) किसी विशेष धर्म के अन्दर किसी विशेष समुदाय का बोल बाला या मनमानी करवाना।

(ii) महिलाओं तथा दलितों का शोषण व भेदभाव

8. (i) धर्म तथा राजसत्ता का सम्बन्ध अलग-अलग होना।

(ii) दोनों एक दूसरें के मामलों में हस्ताक्षेप नहीं करते।

(iii) इंटरनेट का प्रयोग, पश्चिमी पोशाक का पहनना मैकडोन्लड का खाना पीना जैसी लाखों चीजों का प्रचलन वर्चस्ववाद कहलाता है।

9. हाँ, धर्म निरपेक्षता है क्योंकि अनुच्छेद 29 के अनुसार, अल्पसंख्यकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है।

अनुच्छेद 31 अल्पसंख्यक तथा अन्य सभी अपनी रूचि की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तरः-

1. (i) भारत में धार्मिक सहनशीलता है जो पश्चिमी देशों में नहीं है।

(ii) विभिन्नता के साथ भेदभाव नहीं, अल्पसंख्यकों को सरंक्षण प्रदान।

2. अपने धर्म को अधिक महत्व देना दूसरे धर्म को हीन समझना।

(i) भेदभाव करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता समाप्त करना।

(ii) दोषी अधिकारियों को दण्डित करना

(iii) भड़काऊ शिक्षा सामग्री में बदलाव

(iv) भेदभाव पैदा करने वाले समाचारों पर रोक

(v) अफवाहों व झूठी खबरों पर ध्यान न देना इन्हें फैलने से रोकना

3. विभिन्न भाषा, जाति, धर्म, विचार आदि के लोगों में बंधुता समानता और एकता बनाए रखने के लिए।

4. (i) धर्म निरपेक्षता एक असंभव परियोजना मानी जाती है।

(ii) वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा मिलता है।

(iii) अल्पसंख्यकों को आर्थिक सहायता एक प्रकार से समानता के अधिकार का विरोध है।

चार अंकीय/कार्टून चित्र/अवतरण आधारित प्रश्नों के उत्तरः-

1. पगडी पहनने पर, बुर्का पहनने पर, धार्मिक प्रतीकों पर रोकं

2. फ्रांस धर्म निरपेक्षता का यूरोपीय (पश्चिमी) मॉडल है।

3. (i) फ्रांस धर्म के प्रतीकों पर रोक लगाता है भारत नहीं

(ii) भारत में अपने धर्म का प्रचार-प्रसार कर सकते हैं परंतु फ्रांस में नही। (कोई अन्य)

छः अंकीय प्रश्नों के उत्तरः-

1. 1. धर्म विरोधी, 2. पश्चिम से आयातित, 3. अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा,

4. हस्तक्षेपकारी, 5. वोट बैंक की राजनीति, 6. एक असंभव परियोजना।

2. लोगों में प्रेम, बंधुता, एकता की भावना पैदा करना, अखण्डता को बचाना, अल्पसंख्यक लोगों की संस्कृति व भाषा का विकास।

3. (i) हां, ये न्यायसंगत है, ताकि अल्पसंख्यक अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें और आर्थिक रूप से पिछड़ों की भावनाओं का आदर हो सके।

(ii) नहीं, ये धर्म निरपेक्षता के विरूद्ध है क्योंकि सरकारी कार्यालय किसी विशेष धर्म का अनुष्ठान करना अन्य धर्मों का विरोधी है।

नमूना प्रश्न पत्र

राजनीति विज्ञान (028)
कक्षा XI (2023-24)

आवंटित समय: 3 घंटे अधिकतम अंक: 80

निर्देश:

1. प्रश्न पत्र में कुल 30 प्रश्नों के साथ पांच खंड (ए, बी, सी, डी और ई) हैं।
2. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
3. प्रश्न संख्या 1-12 एक-एक अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं।
4. प्रश्न संख्या 13-18 प्रत्येक 2 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50-60 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए।
5. प्रश्न संख्या 19-23 प्रत्येक 4 अंक का है। इन प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक 100-120 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए। 4 अंकों के प्रश्नों में से दो में आंतरिक विकल्प है।
6. प्रश्न संख्या 24-26 पैसेज, कार्टून और मानचित्र आधारित प्रश्न हैं। तदनुसार उत्तर दें।
7. प्रश्न संख्या 27-30 प्रत्येक 6 अंकों का है। इन प्रश्नों के उत्तर 170-180 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए।
8. 6 अंक वाले प्रश्नों में आंतरिक विकल्प है।

खंड अ (12 अंक)

1. निम्न में से कौन सा समानता का आयाम नहीं है? 1 अंक

(अ) राजनीतिक समानता

(ब) सामाजिक समानता

(स) धार्मिक समानता

(द) आर्थिक समानता

2. “ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम “ किसने लिखी है? 1 अंक

(अ) महात्मा गांधी

(ब) आंग संग सुकी

(स) नेल्सन मंडेला

(द) अब्राहम लिंकन

3. निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लूटो द्वारा लिखी गई है? 1 अंक

(अ) द पॉलिटिक्स

(बी) रिपब्लिक

(स) ओन लिबर्टी

(द) अ थ्योरी ऑफ़ जस्टिस

4. संुकित रार्ि दारा मावन अधिकार की सा विभौम घोणिा क घोणिा ___________ को की गई थी

(अ) 9 कदसंबर 1948 1 अंक (ब) 10 कदसंबर 1948

(स) 11 कदसंबर 1948

(द) 12 कदसंबर 1948

5. एक रार्ि के निमिाण के लिए निमनलिखित में से ककसकी आवशकिता नहीं है?

(अ) समान सोच 1 अंक

(ब) समान धर्म

(स) समान राजनीतिक मूल्य

(द) सामान्य भूमि

6. निम्नलिखित प्रश्न में, कथन (A) के बाद कारण (R) का कथन है। 1 अंक
उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए:
अभिकथन (A) : भारत सभी धर्मों को समान महत्व देता है।

कारण (R) : भारत की धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी देशों से भिन्न है।

अ. अभिकथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है

ब. अभिकथन और कारण दोनों सही है तथा कारण, कथन की सही व्याख्या करता है

स. अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है

द. अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है

7. निम्नलिखित को मिलाएं 1 अंक

क्र.स.	अधिकार	अनुच्छेद
1	स्वतंत्रता का अधिकार	25-28
2	समानता का अधिकार	23-24
3	शोषण के विरुद्ध अधिकार	19-22
3	धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार	14-18

8. राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? 1 अंक

(अ) भारत के राष्ट्रपति

(ब) प्रधानमंत्री

(स) सुप्रीम कोर्ट

(द) भारत का चुनाव आयोग

9. हाल ही में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है? 1 अंक

(अ) भारतीय जनता पार्टी

(ब) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

(स) बहुजन समाज पार्टी

(द) आम आदमी पार्टी

10. भारत में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? 1 अंक

(अ) राष्ट्रपति

(ब) प्रधानमंत्री

(स) भारत के मुख्य न्यायाधीश

(द) ग्रह मंत्री

11. धन विधेयक किस सदन में पेश किया जा सकता है? 1 अंक

(अ) राज्य सभा

(ब) लोक सभा

(स) ककसी भी सदन में

(द) न लोकसभा में न राज्यसभा में

12. भारत में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? 1 अंक

(अ) उच्चतम न्यायालय

(ब) प्रधानमंत्री

(स) संसद

(द) भारत के मुख्य न्यायाधीश

खंड-ब (12 अंक)

13. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? 2 अंक

14. संविधान में संशोधन क्यों किए जाते हैं? 2 अंक

15. स्थानीय सरकार लोकतंत्र को कैसे मजबूत करती है? 2 अंक

16. धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? 2 अंक

17. क्या वैश्वीकरण के युग में राष्ट्रवाद अप्रासंगिक है? व्याख्या कीजिये 2 अंक

18. किसी व्यक्ति के लिए किसी देश की नागरिकता क्यों आवश्यक हैं? 2 अंक

खंड-स (16 अंक)

19. अधिकारों के साथ हमेशा जिम्मेदारियां (कर्तव्य) आती हैं। इस कथन के समर्थन में लिखिए। 4 अंक

20. राजनीति वह नहीं है जो हमारे राजनेता कर रहे है। इसे समझाओं 4 अंक

अथवा

हमे विद्यालय स्तर पर राजनितिक सिद्धांत क्यों पढना चाहिए? 4 अंक

21. क्या हमें अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंद लगाना चाहिए? अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। (4 अंक)

22. संविधान फैल नहीं हुआ लेकिन हमने इसे फेल करने पर मजबूर कर दिया हैं। आप इस बात से सहमत है? व्याख्या कीजिये (4 अंक)

अथवा

भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया समझाए (4 अंक)

23. कहा जाता है कि हमारा संविधान लोगों के प्रतिनिधि द्वारा नहीं बनाया गया है इसलिए यह प्रतिनिधिमूलक नहीं है। अपने उत्तर के समर्थन में उचित तर्क लिखें। (4 अंक)

खंड-द (12 अंक)

24. अनुच्छेद 368: संसद इस अनुच्छेद में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इस संविधान के किसी भी प्रावधान को जोड़ने, बदलने या निरस्त करने के माध्यम से अपनी संवैधानिक शक्ति में संशोधन कर सकती है।

हम पहले ही देख चुके हैं कि हमारे संविधान निर्माता एक संतुलन बनाना चाहते थे। यदि आवश्यक हो तो संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। लेकिन इसे अनावश्यक और बार-बार होने वाले परिवर्तनों से बचाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, वे चाहते थे कि संविधान "लचीला और साथ ही 'कठोर' हो। लचीले का अर्थ है परिवर्तनों के लिए खुला और कठोर का अर्थ है परिवर्तनों के प्रति प्रतिरोधी एक संविधान जिसे बहुत आसानी से बदला या संशोधित किया जा सकता है, उसे अक्सर लचीला कहा जाता है। संविधानों के मामले में, जिनमें संशोधन करना बहुत कठिन है, उन्हें कठोर बताया गया है। भारतीय संविधान इन दोनों विशेषताओं को जोड़ता है।

(i) हमारे संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे है? 1 अंक

(अ) अध्यक्ष

(ब) संसद

(स) प्रधानमंत्री

(द) राज्यों के मुख्यमंत्री

(ii) हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन का प्रावधान किया गया है 1 अंक

(अ) अनुच्छेद 370

(ब) अनुच्छेद 371

(स) अनुच्छेद 368

(द) अनुच्छेद 369

(iii) हमें संविधान में संशोधन क्यों करना चाहिए? 1 अंक

(अ) संविधान के कुछ प्रावधान कुछ समय बाद अप्रासंगिक हो जाते हैं।

(ब) हमारे पक्ष में प्रावधान बनाने के लिए

(स) संविधान को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए

(द) इनमे से कोई भी नहीं

(iv) हमारा संविधान किस प्रकार का हैं? 1 अंक

(अ) कठोर

(ब) लचीला

(स) कठोर और लचीला दोनों

(द) इनमे से कोई भी नहीं

25. भारत के दिए गए रूपरेखा राजनीतिक मानचित्र में, चार राज्यों को (1), (2), (3) और (4) के रूप में चिह्नित किया गया है। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर इन राज्यों की पहचान करें और अपनी उत्तर पुस्तिका में उपयोग की गई जानकारी के संबंधित क्रमांक और संबंधित अक्षरों के साथ

निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार उनके सही नाम लिखें:

1. सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य 1 अंक
2. राज्य जिसमें फिल्म उद्योग मौजूद है 1 अंक
3. राज्य जहां कन्नड़ भाषा बोली जाती है 1 अंक
4. राज्य जिसकी राजधानी अमरावती है। 1 अंक

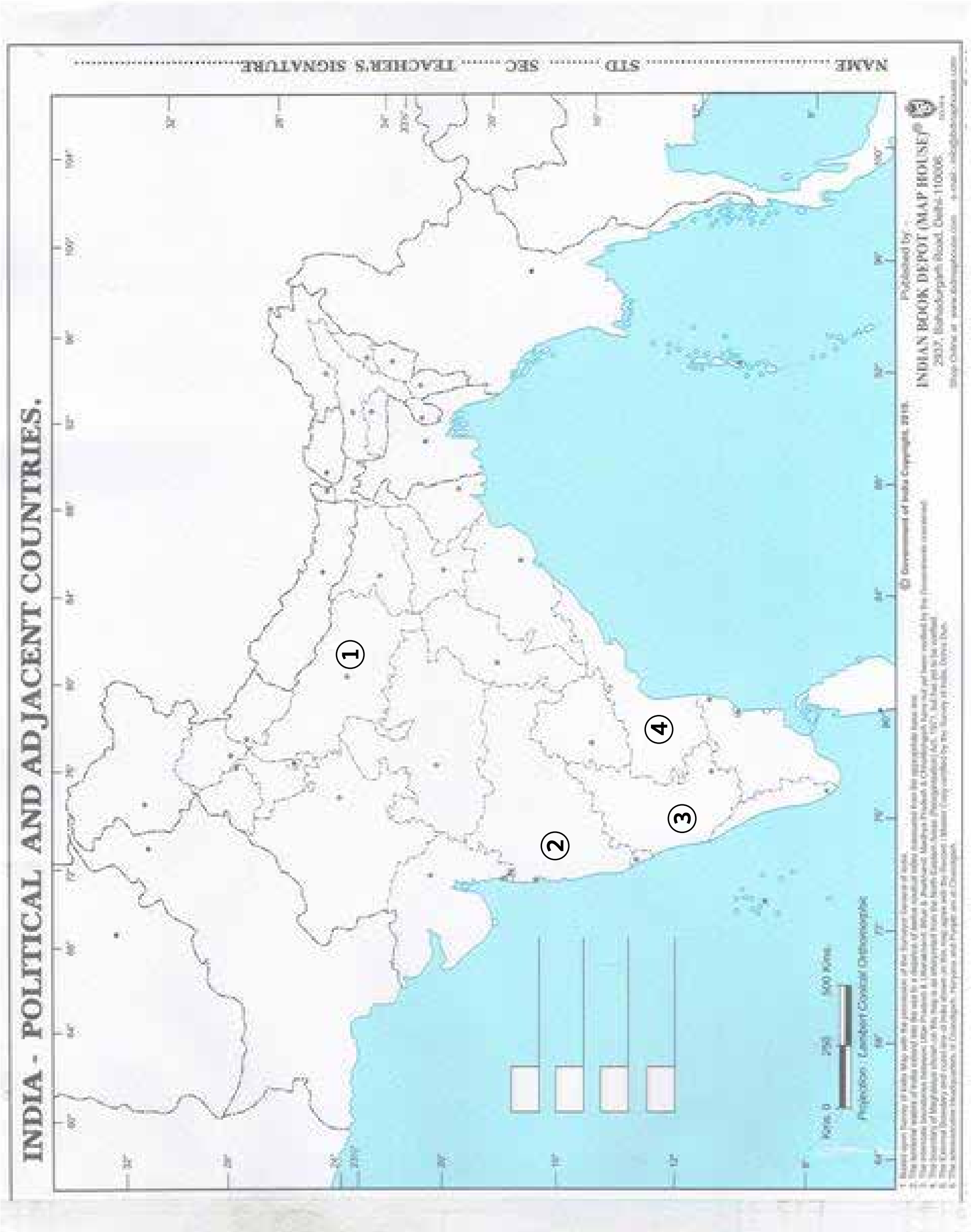
INDIA - POLITICAL AND ADJACENT COUNTRIES.
NAME
STD
SEC
TEACHER'S SIGNATURE
1
2
3
4
INDIAN BOOK DEPOT (MAP HOUSE)
Projection : Lambert Conical Orthomorphic

क्र.स.	सम्बंधित अंक	राज्य का नाम
1		
2		
3		
4		

26. दिए गए कार्टून का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें:

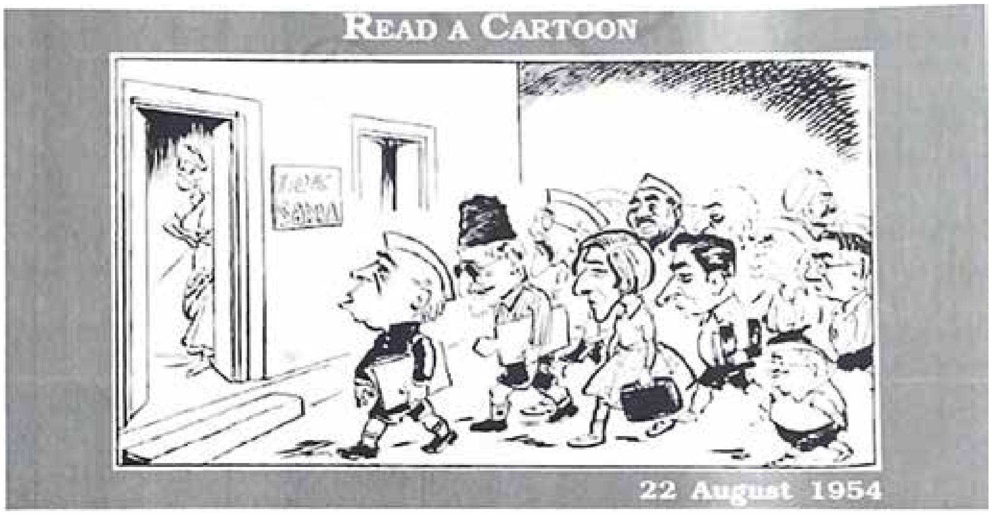

1. मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? 1 अंक

2. प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की जवाबदेही किसके प्रति होती है? 1 अंक

3. बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का क्या महत्व है? 2 अंक

खंड ड. (24 अंक)

27. भारत में सकारात्मक कार्य उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच की खाई को कम कर रहे हैं। इस कथन के समर्थन में तर्क लिखिए 6 अंक

अथवा

जॉन राल्स द्वारा प्रतिपादित न्याय के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। 6 अंक

28. वैश्वीकरण के युग में मानव अधिकारों की अवधारणा मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बनकर उभरी है। विस्तार से व्याख्या करो 6 अंक

अथवा

कोई व्यक्ति भारत में नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है? सभी तरीके बताएं 6 अंक

29. समकालीन दिनों में राष्ट्रवाद की परिभाषा कैसे बदल गई है? व्याख्या कीजिये 6 अंक

अथवा

भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपना मत लिखिए 6 अंक

30. भारतीय राजनीति में अपराधी दूसरों की अपेक्षा अधिक सफल होते हैं। अपने विचार विस्तार से लिखें। 6 अंक

अथवा

हमें भारत में संसद की आवश्यकता क्यों है? सहायक तथ्य लिखें। 6 अंक

अभ्यास प्रश्न पत्र (हल सहित)
2023 2024

कक्षा 11 | विषय: राजनीतिक विज्ञान

समय: 3 घंटे | अधिकतम अंक: 80

सामान्य निर्देश:-

1. प्रश्न पत्र में कुल 30 प्रश्नों के साथ पांच खंड (ए, बी, सी, डी और ई) हैं।
2. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
3. प्रश्न संख्या 1-12 एक. एक अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। 4. प्रश्न संख्या 13-18 प्रत्येक 2 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50-60 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए ।
5. प्रश्न संख्या 19-23 प्रत्येक 4 अंक का है। इन प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक 100-120 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए। 4 अंकों के प्रश्नों में से दो में आंतरिक विकल्प है
6. प्रश्न संख्या 24-26 पैसेज, कार्टून और मानचित्र आधारित प्रश्न हैं। तदनुसार उत्तर दें।
7. प्रश्न संख्या 27-30 प्रत्येक 6 अंकों का है। इन प्रश्नों के उत्तर 170-180 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए। 8. 6 अंक वाले प्रश्नों में आंतरिक विकल्प होता है।

खंड (12 अंक)

1. भारतीय संविधान सभा की सर्वप्रथम बैठक कब हुई थी ?

   a. 7 दिसंबर 1946 b. 15 अगस्त 1947

   c. 9 दिसंबर 19465 d. 26 जनवरी 1950

उत्तर:- (c) 9 दिसंबर 1946

2. "मोतीलाल नेहरू समिति" ने "अधिकारों की एक घोषणा पत्र" की मांग कब उठाई थी?

   a. 1947 b. 1950

   c. 1926 d. 1928

उत्तर:- 1928

3. निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नजदीक बैठता है?

a. परिवार की बैठक में होने वाली चर्चा।

b. कक्षा संचालक (क्लास मॉनिटर) का चुनाव।

c. किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने उम्मीदवार का चयन।

d. मीडिया द्वारा कराए गए जनमत संग्रह।

उत्तर:- (a) परिवार की बैठक में होने वाली चर्चा।

रिक्त स्थान भरिए..

4. जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तब तक भारत को 1919 और.................. के अधिनियम के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था के संचालन का कुछ अनुभव हो चुका था।

उत्तर:- 1935

5. वर्तमान में लोकसभा के..............निर्वाचन क्षेत्र हैं। ये संख्या 1971 की जनगणना पर आधारित है।

उत्तर:- 543

6. न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि सरकार के अन्य दो अंग............... और कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाएं ताकि वह ठीक ढंग से न्याय कर सके।

उत्तरः विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के

निम्नलिखित कथन को सही करके पुनः लिखिए:-

7. भारतीय संघ को मजबूत करने के लिए, भारतीय संविधान द्वारा एक सशक्त राज्य सरकार की स्थापना की गई है।

उत्तरः- भारतीय संघ को मजबूत करने के लिए भारतीय संविधान द्वारा एक सशक्त केंद्र सरकार की स्थापना की गई है।

निम्नलिखित कथनों की जांच सत्य और असत्य कथन के आधार पर कीजिए :-

8. आधुनिक समय में, स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आए।

उत्तर:- सत्य

9. अनुच्छेद-3 संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है।

उत्तरः- असत्य

निम्नलिखित प्रश्न (10-12) में, अभिकथन (A) के बाद कारण (R) का कथन है।
निम्नलिखित उपयुक्त विकल्प चुनें:-

(a) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, और कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।

(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करताहै।

(C) अभिकथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

(C) अभिकथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।

10. अभिकथन (A) : भारतीय संविधान किसी एक शीर्षक में अटकने से इंकार करता है।

कारण (R): भारतीय संविधान उदारवादी लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, संघ वादी, सामुदायिक जीवन मूल्यों का हामी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ साथ ऐतिहासिक रूप से अधिकार, वंचित वर्गो के प्रति संवेदनशील है।

उत्तरः- (a) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।

11. अभिकथन(A) : नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन के 28 वर्ष जेल में बिताए।

कारण (R) : नेल्सन मंडेला ने अपनी आत्मकथा " लॉन्ग वॉक टु फ्रीडम पुस्तक में लिखी हैं।

उत्तरः- (b) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन कारण (R), कथन की सही व्याख्या नहीं करता है।

12. अभिकथन (A): समानता की अवधारणा में यह निहित है कि सभी मनुष्य अपनी दक्षता और प्रतिभा विकसित करने के लिए समान अवसरों के हकदार हैं।

कारण(R) : पुरुष स्त्रियों से बढ़कर हैं। यह एक प्राकृतिक सत्य है ।

उत्तरः- (d) अभिकथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।

खंड-बी (12 अंक)

13. राजनीतिक सिद्धांत के किन्ही दो क्षेत्रों को समझाइए।

उत्तर:- राजनीतिक सिद्धांत के दो क्षेत्र:

(i) राज्य और सरकार का अध्ययन।

(ii) शक्ति और राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन।

14. "रॉल्स के अज्ञानता की आवरण से क्या तात्पर्य है? समझाइए।

उत्तरः- "रॉल्स के "अज्ञानता की आवरण" से तात्पर्य : हम खुद को ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करें जहां हमें यह फैसला लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाए और साथ ही हमें यह भी पता न हो कि समाज में हमारी जगह क्या होगी, तब हम ऐसा निर्णय लेंगे जो सभी के लिए हितकर होगा।

15. किन्ही दो राजनीतिक अधिकारों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:- राजनीतिक अधिकार:-

(i) मत देने का अधिकार। (ii) निर्वाचित होने का अधिकार ।

16. एक नागरिक का दूसरे नागरिकों के प्रति क्या कर्तव्य है?

उत्तर:- एक नागरिक का कर्तव्य है कि वह दूसरे नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करें। सभी नागरिकों को रोजमर्रा के जीवन में सम्मिलित होने और योगदान करने का दायित्व शामिल है।

17. "राष्ट्रवाद साम्राज्यों के पतन के लिए जिम्मेदार रहा है। स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:- बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप में ऑस्ट्रिया हंगरी और रूसी साम्राज्यों के पतन तथा उनके साथ एशिया और अफ्रीका में फ्रांसीसी, ब्रिटिश, डच और पुर्तगाली साम्राज्यों के बंटवारे में राष्ट्रवाद ही था।

18. संविधान के दो महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख कीजिए ।

उत्तर:- संविधान के दो महत्वपूर्ण कार्य:-

(i) संविधान नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराता है, जिससे समाज एक दूसरे में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास पैदा होता है।

(ii) संविधान यह तय करता है कि समाज में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी।

19. हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों है?

उत्तर:- मौलिक अधिकार व्यक्ति के मूल विकास, सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। समाज में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक विकास लाने में मौलिक अधिकार सहयोग प्रदान करते हैं।

खंड.सी (20 अंक)

20. 'सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत' और ' समानुपातिक प्रतिनिधित्व' चुनाव व्यवस्था में कोई चार अंतर लिखिए।

उत्तर:-

'सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत'	'समानुपातिक प्रतिनिधित्व' चुनाव व्यवस्था
(i) देश को छोटे-छोटे निर्वाचन क्षेत्र में बांट देते हैं।	(i) पूरे देश का एक ही निर्वाचन क्षेत्र होता है।
(ii) हर निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि चुना जाताहै।	(ii) एक से अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं।
(iii) मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है।	(iii) मतदाता पार्टी को वोट देता है।
(iv) प्रत्याशी को मतदाता व्यक्तिगत रूप से जानता है।	(iv) प्रत्यासी को मतदाता जातिगत रूप से नहीं जनता है

21. भारत में प्रधानमंत्री पद की शक्तियों में आए बदलाव का वर्णन कीजिए।

उत्तर:- प्रधानमंत्री पद की शक्तियों में निम्नलिखित बदलाव आए हैं :-

(i) प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ गई।

(ii) राजनीतिक सहयोगियों से परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी है।

(iii) प्रधानमंत्री के विशेषाधिकारों पर अंकुश लगा है।

(iv) सहयोगी दलों के साथ बातचीत तथा समझौते के बाद ही नीतियां बनती हैं।

अथवा

लोकसभा की चार शक्तियां का वर्णन कीजिए।

उत्तर:- लोकसभा की चार शक्तियां:-

(i) विधायिका संबंधी शक्तियां (ii) वित्त संबंधी शक्तियां

(iii) न्यायिक शक्तियां (iv) कार्यकारणी पर नियंत्रण संबंधी शक्तियां

(v) संविधान में संशोधन संबंधी शक्तियां. (कोई चार)

22. हमें संसद की आवश्यकता क्यों है? चार कारणों द्वारा स्पष्ट कीजिए |

उत्तर; (i) संसद विधि निर्माण करती है।

(ii) संसद बजट पारित करती है।

(iii) संसद सरकार पर नियंत्रण करती है।

(iv) संसद संविधान में संशोधन करती है।

अथवा

लोकसभा अध्यक्ष के कोई चार कार्यों का वर्णन कीजिए।

उत्तर :- लोकसभा अध्यक्ष के निम्नलिखित कार्य हैं-

(i) लोक सभा की बैठकों की अध्यक्षता करना।

(ii) लोकसभा प्रस्ताव को अनुमति देना ।

(iii) सदन की प्रवर समितियों तथा अन्य समितियों के सभापतियों की नियुक्ति करना।

(iv) वित्त विधेयक पर निर्णय लेना।

23. कौन से मुद्दों पर भारत में संसद और न्यायपालिका के बीच टकराव की स्थिति रही है।

विभाजन के बावजूद संसद व न्यायपालिका के बीच टकराव भारतीय राजनीति की विशेषता रही है। जो

निम्नलिखित हैं:-

(i) संपत्ति का अधिकार के संबंध में।

(ii) संसद की संविधान को संशोधित करने की शक्ति के संबंध में।

(iii) निवारक नजरबंदी कानून के संबंध में।

(iv) नौकरियों में आरक्षण संबंधित कानून के संबंध में।

उत्तर:- भारतीय संविधान में सरकार के प्रत्येक अंग का एक स्पष्ट कार्यक्षेत्र है। इस कार्य विभाजन के इस कार्य (iii)

खंड.डी (12 अंक)

24. निम्नलिखित कार्टून का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए तथा नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए:-

27 अप्रैल 1952

'जब नेहरू राज्यपालों की नियुक्ति कर रहे थे तो उनमें से कुछ मंत्री पद छोड़ने को इच्छुक नहीं थे।''

24.1 राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?

(a) प्रधानमंत्री (b) उप प्रधानमंत्री

(c) राष्ट्रपति (d) उपराष्ट्रपति

उत्तर:- (c) राष्ट्रपति

24.2 राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है?

(a) 2 वर्ष (b) 4 वर्ष

(c) 6 वर्ष (d) 5 वर्ष

उत्तर:- (d) 5 वर्ष

24.3 कौनसे आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कठि राज्यपालों की नियुक्ति अनिवार्य तथा निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए।)

(a) शाह आयोग (b) मंडल आयोग

(c) सरकारी आयोग (d) सरकारिया आयोग

उत्तर:- (d) सरकारिया आयोग

24.4 राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता ह ?

(a) अनुच्छेद 356 (b) अनुच्छेद 352

(c) अनुच्छेद 358 (d) अनुच्छेद 556

उत्तर:- (a) अनुच्छेद 356

25. निम्नलिखित गद्यांश का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए:-

संविधान कोई जड़ और अपरिवर्तनीय दस्तावेज ही नहीं होता। संविधान की रचना मनुष्य ही करते हैं और इस नाते उसमें हमेशा संशोधन, बदला और पुनर्विचार की गुंजाइश रहती है। संविधान समाज की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होता है। संविधान समाज को लोकतांत्रिक ढंग से चलाने का एक ढांचा भी होता है, जिसे समाज खुद अपने लिए गढ़ता है।

25.1 संविधान से आपका क्या अभिप्राय है?

(a) सविधान नियमों का समूह है।

(b) संविधान कानूनों का समूह है।

(c) संविधान सिद्धांतों का समूह है।

(d) उपरोक्त सभी ।

उत्तर:- (d) उपरोक्त सभी।

25.2 भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे ?

(a) डॉ. बी एन राव (b) डॉ. बी आर अंबेडकर

(c) डॉ. बीआर वर्मा (d) डॉ. राजेंद्र प्रसाद

उत्तर:- (b) डॉ. बी आर अंबेडकर

25.3 भारतीय संविधान की जीवंतता का क्या प्रमाण है?

(a) दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है।

(b) दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए संविधान है।

(c) समय की मांग के अनुसार हुए संविधान संशोधन ।

(d) उपरोक्त में कोई नहीं ।

उत्तर:- (c) समय की मांग के अनुसार हुए संविधान संशोधन ।

25.4 संविधान का निर्माण किया जाता है.....

(a) सरकार की इच्छाओं के अनुरूप।

(b) समाज की इच्छाओं के अनुरूप।

(c) राष्ट्रपति की इच्छाओं के अनुरूप।

(d) प्रधानमंत्री की इच्छाओं के अनुरूप।

उत्तर:- (b) समाज की इच्छाओं के अनुरूप ।

26. भारत के रेखा मानचित्र में चार द्विसदनात्मक विधानसभा वाले राज्यों के नाम भरिए।

उत्तर:- (i) आंध्र प्रदेश (ii) महाराष्ट्र (iii) उत्तर प्रदेश

(iv) कर्नाटक (v) तेलंगाना) (vi) बिहार (कोई चार)

खंड.ई (24 अंक)

27. जनहित याचिका किस प्रकार गरीबों की मदद कर सकती है ?

उत्तर:- 27

i. अधिकार प्राप्त करना केंद्र / राज्य सरकार द्वारा भेदभाव पूर्ण व्यवहार को रोक कर ।
ii. राज्यों के द्वारा कार्य करते समय केंद्र सरकार का हस्तक्षेप ना करना ।
iii. केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता ना देना विकास संबंधी योजनाएं ना बनाने पर हस्तक्षेप । आदि..

अथवा

न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है क्या आप इस कथन से सहमत हैं ?

उत्तर:- 27.

i. मौलिक अधिकारों की रक्षा
ii. न्यायिक पुनरावलोकन
iii. न्यायिक सक्रियता
iv. सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का महत्वपूर्ण निर्धारण आदि

28. पंचायती राज व्यवस्था से क्या अभिप्राय है? यदि आप जिला कलेक्टर होते तो आप गावों की किन किन समस्याओं का समाधान करते ?

उत्तर:- गांव के स्थानीय शासन को पंचायती राज कहा जाता है। इसके तीन स्तर हैं और उन तीनों की व्याख्या करनी है।

अथवा

यदि आप अपने गांव की सरपंच होते तो समाज आपके कार्यों में किस प्रकार की बाधा उत्पन्न करता ? तब आप उन बाधाओं से कैसे छुटकारा पाते ?

उत्तर:- विद्यार्थियों द्वारा अपनी वैचारिक शक्ति का प्रयोग करते हुए समस्याएं और उनका निवारण स्वयं लिखना है

29. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है ? आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे ? उदाहरण सहित बताइए।

उत्तर:- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपने विचारों को प्रकट करने की आजादी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है व्यक्ति अपने विचार को कहकर लिखकर या किसी माध्यम से प्रकट कर सकते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रतिबंधों के कारण लोगों के स्वतंत्रता कायम रह सकती है। बहुत ज्यादा प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते वो स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करते हैं।

अथवा

जॉन स्टुअर्ट मिल के हानि सिद्धांत का वर्णन करो।

उत्तर:- किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता उदेश्य आत्मरक्षा है सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र लक्ष्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। अतः हानि पहुंचाने वाले कार्यों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं इसे ही हानि का सिद्धांत कहते हैं।

30. सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले तीन सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर:- समान लोगों के बीच समानता का बर्ताव।
जरूरतमंद के लिए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं और अवसरों का प्रावधान।
लाभ तय करते समय विभिन्न प्रयासों को मान्यता देना।
विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल।

अथवा

न्याय के विभिन्न आयामों की सविस्तार व्याख्या करें

उत्तर:- न्याय के विभिन्न आयाम :-

1. विधिक न्याय
2. राजनीतिक न्याय
3. सामाजिक न्याय
4. आर्थिक न्याय (चारों की व्याख्या)

Notes

Notes